षोडश माला, खंड 1, अंक 6

बुधवार, 11 जून, 2014
21 ज्येष्ठ, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 1 में अंक 1 से 6 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : एक सौ पन्द्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. श्रीधरन
महासचिव
लोक सभा

पी.वी.एल.एन. मूर्ति
संयुक्त सचिव

ऊषा जैन
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

संतोष कुमार मिश्र
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

देवेन्द्र कुमार शर्मा
सहायक सम्पादक

© 2014 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

[षोडश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2014/1936 (शक)]

अंक 6, बुधवार, 11 जून, 2014/21 ज्येष्ठ, 1936 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2
अध्यक्ष द्वारा बधाई	
किशोरों द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई	2-3
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) बिहार में उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना में लोहे के फाटक (जलद्वार) का निर्माण किए जाने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सुशील कुमार सिंह	3
(दो) देश के किसानों को बेहतर बीमा कवर दिए जाने हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश सिंह	4
(तीन) कृषि उत्पादों का आसानी से क्रय सुनिश्चित करने हेतु महाराष्ट्र में खेतों तक सड़क सम्पर्क बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.टी. नाना पाटील	5
(चार) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनों की सेवाएं बहाल किए जाने आवश्यकता	
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	5
(पांच) महाराष्ट्र के अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (मुम्बई-विशाखापत्तनम) को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	6
(छह) उत्तराखंड में 2013 में आई बाढ़ और भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण और प्रभावित हुए लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'	6

विषय	कॉलम
(सात) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय में उच्च न्यायालय की एक खंड-पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनुराग सिंह ठाकुर.....	7
(आठ) संविधान के अनुच्छेद 370 का निरसन किए जाने की आवश्यकता	
श्री कीर्ति आज़ाद.....	7
(नौ) बिहार में पटना और मनेर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	8
(दस) दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्रवाल.....	8
(ग्यारह) अरुणाचल प्रदेश की तांगसा, नोक्टे, टुट्चा, वांगचु और युबीन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री निनोंग एरिंग	9
(बारह) ट्रेन संख्या 12605 और 12606 (पल्लवन एक्सप्रेस) तथा 16101 और 16102 (रामेश्वरम एक्सप्रेस) का तमिलनाडु के किरानूर रेलवे स्टेशन पर ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. कुमार	9
(तेरह) तमिलनाडु में कुड्डालोर तिरूपपुलियार रेलवे स्टेशन पर सेंथुर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 16735/16736) का स्थायी ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री ए. अरुनमोझीथेवान.....	10
(चौदह) पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री कल्याण बनर्जी.....	11
(पंद्रह) ओडिशा राज्य में औद्योगिक सुधार के लिए राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब.....	11
(सोलह) नासिक में कुम्भ मेले के आयोजन के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे	12

विषय	कॉलम
(सत्रह) केरल में कोल्लम बाईपास निर्माण को समयबद्ध पूर्ण किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	12
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
263वां प्रतिवेदन	13
सदस्य द्वारा निवेदन	
पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय बलों की कुछ कंपनियों को हटाए जाने के प्रस्ताव के बारे में	13
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	
श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी	15
श्री पी.पी. चौधरी	18
श्रीमती पी.के. श्रीमती टीचर	19
एडवोकेट ज्वायस जार्ज	21
श्री तारिक अनवर	23
श्री शिवकुमार चनाबसप्पा उदासि	27
कुमारी शोभा करंदलाजे	29
श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल	32
श्रीमती सुषमा स्वराज	32
श्री रामचंद्र हंसदाह	41
श्री कमलेश पासवान	42
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	44
श्री प्रसन्न कुमार पाटसानी	46
श्री मुलायम सिंह यादव	47
डॉ. किरीट पी. सोलंकी	52
श्रीमती जयश्रीबेन कनुभाई पटेल	54
श्री आर. ध्रुवनारायण	58
श्री दद्दन मिश्रा	61
कैप्टन अमरिंदर सिंह	62
श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा	63
श्री डी.के. सुरेश	71

विषय	कॉलम
प्रो. सुगाता बोस	76
श्रीमती रमा देवी	81
श्री बी. श्रीरामुलु	83
श्री विष्णुपद राय	85
डॉ. धरम वीरा गांधी	88
श्री किरेन रिजिजु	91
श्री रमेन डेका	95
श्री राजीव शंकरराव सातव	96
श्री बदरूद्दीन अजमल	97
श्री रामसिंह राठवा	100
डॉ. पी. वेणुगोपाल	101
श्री जयदेव गल्ला	103
श्री अरविंद सावंत	106
डॉ. रत्ना डे (नाग)	109
श्री अर्जुन राम मेघवाल	111
डॉ. काकली घोष दोस्तीदार	115
श्री ई. अहमद	119
डॉ. ए. सम्पत	121
श्री एंटो एंटनी	125
श्री अनिल शिरोले	126
श्री हंसराज गंगाराम अहिर	127
श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल	129
श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम	132
श्री सुरेश चन्नाबसप्पा अंगाडी	135
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	137
श्री एम.आई. शानवास	140
श्री पी.के. बीजू	142
श्री कौशलेन्द्र कुमार	143
श्री दुष्यंत चौटाला	146
श्री गणेश सिंह	148

विषय	कॉलम
श्री जगदम्बिका पाल	152
श्रीमती कमला पाटले	155
श्री कादीयाम श्रीहरी	156
कुंवर भारतेन्द्र	159
श्रीमती ज्योति धुर्वे	160
श्री असादुद्दीन ओवैसी	160
श्री नेफिड रिओ	164
श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे	166
श्री प्रेम दास राय	168
श्री जोस के. मणि	169
श्री वीरेन्द्र कश्यप	171
श्री राजू शेट्टी	173
श्री रतन लाल कटारिया	174
श्री अजय	176
श्री एन.के. प्रेमाचंद्रन	177
श्री शरद त्रिपाठी	180
श्रीमती कोथापल्ली गीता	180
श्री सी.एन. जयदेवन	181
श्री भगवंत मान	183
श्रीमती रंजीत रंजन	183
श्री ए.टी. नाना पाटिल	185
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	186
डॉ. थोकचोम मेन्या	187
श्री नरेन्द्र मोदी	191
विदाई उल्लेख	204
राष्ट्र गीत	206

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. एम. तंबिदुरै
श्री हुक्मदेव नारायण यादव
प्रो. के.वी. थॉमस
श्री अनंदराव अडसुल
श्री प्रहलाद जोशी
डॉ. रत्ना डे (नाग)
श्री रमेन डेका
श्री कोनाकल्ला नारायण राव
श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी. श्रीधरन

लोक सभा

बुधवार, 11 जून, 2014/21 ज्येष्ठ, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : महासचिव अब उन सदस्यों के नाम पुकारेंगे, जिन्होंने शपथग्रहण अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है।

महासचिव : श्री प्रकाश बबन्ना हुक्केरी।

श्री प्रकाश बबन्ना हुक्केरी (चिक्कोडी) – अनुपस्थित।

प्रो. सांवर लाल जाट (अजमेर) – अनुपस्थित।

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर) – शपथ – अंग्रेजी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि श्री ए. नरेन्द्र, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अब तेलंगाना में है, का तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया, का दु:खद निधन हो गया है। श्री नरेन्द्र केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे। यह उद्योग संबंधी समिति, याचिका समिति, वक्फ बोर्ड की संचालन संबंधी संयुक्त समिति और रसायन तथा उर्वरक संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

श्री नरेन्द्र वर्ष 1983 से 1994 तक तीन कार्यकालों के लिए आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे। श्री ए. नरेन्द्र का निधन 9 अप्रैल, 2014 को हैदराबाद में 68 वर्ष की आयु में हुआ।

हम श्री ए. नरेन्द्र के दु:खद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष जी, मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी 6 जून, 2014 की उद्घोषणा जिसके द्वारा 28 अप्रैल, 2014 को उनके द्वारा जारी पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है तथा (पपप) जिसे उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत उनके द्वारा परिवर्तित किया गया था तथा 8 जून, 2014 से उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में 1 जून, 2014 के उपर्युक्त राजपत्र में सा.क.नि. 373(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 385(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 16/16/14]

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया शांत रहें, एक अच्छी बात कहनी है।

पूर्वाह्न 11.05½ बजे

अध्यक्ष द्वारा बधाई

किशोरों द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे तेरह वर्षीय कक्षा IX की छात्रा मलावथ पूर्णा द्वारा हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उर्म की महिला पर्वतारोही बनने की उपलब्धि हासिल करने का उल्लेख करते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। इस मुहिम में पूर्णा का साथ अन्य किशोर, साधनपतली आनंद कुमार ने दिया था ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं।

अनेक माननीय सदस्य : यह तेलंगाना से हैं। महोदया।

माननीय अध्यक्ष : यह ठीक है। यह अब तेलंगाना है। वे अब संपूर्ण भारत के हैं। वे भारतीय हैं और यह महत्वपूर्ण उपलब्धि दोनों ने 24 मई, 2014 को प्राप्त की।

मुझे विश्वास है कि यह सदन दोनों युवाओं को इस उपलब्धि पर बधाई देने में मेरे साथ हैं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मैं उनकी सफलता की कामना करती हूं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब नियम 377 के अंतर्गत, अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गयी हैं। वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे स्वयं 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्ची रख दें। केवल वही मामलें पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर को सभा पटल पर रख दी गई हो। शेश व्यपगत माने जाएंगे।

(एक) बिहार में उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना में लोहे के फाटक (जलद्वार) का निर्माण किए जाने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) **:** मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद (बिहार) और गया जिले के लगभग एक लाख दस हजार हैक्टेयर (110000 हैक्टेयर) जमीन की सिंचाई के लिए शुरू की गई अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना में सन् 1975 में कार्य शुरू हुआ। अभी तक लगभग 800 करोड़ रुपये से भी ज्यादा राशि खर्च करके भी परियोजना अधूरी है जबकि प्रारंभिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपये थी। साथ ही स्थापना व्यय के रूप में प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो रहा है और हजारों करोड़ रुपये परियोजना को पूर्ण करने के लिए लगेंगे।

इस महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजना के डैम (कुटकु डैम) में लोहे के फाटक लगाने पर सन् 2007 में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे डैम में पानी नहीं जमा होने के कारण बिहार और झारखंड की सवा लाख हैक्टेयर जमीन सिंचाई से वंचित हो रही है जिससे लगभग पांच लाख किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। जिससे लगभग पांच लाख किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। यह पूरा क्षेत्र उत्पाद प्रभावित भी है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुटकु डैम के डूब क्षेत्र में जाने वाली 6203 हैक्टेयर वन भूमि के बदले में वनीकरण के लिए उतनी ही भूमि लेने के शर्त को हटाते हुए लोटे के फाटक लगाए जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को अविलंब हटाया जाए जिससे इस खूबे इलाके में सिंचाई के साथ-साथ पेयजल का संकट दूर हो सके।

(दो) देश के किसानों को बेहतर बीमा कवर दिए जाने हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) **:** भारत देश कृषि प्रधान देश हे। कभी हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि थी। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या इस कार्य पर निर्भर है। देश के किसान हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होते हैं। जिसके कारण वे कर्ज के बोझ से दबते रहे हैं और इसी कारण से आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं।

वैसे भी खेती से किसानों की स्थिति खराब हो रही है। कृषि योग्य भूमि घट रही है। एक समय ऐसा आएगा जब देश एक-एक दाने अनाज के लिए विदेशों का मोहताज हो जाएगा।

देश में जिस अनुपात में सिंचाई, बिजली की आवश्यकता है, उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लगातार कृषि उत्पादन में खर्च बढ़ता जा रहा है। उस पर रोक नहीं लग पा रही है। मध्य प्रदेश, सहित कई राज्यों ने खेती के घाटे के धंधे को फायदे का धंधा बनाने के लिए कई कारगर उपाय किए हैं, किन्तु केन्द्र सरकार के सहयोग के बगैर किसानों की मदद नहीं हो सकती है। इसीलिए केन्द्र एवं राज्य सरकार को मिलकर राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू हो जाए जिसमें किसान के खेत को इकाई माना जाए तथा प्रीमियम की राशि में 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार 40 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 20 प्रतिशत राशि किसान खुद जमा रके और इस आधार पर 100 प्रतिशत फसलों का बीमा की योजना बनाई जाए तभी देश का किसान उभर सकता है।

अभी भी फसल बीमा योजना है। उनका लाभ न के बराबर किसानों को मिल रहा है। देश को एक राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की जरूरत है।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(तीन) कृषि उत्पादों का आसानी से क्रय सुनिश्चित करने हेतु महाराष्ट्र में खेतों तक सड़क सम्पर्क बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) : मैंने पिछले यूपीए-2 सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट किसानों के संदर्भ में रखा और उसे महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी लेकर केन्द्र सरकार के पास लाया था। हमारे देश में लगभग 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग किसान हैं, पर आज तक की सरकारों ने किसानों के लिए गांव से खेतों को जोड़ने वाले सस्तों पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए किसानों की मेहनत का फल उन्हें मिलते-मिलते रह जाता है। क्योंकि गांवों से खेतों को जाने के लिए सही रास्ता नहीं होने के कारण मानसून में थोड़ी-सी बारिश होने पर भी किसान अपने खेतों में जा नहीं सकता और उसका अनाज खेतों में ही खराब हो जाता है। इसे देखते हुए हमने महाराष्ट्र के जलगांव जिले के लिए वह पायलट प्रोजेक्ट डाला था।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इस समस्या का समाधान अवश्य करेगी और देश के किसानों को यह सौगात जल्द से जल्द मिल सकेगी।

(चार) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनों की सेवाएं बहाल किए जाने आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : पूरे देश में जो कुल 1260 गाड़ियों का ठहराव रद्द करने का आदेश पूर्व रेल मंत्री ने दिया है, उसे रद्द करते हुए जनहित में पुन: चालू करने का कष्ट करें। मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर, उत्तर प्रदेश के उत्तर-मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में पुखरायां, उरई, एटमोठ, चिरगांव स्टेशनों पर निम्न गाड़ियों का ठहराव पुन: बहाल किया जाए।

(1) 12103- 04 (पूना एक्स.)

(2) 12943-44 (उद्योग नगरी)

(3) 12107-08 (कुर्ला एक्स.)

(4) 12173-74 (उद्योग नगरी)

(5) 15015-16 यशवंतपुर

(6) 16094 मद्रास

(7) 12593-94 (एसी स्पे.)

(8) 15101-02 (जनसाधारण)

(9) 25111-12 (गोरखपुर-त्रिवेन्द्रम)

(10) 12591-22 (बरौनी-कोचीन)

(11) 12589-90 (गोरखपुर-सिकन्दराबाद)

(12) 12591-92 (गोरखपुर-बेंगलूरु)

(13) 12541-42 (गौरखपुर-मुम्बई एलटीटी)

(14) 1105-06 (झांसी बैरगपुर)

(15) 1109-10 (इंटरसिटी एक्स.)

(पांच) महाराष्ट्र के अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (मुम्बई-विशाखापत्तनम) को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : मुम्बई-विशाखापत्तनम (नेशनल हाइवे) राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 22 मालशेज घाट, अहमदनगर होकर गुजरता है। यह राजमार्ग देश का सबसे खतरनाक और बेहद जोखिम भरा और जानलेवा है। इसका दोहरीकरण भी इतना सिकुड़ गया है कि अगर आमन-सामने दो वाहन आए तो एक ही रूकना पड़ता है। मालशेज घाट क्षेत्र में वाहन चलाने का अर्थ है हर पल मौत से खेलना। इस राजमार्ग पर जरा सी भी गलती भरी पड़ सकती है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के दस अंकीय कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र में सड़क सुधार अंकित है। अत: मैं सरकार से विनती करता हूं कि अहमदनगर ग्रामीण क्षेत्र में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 222 को सगुम बनाने के साथ-साथ चार लेन वाला बनाया जाए ताकि आम जनता उस रास्ते पर ग्रामीण क्षेत्र से आसानी से सफर कर सकें।

(छह) उत्तराखंड में 2013 में आई बाढ़ और भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण और प्रभावित हुए लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' (हरिद्वार) : जैसा कि सर्वविदित है कि गत वर्ष उत्तराखंड में आई भीषण दैवीय आपदा से जानमाल की भारी तबाही हुई। राज्य में पुन: निर्माण का कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है और आज भी वहां हालात गंभीर है। सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, जो गांव के गांव बह गए और जिन लोगों के मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गए उनके न ही मकान बने और न ही उन्हें चिन्हित करके भूमि प्रदान की गई। जो गांव बहे हैं अभी तक उन्हें अन्यत्र नहीं बसाया गया है लोग दर-दर भटकने को मजबूर हैं। केदारनाथ सहित आपदा प्रभावित ज्यादातर इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमान्त क्षेत्र है। ऐसे में वहां सड़क निर्माण

न होना किसी भी आपात स्थिति में सैन्य आवागमन व रक्षा उपकरणों तथा रसद को प्रभावित कर रहा है।

अत:, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस विषय पर राज्य सरकार को निर्देश देकर आपदाग्रस्त क्षेत्र में सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर युद्धस्तर पर करवाएं ताकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को व्यवस्थित किया जा सके तथा आपदा से प्रभावित पीड़ित परिवारों एवं गांवों को शीघ्रतिशीघ्र समतल वन भूमि में बसाने की व्यवस्था करें।

(सात) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय में उच्च न्यायालय की एक खंड-पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश) : मैं सरकार और देश का ध्यान हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश 55.673 वर्ग किलोमीटर विस्तृत भू-भाग में फैला उत्तुंग हिमालय की शृंखलाओं में बसा पहाड़ी प्रदेश है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5.739 वर्ग किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है, जहां कांगड़ा से बस द्वारा जाने में प्राय: 12 घंटे लगते हैं। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लगभग मध्य भाग में स्थित है। जहां कांगड़ा से बस द्वारा जाने में प्राय: 12 घंटे लगते हैं। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लगभग मध्य भाग में स्थित है। जहां जिला मंडी, ऊना, हमीरपुर एवं चंबा जिलों में सटा हुआ है तथा प्रदेश की कुल आबादी का 64 प्रतिशत घनत्व इस क्षेत्र में है और इसी क्षेत्र के अधिकांश प्रकरण हिमाचल उच्च न्यायालय, शिमला में विचाराधीन हैं। न्याय की अवधारणा है कि देश के लोगों को सस्ता, शीघ्र एवं सुलभ न्याय मिले, परंतु कांगड़ा के लोगों को इस अवधारणा के विपरीत महंगा, विलंब से तथा दुर्लभ न्याय मिलता है, जो न्यायसंगत नहीं है। वर्तमान में कांगड़ा मुख्यालय पर ट्रिब्यूनल कोर्ट कुछ अंतराल के बाद बैठती है, लेकिन इससे लोगों को पूर्ण सुविधा नहीं मिल पाती है।

मेरा भारत के विधि एवं न्याय मंत्री से निवेदन है कि वे हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कांगड़ा जिला मुख्यालय में स्थापित करने हेतु अविलंब आदेश दें।

(आठ) संविधान के अनुच्छेद 370 का निरसन किए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के चलते महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, विस्थापित, अल्पसंख्यकों की सामाजिक स्थिति बेहद खराब है। विकास की दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू और कश्मीर बहुत पीछे है, प्रत्येक कश्मीरी के मूल अधिकार बहुत ही सीमित है, निवेश शून्य होने के कारण रोजगार के अवसर शून्य है, लोक रोजी रोटी के लिए परंपरागत कार्यों पर निर्भर हैं। धारा 370 हटते ही जम्मू और कश्मीर राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र के साथ हर क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर विकास कर सकता है। जम्मू और कश्मीर पर दुश्मन देश की गिद्ध दृष्टि हमेशा जमी रहती है। जिससे भारत की संप्रभुता को खतरा बना रहता है, इसलिए वहां पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाती जिसके दुष्परिणाम हमारे देश को समय-समय पर भुगतने पड़े हैं।

धारा 370 एक अस्थायी प्रबंध है, इसे अतिशीघ्र खत्म कर देश की संप्रभुता को मजबूत करने की अति आवश्यकता मौजूदा परिवेश में है।

(नौ) बिहार में पटना और मनेर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : एनएच-30 पटना से मनेर होते हुए आरा और बक्सर जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों भारी वाहन और अन्य सवारी गाड़ियां चलती हैं। मनेर सरीफ सूफी सर्किट में आता है इसके कारण इसकी महता और अधिक है। उर्स के मेले में देश विदेश से हजारों पर्यटक वहां आते हैं। किन्तु पिछले एक वर्ष से सड़क की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है और सड़क गड्ढ़े में तब्दील हो गई है। प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं में सैंकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। बरसात में तो सड़क पर चलता मुश्किल हो जायेगा। एनएचएआई द्वारा टेन्डर हुआ लेकिन अभी तक कोई कार्य आरंभ नहीं हुआ।

मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि पटना-मनेर एनएच-30 का मरम्मत और विकास कार्य अविलंब आरंभ करवाने की कृपा करें।

(दस) दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पूर्व की केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री जी द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने प्रमुख परियोजनाओं की पूर्णता के लिए समय-सीमा निर्धारित की थी। जिन परियोजनाओं के लिए यह समय-सीमा तय की गई थी उनमें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस

वे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार इस एक्सप्रेस वे का कार्य 15 मार्च, 2014 तक पूर्ण कर लिया जाना था। इसके पूर्व दिनांक 07.07.2009 को मेरे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 329 के जवाब में तत्कालीन माननीय मंत्री जी ने बताया था कि इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य दिसंबर, 2014 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस उत्तर के दो वर्ष पश्चात् पुन: दिनांक 08.08.2011 को मेरे द्वारा पूछे गए आतारांकित प्रश्न संख्या 1161 में माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य दिसंबर, 2015 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संकल्पना के अनुसार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे को बहुत पहले बन जाना चाहिए था परंतु विभिन्न आश्वासनों के बाद भी इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। इस कार्य को पूरा करने की दो समय सीमाएं दिसंबर, 2014 तथा दिसंबर, 2015 को तत्कालीन माननीय मंत्री जी द्वारा बताई गई थी तथा एक तीसरी समय-सीमा 1 मार्च, 2014 स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल द्वारा घोषित की गई थी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे का कार्य तुरंत आरंभ किया जाये तथा इस हाइवे के पूर्ण होने की समय-सीमा निर्धारित की जाये।

(ग्यारह) अरुणाचल प्रदेश की तांगसा, नोक्टे, टुट्चा, वांगचु और युबीन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री निनोंग एरिंग (अरुणाचल पूर्व) : मैं माननीय जनजातीय कार्य मंत्री के ध्यान में यह बता लाना चाहता हूं कि ऐसी पांच जनजातियां हैं जिन्हें अन्य नागा जनजातियों के रूप में जाना जाता है और जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। अरुणाचल के तीरप और चांगलांग जिले की ये जनजातियां हैं तांगसा, नोक्टे, टुट्चा, वांगचु और युबीन है। अत: यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी जाए।

(बारह) ट्रेन संख्या 12605 और 12606 (पल्लवन एक्सप्रेस) तथा 16101 और 16102 (रामेश्वरम एक्सप्रेस) का तमिलनाडु के किरानूर रेलवे स्टेशन पर ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली) : जम्मू तमिलनाडु के पुडुकोट्टी जिले में किरानूर टाउन पंचायत मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुडुकोट्टी लाइन के मध्य में स्थित है और इन दोनों कस्बों से इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है । इस कस्बे की कुल जनसंख्या लगभग 65,000 है। इसमें से अधिकतर लोग कृषि और व्यापार पर निर्भर है। वे नियमित अंतराल पर पुडुकोट्टी और तिरुचरापल्ली की यात्रा करते रहते हैं। वे अपने संबंधित गंतव्य पर सड़क मार्ग द्वारा पहुंचते हैं। हालांकि किरानूर में रेलवे स्टेशन है लेकिन केवल यहां पैसेंजर ट्रेन रूकती हैं। अब ट्रेन संख्या 12605 और 12606, पल्लवन एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 16101 और 16102 रामेश्वरम एक्सप्रेस किरानूर से होकर गुजरती है। किरानूर के लोग पल्लवन और रामेश्वरम एक्सप्रेस को किरानूर में ठहराव प्रदान करने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि वे समीप के पुडुकोट्टी और तिरुचरापल्ली से आसानी से पहुंच सके।

मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे पल्लवन एक्सप्रेस अर्थात् ट्रेन संख्या 12605 और 12606 और रामेश्वरम एक्सप्रेस अर्थात् 16101 और 16102 को किरानूर रेलवे स्टेशन में ठहराव प्रदान करने संबंधी आदेश दे।

(तेरह) तमिलनाडु में कुड्डालोर तिरूपपुलियार रेलवे स्टेशन पर सेंथुर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 16735/16736) का स्थायी ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री ए. अरुनमोझीथेवान (कुड्डालोर) : मैं तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जोकि एक जिला मुख्यालय भी है। यहां पर एक छोटा पत्तन भी है। इस शहर की कुल जनसंख्या लगभग 2 लाख है। कुड्डालोर में सरकारी अस्पताल, केन्द्र और राज्य सरकारों के कार्यालय तथा इंजीनियरिंग और कला महाविद्यालय भी स्थित है। कुड्डालोर में अपर्याप्त रेल सुविधा के कारण किसान, केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, व्यापारियों, उपचार के लिए अस्पताल में आने वाले रोगियों तथा छात्रों को सड़क परिवहन पर निर्भर होना पड़ता है। चेन्नई-ईगर्माट और तिरुचेन्डूर के लिए चलने वाली 'सेंथुर एक्सप्रेस' (ट्रेन संख्या 16736 और 16735) कुड्डालोर से गुजरती है और इसका कुड्डालोर तिरुपापूलियार रेलवे स्टेशन पर अस्थायी ठहराव है। दक्षिण रेल के प्राधिकारियों द्वारा छह महीनों में एक बार उक्त ट्रेन के ठहराव का नवीकरण किया जाता है। पिछले छह महीनों से इस ट्रेन के ठहराव का नवीकरण नहीं किया गया है जिसके कारण लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। इसलिए आपको कुड्डालोर तिरुपापूलियार रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्थायी ठहराव प्रदान करने का अनुरोध कर रहे हैं। मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से माननीय रेल

मंत्री से 'सेंथूर एक्सप्रेस' का कुड्डालोर तिरुपापूलियार रेलवे स्टेशन पर स्थायी ठहराव प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के सोलप के निकट बॉम्बे रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल का एक हिस्सा पांच वर्ष पूर्व गिर गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस प्रत्र का पुनर्निर्माण कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके परिणामस्वरूप हर समय यहां भारी यातायात जाम रहता है। इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

(पन्द्रह) ओडिशा राज्य में औद्योगिक सुधार के लिए राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : नीतिगत मामले के रूप में, ओडिशा ने कई बार कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है कि राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से राज्य स्थित उद्योगों हेतु पहले कोयले की आवश्यकता पर विधिक विचार किया जाए। वस्तुत: ओडिशा में वर्तमान में जारी औद्योगिक परिवर्तन हेतु राज्य में अभी स्थापित किए जा रहे विद्युत संयंत्रों और इस्पात संयंत्रों हेतु कोयले की अतिरिक्त 250 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) आपूर्ति की आवश्यकता होगी, जिसमें से अभी केवल 50 एमटीपीए ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

यद्यपि, कोयला मंत्रालय से सरकारी वितरण मार्ग के अंतर्गत राज्य के सरकारी क्षेत्र के खनन उपक्रमों के लिए कोयला भण्डारों के न्यूनतम 7000 एमटी के आवंटन हेतु अनुरोध किया जा रहा है, राज्य से कोयला ब्लॉकों का आवंटन अन्य राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को किया गया है, जिसमें इन चालू परियोजनाओं हेतु कोयले की आवश्यकता की अनदेखी की गई है। वस्तुत:, कोयला मंत्रालय की अधिसूचना दिनांकित 31.12.2012 द्वारा आवंटन हेतु अधिसूचित चार कोयला ब्लॉकों में से केवल एक ब्लॉक ही ओटीपीसीएल, राज्य विद्युत सरकारी क्षेत्र उपक्रम, को आवंटित किया गया, जबकि चंद्रबिला कोयला ब्लॉक सहित शेष तीन को अन्य राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों/केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को इस तथ्य के बावजूद आवंटित किया गया कि इन सभी ब्लॉकों का आवंटन ओपीजीसी सहित राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को आवंटित करने की सिफारिश की गई थी।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ओडिशा राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को वरीयता के आधार पर कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए तत्काल कदम उठाएं।

(सोलह) नासिक में कुम्भ मेले के आयोजन के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक) : नासिक में जुलाई, 2015 में कुम्भ मेला आयोजित किया जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पुख्ता इंतजाम करने के लिए काफी अधिक खर्च होने की संभावना है। इस संबंध में संघ सरकार से अनुरोध है कि इस आयोजन के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करें और इसे महाराष्ट्र सरकार को जारी करें ताकि सारी व्यवस्थाएं की जा सकें।

(सत्रह) केरल में कोल्लम बाईपास निर्माण को समयबद्ध पूर्ण किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : 45 मीटर चौड़ाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कोल्लम बाईपास हेतु भूमि अधिग्रहण 1978 में पूरा किया गया था। परन्तु कल्लमहगम से मेयुराम तक का खंड ही दो लेन ट्रेफिक के लिए 12 मीटर चौड़ाई के साथ पूरा किया जा सका है। शेष 8.35 किमी. पर पिछले 35 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। यद्यपि, निर्माण को पैकेज-II, एनएचडीपी-III में सम्मिलित किया गया था, परन्तु कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार ने ईपीसी के आधार पर 50:50 लागत भागीदारी आधार पर बाईपास के निर्माण के लिए समझौता किया है, यद्यपि, प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, कार्य में निविदा प्रक्रियाओं के कारण विलंब हो रहा है।

कोल्लम शहरी भारी यातायात सघनता का सामना कर रहा है और एक किमी. की दूरी तय करने में एक घंटे का समय लगता है। इस यातायात सघनता का एकमात्र समाधान बाईपास का शीघ्र निर्माण है। सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा एनएचएआई को कोल्लम बाईपास के लिए समयबद्ध कार्यवाही और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

इसलिए, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से हस्तक्षेप करने और कोल्लम बोर्ड के समयबद्ध निर्माण हेतु तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

263वां प्रतिवेदन*

[अनुवाद]

महासचिव : महोदया, मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यकरण विषयक मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 263वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.07½ बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय बलों की कुछ कम्पनियों को हटाए जाने के प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल राज्य से केन्द्रीय बलों की 13 कम्पनियों को हटाया जा रहा है। यह सूचना हमें मिली है। इन बलों को झारखंड-मिदनापुर सीमा, जंगलमहल सीमा और दार्जिलिंग-नेपाल सीमा पर तैनात किया गया है।

हम संघीय ढांचे में विश्वास करते हैं और फिर इसका कुछ सांविधानिक दायित्व भी है। बेहतर होगा कि माननीय गृह मंत्री इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बात करें और तब इस पर निर्णय लें। श्री राजनाथ सिंह, मैं आपसे इस मुद्दे के संबंध में अनुरोध करुंगा। बंगाल अब एक प्रादर्श और सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। यदि ऐसा हुआ और कोई आकस्मिक घटना हुई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अत:, आप इस निर्णय को रोकें, राज्य सरकार से बात करें की और तद्नुसार निर्णय लें।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि मैं पूरे मामले की जानकारी हासिल करूंगा और इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश के फेडरल करेक्टर की संसेटिविटी पर किसी भी सूरत में हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देंगे।

---

*समिति (2013-14) ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व 6 मई, 2014 को माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सभापति ने प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था।

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिंदर सिंह (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदया, मैं सभा का ध्यान देश की सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह सत्ता पक्ष के एक माननीय मंत्री से संबंधित है। उनकी अभी सरकार ही इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में गयी है। यहां यह कहा गया है कि "और सेना प्रमुख के रूप में सिंह द्वारा उन पर लगाई गई अनुशासनिक रोक को वर्णित किया गया... "...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अखबार में छपी खबर का आप यहां हवाला नहीं दे सकते।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिंदर सिंह : ठीक है महोदया, मैं अखबार से नहीं पढ़ूंगा। पर क्या मंत्री जी ऐसा ट्वीट कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आज हम शून्य काल नहीं ले रहे हैं, मैंने आपकी बात समझ ली है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने मुद्दा उठाया है। ठीक है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह : महोदया, उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा मद संख्या 6 पर विचार करेगी। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इसे अभी नहीं ले सकते।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी बोलें।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, अन्य कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी कृपया आप बोलिए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.11 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव — *जारी*

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा मद संख्या 6 पर विचार करेगी। श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जाएगी।

श्री राजमोहन रेड्डी बोलें।

...(व्यवधान)

श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी (नेल्लोर) **:** माननीय अध्यक्ष मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। 9 जून, 2014 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत के माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का जो अवसर आपने दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : श्री राजमोहन रेड्डी के भाषण के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वहीं दूसरी ओर मैं माननीय प्रधानमंत्री को 16वीं लोक सभा के चुनावों में उनकी प्रचंड जीत के लिए बधाई देना चाहूंगा...*(व्यवधान)* इसके 30 वर्ष पहले ही कोई एक पार्टी सत्ता में आई थी...*(व्यवधान)* उसके बाद से गठबंधन का युग शुरू हो गया। तीस वर्षों के उपरांत, देश के लोगों ने पुन: एक ही पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत दिया है। इसके माध्यम से देश के लोगों ने लोकतंत्र की परिभाषा को दर्शाया है जो जनता द्वारा, जनता की ओर जनता के लिए है। यह बहुत ही बड़ी बात है। अन्यथा, एक साधारण सी पृष्ठभूमि और साधारण शुरुआत का व्यक्ति इस महान और लोकतंत्र के सबसे बड़े पद, प्रधानमंत्री के पद, पर आसीन नहीं होता। इसलिए, हम माननीय प्रधानमंत्री, उनके दल और उनके सहयोगियों को तहेदिल से बधाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर, मैं उनके द्वारा व्रूक्त की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनसे आग्रह करना चाहूंगा।

देश के लोगों को आपसे और आपकी सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद् को देश की समस्याओं से निपटने तथा इसकी राजकोषीय और आर्थिक स्थिति बहाल करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। देश बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है। जैसे अनेक राज्य बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। हमें इस समस्या से अतिशीघ्र निपटना होगा। यह समस्या कोयले तथा प्राकृतिक गैस की कमी के कारण उत्पन्न होती है। उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। पिछले तीन वर्षों से कोयला निकालने में अतिरिक्त वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए कोयला आधारित सभी विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन नहीं हो रहा है। अधिकांश राज्य इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

प्राकृतिक गैस की भी कमी है। प्राकृतिक गैस आधारित बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गई है। किन्तु अधिकांश परियोजनाएं प्रचालनात नहीं है। उदाहरण के लिए कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक कंपनी को छोड़कर तीन अन्य कंपनियां, जिन्हें गैस उत्पादन के लिए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, एक घन मीटर गैस का भी उत्पादन नहीं कर रही है एवं सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अवसंरचना की भी यही स्थिति है। मैं राष्ट्रीय राजमार्गों का उदाहरण देता हूं। सभी परियोजनाएं रुक गई हैं क्योंकि कोई निर्णय लिया ही नहीं गया। निर्णय लेने वाला कोई था ही नहीं। कम-से-कम अब लोगा नई सरकार से आशा कर रहे हैं कि वह इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शीघ्र निर्णय ले। उनमें ठहराव आ गया है। सरकारी-निजी साझेदारी के भागीदार धारक बर्बादी के कगार पर हैं। इसके साथ ही अनर्जक बातें बैंकिंग क्षेत्र के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं। इसलिए इसमें सुधार किया जाना चाहिए। ऐन वक्त पर सम्यक और सही निर्णय लिए जाने चाहिए। सभी अवसंरचना कंपनियां असमजस की स्थिति में हैं। बहुत से ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। अत: मैं केन्द्र सरकार के अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में कार्रवाई करे और शीघ्र निर्णय ले।

इसी तरह देश को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की महंगी मुद्रा नीति के बावजूद मुद्रा स्थिति विशेषकर खाद्य वस्तुओं की मुद्र स्फीति बहुत अधिक रही है। दुर्भाग्य यह है कि एक संस्था के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक इस बात की अनुभूति किए बिना कि केन्द्र सरकार द्वारा बहुत अधिक उधारी लिए जाने के कारण उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति बनी है, मुद्रा स्फीति की दर के संदर्भ में रेपो की स्थिति रेपो की दरों तथा ब्याज दरों में यंत्रवत बढ़ोत्तरी की कमी तक स्वयं को सीमित रखता है। केन्द्र सरकार उधारी का उपयोग न केवल पूंजीगत व्यय के लिए बल्कि राजस्व का घाटे को पूरा करने के लिए करती है। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार की उधारियों पर नियंत्रण करने में असमर्थ है इसलिए उससे वस्तुत: उत्पादक कार्पोरेट क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हुई है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदया, इसी तरह अन्वेषण हेतु गैस ब्लॉक के आवंटन में अत्यधिक विलंब हुआ है। इसके परिणामस्वरूप देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है जोकि दुगुना महंगा है। इसके अलावा यह भुगतान संतुलन की स्थिति पर प्रभाव डालता है। देश को 2013-14 में 138 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।

यदि हमारे पास कोयला और प्राकृतिक गैस नहीं होगी तो हम देश में बिजली की स्थिति में कैसे सुधार की आशा कर सकते हैं? बिना बिजली के हम विकास कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार बिना विकास के सामाजिक सुरक्षा कैसे हो सकती है? यदि हम ऐसे सामान का आयात कर रहे हैं जिसे भारत में बनाया जा सकता है तो हम न केवल विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे बल्कि हम देश में बेरोजगारी का आयात भी कर रहे हैं।

देश कठिन दौर से गुजर रहा है। हमें अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। समय की मांग समानता के साथ विकास करने की है। तेज आर्थिक विकास गरीबी में तेजी से न केवल कभी करने का उपाय है बल्कि यह स्वयं सिद्ध है। हमें शासन चाहिए। हमें अपने राजनीतिक अंतर्विरोधों को भुलते हुए इस महान प्रयास में मिलकर कार्य करना चाहिए। यदि हम अब असफल रहेंगे तो जिन लोगों ने हमें यहां भेजा है, वे हमें माफ नहीं करेंगे।

सरकार को चीन, जो वर्तमान में 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार एकत्र करके उसका निवेश करने की सोच रहा है, के साथ सीमा विवाद के समाधान के लिए राजनीतिक सहमति प्राप्त करने हेतु निर्भकता और सहास का परिचय देना चाहिए। जापान भी 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा के साथ एक बड़ा निवेशक है। हम सबको मिलकर सभी स्तरों पर लाल-पीता शाही और भ्रष्टाचार को दूर कर भारत की छवि को निवेश के लिए बेहतर स्थान के रूप में निखारना चाहिए।

जब राष्ट्र बहुत से महत्वपूर्ण समस्याओं से जूझ रहा है तब आंध्र प्रदेश पहला भाषायी राज्य है जिसका बंटवारा सभी मानकों को दरकिनार करके किया गया। राज्य का विभाजन करने के बाद हमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किए गए वायदे तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा कि गए आश्वासनों का पालन करे। हम भारत सरकार से यह भी अनुरोध करते हैं कि वह आंध्र प्रदेश को दिए गए विशेष दर्जे में वृद्धि करें तथा इसे पांच वर्ष की जगह पच्चीस वर्ष तक बढ़ा दें। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को तेजी से विकास करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।

कृपया यह स्मरण रहे कि इसी सभा में अवसरवादी दल बदलुओं को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था तथा इससे लोकतंत्र की मर्यादा और गरिमा बहाल हुई। इसी तरह एक ऐसा समय आया है जब इस बात पर वाद-विवाद होना चाहिए कि क्या अपने घोषणा-पत्र में जानबूझ कर गलत वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करने सहित उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

अपने घोषणा पत्रों में जानबूझ कर झूठा वादा करने वाले तथा सत्ता में आने के बाद उसे भूलने या नजरअंदाज करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने सहित उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में एक मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख प्रासंगिक होगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए ऐसे वादों जिनको पूरा न किया जा सके, से निर्बाध और निष्पक्ष चुनाव की जड़े हिल जाती हैं। मैं इसके उल्लेख में माननीय प्रधानमंत्री जो स्वयं घोषणा पत्र में किए गए झूठे वादों के खिलाफ है, से अनुरोध करता हूं कि वे समुचित कानून बनाकर इस मामले को तार्किक परिणति तक पहुंचाएं।

अंत में, मैं अपनी पार्टी की ओर से सरकार को सार्वजनिक हित के प्रत्येक मामले में समर्थन देने का आश्वासन देता हूं। महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

***श्री पी.पी. चौधरी** (पाली) : माननीय राष्ट्रपति जी का दिनांक 06.09.2014 को अभिभाषण हुआ, परम्परानुसार सबसे पहले अभिभाषण पर चर्चा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के लिए एक वर्ष के एजेण्डा की घोषणा होती है, इसलिय यह अतिमहत्वपूर्ण है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है, चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा का हो, विदेश नीति का हो, आधारभूत सुविधाओं का हो, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, किसानों की समस्या एवं भारत निर्माण योजना का हो। इसके अतिरिक्त इस अभिभाषण में मुख्यत: राष्ट्रीय सूर्य ऊर्जा मिशन, रेल सम्बंधित योजनाएं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान, विदेशों से काला धन वापस लाया जाना तथा आम आदमी को सुलभ न्याय दिलाने संबंधी योजनाओं आदि का समावेश किया गया है।

महामहिम राष्ट्रपजि जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही बताया है। घरेलू वातावरण में निवेश को और अधिक अनुकूलं बनाने की आवश्यकता के साथ-साथ सार्वजनिक व निजी निवेश, घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेश प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने पर भी जोर दिया है।

इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा विकास दर को 9 प्रतिशत पर स्थिरता प्राप्त होगी। दलित, अल्पसंख्यक,

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

किसानों, महिलाओं व मजदूरों को विकास में पूर्ण भागीदारी प्राप्त होगी।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रेषित करता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती पी.के. श्रीमती टीचर** (कन्नूर): इस अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा 09 जून, 2014 को एक साथ समवेत हुए संसद के दोनों सदनों में दिये गए अभिभाषण के लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट करती हूं।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केन्द्र सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष की नीतियां और कार्यक्रम शामिल हैं।

सरकार द्वारा घोषित की गई नीतियों में से एक में यह प्रस्ताव है देश में स्वर्णिम चतुर्भुज (डायमंड क्वाड्रीलेटरल) हाई-स्पीड ट्रेन आरंभ किया जाना। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसी के साथ ही, सरकार को भारतीय रेल की दयनीय दशा को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। हमारे अधिकांश रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों की स्थिति दयनीय है। रेलवे लाइनों पर मानव मल और भरे हुए गंदे पानी से उल्टी जैसी दुर्गंध के कारण रेलवे प्लेटफार्म पर थोड़े समय के लिए भी खड़े होना मुश्किल है। रेलगाड़ी के डिब्बे चूहों, दीमक और कॉकरोचों से संक्रमित हैं। रेलगाड़ियों के शौचालय गंदे हैं और इनके बहुत सारे नल, पाइप और खिड़कियों के शीशे गायब हैं। दूर तक जाने वाली रेल गाड़ियों में विशेष रूप से छुट्टियों या गार्मियों के दौरान आरक्षण कराने के लिए महीनों पहले टिकट लेने पड़ते हैं। दक्षिण भारत की ओर जाने वाली रेलगाड़ियां पुरानी और जीर्ण-शीर्ण हैं। मानव मल के कारण रेल लाइनों में जंग लग रही है। न तो प्लेटफार्म और न ही रेलगाड़ियों में नि:शुल्क स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाला भोजन निम्न गुणवत्ता वाला है और मात्रा में बहुत गम है। हमारे अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट या स्वचालित सीढ़ियों की कमी के कारण लोग, विशेषरूप से महिलाओं और बुजुर्गों को अपने सामान के साथ प्लेटफार्मों पर आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे रेलगाड़ियों में चोरी और झपटमारी आम बात है। इसलिए रेलवे की स्थितियों को सुधारना हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए।

यह एक स्वागत योग्य कदम है कि सरकार संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। यह जानकर खुशी हुई है कि सरकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपराध संबंधी न्याय तंत्र को सुदृढ़ बनाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व खुले आम भारत में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे यौन हमलों, तेजाबी हमलों और हिंसा को देख रहा है। यह जानकर दु:ख होता है कि हाल ही के यौन उत्पीड़न हमले और उत्तर प्रदेश के बदायूं में लड़कियों की निर्मम हत्या की किसी और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने निंदा की थी। दिल्ली का निर्भया यौन उत्पीड़न हमला और निर्मम हत्या का मामला और मुम्बई की शक्ति मिल का यौन उत्पीड़न का मामला अभी भी हमारे मानस-पटल पर जिंदा है। यद्यपि देश में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त अपराध निरोध कानून हैं लेकिन हमारी सरकारें इन्हें उचित रूप से कार्यान्वित करने में असफल रही हैं।

बाल दुर्व्यापार और मादक द्रव्य दुर्व्यापार देश में व्यापक पैमाने पर प्रचलित है। यह जानकर वास्तव में आश्चर्य होता है कि केरल में दुर्व्यापार के द्वारा लाए गए 119 बच्चों में से 19 बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के हैं। मीडिया और आम जनता के हस्तक्षेप के सभी 119 बच्चों को केरल सरकार द्वारा झारखंड में उनके माता-पिता के पास वापस भेजा जा रहा है। व्यथित करने वाली ऐसी अनेक रिपोर्ट हैं कि हमारे विद्यालय और महाविद्यालयों में परिसरों में मादक दृव्यों का उपयोग बढ़ रहा है। छात्रों द्वारा मादक-द्रव्यों के उपयोग को रोकने के लिए परिसरों में छापे मारने के लिए प्रभवी कदम अवश्य उठाए जाने चाहिए। देश के संगठित मादक-द्रव्य माफिया नेटवर्क का पता लगाने और उनको दंड देने के लिए प्रभावी तंत्र लागू किया जाना चाहिए। सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू रहित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

देश में गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाये। निजी शैक्षणिक संस्थाओं की संकाय, अनुसंधान सुविधा, प्रयोगशाला आदि की नियमित जांच करने के लिए सुदृढ़ तंत्र होना चाहिए। निजी संगठनों द्वारा चलाए जा अनेक अभियांत्रिकी और चिकित्सा महाविद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। ऐसी संस्थाओं की मान्यता रद्द की जानी चाहिए।

देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों में खेल अवसंरचना की व्यापक पैमाने पर स्थापना की जानी चाहिए।

हम जानते हैं कि बड़ी मात्रा में खाद्यान्न हमारे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़ा सड़ रहा है या चूहों और कीड़ों द्वारा खाया जा रहा है जबकि देश में प्रतिदिन बहुत से लोग रात को भूखे ही सोते हैं। इसे रोकने के लिए पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। गरीबी विरोधी योजना को राज्य सरकारों के सहयोग से प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देश में किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायें। किसानों को उर्वरक नियंत्रित और राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराया जाए। उनको कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जायें। किसानों को फसल बीमा की सुविधा होनी चाहिए। कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाये।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया जाना चाहिए। पथ विक्रेताओं के लिए बनाए गए कानून को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। देश में सब्जियों और फलों को नष्ट होने से बचाने के लिए देश में शीतागारों की श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए।

देश में काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए। केरल की पर्यटन क्षमता के विकास हेतु ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। देश में न्यायिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता हेतु कानून बनाए जाने चाहिए। लंबित मामलों के निपटारे हेतु न्यायालयों की रिक्तियां तुरंत भरी जानी चाहिए। लंबित मामलों के निपटारे हेतु न्यायालयों की रिक्तियां तुरंत भरी जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। देश में और अधिक एम्स, नर्सिंग और भेषज कॉलेज स्थापित किए जाने चाहिए। एक अधिक रोजगारोन्मुखी शिक्षा नीति बनाई जानी चाहिए। बेरोजगार युवाओं के लिए और अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाने चाहिए। बिराश्रितों के लिए 1000/- रुपए प्रति मास की एक वृद्धावस्था पेंशन होनी चाहिए। केरल में, विशेषकर कन्नूर में एक कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। देश में रबर उत्पादकों की सहायता हेतु रबड़ के आयात पर रोक लगाई जानी चाहिए।

***एडवोकेट ज्वायस जॉर्ज** (इडुक्की) : संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करने के लिए मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं।

मैं नव गठित लोग सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। चाहे सरकार के पास सदन में पूर्ण बहुमत है, मैं आशा करता हूं कि सुदृढ़ धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राष्ट्र की विविधता और एकता में अनुरोध लाने के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। संपूर्ण राष्ट्र लोकतंत्र की मजबूत नींव पर निर्मित है जिसकी आधारशिला धर्मनिरपेक्षता है। विभिन्न विश्वासों और धर्मों वाले लोगों के बीच राष्ट्र की बहुलता, सहिष्णुता के सिद्धांत पर विस्तृत रूप से स्वीकार्य है और मानी जाती है। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष मूल्य अनदेखे नहीं किए जाएंगे।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हम कृषक समुदाय को अनदेखा करने राष्ट्र के कल्याण के विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्यवश कृषक समुदाय से संबंधित मामलों को समुचित रूप से संबोधित नहीं किया है। कृषक समुदाय की समस्याओं का समाधान किए बिना एक अच्छा शासन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि 60% जनसंख्या इसी वर्ग के लोगों की है।

कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को अपने जीवन-यापन में बहुत समस्याएं आ रही है। नकदी फसलों जैसे रबड़, इलायची, काली मिर्च आदि के मामले में यह मुद्दा अंत्यत गंभीर है। अब 8 महीने के बहुत कम सयम में प्राकृतिक रबड़ की कीमत 250 रुपए से 135 रुपए तक गिर गई है। प्राकृतिक रबड़ की कीमत में इस कमी के कारण, करेल की अर्थव्यवस्था ने एक वर्ष में न्यूनतम 4000 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। कीमत में यह अचानक आई कमी प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क में कमी करने के संबंध में सरकार की नीति के कारण हैं जिसने फिर से विस्तृत पैमाने पर आयात को बढ़ाया है। आयात शुल्क घटाकर टायर विनिर्माताओं को सिंथेटिक रबड़ आयात करने की स्वीकृति देने की सरकार की नीति से किसानों की और दुर्दश हो गई है। इलायची उद्योग भी इसी समस्या का सामना कर रहा है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए वाजिब कीमत प्रदान करके किसानों के हितों की रक्षा हेतु नीतियां और कानून बनाए।

एक अन्य मुद्दा, जो मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा, वह प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले और डॉ. कस्तूरीरंगम की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कार्य समूह की सिफारिशों पर पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) पश्चिमी घाट में रहने वाले लोगों की आशंकाओं से संबंधित है। कृषक समुदाय को इन दोनों रिपोर्टों की अवधारणाएं स्वीकार नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूजीईईपी और एचएलडब्ल्यूजी ने संरक्षण के वास्तविक मुद्दे पर उस क्षेत्र में रह रहे लोगों को सूचित कर, उनकी सहमति लेकर, सक्रिय भागीदारी और उन्हें शामिल कर विचार नहीं किया। ये दोनों रिपोर्टें लोगों को शामिल करने वाली विचार-विमर्श प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना प्राप्त या तैयार की गई। डब्ल्यूजीईईपी का दृष्टिकोण और निष्कर्ष पर्यावरणीय कट्टरता की भांति है।

डब्ल्यूजीईईपी और एचएलडब्ल्यूजी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर प्रकृति को संरक्षित करने का प्रयास पश्चिमी घाट क्षेत्र में रह रहे लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के सिवाय और कुछ नहीं है जो कि गैर-उत्पादक साबित होगा। केरल में संबंध में, डब्ल्यूजीईईपी ने कहा है कि लगभग पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील जोन है। संपूर्ण इडुक्की जिले को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील जोन-1 में वर्गीकृत किया गया है और अस्पतालों, खाद्य

प्रसंस्करण दवाइयों, फार्मों की स्थापना एंव उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग कर किए जाने वाली अन्य कृषि गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की संस्तुति की गई है। यदि किसी भी रिपोर्ट को कार्यान्वित किया गया तो लोगों की विकास को आकांक्षाओं पर कुवाराघात होगा।

अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों पर विशेष रूप से आधारभूत सुविधाओं और अवसंरचना सुविधा के क्षेत्र में और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए कि अनुसूचित जनजातियों के हितों हेतु प्रारंभ की गई योजनाओं के लाभ लक्षित प्रयोजन हेतु उपयोग किए गए।

शिक्षा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों में शिक्षा सुविधाओं में सुधार के प्रयास भी शामिल किए जाने चाहिए। गुणात्मक शिक्षा में कमी से वंचितों को उनके जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में समस्या होगी। इससे गरीबों और वंचित लोगों के उत्थान में रूकावट आएगी।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि प्रकृति के संरक्षण या लोगों का कल्याण करने के लिए उन्हें विश्वास में लिए बिना दिलाए, उन्हें शामिल किए और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किए बिना किए गए किसी भी प्रयास से वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रकृति के संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और कमजोर वर्गों के उत्थान के मामले में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, वह सरकार का रोड मैप होता है। आने वाले दिनों में सरकार की क्या दिशा होगी, आगे देश के हित में उनकी क्या योजना है, उसको वह उजागर करता है, उसको यह दर्शाता है। यह बात सभी लोग जानते हैं कि जो जनादेश आया है, वह भाजपा और एनडीए के पक्ष में आया है और हम उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनादेश होता है, वही अंतिम होता है और हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कल से आज तक जो हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने भाषण दिया, उससे उनके थोड़े अहंकार की बू आ रही है और मैं समझता हूं कि यह किसी भी सरकार या किसी दल के लिए ठीक नहीं है। मुझे उर्दू का एक शेर याद आ रहा है:–

"मिले जरूज़ तो इंसानियत की हद में रहो,
यही तो वक्त है कुदरत के आज़माने का।"

इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार के सभी महत्वपूर्ण लोग यहां बैठे हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि जो जनता ने उन्हें अवसर दिया है, उसका किस तहर से जन हित में वे लाभ उठा सकते हैं। हम इस बात से सरकार को आश्वस्त करते हैं कि जनता और देश के हित में आपकी ओर से जो भी पहल होगी, उसको हमारा समर्थन प्राप्त होगा। विपक्ष के रूप में सिर्फ विरोध के लिए हम विरोध नहीं करेंगे। जहां हम इस बात को महसूस करेंगे कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं, आप अपने वादे से भटक रहे हैं, वहां हम आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे और एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनता लोकतांत्रिक पद्धति को अच्छी तरह समझती है। उनका फैसला बहुत सोचा-समझा होता है। इसलिए वह हमें सर पर भी बैठाती है और कभी-कभी सत्ता से बाहर भी कर देती है। इसलिए इस गलतफ़हमी को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी साहब यहां नहीं हैं जिन्होंने इस धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत की थी। उन्होंने जो कल बातें कहीं, मैं चाहता था कि उनके सामने मैं वे बातें दोहराऊं। धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए उन्होंने जो बातें कल कहीं, हम उसकी अपेक्षा नहीं करते थे क्योंकि राजीव प्रताप रूडी जी को मैं शुरुआत के दिनों से जनता हूं। वह बहुत अच्छे वक्ता हैं। हमने राज्य सभा में उनके साथ काफी लंबा समय गुजारा है। उनका भाषण अच्छा होता है। लेकिन कल के भाषण से ऐसा लगता है कि या तो वे पूरी तरह से होमवर्क नहीं करके आए थे या फिर हो सकता है कि उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे थे इसलिए उनको खुश करने के लिए उन्होंने वे बातें कही। वे बात करते-करते भटक गए और उन्होंने चीन मॉडल की बात कह दी। हम अभी तक चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी गुजरात मॉडल की बात सुन रहे थे कि देश को गुजरात मॉडल पर ले जाना है। लेकिन कल उनके भाषण से ऐसा लगा कि गुजरात मॉडल पीछे हो गया है और अब चीन का मॉडल अपनाना होगा। यह अच्छी बात है, अगर संशोधन आप लोगों ने किया है कि गुजरात मॉडल की जगह चीन मॉडल को अपनाना है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, यह आपका फैसला है।

माननीय अध्यक्ष, राजीव प्रताप रूडी जी अपने भाषण में यह भी बोल गए कि 65 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कांग्रेस या यूपीए सरकार रही, उसने कुछ भी नहीं किया।...*(व्यवधान)* उन्होंने 65 साल कहा है। आप उनका भाषण सुन लें, पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। वे अब यहां नहीं हैं। हम आप सब को नहीं बल्कि उनको भी याद दिलाना चाहते हैं कि 65 साल में माननीय अटल जी की सरकार भी छह साल रही, जनता पार्टी की भी सरकार रही जिसमें आडवाणी जी भी थे। कई सरकारें आई और गईं, वे यह बात भूज गए और सिर्फ उनको याद रहा कि 65 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)* हालांकि कांग्रेस के नेता ने बहुत विस्तार से दस साल में यूपीए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने की कोशिश की। लेकिन जब आप कोई नजरिया बना लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता

है उसे स्वीकार करना। आने वाले समय में इतिहास बताएगा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में क्या उपलब्धियां हुई, हर क्षेत्र में हमने क्या-क्या कार्य किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, हम जो भी कर सकते थे हमने करने का प्रयास किया।...*(व्यवधान)* ठीक है, जनता का फैसला है, हमने तो पहले ही कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं।

महोदया, राजीव प्रताप रूडी जी के भाषण के बाद राम विलास जी ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। राम विलास जी यहां बैठे हैं, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब वे भाषण देते हैं तो जरा संयम बरता करें। आज से कुछ दिन पहले तक उनकी भाषा कुछ और थी। वर्ष 2012 से 2014 तक उन्होंने देश को और हम सबको बताया कि गुजरात में जो फसाद हुए, दंगे हुए उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने जो बताया कि 2002 के बाद जो कुछ हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनकी जो एक धारणा थी वह एकाएक बदल गई। यू टर्न उन्होंने जो लिया है...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्षः आपके पास बहुत थोड़ा समय है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति दी है। आप अपनी बात जारी रखें। बताइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर : माननीय अध्यक्ष, मेरी एक नेक सलाह राम विलास जी को है कि पांच साल बाद फिर इस देश का मौसम बदलेगा। इस देश का मौसम फिर बदलेगा। इसलिए ऐसी स्थिति न हो, क्योंकि उस समय आपको फिर से वापस आने की गुंजाइश रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि आपको फिर से यू टर्न करना पड़े। आज नरेन्द्र मोदी जी उनके लिए बहुत अच्छे हो गये हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी हो गई है और उसकी सारी कमियां दूर हो गई हैं। यह उनकी धारणा हो सकती है, लेकिन देश इस बात को एक लम्बे समय तक याद रखेगा कि आपको इस बात की जानकारी हासिल करने में 12 साल लग गये कि भारतीय जनता पार्टी का क्या परिप्रेक्ष्य है, उसका क्या करैक्टर है।...*(व्यवधान)*

अब मैं आखिर में कहूंगा कि आपने देश के लोगों को एक सुनहरा सपना दिखाया है। नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि मुझे साठ महीने चाहिए, देश की जनता ने उन्हें साठ महीने दे दिये। अब कोई बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास पूर्ण बहुमत आ गया। हालांकि आपको वोट 31 प्रतिशत ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया। अब आप यह भी हनीं कह सकते कि हमारे सहयोगी हमें मदद नहीं कर रहे हैं या हमारे काम में वे रोड़े अटका रहे हैं, यह आप नहीं कह सकते। अब आपका पूर्ण बहुमत है, आपकी सरकार है। इसलिए अब आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। अब किसी तरह का बहाना यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने कहा कि बहुत जल्दी अच्छे दिन आ गये। लेकिन देश की जनता अभी इंतजार में है, उसके दिन कब आयेंगे, वे इसका इंतजार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं, मैंने अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में पढ़ा कि हमारी भाजपा की सरकार को चिंता है। मैं यही कहूंगा कि अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा में लाने की आप बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें देश के विकास से जोड़ा जाए तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी पार्टी में इसकी शुरुआत करें। आप अपनी पार्टी में एक भी सांसद को चुनवा कर नहीं ला सके। आपके 282 सांसद चुनकर आये और एक भी मुस्लिम सांसद चुनकर नहीं आया। एक बेचारा...*(व्यवधान)** था, उसे भी आपने हरवा दिया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप सेक्युलर हैं...*(व्यवधान)* आज दुनिया देख रही है, दुनिया इस बात पर आश्चर्य कर रही है कि जो पार्टी सत्ता में हैं, उस पार्टी में इस देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, उसे कहीं जगह नहीं मिली और आप कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए यह करने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है, चूंकि...*(व्यवधान)** लोक सभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनका नाम सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, हम निकाल देंगे।

श्री तारिक अनवर : मैं समाप्त करूंगा, चूंकि समय का अभाव है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। लेकिन फिर मौका मिलेगा, फिर आपसे हम लोग बातचीत करेंगे। अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप इस बात का बहुत ढोल पीट रहे हैं कि हमने सार्क के तमाम देशों के लोगों को यहां बुला लिया। लेकिन आप भूल रहे हैं कि यह भारतवर्ष, जिसने पूरे नॉन-इलाइन मूवमैन्ट की अगुवाई की है। एक समय था कि हमारे देश के साथ दुनिया के जो तमाम कमजोर राष्ट्र थे, पिछड़े थे, विकासशील थे, हम उन सबको आगे लाये और सबसे लड़ाई लड़ी है। भारत हमेशा विदेशी मामलों में आगे रहा है और इसलिए आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने सार्क देशों को बुला लिया तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया, ऐसी बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुषमा स्वराज, आप बोलिये।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री तारिक अनवर : अंत में मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारी बात अधूरी रह गई, लेकिन जब अप कह रही हैं कि समय का अभाव है तो मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[अनुवाद]

***श्री शिवकुमार चनाबसप्पा उदासि** (हावेरी) : सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी, समस्त मंत्रि परिषद् और 16वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

2014 के आम चुनाव, उम्मीद के चुनाव थे। मतदाताओं का सर्वाधिक प्रतिशत सामने आना, लोकतंत्र की जीत है और पुनरूत्थानशील भारत के लोगों की जीत है।

भारत के लोगों ने विकास के पक्ष में निर्णायक रूप से मत दिया है। लोगों को हमारे प्रसिद्ध और प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार से काफी आशाएं, आकांक्षाएं और काफी उम्मीद हैं। मुझे आशा है कि हमारी सरकार समाज के कमजोर और दलित वर्गों का भारत की प्रगति में समान भागीदार बनाने के प्रति प्रतिबद्ध होगी।

मैं राष्ट्रपति के भाषण का समर्थन करता हूं, जिसमें सरकार सुशासन के माध्यम से चहुंमुखी विका के पक्ष में है और लोग "एक भारत-श्रेष्ठ भारत पर दृढ़ हैं" तथा सरकार न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के आदेश पर काम करते हुए "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत की शपथ ले रही है।

सरकार गरीबों के उत्थान के प्रति समर्पित है और गरीबी उपशमन के लक्ष्य को हासिल करने, कृषि में निवेश को बढ़ाने, विशेषकर कृषि अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने और सभी किसानों को एकसमान फसल बीमा और मौसम बीमा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य है "हर खेल को पानी", जिसे जल संचय और जल सिंचन जल संरक्षण की मदद से कार्यान्वित किया जाएगा और भू-जल पुनर्भरण तथा सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाया जाएगा।

कौशल विकास से युवा पीढ़ी को अत्याधुनिक कौशल प्राप्त होगा और देश में बेरोजगारी में कमी आएगी। कुशल भारत के लक्ष्य को लेकर और सरकार राष्ट्रीय बहु-कौशल मिशन शुरू कर रही है, जिससे हमारे युवा विश्व की युवा पीढ़ी से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। हमें आशा है कि मंहगाई घटाकर और कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित कर राजकोषीय घाटे में सुधार कर पाएंगे और देश के लोग वहनीय जीवन जी सकेंगे। विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी को मजबूत बनाने और जीडीपी में वृद्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारे 50 प्रतिशत से अधिक निर्यातों, रोजगार आदि के लिए उत्तरदायी है। यह केवल आजीविका ही नहीं है बल्कि हमारे आम जन की जीवन रेखा है। लेकिन कृषि भारत में दुर्भाग्य का खेल बन चुकी है। पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार का समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण नहीं था, जो कि आपने गुजरात में मुख्य मंत्री के रूप में कार्यान्वित किया है। गुजरात कृषि मॉडल एक समय की कसौटी पर खरा उतर चुका मॉडल है और इसने उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। समग्र राष्ट्र को ऐसे समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने में समय लग सकता है।

जैसा कि आपको पता है कि पूर्व शासन में जब खाने की कीमतें आसमान छू रही थी, किसानों ने आत्महत्या की क्योंकि उन्हें अपने कृषि उत्पादों के लिए कीमतें नहीं मिल रही थी। उर्वरक राजसहायता समाप्त कर दी गई थी जिससे कृषि लागतें बहुत अधिक बढ़ गई और इसने किसानों की जिंदगी को बुरी तरह से और घातक रूप से प्रभावित किया है। मैं नई सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृषि क्षेत्र को एक प्रोत्साहन के रूप में किसानों को उर्वरक राजसहायता प्रदान करे।

भारत सरकार की फसल बीमा योजना प्रारंभ से ही रुग्ण है। अधिकांश किसानों को नहीं पता कि ये क्या है। यह एक कार्यक्रम किसानों की सहायता के लिए था, लेकिन अधिकांश किसानों के बीच संवादहीनता की स्थिति है। योजना की स्पष्ट कमियां ये हैं: फसलों का कम कवरेज, किसानों की कम जागरुकता, संस्थानिक ऋणों तक किसानों की कम पहुंच, कम प्रचालन निष्पाद, किसानों का अल्प शिक्षित होना, सामान्यत: प्राथमिक क्षेत्र और मुख्यत: कृषि ऋण में लक्ष्य प्राप्त करने में बैंकों का लगातार अफसल होना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का कम होना, प्राकृतिक विपदाओं द्वारा कृषि हानि को मापने के मापदंड जो कि किसानों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अब मैं यह चाहता हूं कि समय आ गया है कि प्रचलित प्रणाली की कमियों को दूर किया जाए और योजना के लाभों को किसानों के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक समरूप और अभिन्न फसल बीमा योजना पर विचार किया जाए जो कि किसानों के लिए और अधिक लाभदायक होगी और एक ऐसी प्रणाली विकसति की जाए जो कि ऐसे लाभों को किसानों के दरवाजे तक पहुंचाएगी।

मैं नाशवान कृषि उत्पादों हेतु उच्च गति की ट्रेनों की हीरक चर्तुभुज परियोजना और विशेष रूप से विशिष्ट कृषि रेल नेटवर्कों के साथ रेलवे की संपर्क सहित अवसंरचना विकसित करने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार के कदम का स्वागत करता हूं जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो। एक नई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और शहरी अवसंरचना को सुधार कर, जो कि अभी कमजोर है, और पर्यटक गंतव्य किसान का संवर्धन करके जीडीपी में सुधार करने से, अर्थ एवं अकुशल युवा रोजगार सृजन होगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस देश के लोगों ने इस सरकार में अत्यंत विश्वास और आशा व्यक्त की है और हमें एक मजबूत, आत्म-निर्भर, आत्म-कुशल और आत्म-विश्वासी भारत का निर्माण करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए ताकि राष्ट्रों की जमात में इसे एक उचित स्थान प्राप्त हो। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि एक मजबूत और जीवंत भारत के निर्माण हेतु सरकार के प्रयासों का अपने मौलिक कर्त्तव्यों के साथ समर्थन करे। इन शब्दों के साथ, मैं नई सरकार के एक मजबूत राष्ट्र बनाने की नई और नवाचारी विचारधाराओं का सर्मथन करता हूं और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की अगुवाई में नई सरकार के लिए कुछ शब्द कहता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।

***कुमारी शोभा करंदलाजे** (उदुपी चिकमंगलूर) : मैं श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा प्रस्तुत और श्री राम विलास पासवान जी द्वारा समर्थित, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने हेतु भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्रीकाल के दौरान संसद का सदस्य होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र उदीपी चिकमंगलुर के लोगों और कर्नाटक के लोगों के प्रति भी अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली नई सरकार हेतु रूपरेखा प्रस्तुत की है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 19 में समाज के चहुंमुखी विकास में महिलाओं के महत्व के बारे में उल्लेख किया गया है और सरकार उन्हें संसद और राज्य विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। "बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ", श्री प्रतिबद्धता के साथ, "सरकार महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार हेतु शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी, और अपराध न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करेगी।"

हाल में हुई निर्मम घटनाओं की तरफ इस सम्मानित सभा का ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे काफी पीड़ा होती है। बलात्कार की घटनाओं में, विशेषत: महानगरों जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और बेंगलूरु में, वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में किशोरियों को जिंदा ही टांग दिया गया। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं ने देश को झकझोर दिया। उत्तर प्रदेश की तरह, अधिकांश राज्यों में प्रशासन और पुलिस ने जनता में विश्वास पैदा करने के लिए कानून के नियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। इस प्रभावकारिता ने कानून व्यवस्था में कमी किया है तथा लोगों के मनोबल को तोड़ा हैं।

प्राय: प्रतिदिन, भयावह बलात्कार मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं और जिसके कारण अमेरिका तथा अन्य देश भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रिपोर्टों पर संत्रस्त हैं। केन्द्र और सभी राज्यों को बलात्कार मामलों के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में देश में बलात्कार नहीं हों।

अत: मैं सरकार से महिलाओं के विरुद्ध इस निर्दयता को समाप्त करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं। मैं दलगत भावना से ऊपर उठ कर सभी माननीय सदस्यों से ऐसी अमानवीय घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठाने और निर्दोष महिलाओं और बालिकाओं के जीवन को बचाने के लिए हाथ मिलाने का अनुरोध करती हूं। महिलाओं की रक्षा करने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए।

भारत की विशाल जनसंख्या उसकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। भारत की आधी जनसंख्या 25 की उम्र से नीचे है। इस युवा समूह में 600 मिलियन लोग हैं।

भारत की युवा जनसंख्या को मुख्य रूप से नौकारियों और आर्थिक अवसरों की तलाश होती है। वे श्री नरेन्द्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास और आस्था रखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को "ऐसा व्यक्ति जो, अपने प्रयासों द्वारा, सामान्य परिवार से उठाने वाला" के रूप में जाने जाते हैं। उनका सफल जीवन उन मतदाताओं को प्रेरित करता है, जो अपनी रहन-सहन की स्थिति और आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए उत्सकतावश प्रतीक्षा कर रहे हैं। युवा पीढ़ी मजबूत भारत की ओर देख रही है। हमारी सरकार के लिए भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्राथमिकता क्षेत्र है। इन राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देने से प्रत्येक भारतीय प्रसन्न हुआ है। सभी, राष्ट्र-विरोधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही चाहते हैं।

राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा संख्या 12 में हमारी युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं के बारे में सही बताया गया है। इस अभिभाषण में युवावओं विशेषकर शिक्षित युवाओं के लिए नौकरियों के निर्माण द्वारा अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने में निभाई जा रही भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। "मेरी सरकार केवल युवा विकास की संकल्पना की बजाए युवा संचालित विकास व्यवस्था प्रदान करेगी।"

इस वर्ष लोक सभा चुनाव में मतदाता संख्या दर्शाती है कि युवाओं के मध्य जागरुकता बढ़ रही है कि उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में और अधिक सम्मिलित होना चाहिए। विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश, भारत में 1.2 बिलियन लोगों का निवास है और इसके 815 मिलियन (लगभग 82 करोड़) लोगों ने हाल ही के आम चुनावों में श्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को स्पष्ट जनादेश दिया है। इसका श्रेय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी को जाता है, जिन्होंने आम लोगों विशेषकर देश के युवाओं को अपनी 400 से अधिक चुनावी सभाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रभावित किया, मैं उन्हें परिवर्तन के लिए मतदान करने के लिए देशभर में युवाओं तक अपना मजबूत संदेश पहुंचाने के लिए बधाई देती हूं।

हमारे लोग, विशेषकर किसान मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। मैंने सुदूर गांवों और वन क्षेत्रों में महिलाओं को अपनी जीविका के लिए कठिन श्रम करते देखा है। तथापि, उन्हें अपनी क्षमता और दक्षता को व्यक्त करने के लिए सही अवसर नहीं मिलता है। अवसरों की कमी ने इनके जीवन को गरीबी के दुष्चक्र में धकेल दिया है। मेरा मानना है कि भारत में गरीबी समान अवसरों की अनुपस्थिति के कारण है। अवसरों की कीम से असमानता उत्पन्न हो रही जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। इसे राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा संख्या 7 में सही ढंग से वर्णित किया गया है "हमारी सरकार गीरबों के लिए समर्पित है। गरीबी का कोई धर्म नहीं है, भूख का कोई सम्प्रदाय नहीं और निराशा का कोई भूगोल नहीं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत में गरीबी के अभिशाप को समाप्त करना है। मेरी सरकार केवल "गरीबी उपशमन" से संतुष्ट नहीं होगी और स्वयं को "गरीबी उन्मूलन" के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करती है।

मैं कहना चाहूंगी कि संभावत: हमारे प्रधानमंत्री भारतीय इतिहास में ऐसे पहले राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने यह दर्शाया है कि वे न केवल परिश्रमी हैं बल्कि अपने साथियों और नौकरशाहों को भी प्रोत्साहित करते हैं ताकि राष्ट्र को बिना भय या पक्षपात के समर्पित सेवा प्रदान की जा सके। वह 'कर्म ही पूजा' के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और इसे व्यवहार में लाते हैं। सचिवों को उनका परामर्श है "काम करो और तरक्की पाओ"।

मैं कई वर्षों से नीतिगत मामलों से जुड़ी हुई हूं क्योंकि मैंने विधान परिषद् के सदस्य के रूप में विभिन्न समितियों में कार्य किया है और मंत्री के रूप में अनेक महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है। मेरा विचार है कि राजनीतिक दलों में अनेक लोग घटनाओं की आलोचना और विश्लेषण में अपरा समय बर्बाद करते हैं। वे सब कुर्सी पर बैठकर आलोचना करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आज से वे अपना कीमती समय अर्थहीन आलोचना में बर्बाद नहीं करेंगे और श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ जुड़कर राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ करे।

देश, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के अंतर्गत एक नई राजनीतिक संस्कृति को देख रहा है। देश का नए प्रकार के शासन की देख रहा है जोकि स्वच्छ, सक्षम, करुणापूर्ण और पारदर्शी है। इसे राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 21 और 22 में स्पष्टत: वर्णित किया गया है। "मेरी सरकार निष्पादन पर ध्यान केन्दित करते हुए स्वच्छ और दक्ष प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है" हमारी नौकरशाही के विश्वास और जोश को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जायेंगे। पहुंच बढ़ाने के लिए सरकारी रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।

[हिन्दी]

***श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल** (भिवंडी) : मैं राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण का समर्थन करता हूं। उन्होंने देश की जनता के प्रति विश्वास निर्माण करके देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए कटिबद्धता जताई है। देश की जनता की अपेक्षा और उम्मीदों को यह सरकार पूरा करेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में आज इस सदन में अपनी बात रखते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं।

अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी को भेजा जाने वाला धन्यवाद प्रस्ताव, जो कल श्री राजीव प्रताप रूडी ने इस सदन में प्रस्तुत किया था, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि हमारी संसद की यह परंपरा है कि जब कभी नव-वर्ष का पहला सत्र होता है या लोक सभा चुनाव के बाद जब कोई सरकार का गठन होता है, तब उसके बाद के पहले सत्र को राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। आप स्वयं आठवीं बार की सांसद हैं, बहुत वरिष्ठ सदस्य, आडवाणी जी यहां बैठे हुए हैं और भी अन्य अनेक ऐसे सांसद हैं, जिन्होंने इस तरह के अभिभाषणों को अनेक बार सुना है, पढ़ा है और उस पर चर्चा भी की है। लेकिन आज मैं यह कहना चाहूंगी कि इस राष्ट्रपति अभिभाषण की आभा निराली है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आप इसे निराला कैसे कहती हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि महाभारत का एक प्रसंग है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वे सरों की शैय्या पर लेटे थे। उन्होंने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और कहा – सुनो युधिष्ठिर, कभी अतीत को कोस कर अपनी जिम्मेदारी से बरी मत होना। अगर अतीत अच्छा होता तो लोग उसे बदलते ही क्यों। लेकिन अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए, उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना। अध्यक्ष जी, आपने इस भाषण को राष्ट्रपति जी के साथ आसंदी पर बैठ कर सुना है। आपने पाया होगा कि इस अभिभाषण के प्रथम पृष्ठ से ले कर अंतिम पृष्ठ तक हमने पहले ही सरकार का कोई आक्षेप नहीं किया है। बल्कि यह देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनका निाकरण करने की हमारी क्या दृष्टि है, केवल उसका खुलासा किया है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अध्यक्ष जी, एक-दो पैरा में हमने कुछ आंकड़े जरूर दिए हैं, लेकिन वे आंकड़े ऐसे हैं कि यदि यूपीए सरकार अपनी ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती तो वे आंकड़े जस के तस आते क्योंकि वे प्रामाणिक हैं, सरकारी हैं और अधिकृत हैं। अगर उन आंकड़ों को हमारे साथी, अपने ऊपर आक्षेप मानते हैं तो फिर मुझे जन कवित दुष्यंत की वे दो पंक्तियां कहनी होंगी, जिनमें उन्होंने व्यंग्य किया है कि – मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।

अध्यक्ष जी, ये अभिभाषण हमे मिले स्पष्ट जनादेश से शुरू होता है। मैं आज यह कहना चाहूंगी कि इस जनादेश ने भारत की राजनीति में एक नया आराम जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जनादेश पहले नहीं आए हैं। इससे भी बड़े-बड़े जनादेश आए हैं। सन् 1984 में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली थीं। सन् 1980 में 300 से ज्यादा सीटें मिली थीं। लेकिन इसको मैं एक नया आयाम क्यों कह रही हूं? क्योंकि सन् 1984 के बाद, देश में एक परिवर्तन आया, जिसमें किसी भी दल को अपने तौर पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला करता था। भारत की राजनीति का विश्लेषण करने वाले राजनैतिक पंडित यह कयास लगा रहे थे कि आगे कम-से-कम 20 वर्ष तक यह संभव नहीं होगा। इसीलिए जब हम अपने तौर पर 272 प्लस की बात करते थे, तो कुछ अचंभित होते थे, कुछ उपहास करते थे और कुछ हमसे पूछते थे कि स्टेट के स्टेट आपके खाली पड़े हुए हैं तब आप 272 कैसे लाएंगे। मुझसे अगर किसी ने पूछा तो मैं हंसकर केवल एक बात कहती थी कि 16 मई को देखना।

अध्यक्ष जी, आप साक्षी हैं कि जब 16 मई को चुनाव परिणाम आने लगे तो लोगों ने देखा कि हिमाचल में 4 में से 4, उत्तराखंड में 5 में से 5, दिल्ली में 7 में से 7, राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, मध्य प्रदेश में 29 में से 27, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 और जब उत्तर प्रदेश खुला तो 80 में से 73 सीटें पाते ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई। 282 सीटें हमें भाजपा के तौर पर मिलीं और 336 सीटें हमें अपने सहयोगी दलों के साथ मिलीं। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा था और दूसरा कारण था कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसीलिए जात-पात की दीवारें ढह गईं, उम्मीदवार गौण हो गए और लोगों ने लाखों-लाख के अंतर से हम लोगों को जिताया। लेकिन आपके माध्यम से मैं भाई तारिक अनवर जी को भी कहना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि जितनी बड़ी विजय उतनी बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए इस विराट जीत को हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, सर झुकाकर स्वीकार करते हैं।

महोदया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया कि यह उम्मीदों का चुनाव है। यह सच है और हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और खरा उतरने के लिए जरूरी था कि हम पितमाह का दूसरा सूत्र सुनते, गलतियों से सबक लेने का। तो वे गलतियां क्या थीं, इसके लिए हमने उन कारणों की पहचान की, जिसके कारण इस देश में जनआक्रोश उमड़ा था। हमें ऐसे 10 कारण दिखाई दिये। पहला कारण था महंगाई की मार, दूसरा कारण था घोर भ्रष्टाचार, तीसरा कारण था घोटालों की भरमार, चौथा कारण था किसानों का हाहाकार, पांचवां कारण था बंद कारोबार, छठा कारण था मंद व्यापार, सातवां कारण था युवा बेरोजगार, आठवां कारण था महिलाओं से दुराचार, नौंवा कारण था संस्थाओं से दुर्व्यवहार और दसवां कारण था सैनिकों के साथ सीमा पर अत्याचार। इन दस कारणों को जब हमने चिन्हित किया तो हमने कहा कि एक-एक कारण का हम संज्ञान लेंगे और इस अभिभाषण में हम यह बतायेंगे कि हम इन कारणों को कैसे समाप्त करना चाहते हैं? मुझे खुशी है कि हमने एक-एक का संज्ञान लिया। महंगाई की मार का संज्ञान हमने अभिभाषण में पैरा आठ में लिया और हमने दो बातें कहीं। पहला – खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ने से रोकना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और दूसरा मेरी सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। यानी अपनी प्राथमिकता तय करते समय उस आम आदमी और उस आम औरत को जिसकी रसोई पर मार पड़ती थी, हमने अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा और उसको खत्म करने के उपाय के रूप में कालाबाजारी और जमाखोरी दोनों को रोकने के प्रभावी कदम का जिक्र किया। दूसरा कारण मैंने बताया घोर भ्रष्टाचार। पैरा 23 में हमने उसका जिक्र किया। मेरी सरकार देश को भ्रष्टाचार और कालेधन जैसी बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए कृत-संकल्प है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हुए इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। यानी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प भी दिखाया और जो काम किया है, उसका उल्लेख भी किया।

तीसरा मैंने कहा था घोटालों की भरमार। उसका संज्ञान हमने पैरा 21 में लिया। मेरी सरकार एक साफ-सुथरा और कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार पारदर्शी प्रणाली कायम करने और सरकारी सेवाएं समय पर मुहैया कराने पर बल देगी। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि अगर कार्यप्रणाली पारदर्शी हो जाए, ई-टेंडरिंग हो रही है, ई-गवर्नेंस हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है तो घोटालों की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसमें अपने अपना संकल्प दोहराया कि हम साफ-सुथरा प्रशासन देंगे और प्रणाली को पारदर्शी बनायेंगे।

चौथी बात मैंने कही थी किसानों का हाहाकार। हमने पैरा दस में उसका संज्ञान लिया। कृषि हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है। पिछले कुछ समय से हमारे किसान बहुत ही विषय परिस्थिति

में हैं और हताशा के कारण कुछ तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मेरी सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण हालात को पूरी तरह बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। वैज्ञानिक तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी अपनाकर खेती को लाभकारी उद्यम में बदलने के लिए उपाय किए जाएंगे।

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं, अपने यहां कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान। जितने भी पेशे हैं, उनमें सबसे ऊपर खेती को माना जाता था। लेकिन आज हालत यह हो गयी है कि खेती लाभ का धंधा रही नहीं। लोग खेती से पलायन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के किसान क्रॉप हॉलीडेज की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि जितना उन्हें मिलता है, वह लागत से कहीं-कहीं कम है, इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए खेती को लाभ का उद्यम बनने के लिए हम कुछ करें। हमने दोनों बातें कही हैं। हमने अपनी प्रतिबद्धता भी जतायी किसान को इस विषय परिस्थिति से निकालने की और हमने यह भी कहा कि हम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इसको वापस लाभ का उद्यम बनायेंगे।

पांचवीं बात मैंने कही थी बंद कारोबार। उसका संज्ञान हमने पैरा 26 में लिया।

"मेरी सरकार एक ऐसा नीतिगत वातावरण तैयार करेगी जिसमें स्थायित्व हो और जो पारदर्शी तथा निष्पक्ष हो।

...व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए सुधार किए जाएंगे।"

अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस बात की साक्षी हैं कि पिछले पांच वर्षों में ऐसा लगता था जैसे देश ठप्प हो गया है। कुछ चल नहीं रहा था। लीकिन हमारे सामने यह चुनौती है इस ठप्प देश को खड़ा करने की, खड़ा करके चलाने की और चलाने के बाद दौड़ाने की। मुझे खुशी है कि जो तीन मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखे – स्किल, स्केल और स्पीड, जिसका जिक्र भी इसमें आया है, उसके माध्यम से हम इस देश को खड़ा भी करेंगे, चलाएंगे भी और बहुत जल्दी दौड़ाएंगे भी। इसका एक अभिप्राय इस अभिभाषण में दिया गया है।

छठा मैंने कहा था मंद व्यापार। उसका संज्ञान हमने पैरा 29 में लिया है।

"वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य पद्धतियों को सरल बनाया जाएगा और व्यापार ढांचा मजबूत किया जाएगा ताकि कारोबार संचालन, समय तथा लागत में कमी लाई जा सके।"

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि व्यापार का सीधा रिश्ता किसान की खुशहाली से होता है और व्यापार का सीधा रिश्ता उद्यमी की खुशहाली से होता है। अगर आपका मैनुफैक्चरिंग सैक्टर खुश है तो व्यापार खुश है। अगर किसान की जब में पैसा है तो व्यापार खुश है और उन दोनों के हालात बदलने के लिए हमने कहा है कि हमारा व्यापार जो आज मंद है, वह केवल भारत में ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार में हम प्रतिस्पर्द्धा लाने के लिए तैयार है। इसका उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है।

सातवीं मैंने कहा था युवा बेरोज़गार। उसका संज्ञान हमने पैरा 12 में लिया है। हमने कहा है कि:

"मेरी सरकार केवल 'युवा विकास' की संकल्पना की बजाय 'युवा संचालित' विकास व्यवस्था प्रदान करेगी।"

और हमने कहा है कि:–

"मेरी सरकार 'हर हाथ को हुनर' के उद्देश्य से औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास के बीच की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगी।...

...मेरी सरकार 'हुनरमंद भारत' के लक्ष्य से "नेशनल मल्टी स्किल मिशन" भी शुरू करेगी।"

आप जानती हैं कि बेरोज़गारी केवल सरकारी नौकरियों से दूर नहीं हो सकती। उसके लिए हमारे योजना में कौशल का विकास करने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हमने नाम दिया कि भारत जाना जाएगा एक हुनरमंद भारत के रूप में, और बहुत बार पढ़ाई इसके आड़े आती है। इसलिए हमने कहा कि वह जो बीच का अंतर है, हम उसको भी खत्म करेंगे। लेकिन एक मल्टी स्किल मिशन हम लागू करेंगे जिसमें हम अपने युवाओं में और युवा प्रतिभाओं में तरह-तरह के कौशल का विकास कर सकें ताकि स्वरोज़गारी होकर वे आत्मसम्मान से ज़िन्दगी जी सकें, यह हमारा अभिप्राय इस अभिभाषण में है।

आठवीं बात मैंने कही थी महिलाओं से दुराचार। उसका संज्ञान हमने पैरा 19 में लिया है।

"मेरी सरकार समाज के विकास और राष्ट्र की समृद्धि में, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। वह संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। "बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ" ओर बेटी पढ़ाओ की प्रतिबद्धता के साथ, मेरी सरकार बालिका को बचाने और उसकी शिक्षा के लिए व्यापक जन-अभियान आरंभ करेगी।...

...सरकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बिल्कुल सहन न करने की नीति अपनाएगी और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दाण्डिक न्याय प्रणाली को समुचित रूप से मज़बूत किया जाएगा।"

अध्यक्ष जी, मैंने इस बात को बार-बार कहा है कि यदि हम महिलाओं का उत्थान चाहते हैं और उनका कल्याण चाहते हैं तो चार चीज़ें जरूरी हैं – शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और राजनैतिक सशक्तीकरण। जहां तक शिक्षा का सवाल है, हमने कहा है कि बेटी पढ़ाओ हमारे लिए एक अभियान बनेगा। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, हमने कहा है ज़ीरो टॉलरैन्स अगेन्स्ट विमैन्स वॉयलैंस, हमने ज़ीरो टॉलरैंस की बात यहां कही है कि हमारी सरकार हिंसा को बिल्कुल सहन नहीं करेगी और ज़ीरो टॉलरैन्स की नीति अपनाएगी। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, आर्थिक स्वावलंबन के लिए हमने यहां कहा है कि वह देश के विकास में बराबर की भागीदार होगी और जहां तक राजनैतिक सशक्तीकरण का ताल्लुक है, हमने 33 प्रतिशत आरक्षण की बात की।

अध्यक्ष जी, महिला सशक्तीकरण की बात तो बहुत पार्टियां करती हैं लेकिन हमने पिछले एक महीने में इसको कर दिखाया है। गुजरात में मुख्य मंत्री का पद खाली हुआ तो हमने एक महिला मुख्य मंत्री को वह पद दिया। हमारी कैबिनेट बनी तो 23 कैबिनेट मंत्रियों में से छह कैबिनेट मंत्री महिलाएं हैं, यानी 25 प्रतिशत का हिस्सा हमने महिलाओं को दिया। एक महिला ने यह स्पीकर का पद खाली किया तो हमने आप जैसे गरिमामयी व्यक्तित्व को इस पर सुशोभित किया। इसमें मैं कहना चाहती हूं कि कहना और करना एक अलग चीज है। हमने अगर यहां 33 फीसदी आरक्षण की बात की है तो मैं यह कहना चाहती हूं, इस समय सोनिया जी नहीं बैठीं, खरगे जी बैठे हैं। खरगे जी, आपकी पार्टी यह विधेयक राज्य सभा में लायी थी और हमने समर्थन किया था। मैं आपसे आश्वासन चाहती हूं कि जब मेरी पार्टी इस विधेयक को यहां लेकर आए तो आप समर्थन करें। क्योंकि मेरा यह निश्चित तौर पर मानना है कि आप सारे काम कर दें, लेकिन महिला को आप अगर राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं करेंगे तो आपकी बारीक क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। इसलिए 33 प्रतिशत का आरक्षण का विधेयक पास करने वाली यह 16वीं लोक सभा होनी चाहिए। बहुत सी लोक सभाएं किसी न किसी मील के पत्थर विधेयक के लिए जानी जाती हैं और यह 16वीं लोक सभा मील का पत्थर विधेयक महिला आरक्षण का पारित करे, इसके लिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करती हूं। क्योंकि जितने इधर बैठे हैं, यह सब अलग-अलग से कह चुके हैं कि महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। तो हमने जो करके दिखाया है, यह भी हम करके दिखाएंगे और 16वीं लोक सभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित करा के हम 33 प्रतिशत का आरक्षण संसद और विधान सभाओं में उन्हें देने का काम करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : जल्दी पास कराइए, हम उसका स्वागत करते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : बहुत धन्यवाद।

नौवीं बात मैंने कही थी– संस्थाओं से दुर्व्यवहार। उसका संज्ञान हमने पैरा 20 में दिया है– भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है, परन्तु काफी वर्षों से इसकी संघीय भावनाओं को कमजोर किया गया है। राज्यों और केन्द्र को सामंजस्यपूर्ण टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों के साथ सक्रियता से कार्य करने के लिए मेरी सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद् को पुनः सशक्त बनाएगी।

अध्यक्ष जी, संघीय ढांचा इस देश के संविधान का मूल प्राण है। इसी तरह से संस्थाएं, सीवीसी, सीएजी और सीबीआई, यह लोकतंत्र के वह खम्भे हैं, जिन्हें निष्पक्षता से काम करने का अधिकार होना चाहिए और संघ और राज्यों के बीच में टकराव इस देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि यह जो परिषदें बनी हैं, हम इनका पुनर्गठन करेंगे और इनको एक सशक्त टीम इंडिया के रूप में खड़ा करेंगे।

दसवें बिन्दु में कहा था– सैनिकों के साथ अत्याचार। उसका संज्ञान हमने पैरा 42 में दिया है– मेरी सरकार अपने वीर एवं निस्वार्थ सैनिकों के ऋण को चुकाने के लिए सब कुछ करेगी। सरकार अपने सैनिकों के पराक्रम का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाएगी। एक रैंक, एक पेंशन योजना लागू की जाएगी।

अध्यक्ष जी, जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है या अपने शहीदों का अपमान करता है, वह देश बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए हमने यह कहा है कि हम युद्ध स्मारक बनाएंगे और हमने शब्द इस्तेमाल किया– "सब कुछ करेगी।" अपने वीर और निस्वार्थ सैनिकों के सम्मान के लिए यह सरकार सब कुछ करेगी, इस अपनी प्रतिबद्धता को हमने पैरा 42 में दिया है।

अध्यक्ष जी, यह जो दस बिन्दु हमने चिन्हित किए थे, उन दस बिन्दुओं पर हम क्या करेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका जिक्र मैंने आपने सामने किया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बहुत अनूठी पहलें हैं, जिनका जिक्र हमने इस अभिभाषण में किया है। कल खरगे जी बोलते हुए कह रहे थे कि दो-दो शब्द लिख दिए, योजना तो बतायी नहीं। आप बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, सरकार में भी रहे हैं। आप यह जानते हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद बजट आता है और यह परम्परा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में केवल दिशा दिखायी जाती है, बजट में योजनाएं लायी जाती हैं और उन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए राशि भी आवंटित की जाती है। इसलिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए उस बजट की, जिसमें योजनाओं का खुलासा होगा। लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में भी हमने कुछ बड़ी योजनाएं बतायी हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमने कहा है– हम हर राज्य को आईआईटी देंगे, क्या यह योजना नहीं है? हमने कहा है– हम हर राज्य को आईआईएम देंगे, क्या यह योजना नहीं है? हमने कहा है– हम हर राज्य में एम्स जैसे अस्पताल का निर्माण करेंगे, क्या यह योजना नहीं है? हमने कहा है– हम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस सौ नये शहर

बनाएंगे, क्या यह योजना नहीं है? हमने कहा है– स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों जैसी योजना के तर्ज पर हम रेल का हीरक चतुर्भुज बनाएंगे, क्या यह योजना नहीं है? हमने कहा है– हम गंगा का पुनरुद्धार करेंगे, क्या यह बड़ी योजना नहीं है?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : रूडी साहब को यह बताना था, वह पूरा बोल देते तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती एक्सप्लेन करने में।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, आज मुझे अपने कुछ साथियों की याद आ रही है जो सदन में नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के रेवती रमण सिंह, वामपंथी प्रबोध पांडा और मेरे साथी शाहनवाज़ हुसैन, कोई सत्र ऐसा नहीं बीता, जिसमें इन तीनों को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी के पास न गयी हूं, गंगा के पुनरुद्धार के लिए। हम बार-बार एक बात कहते थे कि प्रधानमंत्री जी, गंगा को निर्मल और अविरल बहने दें। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हम न गंगा पुनरुद्धार का अलग मंत्रालय स्थापित किया। क्यों? क्योंकि गंगा हमारे लिए नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए मां है और मुझे खुशी है कि यह बात कहते। जो संसद उस दिन केन्द्रीय कक्ष में बैठे होंगे, जब जापान के प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने गंगा पर बोलते हुए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर) **:** कल मैंने सरकार से अनुरोध किया था कि वे न सिर्फ गंगा नदी बल्कि कावेरी जैसी अन्य नदियों पर भी विचार करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : कृपया बैठ जाइए, मैं उसके बारे में बोलूंगी।

तम्बिदुरै जी, मंत्रालय है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार।...*(व्यवधान)* एक मिनट।...*(व्यवधान)* उस मिनिस्ट्री का नाम है।...*(व्यवधान)* वे समझ गए।...*(व्यवधान)* वे मान गए।...*(व्यवधान)* मंत्रालय का नाम ही यह है। मंत्रालय का नाम है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार...*(व्यवधान)* इसलिए गंगा को हम न एक अलग महत्व दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) **:** किसी नदी विशेष के लिए एक अलग मंत्रालय क्यों होना चाहिए? यहां जब पम्पा जैसी अन्य कई नदियां हैं तो किसी नदी विशेष के लिए एक अलग मंत्रालय क्यों होना चाहिए?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे इस से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि गंगा पुनरुद्धार का काम हम ने बहन उमा भारती जी को सौंपा है जिन्होंने अपना जीवन गंगा जी के प्रति समर्पित कर दिया।

मैं कह रही थी कि उस दिन जापान के प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय कक्ष में गंगा जी को गंगा मैया कह कर जिस समय संबोधित किया था तो करतल ध्वनि से केन्द्रीय कक्ष गूंज उठा था।...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) **:** गंगा के साथ यमुना को भी जोड़ा जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्रीमती सुषमा स्वराज : बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* प्लीज, आप लोग चुप रहिए। आप लोग क्यों बोलते हैं?...*(व्यवधान)*

हिन्दुस्तान की तहज़ीब को गंगा-जमुनी तहज़ीब कहा जाता है। आप ने बिल्कुल सही बात कही है। हम ने कहा कि सारे नदी विकास, लेकिन गंगा के लिए चूंकि अलग महक़मा बना है, इसलिए मैंने गंगा पुनरुद्धार का ज़िक्र किया।

अध्यक्ष जी, कल खरगे जी ने बोलते हुए कहा कि कुछ नहीं है, यह तो मार्केटिंग की सफलता है। अगर किसी को सीखना है तो मार्केटिंग बीजेपी से सीखे। खरगे जी, मैं आप को बताना चाहती हूं। मार्केटिंग का एक बुनियादी सिद्धांत है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती।...*(व्यवधान)* अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती।...*(व्यवधान)*

मार्केटिंग की कोशिश आप ने भी की, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जनता के मन को भा गया। इसलिए यह मार्केटिंग की सफलता नहीं, प्रोडक्ट की विशेषता है।

अध्यक्ष जी, अब मैं विदेश नीति पर थोड़ी बात करना चाहूंगी। पैरा 43 में हम ने उसका ज़िक्र किया है और तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है:–

> "मेरी सरकार एक सशक्त, आत्मनिर्भर तथा विश्वास से भरपूर भारत का निर्माण करने और देश को राष्ट्रों के समुदाय में उसका सही स्थान दिलाने के लिए वचनबद्ध है।"

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं स्वयं इस विभाग को देख रही हूं और मैं कह सकती हूं आपसे कि रातो-रात दुनिया में भारत का महत्व बढ़ गया है। जो अख़बारों में खबरें छपतीं थीं कि "भारत की सफलता का दौर समाप्त हो गया है।" अब उनको लगने लगा है कि नहीं, भारत की संभावना वापस लौटी है, भारत का पोटेंशिएल वापस लौटा है। मैं आप से बताऊं कि भारत में कौन सबसे पहले आए, भारत के प्रधानमंत्री कहां सबसे पहले जाएं, इसके लिए एक दौड़ लगी हुई है। यह एक शुभ संकेत है क्योंकि बाकी के देश हमारी प्रगति में भागीदार बन कर अपनी प्रगति भी करना चाहते हैं। हम इस शुभ संकेत का सूत्र पकड़ कर आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की नाक ऊंची करेंगे, यह हमारी कटिबद्धता है। इसी सूत्र को जब हम आगे ले जाते हैं तो मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दो पंक्तियां याद आती हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

उन्होंने स्वयं बोली थीं–

"स्वप्न देखा था कभी, जो आज फिर धड़कन में है,
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है।"

अध्यक्ष जी, उस नये इरादे को बनाने का ही संकल्प इस अभिभाषण में लिया गया है। मैं आपके माध्यम से देश को विश्वास दिलाती हूं कि देश की जनता का आशीर्वाद लेते हुए और अपने तमाम विपक्षी साथियों का सहयोग लेते हुए हम इस इरादे को पूरा करेंगे। यही विश्वास दिलाते हुए राजीव रूडी जी ने जो प्रस्ताव कल रखा था, उसका मैं समर्थन करती हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी अपने आपको सुषमा स्वराज जी द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करते हैं।

***श्री राम चंद्र हंसदाह** (मयूरभंज) : महामहिम, राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर मान्यवर सांसद राजीव प्रताप रूडी जी जो प्रस्ताव लाए हैं। उनका तो मैं समर्थन करता हूं। उसके लिए जिन विषयों पर कुछ बातें छोड़ दिए हैं, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करना चाहता हूं।

कल रूडी जी ने जब भाषण दिया था तो उन्होंने एक टिप्पणी दी थी वे बोले थे कि – "भारत माता की जय। जो बोलता है व आरएसएस का परिचय देता है। लेकिन महोदय, मुझे नहीं, पता कब से बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत से नारा केवल आरएसएस के लिए पेटेंन्टयुक्त हो गया है।

विविधता में एकता – वह हमारा भारत देश का चरित्र होता है। कोई भी भारतीय भारत के मानचित्र को सेल्यूट करते हुए 'भारत माता की जय' कहने से देशभक्त नहीं बन जाता है। परंतु जो देश की विविधता को समझता है, देश में निवास करने वाले सभी जाति, धर्म, संस्कृति के लोगों को सम्मान देता है वही केवल वास्तव में देशभक्त है।

[अनुवाद]

कल हमारे भाजपा के नेता ने सदन में हमारे राज्य ओडिशा के पिछड़ेपन के बारे में उल्लेख किया था। केवल हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि जनजातीय बहुल झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्य भी विकास संबंधी मानदंडों में पिछड़ रहे हैं। यह अच्छा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समाज के इस पिछड़े और पददलित वर्गों को समानता और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 330 और 335 को शामिल किया था। हालांकि यह एक अस्थायी व्यवस्था थी जो शुरुआती 10 वर्षों के लिए की गई थी, किन्तु हमें यह 60 वर्षों से अधिक समय के लिए जारी रखना पड़ा। परन्तु स्वतंत्रता के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम सामाजिक समानता लाने में असफल रहे।

[हिन्दी]

***श्री कमलेश पासवान** (बांसगांव) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो कुछ चर्चा हुई, मैंने उसे ध्यान से सुना। जैसाकि राष्ट्रपति जी ने कहा कि यह उम्मीदों का चुनाव रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता को इस नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और यही वजह रही कि लम्बे अरसे के बाद 66.4 प्रतिशत मतदाताओं ने इस चुनाव में जबरदस्त भागीदारी की तथा किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया। मुझे उम्मीद है कि जनता ने हम पर जो भरोसा जताया है, हम उस पर खरे उतरेंगे और जो हमारा उद्देश्य है सुशासन और विकास, उसके लिए कार्य करेंगे। यह एक स्थिर और ईमानदार सरकार साबित होगी और जैसाकि इसका आदर्श वाक्य है, संगठित, सुदृढ़ और आधुनिक भारत– "एक भरत-श्रेष्ठ भारत", उसपर गम्भीरता से कार्य करेगी। यह सरकार जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त भारत देगी।

महामहिम ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। बहुत से मुद्दों पर चर्चाएं हो चुकी हैं। जैसाकि उन्होंने कहा कि सरकार परम्परा, कौशल प्रतिभा, पर्यटन, व्यापार और प्रौद्योगिकी (5 टी-ट्रैडीशन, टैलेंट, टूरिज्म, ट्रैड और टेक्नोलॉजी) से जुड़ी अपनी ताकत के बल पर फिर से ब्रांड इंडिया को कायम करेगी। लेकिन मैं यहां पर्यटन और रेलवे पर अपनी बात रखूंगा, क्योंकि पर्यटन और रेलवे एक-दूसरे के पूरक हैं। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बांसगांव लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। और यह क्षेत्र इन दोनों ही सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है। मैंने 15वीं लोक सभा में इन दोनों मुद्दों को सदन में कई बार उठाया है, आश्वासन मिलते रहे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बांसगांव में पर्यटन की व्यापक एवं अपार संभावनाएं हैं, जो हमारी सामाजिक-आर्थिक प्रगति में विशेष भूमिका अदा कर सकती हैं। बांसगांव संसदीय क्षेत्र प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक एवं सत्ता का केन्द्र रहा है। रामायणकालीन श्री राम-जानकी मार्ग, बांसगांव का अवशेष प्रशासनिक केन्द्र, दुग्धेश्वरनाथ का प्राचीन मंदिर, बरहज का तीर्थस्थल, ऐतिहासिक दोहरीघाट आदि अनेक पवित्र स्थलों एवं प्राचीन नदियों के बीच घिरा हुआ बांसगांव संसदीय क्षेत्र है।

जैसाकि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्मों के तीर्थ-स्थलों के सौन्दर्यकरण और वहां जन सुविधाओं एवं अवसंरचना के सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। सरकार ऐसे 50 टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए मिशन के रूप में परियोजना शुरू करेगी, जो विशिष्ट विषय-वस्तु पर आधारित होंगे। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि बांसगांव के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए इसको टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया जाए।

जैसाकि ज्ञात है कि सरकार एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम तैयार करेगी जो अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। नई वित्तीय पद्धतियों के प्रयोग द्वारा रेलों में निवेश में वृद्धि लायी जाएगी। विगत कुछ वर्षों के गतिरोध को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए त्वरित, समयबद्ध और पूर्ण निगरानी रखते हुए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में दो रेल परियोजनाएं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर से संलग्न हैं। रेलवे की पर्याप्त सुविधाओं से वंचित इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रेल लाइन सहजनवां-दोहरीघाट के निर्माण हेतु सर्वे कार्य जो सन् 1992 में ही पूर्ण हो चुका है और जिसकी न्यूनतम लागत मात्र 66 करोड़ 95 लाख रुपये है, को अब तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है। यह पूर्वांचल की एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना है, जिसके पूर्ण होने से प्रमुख बौद्ध स्थलों – सारनाथ, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु को आपस में जोड़ने से आम जन को भी काफी राहत मिलेगी।

वहीं दूसरी अति महत्वपूर्ण रेल परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश की बरहज बाज़ार से फैजाबाद वाया दोहरीघाट नई रेल लाइन की है। जिसका सर्वे कार्य सन् 2005 में पूरा हो चुका है, जिसकी न्यूनतम लागत 781 करोड़ 78 लाख रुपये मात्र है, जिसको अब तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के निर्माण से जाहं असम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं दिल्ली को जोड़ने वाली यह परियोजना मात्र 194 किलोमीटर की है एवं जिसके बनने से दिल्ली जाने की दूरी सबसे कम हो जाएगी और रेलवे के अन्य मार्गों पर दबाव भी काफी कम हो जाएगा। इस रेल लाइन के निर्माण से सारनाथ, काशी, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और नेपाल की यात्रा सस्ती एवं सुलभ हो सकती है। इससे रेलवे को भी फायदा होगा।

इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एनएच-29 सड़क जो सारनाथ से गोरखपुर होते हुए लुम्बिनी व कुशीनगर को जाती है तथा यह सड़क इलाहाबाद सहित कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों एवं व्यवसायिक केंद्रों को भी जोड़ती है। वर्तमान समय में यह सड़क काफी जर्जर एवं गड्ढो से युक्त हो गई है, कहीं-कहीं तो यह सड़क 5-5 फीट लंबे-चौड़े गड्ढ़ों में तब्दील हो गई है। खराब सड़क होने के कारण आए दिन दुर्घटना व रास्ता जाम जगा रहता है। पिछली सरकार द्वारा केवल आश्वासन ही मिलते रहे, कार्य कुछ नहीं हुआ। इस सड़क की मरम्मत के लिए स्थानीय जनता आंदोलनरत है।

इसी तरह राम-जानकी मार्ग अयोध्या से लेकर बड़हलगंज, बरहज, मैहरौना होते हुए बिहार के जनकपुर तक जाता है, जो ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के साथ व्यावसायिक व आम जनता के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। यह मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कुछ जगहों पर कार्य तो प्रारंभ हुआ था, किन्तु वर्तमान समय में बंद पड़ा हुआ है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि एन.एच.-29 को चार लेन का बनाया जाए तथा रामायणकालीन राम-जानकी मार्ग की मरम्मत करवाकर ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया जाए।

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह) : आज लगभग 30 वर्षों के पश्चात् भाजपा नेतृत्व की सरकार ने भारी जनमत से सत्ता में आकर ऐ इतिहास रचा है।

श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने पूरे देश के लोगों के अंदर एक आशा की किरण दिखाई है तथा एक सकारात्मक विश्वास बनाया है। इस सरकार ने पूरे देश में सुशासन लाने का दृढ़ संकल्प लेते हुए "एक श्रेष्ठ भारत" बनाने का बीड़ा उठाया हैं जिसके लिए हम सभी उनके साथ हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश को गरीबीयुक्त कराने का संकल्प लिया है। पिछले कई वर्षों में महंगाई ने गरीबों के साथ-साथ सभी वर्गों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में इस सरकार ने महंगाई एवं खाद्य विषमताओं को समाप्त करने हेतु जो कदम उठाए हैं, देशवासियों की भावना सार्थक होगी और सरकार बधाई की पात्र बनेगी।

70 प्रतिशत से ज्यादा लोग गांवों में बसते हैं, जहां उनकी अनेक समस्याएं होती हैं। ऐसे में सरकार शहरों के साथ-साथ गांवों के विकास हेतु भी नया मॉडल तैयार कर रही है। इससे देश का चहुंमुखी विकास होगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत कृषि प्रधान देश है और सरकार ने कृषि क्षेत्र में धनराशि बढ़ाकर कृषि ढांचे तथा कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के अपने वादे को पूरा किया इससे कृषि क्षेत्र में और भी विाकस होगा। "राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति" के तहत अकृषि योग्य भूमि का भी विकास होगा। कृषि सिंचाई हेतु "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" द्वारा एक बड़ी हरित क्रांति की शुरुआत होगी।

भारत विश्व में सबसे विकासशील देश है। "नेशनल मल्टी स्किल मिशन" तथा "नेशनल स्पोट्स्र टेलेन्ट सर्च सिस्टम" द्वारा अपने युवाओं की विकास में भागीदारी तथा खेलकूद की प्रतिभा को प्रकाश में लाने के अवसर जैसा प्रशंसनीय कार्य किया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में "होलीस्टिम हेल्थकेयर सिस्टम" तथा "नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन" से स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। भारत की प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति योग और आयुष इत्यादि को बढ़ाना देने पर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

अन्य योजनाओं के अलावा "वन बंधु कल्याण योजना" के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। भारत के विकास में सबको जोड़ना प्रशसंनीय है।

"बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" जैसे संकल्पों के साथ-साथ महिलाओं के शोषण रोकने हेतु बनाई जाने वाली नीतियों का मैं स्वागत करता हूं।

कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास तथा आतंकवाद को जड़ से मिटाने हेतु लिए गए संकल्पों की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

रेलवे क्षेत्र का आधुनिकीकरण करते हुए हाई स्पीड ट्रेन को चलाना इस सरकार की प्रमुख देन होगी।

"राष्ट्रीय ऊर्जा नीति" के द्वारा विविध ऊर्जा संसाधनों का निर्माण होगा तथा सौर ऊर्जा गैस ग्रिड के निर्माण से बिजली की कमी दूर होगी।

शहरीकरण के द्वारा 100 नये शहर बसाने जैसे संकल्पों से देश में बिना छत के कोई नहीं बचेगा।

हिमालय को बचाने हेतु "हिमालय पर राष्ट्रीय मिशन" नीति से लाभ होगा। मांग गंगा भारत की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण नदी है। जो एक लम्बे समय से प्रदूषित चल रही है। उसको बचाने हेतु जो संकल्प लिया गया। मैं उसका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विकास, प्रगति, अर्थव्यवस्था और सुशासन की राजनीति का रोड मैप दिखाई देता है, जिसके द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को उच्च शिखर तक ले जाएगी। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन नीतियों से देश फलेगा-फूलेगा और विकासशील देश से विकसित देश कहलाएगा।

[अनुवाद]

***श्री प्रसन्न कुमार पाटसानी** (भुवनेश्वर) : संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण वर्तमान सरकार का मात्र चुनावी घोषणापत्र है न कि एक भावी रूपरेखा। संसद को संबोधित करते हुए श्री मुखर्जी ने कहा कि नई सरकार व्यापार सुधार कार्यसूची पर कार्य करेगी जिसमें सरकारी और निजी भागीदारी से रोजगार सृजन का फोकस होगा और यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना इसकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। इस वक्तव्य में आगामी वर्षों में सरकार के लिए लक्ष्यों को पूरा करने संबंधी रूपरेखा की कमी थी। मैंने सरकार से आग्रह किया था कि वे कश्मीर में स्थानीय हिन्दु लोगों के पुनर्वास और जैसे जटिल मुद्दों पर सभी दलों में आम सहमति बनाएं।

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग की गई चुनी गई सरकार को 'ठोस रूपरेखा' के स्थान पर शब्दजाल और चुनावी नारे पसंद है जिस पर वह आगामी महीनों के लिए योजना बनाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इसें गत छह महीने के दौरान मोदी जी द्वारा चुनावी अभियान में प्रयुक्त किए गए नारों की भरमार है।

प्रधानमंत्री का 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' के वादे का अर्थ क्या यह है कि मंत्रियों की भूमिका न्यूनतम की जाए और प्रधानमंत्री की भूमिका अधिकतम हो?

सरकार पूर्व उन्मुख नीति, ब्रिकस इब्सा, पश्चिमी एशिया और अफ्रीकी देशों से जुड़ी भारतीय नीति का उल्लेख करने में असफल रही।

मैं बताना चाहूंगा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) जिसकी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक बाद घोषणा की थी, यह उच्चतम न्यायालय के निर्देश का परिणाम थी, जबकि सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना की जाएगी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में गई घोषणा के विपरीत है जिसमें विद्यमान संस्थानों के सुदृढ़ीकरण की बात कही गयी है। क्या सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना की पुनरीक्षा करना चाहती है जिसे पहले ही स्वीकृत कर लिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक अभूतपूर्व योजना होगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का सुशासन, रोजगार सृजन अथवा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान नहीं है क्योंकि कोई ठोस रूपरेखा नहीं है। वे इसे कैसे पूरा करेंगे? राष्ट्रपति का अभिभाषण

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उन सपनों और आशाओं का स्पष्ट विवरण है जिसे हमने गत तीन महीनों में बाजार में देखा है। अगले कुछ महीनों में यह सुनिश्चित होगा कि सरकार इन सपनों और आशाओं को किस प्रकार सच करेगी।

मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि योग और आयुष को महत्व देना चाहिए और देशभर में विशेष विश्वविद्यालय खोलने की पहल करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया और समय पर दिया, इसके लिए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जहां तक अभी विदेश मंत्री जी ने भी भाषण दिया और राष्ट्रपति अभिभाषण में से कुछ उद्धृत भी किया। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहते हैं, इस चुनाव में बहुत सारी बातें कही गईं। प्रधानमंत्री जी ने जोर-जोर से चार बातें मुख्य रूप से कहीं। उन्होंने कही तो बहुत सी बातें, उनमें से चार मुख्य बातों पर ही हम जिक्र करेंगे, वह तो उनका लम्बा भाषण है। उन्होंने कहा कि आते ही महंगाई खत्म करेंगे। 26 तारीख को उन्होंने ओथ ले ली। हम मानते हैं कि महंगाई खत्म नहीं कर सकते थे। अगर महंगाई खत्म नहीं कर सकते थे तो थोड़ी-बहुत महंगाई कम कर देते। अगर कम भी नहीं कर सकते थे, तो महंगाई ठहर तो सकती थी।

अध्यक्ष महोदया, ये सरकार बनते कई चीजों पवर महंगाई और बढ़ी है।...*(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य : महंगाई बढ़ी नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : कई चीजों पर महंगाई बढ़ी है।... *(व्यवधान)* ऐसे बोलने से क्या होता है।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : डीजल के भाव कैसे बढ़ गए?...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आज से ही महंगाई खत्म करिए।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से सीधा सवाल है।...*(व्यवधान)* वह तो हम जानते हैं, आप क्या, आदरणीय अटल जी ने भी कहा था कि मुलायम सिंह जी जब खड़े होंगे तो हमारी तरफ से थोड़ा-बहुत कुछ होगा ही। बीजेपी की तरफ से यह नयी बात हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि महंगाई ठहर तो सकती थी, फिर महंगाई बढ़ी क्यों? कई चीजों में महंगाई बढ़ गई।...*(व्यवधान)* इसलिए आप परेशान क्यों हो?...*(व्यवधान)* अगर ये बहकावे में जनता ने बहुमत दे दिया है तो अब तो आपको इसमें खरा उतरना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* आपने ही वायदा किया है कि महंगाई खत्म करेंगे। हमने तो नहीं कभी कहा महंगाई खत्म करेंगे। हमें ये कहते कि इतनी जल्दी महंगाई खत्म नहीं कर सकते, मैं मानता हूं।...*(व्यवधान)* लेकिन महंगाई जो थी, उतनी रहनी चाहिए। फिर कुछ चीजों की महंगाई क्यों बढ़ी? यह सवाल है, इसका उत्तर सही आना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने कहा, ऐसा नौजवानों को भड़काया कि हम सब नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कोई भी बेरोजगार बेकार नहीं रहेगा।...*(व्यवधान)* आप चुप बैठो।...*(व्यवधान)* हम तो आपकी ही बात कह रहे हैं।...*(व्यवधान)* आपको मुझ से परेशानी रहेगी, अभी क्या, और रहेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव (सिलचर) : संसद में उनकी भाव भंगिमा क्या है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हो गई परेशानी। ये सच बात सुनने को तैयार नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मैं सच बात कह रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं तो आपकी बात कह रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं और यदि दिला रहा हूं कि आज भूले नहीं।...*(व्यवधान)* आपने जो कहा, वही तो मैं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)* आपको क्या हो गया? कह दो कि यह नहीं कहा, इतना ही असत्य बोल दो, तो कोई बात नहीं। वह तो मैं जानता हूं कि अफवाह फैलाना इनका काम है। इस तरह से अपके देश में जो लगभग रजिस्टर्ड हैं। वे कम से कम, लगभग 6 करोड़ पढ़े-लिखे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने अपना नाम एम्पलायमेंट दफ्तर में रजिस्टर्ड नहीं कराया और बहुत सारे लोग हैं, जो अन्य धन्धों में हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, जैसे खेतिहर मजदूर हैं। उन्हें जब खेती का काम होता है, तब काम मिल जाता है और खेती का काम खत्म होता है तो 6 महीने से ज्यादा उनको काम नहीं मिलता है। अब ये जो कम से कम 8-10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, मैं इतना ही जानना चाहता हूं, हम भी जानते हैं कि अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन यह तो बताना पड़ेगा कि कब तक बेरोजगारी खत्म करोगे और कब तक महंगाई खत्म करोगे या कब तक महंगाई कम कर दोगे या महंगाई को ठहरा कर रखोगे? यह मैं अपसे आश्वासन चाहता हूं। यह सरकार को बताना पड़ेगा। यह आपने ही तो वायदा किया, जिसके आधार पर आपको वोट मिले तो बार-बार यह असत्य नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं।

दूसरी बात है, आपने इतनी गम्भीर बात कही कि मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि, मैं अच्छी तरह जानता हूं। आपने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी, कश्मीर का हिस्सा मैं वापस लूंगा, कब तक लोगे, बता देना और फिर कहा कि चीन ने जो कब्जा किया है, वह वापस लेंगे। ये ऐसे नारे थे तो जनता वोट देगी, नौजवान वोट देगा, सारा देश इकट्ठा हो जायेगा, अगर आप कश्मीर को लेंगे, जो पाकिस्तान के कब्जे में है तो हम आपका साथ देंगे। अगर चीन ने जो कब्जा किया है, उससे आप जमीन वापस लेंगे, हमारा पूरा देश का हिस्सा वापस लेंगे तो हम सहयोग करेंगे, आप लीजिए। लेकिन कब तक लेंगे, यह बताना पड़ेगा। कश्मीर का हिस्सा कब तक लेंगे, चीन जो जमीन दबाए बैठा है, वह कब तक लेंगे और कब तक कश्मीर को पाकिस्तान से छीन करके एक कर दोगे? जब नवाज शरीफ आये थे तो आपने जरूर बात की होगी कि हमारा कश्मीर दे दो, लेकिन यह इन्हें बताना चाहिए, क्योंकि, आने जब भेंट की है तो यह लोकतंत्र है, इसलिए आपकी नवाज शरीफ से कश्मीर के बारे में क्या-क्या बात हुई और अन्य बारे में हुई है। यह सदन है और सदन के बीच प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि कितनी सहमति हुई, कितनी असहमति हुई। फिर आपने आगे के लिए क्या सोचा है, यह सदन को नहीं बताओगे क्या या सब जगह ऐसे ही छिपाकर रखोगे? हमने छिपाकर तो बहुत बड़े-बड़े बहुमत देखे हैं। आपका बहुमत तो 282 है, हमने 1971 का भी इन्दिरा जी का बहुमत देखा है, और 1984 का देखा है, राजीव गांधी जी 412 की संख्या में जीते थे। आप तो 282 जीते हैं। 1971 में भारी बहुमत से जीते, फिर 1977 में क्या हुआ? दो साल में, तीन साल में ही हालत खराब हो गई। इन्दिरा जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और इमरजेंसी के बाद क्या हाल हुआ तो इतना घमण्ड नहीं होना चाहिए, जितना हमें घमण्ड दिखाई दे रहा है। कुछ माननीय सदस्यों को छोड़कर, नहीं, आप उनमें नहीं हैं। उनमें बहुत सारे लोग नहीं हैं। लेकिन उछल रहे है, हमने देखा है, हमने मुकाबला भी किया है, सब कुछ किया है। हमने 1971 भी देखा है और हमने 1984 भी देखा है और फिर हमने 1989 भी देखा है। 1971 के बाद 1977 में क्या हुआ और 1984 के बाद 1989 में क्या हुआ, इसको ध्यान में रखोगे कि नहीं रखोगे। इसलिए आपके 282 सदस्य हैं, उस समय इन्दिरा जी की जो हवा थी, इन्दिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी की जो हवा थी, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, और वे बातें दोहराएंगे नहीं। हमने तो अपनी बातें सुनकर भी लिखीं कि हम जो लोग बोल चुके हैं, उसको नहीं दोहराना।

आप दस सालों में पूरे के पूरे पक्के मकान बना देंगे, दस साल के अन्दर, आप कौन से मकान बनाएंगे, किन-किन के मकान बनाएंगे। अब आपने ऐसा बयान दे दिया कि सभी तैयार हो गये कि मेरा भी मकान बन सकता है, मेरा भी मकान बन सकता है। जब यह हलचल पैदा होगी कि उनका भी बन गया, मेरा नहीं बना, तब पता चलेगा। ऐसा तो अंदाजा देते रहो। आपने तो ऐसा कह दिया, मैं भी तो सरकार चला चुका हूं, प्रदेश की ही सही, लेकिन जब एक घोषणा कर दोगे, क्योंकि अब पूरे देश में यह चर्चा है कि मेरा भी पक्का मकान बनेगा, मेरा भी पक्का मकान बनेगा, किसका नहीं बनेगा और किसका बनेगा, तब मुश्किल होगी। अभी तो आपने घोषणा कर दी है। आप इतने जो पक्के मकान बनाने जा रहे हैं, दस साल के अंदर सब पक्के मकान बन जाएंगे, तब तो दुनिया का सबसे अच्छा देश हो जाएगा।...*(व्यवधान)* जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। यह मारा नारा है, यह तो समाजवादियों का नारा है। हमने हमेशा यही नारा दिया कि मांग रहा है हिन्दुस्तान, रोटी, कपड़ा और मकान। यह हमारा नारा है, डॉ. लोहिया जी का नारा है, जय प्रकाश जी का नारा है, आचार्य जी का नारा है, जो सबसे पहले आजादी के बाद नारा दिया गया था।

माननीय अध्यक्ष : कांक्लूड करिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हम संक्षेप कर रहे हैं। आप कहें तो कभी बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

भाषा के मामले में उन्होंने अच्छी बात कही, मैं उससे सहमत हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम केवल हिन्दी की बात नहीं करते हैं, हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि तमिल भी चले, तेलगू भी चले, कन्नड़ भी चले, सारी भारतीय भाषाएं चलें, चाहे बांग्ला हो, कोई भी हिन्दुस्तानी भाषा हो, वह चले। इस बात से मैं सहमत हूं। अगर आप इन्हें चला देंगे तो हम कहेंगे कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाकर इन्हें बधाई दे दो। आप इन्हें चलाइये, यह बेहतर है, इसे देश चाहता है। आप लोग भी विदेशी भाषा की बात करते हैं। इधर के भी माननी सदस्यों से कहेंगे कि विदेशी भाषा कम बोलिये। यह हम आपको बता रहे हैं। इस मामले में तो हम मानते हैं कि देशी भाषा उधर ज्यादा बोली जा रही है। हम समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी में देशी भाषा सबसे ज्यादा बोली जा रही है। विदेशी भाषा से इधर से ज्यादा बोली जाती है। हम आपको बता रहे हैं। सुषमा जी, आपने तो हमेशा भारतीय भाषा तो इधर से ज्यादा बोली जाती हैं हम आपको बता रहे हैं। सुषमा जी, आपने तो हमेशा भारतीय भाषा बोली है, हिन्दी बोली है, मैं इस बात को मानता हूं। हम भी उन्हीं में से हैं। मैं धोती पहनता हूं तो कोई मैं अनपढ़ हूं या क्या डिग्री मेरे पास नहीं है? मैं भी लेक्चरार रहा हूं।...*(व्यवधान)* कई साल पढ़ाया, एमएलए होकर पढ़ाया, मिनिस्टर होकर पढ़ाया, लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि यह अच्छा काम है। आप देशी भाषा को आगे लायें, देशी भाषा का मतलब केवल हिन्दी नहीं, सारी भारतीय भाषाओं, खास तौर से क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी-अपनी बात बोलें। अध्यक्ष महोदया, इसका अनुवाद करने की व्यवस्था करिए। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। अपनी भाषा में जो अभिव्यक्ति की जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है। गिटपिट-गिटपिट का प्रभाव नहीं पड़ता है। गिटपिट-गिटपिट में बता रहा हूं कि एक परसेंट सुनते होंगे, वे जहाज में चलते हों, रेल

[श्री मुलायम सिंह यादव]

में चलते हों, कहीं भी चलते हों, किसान आज गांव में बैठकर टीवी खोलने लगा है। जो भारतीय भाषा यहां बोलेंगे, वह सुनेगा।

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैसे में जानता हूं कि मेरा ज्यादा समय नहीं है। मैं यही कहूंआ कि क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान दीजिए, भारतीय भाषाओं को स्थान दीजिए। महोदया, आपका बारबार आदेश हो रहा है, मैं स्वीकार करता हूं। कभी और मौका आएगा, तब सारी बातें कह दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : कैप्टन अमरिंदर सिंह जी।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) **:** भड़काना शब्द इन्होंने कहा, नौजवानों को भड़काया, यह शब्द असंसदीय है।*...(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर (कटिहार) **:** भ्रमित कह दें तो ठीक होगा। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : तारिक अनवर जी, आपस में बातें नहीं करें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदया, यह लोक सभा का पहला सत्र है और बहुत से साथी बोलना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को चार बजे बोलना है, उन्हें राज्य सभा में भी जाना है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य एकमोडेट हो जाएं, इसलिए अगर सदन चाहे तो आज हम लंच न करें तो ज्यादा उचित रहेगा।

माननीय अध्यक्ष : आज लंच नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बैनर्जी (श्रीरामपुर) **:** मैडम, लंच होगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा।*...(व्यवधान)* आपने बोला कि लंच नहीं होगा।*...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, लंच ब्रेक नहीं होगा।

...(व्यवधान)

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***डॉ. किरीट पी. सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम) **:** मैं विकास एवं सुशासन की नयी विचारधारा के साथ स्पष्ट जनमत और मेंडेट के साथ पिछले 30 सालों के बाद अगर एक पार्टी को सत्ता पर आने का जनमत मिला हो ऐसी भाजपा नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार के भविष्य के रोड मेप माने जाने वाले राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करता हूं।

श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली यह सरकार एक ऐतिहासिक सरकार है और पूरे देश में इस सरकार ने लोगों में एक सकारात्मक भरोसा पैदा किया है।

यह सरकार विकास और सुशासन द्वारा "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" बनाने के लिए कृतनिश्चयी है। इस सरकार ने "सबका साथ-सबका विकास" के मंत्र से चलने की अपनी मंशा जतायी है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में गरीबी समाप्त करने का संकल्प किया है। पिछले कई वर्षों से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तब इस सरकार ने महंगाई एवं फूड इंफ्लेशन को समाप्त करने की दिशा को अपनी प्राथमिकता दी है, जो करोड़ों लोगों की जनभावना को सार्थक करेगी, जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

भारत गांवों में बसता है, और गांव की अनेक समस्याएं है, इस सरकार ने शहरों जैसी सुविधाएं गांवों में उपलब्ध कराने का संकल्प किया है, और रूरल क्षेत्र में अर्बन क्षेत्र जैसा विकास कर अपना "रूर्बन" मॉडल पेश किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नवीन मॉडल से गांवों का विकास होगा।

भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी बढ़ाने के वादे से कृषि क्षेत्र में और भी विकास होगा। नेशनल लेन्डयुज पॉलिसी के तहत नॉन-कल्टीवेबल जमीन का विकास होगा। कृषि के लिए सिंचाई अहम है। पानी की एक-एक बूंद अमूल्य है, तब इस सरकार ने "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" प्रस्तुत करके हर खेत को पानी के लक्ष्य से कृषि में एक दूसरी हरित क्रांति के निर्माण का संकल्प किया है।

भारत विश्व में सबसे युवा देश है। इस युवा धन को देश के विकास और युवा भागीदारी से यूथ लेड विकास में जोड़ने का संकल्प किया है और "नेशनल मल्टी स्किल मिशन" पर सरकार बहुत-बहुत बधाई की पात्र है।

स्पॉर्ट्स को महत्व देते हुए "नेशनल स्पॉर्ट्स टेलेन्ट सर्च सिस्टम" के द्वारा खेलकूद की प्रतिभाओं को उज़ागार करने का अवसर मिलेगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में होलीस्टिक हेल्थकेयर सिस्टम के माध्यम से सभी को प्राप्त, असरकारक एवं एफोर्डेबल सुश्रुषा का संकल्प बधाई के पात्र हैं। सरकार की "नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन" से स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। भारतीय संस्कृति की स्वास्थ्य पद्धति योगा और आयुष पर जोर देने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। सभी राज्यों में एम्स की स्थापना से क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ पूरे देश के हर प्रदेश में होगा।

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर "स्वच्छ भारत मिशन" महात्मा को बड़ी श्रद्धांजलि होगी और भारत निर्माण के ध्येय को सिद्ध करेगा।

सामाजिक न्याय को बल देते हुए इस सरकार की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता का मैं स्वागक करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। अन्य छात्र वर्गों के कल्याण भी योजनाओं के अलावा "वन बंधु कल्याण योजना" के लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी लघुभसियों की स्थिति जस की तस है। भारत के विकास के सभी लोगों को जोड़ने का संकल्प सराहनीय है।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के संकल्प के साथ, "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" संकल्प महिला सशक्तीकरण की ओर संकल्प पर मैं सरकार को बधाई देता हूं। महिलाओं के प्रति अत्याचारों पर सरकार की "जीरो टोलोरेंस" नीति से उसे रोकने पर बल मिलेगा।

भारत का संघीय ढांचा है और पिछले कुछ वर्षों में ये संबंध कमजोर हुआ है। तब भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करके केन्द्र एवं राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करके देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का वादा सराहनीय है और संविधान को मजबूत करेगा। उत्तर पूर्व राज्यों और जम्मू और कश्मीर को मजबूत करना और आतंकवाद पर लगाम लगाने के संकल्प से ये प्रदेश देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के वादे की प्रशंसा करते हैं। देश प्रणाली में सुधार और दृढ़ता के वादे से उद्योग जगत एवं इन्वेस्टर्स को बेहतर विकास में भागीदारी का अवसर मिलेगा।

रेलवे का आधुनिकीकरण और इन्वेस्टमेंट से देश और तरक्की करेगा। हाई स्पीड ट्रेन के "डायमंड चतुर्भुज प्रोजेक्ट" से देश का रेल यातायात, विकसित देशों के समकक्ष आयेगा। "एग्री रेल नेटवर्क" पेरीशेबल एग्री प्रोडक्ट के वहन मे आशीर्वाद रूप होगा।

सागरमाला घोषणा में देश का लंबे समुद्रतट का विकास होगा। "नेशनल एनर्जी पोलिसी" के द्वारा विविध एनर्जी संसाधनों का सुचारू रूप से उपयोग होगा। सोलर एनर्जी गैस ग्रीड का निर्माण होगा और 24×7 दिन तक बिजली का निर्माण किया जायेगा।

शहरीकरण के उपाय में 100 नये शहर बसाए जाएंगे और भारत की स्वतंत्रता के 75 सालों में सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराने का वादा किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं।

भारत की धरोहर हिमालय को बचाने के लिए "नेशनल मिशन ऑन हिमालयास" बेहतरीन संकल्प है और ये सरकार की राजकीय इच्छाशक्ति होने के कारण यह संकल्प जरूर सफल होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है।

गंगा मैया की वजह से इस देश की संस्कृतिक फूली-फली है, मगर इसके प्रदूषित होने से एक गंभीर संकट खड़ा हुआ है।

गंगा शुद्धिकरण के संकल्प के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। अपने पड़ोसी राष्ट्रों से मित्रता बढ़ाने के साथ विश्व में सभी देशों में भारत की गरिमा बढ़ाने का संकल्प विदेश नीति का एक अहम भाग रहा है, जिसका मैं स्वागत करता हूं।

देशवासियों को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से विकास, प्रगति ओर सुशासन की राजनीति के दर्शन कराते हुए रोडमेप के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का बहुत-बहुत स्वागत एवं धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि यह सरकार भारत की दिशा एवं दशा भी बदलेगी और भारत को विश्वगुरू के पद पर ले जाएगी।

***श्रीमती जयश्रीबेन कनुभाई पटेल** (महेसाणा) : आज हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का जो अपना संजोया था उसे साकार करने का संकल्प हमारे गुजरात के सपूत तथा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अपने संसद भवन के ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में प्रथम बार आगमन पर किया था। आज पूरा देश उस संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ इरादे के साथ खड़ा हो गया है।

संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने न सिर्फ सरकार के एजेंडे बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कौशल, व्यापकता और तीव्रता के नारे को स्पष्टता से सामने रखा। उनके भाषण में जिस एजेंडे का खाका खींचा गया है वह समग्रतापूर्ण महत्वाकांक्षी है। यह महत्वाकांक्षी एजेंडा परंपरा, प्रतिभा, व्यापार पर्यटन और प्रौद्योगिकी के इर्द-गिर्द घूमता है।

यह भाजपा प्रेरित एनडीए सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। यूपीए-2 सरकार मानती थी कि देश के सभी संस्थानों पर सबसे पहला अधिकार अब अल्पसंख्यकों का है। लेकिन वर्तमान सरकार का दृढ़ मत है कि देश के सभी संस्थानों पर गरीबों का अधिकार है, क्योंकि गरीबी का कोई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

धर्म नहीं होता, भूख का कोई पंथ नहीं होता और निराशा का भूगोल नहीं होता। यह सरकार गरीबी का पूर्ण निवारण करने के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। उनकी तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष तौर पर कारगर उपाय बनाएगी और राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू करेगी।

हमारे देश में चुनाव लोकतंत्र के राष्ट्रीय पर्व के रूप में जाना जाता है। 2014 में 16वीं लोक सभा का चुनाव वास्तव में एक नई सोच तथा नई उम्मीदों का चुनाव रहा है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने 9 मतदान दिवसों के तहत 864,101,476 पंजीकृत निर्वाचकों ने 66.4 प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान करके लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नई सरकार के हाथों में देश का भविष्य गढ़ने की कुंजी दे दी है। इस चुनाव में महिला निर्वाचकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। 62 फीसदी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं तथा महिलाओं ने 65.63 प्रतिशत रिकॉड मतदान करके पुरुषों के साथ-साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। यह 543 निर्वाचित सीटों पर 11.43 प्रतिशत है। 1952 के प्रथम चुनाव के बाद पहली बार 16वीं लोक सभा में 315 नए चेहरे चुनकर आए हैं। इन चुनावों में देशवासियों द्वारा दर्शाई गई अभूतपूर्व रूचि जीवंत लोकतंत्र की गहराती जड़ों का द्योतक है।

राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी ने 2014 के अपने भाषण में यह आशा व्यक्त की थी कि वर्ष 2014 विगत वर्षों की भांति विभाजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला वर्ष होगा। इस बार मतदाताओं ने एक भारत-श्रेष्ठ भारत के नारे के तहत भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए विवेकपूर्ण मतदान किया जो कि अत्यंत सराहनीय है।

श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गरीबों के प्रति समर्पित भाव से कम कर रही है तथा गरीबी का पूर्ण रूप से निवारण करने के लिए जो रोड मैप लेकर आई है वह अत्यंत सराहनीय कदम है।

देश की 2 तिहाई आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के उद्धार के लिए यह सरकार गांव शहर की गुजरात मॉडल वाली संकल्पना लेकर आई है जो कि सराहनीय है।

चाहे मुद्दा देश के सभी राज्यों में 100 नए शहरों, आईआईटी और आईआईएम की स्थापना का हो या फिर सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राकृतिक संसाधनों का पारदर्शी निष्पादन, रक्षा डिजाइन और उत्पादन के विकास का वैश्विक प्लेटफॉर्म, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तार दृष्टि और साहस का परिचय दिया है इस महत्वाकांक्षी एजेंडे के अनुरूप परिणाम देने के लिए 60 माह के समय की मांग कर निर्णय लेने की गति और क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। योजनाओं के अमल में यथोचित तेजी लाने के लिए सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह मिनिमम गवर्मेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेगी। हमारी सरकार अपने दोनों लक्ष्यों विकास और सुशासन की नीति के आधार पर ही सत्ता में आई है। यह दोनों बातें परस्पर जुड़ी हुई हैं। सरकार की घोषणा जीवन स्तर सुधारने के दिशा में एक समायोचित कदम है। तकनीक के उपयो बेहत जल प्रणाली और अन्य उपायों में कृषि उत्पादकता बढ़ानी होगी। अनाज उत्पादन तक सीमित रहने के बजाए दलहन, फल और सब्जी, डेयरी उत्पाद आदि पर ध्यान देना सरकार की प्राथमिकता होगी।

हमारी सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम को स्कूलों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाकर तथा शैक्षिक प्रोत्साहन देकर खेलों को लोकप्रिय बनाने की सोच सामने रखी है। वह स्वामी विवेकानंद के युवाओं को ललकारते हुए कहा था कि पहले अपने शरीर को शक्तिशाली बनाओं तभी गीता के मर्म को समझ सकोंगे।

महंगाई को काबू करने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार की प्राथमिकता को जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने कहा की नई सरकार इसको काबू में रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। इसके लिए जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कारगर कदम उठाए जाएंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा देश को भ्रष्टाचार के अभिशाप वाले धन के खतरे से मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। कालेधन के खतरे से निपटन के लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार भारतीयों की विदेशों में जमा गैर-कानूनी कमाई को वापस लाने के लिए विभिन्न देशों से संपर्क करेगी। इस काम को विदेशी सरकारों के साथ सक्रियता से संपर्क करके जोर-शोर से आगे बढ़ाया जाएगा।

इसके साथ ही राष्ट्रपति जी ने सरकार और समाज के विकास और राष्ट्र की समृद्धि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। इतना ही नहीं श्री मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के सम्मान स्वरूप लोक सभा अध्यक्ष के रूप में एक महिला को निर्विरोध निर्वाचित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा मंत्री परिषद् में काफी महिलाओं को स्थान दिया है। यह सरकार की महिला सशक्तिकरण तथा उनके सम्मान के प्रति सरकार द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता का ही प्रस्फुटन है।

सरकार ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ मिलकर कार्य करेगा। हिमालय के पारिस्थितिकीय संरक्षण को प्राथमिकता देगी तथा राष्ट्रीय हिमालय मिशन की शुरुआत की जाएगी।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चतुर्भुज परियोजना को पुनर्जीवित करने की बात कही गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में 20 किलोमीटर के

पथ का नित्यप्रति निर्माण होता था, जोकि यूपीए के कार्यकाल में 2-3 किलोमीटर तक प्रतिदिन के हिसाब से घटकर रह गया।

देश के सबसे बड़े उपक्रम रेलवे की बात करें तो यूपीए के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में घोषित 1,26,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं लंबित है। यूपीए सरकार विगत 10 वर्षों में सड़क से संसद तक सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करती रही तथा धरातल पर सरकार का कोई काम दिखाई नहीं दिया। जिसके परिणामस्वरूप देश की जनता ने यूपीए सरकार के खिलाफ बढ़-चढ़कर मतदान किया।

आज भारत युवाओं की 65 फीसदी आबादी वाला विश्व का सबसे युवा देश है। यूपीए सरकार ने अपने एक दशकीय कार्यकाल के दौरान 20 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख युवाओं को रोजगार देने में यूपीए सरकार को लाले पड़ गए जिसके परिणामस्वरूप युवाओं ने यूपीए सरकार के खिलाफ बढ़-चढ़कर मतदान किया तथा श्री नरेंदी मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत माना।

यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भारत परंपरा को निभाते हुए अपने आगे की पीढ़ी के लिए विरासत स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को 8.4 जीडीपी के स्तर पर छोड़ा था, जोकि यूपीए के कार्यकाल में 4.8 के निम्नतम स्तर तक पहुंचा दिया गया, ऐसा तब हुआ जब यूपीए सरकार में कई अर्थशास्त्री मौजूद थे।

श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी त्वरित कार्यशैली के तौर पर अपने मंत्री परिषद् के सदस्यों से 100 दिनों के काम-काज का एजेंडा तलब किया तथा साथ ही उन्हें देश की जनता की समस्याओं को त्वरित गति से सुलझाने की हिदायत भी दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम की भी घोषणा की। सरकार द्वारा दिया गया यह प्रयास अभिनंदनीय है।

कालाधन और भ्रष्टाचार जो भारतीय लोकतंत्र के लिए दीमक की तरह है, उन पर काबू पाने के लिए मोदी जी की सरकार ने विश्व जांच दल गठित कर दिया है। इससे वास्तव में लोकतंत्र के प्रति सरकार की जवाबदेही झलकती है। इससे जनता के बीच सरकार की लोकप्रियता जरूर बढ़ने वाली है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की नीति कि मित्र बदल जाते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जाते। इस उक्ति पर अमल करते हुए मोदी जी की सरकार ने 26 मई को अपने मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में अपने सभी पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित कर दक्षिण एशियाई क्षेत्र और विश्व को एक विशिष्ट और साहसिक संदेश दिया है, जोकि सराहनीय है। इस पहल की तात्कालिक बड़ी उपलब्धि यह है कि श्रीलंका और पाकिस्तान सरकार ने भारतीय मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ रिहा कर दिया है। वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सार्क के नेताओं के साथ हिंदी में बात करके एवं अमेरिका और यूएन की मीटिंग में जो प्रधानमंत्री जी हिन्दी में स्पीच देने वाले हैं वह कदम सराहनीय तथा अभिनंदनीय है, क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्रीय भाषा हिन्दी का गौरव बढ़ाया है।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से पता चलता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उनकी सरकार कितनी दूरदर्शी है। पिछले वर्षों में भारत की साख जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचे गिर गई थी, उसको ऊपर उठाने के लिए तथा भारत को विश्व की ताकत बनाने के लिए भाजपा प्रेरित एनडीए सरकार जरूर सफल होगी। इसका भारतीय जनता को पूर्ण विश्वास है।

अच्छे दिन आने वाले है, इसकी शुरुआत मोदी जी की सरकार ने एलपीजी गैस के दाम 23 रुपये घटाकर कर दी है। यह देश की जनता के लिए एक राहत भरी सौगत है। श्रीमान् मोदी जी की सरकार के आने के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया निरंतर मजबूत हो रहा है।

अंत में राष्ट्रीय महोदय ने श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वस्पर्शी, सवपोषक तथा सर्वसमावेषक नीति की बात कही है, जोकि बहुत महत्वपूर्ण है। इस सरकार में वह क्षमता है कि वह हर आपत्ति को अवसर में पलट देगी एवं विपत्तियों को विकास में परिवर्तित करेगी। अंत में राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने भाषण में उल्लिखित सरकार की तमाम जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का मैं पुरजोर समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर. ध्रुवनारायण** (चामराजनगर) : दिनांक 9 जून, 2014 की समवेत हुई दोनों सभाओं में अभिभाषण देने पर हम राष्ट्रपति महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

एक बार फिर इस महान राष्ट्र के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रणाली में अपनी पूर्व निष्ठा व्यक्त की है। हाल में पूरे हुए संसदीय निर्वाचन में यह बात स्पष्ट दिखी है। उम्र, लिंग, धर्म आदि को नजरअंदाज करते हुए लोगों ने चुनावों में भाग लिया। देश के लोगों ने बड़ी अभिलाषा से नई सरकार के लिए मतदान किया है तथा श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार समय की आवश्यकता तथा इस परिवर्तन के पीछे के तथ्य की अनुभूति करे। मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह समाज के सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए साथ मिलकर कार्य करेगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री आर. ध्रुवनारायण]

आज देश कई समस्याओं का सामना कर रहा है। इन मुद्दों का समाधान करने तथा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को सावधानी से कार्य करना चाहिए। सरकार को राष्ट्र के समग्र विकास के लिए कार्य करना चाहिए। कृषि, मानव संसाधन विकास तथा बुनियादी अवसंरचना विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देश समुचित सामाजिक न्याय तथा महिला सशक्तीकरण, वंचित तबके अभी अल्प संख्यक समुदाय के कल्याण के बिना पूर्ण नहीं हो सकता।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर विचार करे जिन पर देश को इस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:—

- सरकार ने बाजार में खाद्यान्नों की समुचित आपूर्ति करके खाद्यान्न मुद्रास्फीति को कम करने भी अकांशा व्यक्त की है। किन्तु सरकार को किसानों को न्याय देने तथा उनकी उपज का बाजार मूल्य देने में पारदर्शिता और ईमानदारी बरतनी चाहिए।

- सरकार को किसानों की आवश्यकता तथा मांग की उपेक्षा करके केवल अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।

- सरकार बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त 100 नए शहरों की स्थापना की बात कर रही है। सरकार को नए शहरों का विकास करते समय क्षेत्रीय असंतुलन (विकास) के कारकों, पिछड़ेपन, सामाजिक न्याय/पिछड़ापन एक अन्य महत्वपूर्ण कारकों तथा उनके क्षेत्रीय वितरण पर अवश्य विचार करना चाहिए।

- सरकार को सामाजिक न्याय तथा मानव संसाधन विकास पर समान महत्व देना नहीं भूलना चाहिए। आर्थिक वृद्धि उक्त कारकों (सामाजिक क्षेत्र और मानव संसाधन विकास में सरकारी व्यय की कटौती आदि) की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

- सरकार ने सामाजिक न्याय की नीतियों के बारे में अपने दृष्टिकोण पर बहुत अधिक बात नहीं की है। वंचित तबकों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण के लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई गई है। सरकार को सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण हेतु अपनी सकारात्मक कार्य योजना बनाना चाहिए। विशेषकर महिलाओं, दलितों और समाज के निचले तबकों के उत्पीड़न के संबंध में लिए कड़े कानूनों को लागू किया जाए।

- हाल में दलित लड़कियों के विरुद्ध होने वाले अपराध उनके प्रति अविलंब कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाते हैं तथा महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध पर सम्बद्ध तरीके से शीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता हे।

- 'गरीबी का कोई धर्म नहीं होता' नारा केवल नारा नहीं होना चाहिए। सरकार को कई विशेष कार्य विशेष कार्यक्रम जारी रखने के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए। संप्रग सरकार द्वारा गरीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए योजनाएं चलाई गई थी।

- सरकार ने "भूमिगत जल स्तर और उसकी गुणवत्ता में सुधार", "वर्षा जल संचयन" एवं "नदी जल का समुचित उपयोग" जैसी गंभीर चुनौतियों पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। सरकार को राज्य सरकारों से समन्वय करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर इन मुद्दों के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करना चाहिए।

- सरकार को राज्य सरकारों के साथ कार्य करना चाहिए तथा कृषि को सुगम बनाने के लिए संप्रग सरकार के विशेष कार्यक्रमों को जारी रखना चाहिए। सरकार को विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र की मांगों की आवश्यकताओं को भूलना नहीं चाहिए।

- हाल में सड़क दुर्घटनाओं के हताहतों के आंकड़ों की रिपोर्ट एक बड़ी चिंता का कारण है। सरकार को सड़क दुर्घटनाओं के कारण हताहतों होने वाले व्यक्तियों की संख्या में कभी लाने का समाधान या मार्ग ढूंढना चाहिए। सरकार को हताहतों की संख्या में कभी के लिए यथा संभव शीघ्र जीवन सक्षम प्रणाली मैं सुधार तथा रले उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

- सरकार को देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए तथा इस हेतु दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिए। उन्हें वास्तव में सरकार एक स्वरोजगार के लिए विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं आशा करता हूं कि यह सरकार इन अपेक्षाओं को पूरा करेगी तथा अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य करेगी।

[हिन्दी]

***श्री दद्दन मिश्रा** (श्रावस्ती) : मैं महामहिम राष्ट्रीय महोदय के अभिभाषण पर श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। देश की कोटि-कोटि जनता ने विकास पुरुष आरदणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी को "सबका साथ-सबका विकास" सिद्धांत को अपना कर "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" के निर्माण में सहभागी बनाने का अवसर प्रदान किया। अत: उन सभी नागरिकों का सादर अभिनन्दन एवं धन्यवाद।

"यत् पिण्डे तत् बह्माण्डे" जो पिण्ड (शरीर) में है वो ब्रह्माण्ड में है तथा जो ब्रह्माण्ड में है वो पिण्ड में है। महामहिम का अभिभाषण जो सरकार की नीतियों का आइना होता है, इसमें विकास, भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हेतु उन समस्त नीतियों का वर्णन है, जिससे देश समृद्धशाली, वैभवशाली बनेगा।

विश्व के सबसे युवा देश में युवाओं को रोज़गारपरक शिक्षा एवं "युवा संचालित" विकास व्यवस्था प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।" हर हाथ को हुनर" के उद्देश्य से बनायी जानी वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सराहनीय कदम है।

निवेदन है कि मैं जिस श्रावस्ती लोक सभा का प्रतिनिधि हूं, वह पूर्व प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कर्म क्षेत्र रहा है व उन्होंने बार-बार संसद में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। आज़ादी के 65 वर्षों बाद भी यह सीमावर्ती क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है। अत: यहां एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज एवं रोज़गारपरक व्यवसायिक शिक्षा के संस्थानों की अत्यंत आवश्यकता है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। "हर खेल को पानी" जो सिकान भाइयों हेतु हमारे एजेंडे में था, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" लागू करेगी। यह अत्यंत महत्व का विषय है, क्योंकि किसान ही विकास के पथ पर हमारी रीढ़ की हड्डी है।

निवेदन करना चाहता हूं कि श्रावस्ती लोक सभा का सीमावर्ती तराई इलाका अत्यंत उपजाऊ होने के बावजूद भी सिंचाई के साधनों के अभाव में केवल वर्षा जल पर आश्रित रहता है, जिससे किसानों को न ही उचित पैदावार मिलती है और न ही वे देश के विकास में सार्थक योगदान दे पाते हैं। अत: इस हेतु भी आवश्यक कदम उठाये जाये।

"कृषि रेल नेटवर्क" एवं हाई स्पीड ट्रेन अत्यंत सराहनीय कदम है, परंतु मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दु:ख हो रहा है। कि आज़ादी को 65 वर्षों के उपरांत भी श्रावस्ती जिला देश के मैदानी भागों का एक मात्र जिला है, जहां एक इंच भी रेल लाइन नहीं है। इसके बिना विकास की अवधारणा नहीं है। विगत वर्षों में लगातार इस हेतु आंदोलन होते रहे हैं वे क्षेत्र की जनता पूर्णत: आशान्वित है कि विकास पुरुष आरदणीय मोदी जी द्वारा ही दुरूह कार्य संभव होगा।

पर्यटन विकास भी हामरी सरकार की प्राथमिकताओं में है। विदित हो कि श्रावस्ती विश्व प्रसिद्ध बौद्ध एवं जैन धर्मावलम्बियों का तीर्थ स्थल है एवं लाखों विदेशी सैलानी यहां आते हैं, परंतू मूलभूत सुविधाओं एवं नियमित हवाई उड़ान के अभाव में जबकि श्रावस्ती में हवाई पट्टी पहले से है। अगर इस हवाई पट्टी का विस्तार कर नियमित उड़ान शुरू कर दी जाये तो पर्यटन के क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक प्रगति की वहां अपार संभावनायें हैं।

श्रावस्ती लोक सभा क्षेत्र में बलरामपुर जिले में सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अत: सड़कों के विकास हेतु भी कार्य योजना की अत्यंत आवश्यकता है।

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिंदर सिंह (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए अभी खड़ा हुआ हूं। इस पर और आगे बोलने से पूर्व, मैं इस मुद्दे की ओर लौटना चाहता हूं जिसे मैंने पहले उठाया था और जिसकी अपने अनुमति नहीं दी थी। वह मुद्दा इस प्रकार है। हमारे पास बहुत अच्छी सेना है जिसकी संख्या लगभग 1.3 मिलियन है। हमारी सेना बहुत ही अनुशासित है। हमारी सेना विश्व में तीसरी सबसे बड़ी सेना है। इस सेवा में हमारी यह परम्परा रही है कि सेना प्रमुख इत्यादि के रूप में प्रोन्नत होने वाले लोगों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है और इस तरह अंतराल को भरा जाता है। अब मुझे बहुत दु:ख हुआ है कि एक मंत्री ने इस संबंध में कुछ कहा है। यकीनन, यह उनकी संख्या की सरकार है जसने उन पर टिप्पणियां की और उच्चतम न्यायालय को दस्तावेज भेजे। परंतु इसके अलावा भी, आज प्रात: उनके द्वारा ट्वीट में प्रयोग की गई भाषा अपमानजनक है। भारत सरकार ने पहले ही सेना प्रमुख को नियुक्त कर दिया है जो जुलाई में पदभार संभालेंगे। "उन्हें और उनके सहयोगियों को अपराधी कहना और उनके अधीन कार्य करने वाले लोगों को डकैत कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और उनको मंत्री परिषद् से हटाया जाएगा। मुझे लगता है कि इससे इस तरह निपटने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।

हम दो दिनों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को सुन रहे हैं। अनेक मुद्दे है जिन्हें पहले भी उठाया गया है। सदन में हमारी नेता ने भी अनेक मुद्दे उठाए हैं। जैसा कि मैं देखता हूं हमारे पास 58 मदें है जिसे राष्ट्रपति ने आपने भाषण में रखा हैं जैसा कि हमने पहले भी सुना है इनमें

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से 90 प्रतिशत मदें पुरानी है। यह कांग्रेस पार्टी के वही कार्यक्रम हैं जिन्हें सत्तारूढ़ सरकार द्वारा अन्य नाम के अंतर्गत लाया गया है।

प्रश्न यह है कि मुद्दे अनेक है। हम समझते हैं कि गरीबी उपशमन से लेकर वे गरीबी उन्मूलन तक जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं वे इसे कैसे करेंगे। एक चुनाव में भाषण देना ठीक है। परन्तु सदन में समुचित भाषण देने के लिए हमारे पास यह समुचित पृष्ठाधार सूचना होनी चाहिए कि जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वे पांच वर्षों में 100 शहर बनाना चाहते है।। वे पांच वर्षों में 100 शहर कैसे बनाएंगे? हम यह जानना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश के प्रत्येक घर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में 24 घंटे बिजली होगी। इनमें शौचालय होंगे और इनमें सब कुछ होगा। हम जानना चाहेंगे यह कैसे होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वे मात्र वक्तव्य देकर बरी नहीं हो सकते। ये ऐसी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। वे गरीबी उन्मूलन करना चाहते हैं। हमारे साथ पहले से ही नरेगा, स्वास्थ्य योजनाएं और अन्य योजनाओं जैसे कार्यक्रम है। इन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा गरीबी को आठ प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक लाया गया था। हम आगे यह जानना चाहते हैं कि इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए क्या किया जा रहा है ताकि इसे हासिल किया जा सके।

मैं एक बात और जानना चाहूंगा। हमारे देश में विशेषकर उत्तरी राज्यों में एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे नहीं पता इसे क्यों नहीं उठाया गया है। यह नशे का मुद्दा है। मेरे राज्य में 70 प्रतिशत लोग नशे की चपेट में है जो कि पूर्णरूप से एक खतरनाक स्थिति है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मकबूलपुरा नाम का एक मोहल्ला है जहां 90 प्रतिशत लोग नशे की लत की वजह से मर चुके हैं और दस प्रतिशत लोग नशे के आदी है जो मरने वाले हैं। ये ऐसी बाते हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसे उजागर करना चाहिए। हम इस समस्या से कैसे निपटेंगे? क्या नशा-मुक्ति केन्द्रों को धनराशि देंगे? क्या हम इन गतिविधियों को रोकेंगे? मैंने इस मुद्दे को पांच विभिन्न अवसरों पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उठाया था जिसमें मैंने कहा था कि जब तक भारत के पास नशे के संबंध में कोई नीति नहीं होगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा (आनन्दपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप कौन से रूल के तहत प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा : जब पंजाब सरकार ने...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

कैप्टन अमरिंदर सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं इस मुद्दे को किसी सरकार का अपमान करने के लिए नहीं उठा रहा हूं। मुझे लगता है उन्हें महसूस होता है कि मेरा हमला उनके ऊपर है।

सच तो यह है कि राज्य का 70 प्रतिशत बड़ा आंकड़ा है। राज्य सरकार ने नशाखोरों को पकड़ने का कार्यक्रम आरंभ किया है। मैं समझता हूं। उन्होंने करीब 20,000 युवाओं को कैद किया है, जो नशाखोर हैं। उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। उन्हें अस्पताल भेजा जाना चाहिए जहां उनकी देखभाल के लिए नशामुक्ति केन्द्र होने चाहिए। हम कह रहे हैं, कम उम्र के साथियों को मत पकड़ो, यह उन लोगों को पकड़ों जो वासतव में ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं और इस देश में ड्रग्स को ला रहे हैं।

इस देश में ड्रग्स आने के तीन रास्ते हैं। एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तो स्वर्णिम त्रिभुज के जरिए है ही। बीएसएफ से जितना हो सकता है, वह इसे रोकती है, और मैं आश्वस्त हूं कि वे इसे कर रहे हैं। उन्हें सख्ती करनी है, मैं आश्वस्त हूं गृह मंत्री इसे सख्त करेंगे। दूसरा, हमारी स्वयं की राष्ट्रीय ड्रग नीति है। आज मध्य प्रदेश में कानूनन तरीके से ड्रग्स का बेरोकटोक उत्पादन और बिक्री की जा रही है। उसके बाद, पड़ोसी राज्य राजस्थान में, इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता, परंतु लोग इसका व्यापार कर सकते हैं और वे इसमें व्यापार करते हैं। पंजाब, जो पड़ोसी राज्य है, इन सभी ड्रग्स के लिए एक लाभकारी बाजार बनता है और इसी में ये बच्चे फंस रहे हैं।

आप मोहल्लों को गायब होते हुए कैसे देख सकते हो? हम कैसे हजारों गांवों को इसके त्रस्त होते हुए छोड़ सकते हैं? उन्हें पकड़ना ठीक हे, आप उनसे सूचना चाहते हो, तो उन्हें पकड़ो। परन्तु उन्हें जेल में न डालें, उन्हें अस्पताल भेजें। उन्हें अस्पताल जाने दें और उपचार कराने दें। उसके बाद आपके पास जो भी सूचना हो, भारतीय स्वापक ब्यूरो इसमें भी देख सकता है। सरकार को इसे करना चाहिए और इस सबको नियंत्रण में रखना चाहिए। अन्यथा, हमारे सामने गंभीर समस्या होगी।

कल हमने संख्या बल की बात की। मेरे नेता ने बहुत उचित कहा कि हम भले ही 31 प्रतिशत हों, परंतु यह 10 करोड़ लोगों के बराबर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। इसके बावजूद उन्होंने कौरवों और पांडवों के बारे में उदाहरण दिए। यह एक उदाहरण है। इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। महोदया आपने मासाडम के बारे में सुना होगा। 100 व्यक्तियों ने सैनिकों की अक्षौहिणी का मुकाबला किया। जब जूलियस सीजर जर्मनी गया और गॉलों के विरुद्ध लड़ाई की, एक अक्षौहिणी ने गॉलों को पराजित किया। अत:, संख्या से फर्क नहीं पड़ता, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है और हमारे अंदर लड़ने विरोध करने की शक्ति है, और जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जो देश को और भारत के लोगों को प्रभावित करता हो, तो हम उनके लिए लड़ने के लिए हैं और हम ऐसा करेंगे। हम संख्या में मात्र 44 नहीं हैं, हम उससे ज्यादा है। हमारे हृदयों में हम उससे कहीं ज्यादा हैं।

महोदया, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि संप्रग सरकार के दस वर्षों के पश्चात् आज हम मानसून के दौरान बारिश कम होने का सामना कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, कि क्या यह प्रभु की इच्छा है या क्या यह है कि नई सरकार आई है और मानसून नहीं आया हैं वे कहते रहते हैं कि यह एल निनो प्रभाव है, परंतु मैं इसे एल मोदी प्रभाव चाहूंगा। ऐसा इसलिए क्योंक मेरा मानना है कि जब कोई कुछ गलत करता है, और मैं मानता हूं कि गुजरात में गलत हुआ है, मैं सोचता हूं ऊपर ईश्वर है जो हमें भी देखता है...*(व्यवधान)* शायद आप सहमत न हों। सहमत न होने का यह आपका पनी विशेषाधिकार है। परंतु सच्चाई यह है कि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो शायद हमारे ईश्वर को पसंद नहीं...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदया, गुजरात में क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

कैप्टन अमरिंदर सिंह : आपने गोजरा के बारे में नहीं सुना है? आपने इशरत जहां के बारे में नहीं सुना है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : अभी भी समझ नहीं आया। ...*(व्यवधान)* आप न गुजरात जीत पाए न देश जीत पाए हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिंदर सिंह : महोदया, मुझे जो कहना था, मैं कह चुका हूं।...*(व्यवधान)* अब मैं एक रैंक एक पेंशन के मुद्दे पर बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आपके तो कुछ कहने का हक ही नहीं है।...*(व्यवधान)*आप तो बोल ही नहीं सकते।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : विधूड़ी जी बैठ जाइये। हर समय बोलना जरूरी नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिंदर सिंह : अब मैं एक रैंक एक पैंशन पर बोल रहा हूं। आज माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया कि 'एक रैंक एक पेंशन' इस सरकार द्वारा लाई गई थी। परन्तु यह पिछली सरकार द्वारा लाई गई थी। आइए, मैं आपको बताता हूं यह कैसे हुआ...*(व्यवधान)* मैंने चंडीगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की एक बहुत बड़ी बैठक की थी। मेरी पार्टी की अध्यक्ष वहां आई थीं। उन्होंने वहां न प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि यह किया जाएगा और वे संपूर्ण मामले को देखेंगी। जैसी कि उन्होंने प्रतिबद्धता जताई थी पिछली सरकार में यह 'एक रैंग एक पेंशन' लाई थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : दस साल लग गये।...*(व्यवधान)*

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अनुराग जी, आप हर चीज में मत बोलो। हम भी आपको बोलने नहीं देंगे।...*(व्यवधान)* हम कितने आराम से सुन रहे हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हर समय नहीं टोकते।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी भी बोलने की टर्न आने वाली है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, इस प्रकार से बातें नहीं होतीं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कैप्टन अमरिंदर सिंह : मैं कह रहा हूं कि भूतपूर्व सैनिकों की एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी आई थीं और यह प्रतिबद्धता जताई थी। पिछली लोक सभा के अंतिम सत्र में इसे पारित किया गया था और धन की प्रतिबद्धता जताई गई थी। वित्त मंत्री ने और प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि 500 करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं होंगे और जो रक्षा मंत्रालय चाहेगा, वह उपयुक्त समय पर देगा। इसलिए, यह मुद्दा इसके साथ समाप्त हो गया था।

मैं यह कह रहा हूं कि – यह 90 प्रतिशत कार्य का भाग है, जिसका वे दावा कर रहे हैं, परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर सकती...*(व्यवधान)* महोदया, कया आप नहीं चाहती कि मैं बोलू?

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। अब चूंकि वे सरकार में हैं मैं, उन्हें यह याद कराना चाहता हूं। जब श्रीमती सुषमा स्वराज 2009 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहीं थीं, उन्होंने कहा था कि वे महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए समय-सीमा चाहती हैं। क्या अब वे यह प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए तैयार होगी। 'आरक्षण विधेयक' को कब लाया जाएगात्र आइए इसे सुनें।

ये बातें हैं। मुझे उनसे काफी कुछ पूछना है, परन्तु आप मुझे समय नहीं दे रही हैं।

ऐसे अनेक अधिनियम हैं, जिनकी सबके द्वारा प्रशंसा की गई हैं, और जो सबके लिए उपयोगी है। इसका उल्लेख राष्ट्रपति अभिभाषण में क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे पास सूचना का अधिकार अधिनियम है – हम सभी इसको पसंद करते हैं और पूरा देश इसको पसंद करता है; हमारे पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छोटे परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रदान करता है ताकि उस गरीब परिवार के बच्चे कम से रात को भरे पटे के साथ सो सकें। हम यह सब करना चाहते थे; ये मामले हैं जिन्हें देखे जाने की आवश्यकता है।

मैं इसे शीघ्र समाज करना चाहूंगा, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा।

मनरेगा ने अनके चीचें की हैं, झारखंड से मजदूर हमारे राज्य में आते थे। परन्तु मनरेगा के कारण लोगों को अपने राज्य में धन मिल रहा है और इसलिए अब बिहार और झारखंड से मजदूर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि यह योजना कितनी प्रभावी रही है। इन स्कीमों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

हमारे पास ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, जो गरीब लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा का अवसर प्रदान करता है। ये अच्छी बातें हैं।

सरकार का, यदि ये नहीं किये गए हैं तो भी अपने कार्यक्रम और भविष्य हेतु कार्यसूची में इसे संज्ञान में लेना चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : चंदूमाजरा जी।

मेरा सब सदस्यों से निवेदन है कि वे थोड़ा कोआपरेट करें, ताकि सभी सदस्यों को बोलने के लिए हम थोड़ा-थोड़ा समय दे सकें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा (आनन्दपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदय मैं श्री मुलायम सिंह यादव के भाषण को सुनने के बाद अपनी मातृ भाषा पंजाबी में बोलूंगा।

अपराह्न 12.29 बजे

[**डॉ. एम. तंबिदुरै** *पीठासीन हुए*]

***श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा** (आनन्दपुर साहिब) : माननीय महोदय, मुझे संसद की संयुक्त बैठक पर माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी मातृ भाषा पंजाबी में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। शिरोमणि अकाली दल की ओर से, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। लोकतंत्र एक कंगाल को शासक और एक शासक को कंगाल बना सकती है, यह एक आम आदमी को देश का शासक बना सकती है और शासक को सिंहासन से हटा सकती है।

सभापति महोदय, भारत द्वारा आजादी प्राप्त करने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि गैर-कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में भारी बहुमत से विजय प्राप्त की हैं और एक गैर-कांग्रेसी गठबंधन के निर्णायक जनादेश प्राप्त किया है। इस जीत का श्रेय श्री नरेन्द्र मोदी और उनके समर्थ नेतृत्व को जाता है। एक कुशल प्रशासक और अनुभवी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छवि से अद्‌भुत परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसी के कारण लोगों ने उनमें विश्वास जताया है।

महोदय, भारत के लोग पिछली सरकार के भ्रष्टाचार घोटालों, आसमान सूती कीमतों और निरंतर बढ़ती बेरोजगार से परेशान थे, इसीलिए लोगों ने पूर्व यूपीए सरकार को सबक सिखने का निर्णय लिया। लोग आामूल-चूल परिवर्तन चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारी बहुमत के साथ एनडीए को सत्ता में बिठाया।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में वर्तमान सरकार की नीतियों को रेखांकित किया गया है। फिर चाहे यह स्वास्थ्य क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र हो, इन अहम क्षेत्रों को यथोचित महत्ता दी जाएगी। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' एक महत्वपूर्ण योजना है, जहां बालिका और लड़कियों की शिक्षा पर ब्यान केन्द्रित है।

महोदय, मैं दो महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर इस महान सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, हमारे देश का संघीय ढांचा काफी महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने भारत को 'राज्यों का संघ' घोषित किया था। वे ऐसा देश कभी नहीं चाहते थे जहां केन्द्रीय सरकार के पास सभी शक्तियां हों। हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे देश हेतु संघीय ढांचे की परिकल्पना की थी। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर राज्यों की शक्तियों को हड़पने का प्रयास किया है। मनरेगा आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित हैं। केन्द्र द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं और उनपर केन्द्र का नियंत्रण रहता है। राज्य सरकारों के पास कोई अधिकार नहीं होता है। उनके पास कोई आर्थिक

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

शक्ति नहीं होती है। केन्द्र सरकार ने लगातार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है।

समय की सबसे बड़ी आवश्यकता राज्यों को अधिकार प्रदान करना है। किन्तु राज्यों के सभी अधिकारों में कमी की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र और राज्य संबंध में अव्यवस्था की सी स्थिति हो गयी है। इस असंतुलन के कारण कई वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। राज्यों को अपने उचित और वास्तविक वित्तीय बकाया राशि प्राप्त करने के लिए भी केन्द्र के पास भीख मांगनी पड़ती है। यह बड़ी दुखद स्थिति है।

महोदय, वर्तमान सरकार ने राज्यों को शक्ति प्रदान करने और देश की संघीय ढांचे को और मजबूत करने का वादा किया है। इसने हमारी प्रणाली की नब्ज पर हाथ रखा है। मैं आश्वस्त हूं कि श्री नरेन्द्र मोदी की छात्रछाया में संघीय ढांचे में और मजबूती आयेगी।

महोदय, अकाली दल इस देश के संघीय ढांचे की मजबूती के लिए सदैव खड़ा रहा है। हमने राज्यों के सशक्तिकरण के लिए सदा समर्थन किया है। यद्यपि, इसके लिए हमारी भर्त्सना की गई है, फिर भी हम इसके लिए सदा समर्थन किया है। यद्यपि, इसके लिए हमारी भर्त्सना की गई है, फिर भी हम इसके लिए दृढ़ रहे हैं। हमें इसे नोट करते हुए खुशी है कि इस सरकार का इरादा देश के संघीय ढांचे को मजबूत करना है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सही रूप में इसे रेखांकित किया है। राज्यों को उनके बकाये प्रदान किए जाएं। राज्यों को निधियां प्रदान की जानी चाहिए। राज्यों से जुड़े मुद्दों के संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए। केन्द्र की इच्छा राज्यों पर नहीं लादा जाना चाहिए।... *(व्यवधान)*

महोदय, माननीय सदस्य की विघ्न डालने की आदत है। यह उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, योजनाओं को उचित योजना के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए और राज्यों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए। तभी राज्यों का विकास होगा। समृद्ध राज्यों से ही समृद्ध भारत बनेगा। राज्यों का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए और उन्हें उनका अधिकार दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि इस सरकार के तत्वावधान में कृषि पर जोर दिया जाएगा। अमीरों और गरीबों में खाई और चौड़ी हो रही है। हमें इसे रोकना चाहिए। 90 प्रतिशत लोग जरूरतमंद और गरीब हैं और मुश्किल में 10 प्रतिशत लोग हीं अमीर हैं। तथापि, ये 10 प्रतिशत लोग ही सभी लाभों को हड़प रहे हैं। 70 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए, कृषि को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सिंचाई योजनाओं का उल्लेख किया गया है। सिंचाई योजनाओं को लागू करना कृषि के लिए जीवन रेखा साबित होगा। पंजाब जैसे राज्य को भी इससे लाभ प्राप्त होगा। पानी एक चिरस्थायी समस्या है। पंजाब में भूजल स्तर में तीव्र गति से कमी आ रही है। विवेकपूर्ण तीरके से चर्चा जल संचयन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से इस समस्या का समाधान होगा।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा: सभापति महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करूंगा।... महोदय मुझे अपना भाषण समाप्त करने दें। हम सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम सभी का विकास चाहते हैं। इसलिए हम "सबका साथ सबका विकास" की बात करते हैं।... *(व्यवधान)*

महोदय, कांग्रेस पार्टी नीति यूपीए सरकार को केवल स्वयं के विकास में विश्वास था। उन्होंने अपने लोगों को पुरस्कृत किया। वर्ष 1984 में दंगे में सिक्खों का कत्लेआम किया गया। कांग्रेस के एक नेता ने सहजबुद्धि से यह कहा "जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।" इस प्रकार, उन्होंने 1984 के सिक्खों के नरसंहार को उचित ठहराया। महोदय, इस सदन ने कभी भी दंगा पीड़ितों के प्रति सम्मान नहीं व्यक्त किया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चेयरमैन साहब, मुझे दो मिनट और चाहिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे कनक्लूड करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

मैं कहना चाहता हूं कि 'सबका साथ सबका विकास" की बात कही गयी है। जिस कांस्टीट्वेंसी से मैं आया हूं– आनन्दपुर साहिब से, यह गुरू तेग बहादुर साहब ने शुरू किया था और आज मोदी साहब ने इसे शुरू किया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया "एक का नाश, दूसरे का विकास"।...*(व्यवधान)* एक का नाश करते रहे, दूसरे का विकास करते रहे। वर्ष 1984 में यहां कत्लेआम किया, निहत्थे लोगों को मार डाला, बच्चों के गले में टायर डालकर जलाया गया और उनके लीडर ने कहा कि जब बड़ा दरख्त गिरता है, तो धरती कांपती है। ये लोग अपने धर्मनिरपेक्षता के बुर्के में यहां साम्प्रदायिकता पालते रहे। ये लोग साम्प्रदायिकता पालते रहे और इन लोगों ने जो काम किए, उनके लिए यहां दो मिनट के लिए अफसोस भी नहीं किया गया, उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी गयी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***श्री डी.के. सुरेश** (बंगलौर ग्रामीण) : मैं श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा लाए गए और श्री राम विलास पासवान जी द्वारा समर्थित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

इस देश के लोगों को राष्ट्रपति के अभिभाषण से बहुत उम्मीद है क्योंकि यह सरकार की रूपरेखा, संकल्प और इरादों का दस्तावेज होता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुद्रास्फीति और महंगाई को नियंत्रित करने का उल्लेख है। एनडीए की सरकार सत्ता में आयी क्योंकि आपके नेताओं ने सभी चुनावी दौरों के दौरान महंगाई के मुद्दों को उद्धृत किया था। कृपया मैं आपसे यह स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं कि आप खाद्यान्न, सब्जियों, पेट्रोल और डीजल जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुओं, भवन निर्माण वस्तुओं के मूल्यों को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे जिन पर 80 प्रतिशत गरीब और मध्य वर्ग अपनी आजीविका के लिए निर्भर करता है। यद्यपि, आपने अपने चुनावी घोषणापत्र में महंगाई के बारे में यूपीए सरकार पर बार-बार लक्ष्य किया है, इसलिए आप मूल्य में कमी और इस पर नियंत्रण के तरीके के बारे में बिन्दु-वार बताएं ताकि नागरिक आश्वासन से अधिक कार्रवाई की उम्मीद करे। पहले से ही पेट्रोल के मूल्य बढ़े हुए हैं, बिजली की कमी है और आपने अभी तक ईंधन और अन्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारण पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की है। दूसरी ओर हमारी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को वर्ष 2004-05 के 640 रुपए प्रति क्विंटल से 111 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2012-13 में 1350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। धान के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 111.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर 590 रुपए से 1250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कांग्रेस नीति यूपीए सरकार का मानना था कि किसानों को खेती में उनके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की थी। किन्तु एनडीए के नेता इस संबंध में मौन हैं। क्यों?

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 7 में उल्लेख है – "मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है, गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है, भूख का कोई पंथ नहीं होता है और निराशा का कोई भूगोल नहीं होता है।"

महोदय, मैं एनडीए के नेताओं को यूपीए सरकार के गरीबी उन्मूलन की उपलब्धियों के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। जब तक हमारे देश में गरीबी और अमीरी के बीच अंतर कम नहीं हो जाता तब तक हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता, अत: हमारा लक्ष्य पूरे देश में गरीबी और कुपोषण की समाप्ति का होना चाहिए था। इसलिए हमारी यूपीए सरकार ने करोड़ों भारतीयों को खाद्य सुरक्षा देने तथा भूख की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा "ऐतिहासिक अवसर" का सूत्रपात किया गया। 81 करोड़ लोग अर्थात् भारत की 67 प्रतिशत जनसंख्या को योजना के अंतर्गत राजसहायता दरों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। लाभार्थियों को तीन रुपए प्रति किलो चावल, दो रुपए प्रति किलो गेहूं तथा एक रुपए प्रति किलो मोटे अनाज दिए जाएंगे।

किसी अन्य सरकार में गरीबी इतनी तेजी से कम नहीं हुई है जितनी यूपीए सरकार में कम हुई है। भारत में 2007 से 2012 तक गरीबी 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कम हुई है जोकि पिछले दशक की गिरावट की दर की तुलना में दोगुनी दर से अधिक है। लाखों भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है तथा उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव हुआ है।

यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे क्रांतिकारी उपायों के कारण संभव हो पाया है। अप्रैल, 2013 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 12.7 करोड़ घरों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं जोकि विश्व में सबसे अधिक रोजगार शूरू करने वाली योजना है। यूपीए ने कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना के अंतर्गत पूरे देश में ऋण ग्रस्त किसानों को ऋण माफी के लिए 72,000 करोड़ रुपए दिए जिससे ऋण ग्रस्त किसानों 4.3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को ऋण के चंगुल से बचाते हुए उन्हें वह पूंजी और नया जीवन मिला।

महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 8 में उल्लेख है – "मेरी सरकार जमा खोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करेगी।" मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणियों के लगभग 18 करोड़ घरों को देश में टीपीडीएस के अंतर्गत उचित दर की पांच लाख दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से राजसहायता युक्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए कदम उठाया है। इसके अलावा हामरी सरकार ने 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का कम्प्यूटरीकरण किया है एवं 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थियों का डिजटलीकरण का कार्य पूरा किया है तथा यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रहा है। हमने अपनी यूपीए सरकार में अनुसंधान संबंधी ज्ञान को खेतों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना शुरू की थी तथा लगभग सभी ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की है। लगभग 500 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई है। नई सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो उल्लेख किया है, उसमें कुछ नया नहीं है क्योंकि हमने इस दिशा में कार्य शुरू किया है।

इसके अलावा, महामहिम के अभिभाषण में विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का उल्लेख है जो मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए है। शहरों और गांवों में अंतर को समाप्त कीजिए, किसानों में विश्वास का संचार के लिए, परंपरागत और गैर-परंपरागत स्रोतों का तर्क संगत ढंग से मिलकर विद्युत

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। असैन्य प्रयोजनों के लिए परमाणु विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जाए। राष्ट्रीय सौर मिशन का विस्तार किया जाए, घरों और उद्योगों को गैस ग्रिड से जोड़ा जाए तथा कोयला क्षेत्र में सुधार किया जाए।

कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी-ए) को शुरू किया गया है जो हितधारकों को संगत सूचना के प्रावधानों तथा सेवाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता और आप को बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर ले जाने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे आजीविका कहा जाता है, को यूपीए द्वारा शुरू किया गया था। किन्तु नई सरकार ने इसका नाम बदल कर "आरयूआरबीएएन" कर दिया। इसी तरह यूपीए सरकार के निर्मल भारत अभियान का नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही है कि योजनाएं नई हैं और नाम पुराने हैं। हमारी यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक, खाद्य सुरक्षा विधेयक, लोकपाल विधेयक, की रक्षा विधेयक को पारित कर ऐतिहासिक कदम उठाया है। इन सभी कानूनों ने आम आदमी को मान और मर्यादा के साथ जीवन व्यतीत करने में मदद किया है। यूपीए सरकार ने ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों का अधिनियमन कर सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में पूर्व प्रयास किया है।

जहां तक शिक्षा की बात है, यूपीए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया तथा 16 केन्द्रीय विश्व विद्यालयों, 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) 5 नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), योजना और वास्तुकला के दो नए विद्यालय तथा 6 नए विधि विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति के अंतर्गत 20 नए आईआईटी की स्थापना हेतु योजना शुरू की तााि संस्थानों की स्थापना हेतु 15 राज्य सरकारों ने भूमि की पहचान की है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापक के 19,76,502 पदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 12,34,016 पदों पर भर्ती हुई है। 12.31 लाख संस्थानों में पढ़ने वाले 11 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को मध्याहन भोजन का लाभ मिला है।

जहां तक रेल और सड़क अवसंरचना का सवाल है संप्रग सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को जोड़ने के लिए 2 लाख किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण कराया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण सम्पर्क को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आवंटन को 88 प्रतिशत बढ़ाया गया है। विगत एक दशक में लगभग 17,394 किमी. लंबे राजमार्ग बनाए गए अथवा उन्नयन किए गए।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बेंगलूरु एक तेजी से विकसित हो रहा शहर है। इसकी जनसंख्या एक करोड़ से भी अधिक है। अवसंरचना को बेहतर बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि बेंगलूरु के लोग खुश रह सके। इसलिए, सरकार को शहर के यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए यात्री रेल नेटवर्क शुरू करना चाहिए और अविलम्ब शहर के केन्द्र से विमानपत्तन तक एक उच्च गति रेल लिंक शुरू करना चाहिए।

जहां तक देश में जब संबंधी विवादों का सवाल है राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह बहुत बड़ी चिन्ता की बात है कि सम्पूर्ण देश विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे की समस्या का सामना कर रहा है। मैं इस संदर्भ में एक ज्वलंत मुद्दे के बारे में बताना चाहूंगा कि हाल में काबेरी विवाद से संबंधित घटनाओं से दक्षिणी राज्यों विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। जब अंतर्राज्यीय जल मुद्दे की बात आती है तो कर्नाटकम के साथ हमेशा ही अन्याय किया गया है। बात अब यह है कि तमिलाडु केन्द्र सरकार से कावेरी प्रबंधन बार्ड बनाने का आग्रह कर रहा है ताकि कावेरी जल को छोड़ना सुनिश्चित किया जा सके। वहीं दूसरी ओर कर्नाट का एक बड़ा भाग सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति विगत कुछ वर्षों से बनी हुई है। यह मामला उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीन है। इस संदर्भ में कर्नाटक सरकार ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड नहीं बनाए जाने का अनुरोध किया है। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इसे ऐसा ही कोई बोर्ड बनाना चाहिए क्योंकि संविधान के अनुसार जल एक राज्य का विषय है। यदि केन्द्र सरकार एक प्रबंधन बोर्ड की स्थापना करती है तो इससे हमारे देश की संघीय संरचना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्र को ध्यान में रखकर इन समस्याओं निपटा जाना चाहिए।

अब तक, बेंगलूरु कावेरी नदी के 19 टीएमसी पानी का उपयोग कर रहा है। परन्तु लोगों के लिए यह अपर्याप्त है क्योंकि उन्हें सप्ताह में एक बार अथवा कभी-कभी सप्ताह में तीन बार जल मिलता है।

शहर का विस्तार हो रहा है और अधिक जल की आवश्यकता है। यदि शहर की जल आपूर्ति को 19 टीएमसी से नहीं बढ़ाया गया तो लोगों को परेशानी हो जाएगी। यदि किसी भी कारणवश जल आपूर्ति को कम कर दिया गया तो समस्या बद से बदतर हो जाएगी।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि हमारे पास जल बंटवारे के विवादों से निपटने के लिए कोई जल संबंधी राष्ट्रीय नीति नहीं है, ऐसे मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा है। प्राय: इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि और निर्दोष लोगों के मरने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि संबंधित राज्यों के बीच जल बंटवारे के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता हैं अत:, ऐसे विवादास्पद मुद्दों का एक स्थायी समाधान होना चाहिए। केन्द्र सरकार को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

वर्तमान में एक करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाला बेंगलूरु शहर पूर्णत: कावेरी नदी के जल पर निर्भर है। मानदंड को अनुसार, प्रत्येक

नागरिक को प्रतिदिन 150 लीटर जल मिलना चाहिए। शहर को प्रतिदिन कुल 1400 मिलियन लीटर जल की आवश्यकता है। परन्तु, लोगों को अभी भी अपेक्षित जल का आधा भी नहीं मिल रहा है।

यदि बेंगलूरु को पर्याप्त पेयजल और अन्य अवसंरचना नहीं मिलती है तो इससे न केवल बेंगलूरु अपितु राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 43 और 48 में भारत को मजबूत आत्म निर्भर और आत्मविश्वास वाला बनाने और सॉफ्टवेयर संभावना बनाने और ब्रांड इंडिया को पुनर्जिवित करने के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि बेंगलूरु को "सिलिकन वैली", "आईटी कैपिट" और अनेक अन्य नामों से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि भारत के स्नातकों और इंजीनियरों के लिए लाखों नौकरियां सृजित की जाती है, फिर भी बेंगलूरु को विश्व के प्रसिद्ध उद्योग, जो न केवल डॉलर लाता है अपितु विश्व का ध्यान भी आकर्षित करता है जिसे विश्व के विभिन्न राष्ट्रपतियों और प्रधानमत्रियों के दौरे द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है, की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अवसंरचना सुविधा की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। आपकी सूचनार्थ यह सिलिकन वैली अभी भी एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में है जहां विकास हेतु निधियां पर्याप्त नहीं है जिसे केन्द्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है ताकि इसे और अधिक मजबूत और देख का आईकन बनाया जा सके।

आईटी और सेवा क्षेत्र में रोजगार हेतु उच्च शिक्षित और योग्य युवाओं का निरंतर बेंगलूरु की ओर प्रवासन हो रहा है, जिससे वहां की सड़कों, जल, आवास, विद्युत और अन्य ऐसी अवसंरचना जैसे अस्पताल, विद्यालय इत्यादि जिनका अकेले राज्य-वित्त से रख-रखाव नहीं हो सकता पर बहुत दबाव पड़ रहा है तथा उद्योग रोजगार हेतु राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्र को केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में, जो चन्नपटना, रामनगर और कनकपुरा में हथकरघा और प्रसिद्ध रेशम उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जो लाखों कुशल कामगारों को रोजगार मिल रहा है पर वह क्षेत्र असंगठित है। जिसके लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 27, के अनुसार, इन उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। भारत के माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 28 में वैश्विक निवेश और औद्योगिक क्षेत्र और समर्पित माल भाड़ा गालियारा के संदर्भ में हमने पहले ही वहा है कि हमारे जिगानी, बिडाडी, बोम्मसांद्रा, बोम्मनहल्ली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्र सरकार के ध्यानाकर्षण और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 30 में उच्च गति वाली रेलगाड़ियों और रेल नेटवर्क की आवश्यकता पर, हम आपका ध्यान हमारे उप-नगरीय कस्बों कुनिगल, रामनगर, मगड़ी, चन्नपटना, कनकपुरा और अनेकल को इससे जोड़ने की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिससे औद्योगिक श्रमिकों की दैनिक आवाजाही समस्याओं का समाधान किया जा सके।

औद्योगिक श्रमिकों, असंगठित श्रम क्षेत्र, कामगारों के अधिकार और स्वास्थ्य, पेंशन, बीमा संबंधी इनके कल्याण पर भी आपके ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है।

मेरा अगला मुद्दा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षण के माध्यम के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति के बारे में है। इसका राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा-36 में उल्लेख नहीं किया गया है। मैं सम्मानित सदन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का यह दृढ़ मत है कि प्राथमिक शिक्षख में, या तो मातृभाषा या राज्य की क्षेत्रीय प्रशासनिक भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। वैश्विक युग में हमारी भाषा और संस्कृति को बढ़ाना और संरक्षित करना बहुत अनिवार्य है। भारतीय भाषाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति शुरू करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करुंगा, कि शिक्षा के माध्यम के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति शुरू करने के मुद्दे पर विचार करें।

मैं कहूंगा, यह इस नई सरकार के इरादे का एक वक्तव्य मात्र है। तथापि सरकार को मात्र अस्पष्ट वक्तव्य देने के बजाय कार्यान्वयन की समयबद्ध कार्य योजना बताना चाहिए। इस वक्तव्य में छुए गए कई मुद्दे, वास्तव में राज़ग के चुनावी घोषणा पत्र की ही पुनरावृत्ति हैं। चुनाव के समय तो कई दलों द्वारा कई वायदे किए जाते है।। परन्तु जब राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात आती है, यह एक साधारण वक्तव्य था आशय-पत्र मात्र नहीं होना चाहिए। यही पहली बात है जो मैं यहां बताना चाहता हूं कि महोदय, इसमें कोई ठोस कार्यक्रम तैयार नहीं किए गए हैं।

मैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने के सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मैं यह सुझाना चाहूंगा कि सरकार को इन कार्यक्रम को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए बजट में पर्याप्त निधि आबंटित करनी चाहिए।

प्रो. सुगाता बोस (जादवपुर) : सभापति महोदय, अपने दिल के भारत की अलख जगाए हुए, मैं अपनी मातृभूमि की थोड़ी सेवा करने के लिए हमारे इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर विदेश से भारत लौटा ...*(व्यवधान)*

मैं आप सभी को हमारी नेता, ममता बनर्जी और अखिल भारतीय

तृणमूल कांग्रेस के 34 संसद सदस्यों की तरफ से शुभकामना देता हूं। जिनमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही 11 महिलाएं हैं।

मैं इस सम्मानित सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली इस बहस में अपना प्रथम वक्तव्य देने का अवसर पाकर सम्मानित हूं। प्रथम वक्तव्य को बाधित करने की चिरकालीन यहां गौरवमायी परंपरा नहीं है और जब मैं बोलूं तो अपने साथी सदस्यों से शांतिपूर्वक सुनने की अपली करता हूं।

हम अपने राष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति भवन से संसद के केंद्रीय कक्ष में आकर हमें संबोधित करने के लिए बहुत आभारी हैं। हम केवल इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि नई सरकार को इस रस्मी अवसर का उपयोग केवल पुनती कामनाओं के विरुद्ध गाने की बजाये इस देश के लिए बेहतर नीतियों की रूपरेखा बनाने में करना चाहिए। हम सरकार की वह मजबूत भारत बनाने की प्रतिबद्धता को सार्थक हैं। जिससे वह पूर्ण विश्व में शीर्ष सम्मान प्राप्त करे।

हम प्रधानमंत्री द्वारा अपने शपथ ग्रहण समरोह में 'दक्षेस' देशों के अध्यक्षों को आमंत्रित करने की प्रशंसा करते हैं। हमें अपने पड़ोसियों के प्रति एक उदार और सुनिच्चित विदेश नीति की आवश्यकता है जिससे क्षेत्रीय समस्याएं वैश्विक मंच पर प्रमुख भूमिका की वैध महत्वाकांक्षा को बाप्ति न करें। भारत और चीन के लिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती शांपूर्वक ढंग से एक साथ ऊपर आने की है। लेकिन मैं अपने मित्र श्री राजीव प्रताप रूडी को मुक्तकंठ से चीन की विकदावली गाते देखकर दुखी हुआ। चीन एकदलीय तानाशाही और मनमानी संप्रभुता वाला राज्य है। हमारा विकास पथ हमारे अपने लोकतंत्र पर बेहतर ढंग से आधारित होना चाहिए। हम सरकार की इस बात पर सहमत हैं कि संपूर्ण एशिया में स्तरीय अवसंरचना बनाने में जापान हमारा बहुमूल्य साझीदार हो सकता है। एक इतिहासकार के रूप में मैं खुश हूं कि सरकार हमारा सांस्कृतिक क्षमता को पहचानती है। जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की शुरुआत की तो उन्होंने विश्व में भारत की सभ्यता के मार्ग का अनुकरण किया। टैगोर का विश्व बंधुत्व वैश्विक संबंधों के इस समकालीन दौर में हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है। क्योंकि हमारी माननीय विदेश मंत्री जी सभा में उपस्थित हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी विदेश नीति के कार्यान्वयन में अपना सहयोग देंगे।

सभापति महोदय यह सच है कि संघवाद को भावना से ओतप्रोत हमारी राजनीति में दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आयी है। महान स्वदेशी नेता बिपिन चन्द्र पाल ने अपनी पुस्तक 'द सोल ऑफ इंडिया' में उल्लेख किया कि महान राजा भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया उन्हें प्राचीन ग्रन्थों में राजाचक्रवर्ती बताया गया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस शब्द का अर्थ सम्राट नहीं बल्कि राजाओं के वृत में स्थित केन्द्र बिन्दु है। यह प्राचीन समय में महान राजकुमारों और राजा महाराजाओं के लिए एक आदर्श था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुस्लिम बादशाहों के शासनकाल के दौरान भारतीय राज व्यवस्था जो हमेशा से ही संघवादी थी, वह और भी अधिक प्रबल हो गयी। राजशाही का युग समाप्त हो चुका है लोकतंत्र के दौर में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की परीधि के एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना सीखना होगा। हम केन्द्र सरकार के सहयोगी संघवाद के वायदे का स्वागत करते हैं। जब केन्द्र सरकार ऋण ब्याज के रूप में राज सरकारों के राजस्व के बड़े हिस्सों को हड़प कर लेती है जो निश्चय ही संघवाद की इस भावना का उल्लंघन है। मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस बहस के उत्तर में यह स्पष्ट करे कि वह ऋणग्रस्त राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए क्या नीतियां अपनाएगी जो पिछली सरकारों की गैरजिम्मेवार फिजूलखर्ची से ग्रस्त है। मेरे राज्य सहित इन राज्यों का कोई दोष नहीं ये गरीबी उन्मूलन की दिशा में अपने विकास के एजेंडे को लागू नहीं कर सकते आधारणा कि 19वीं सदी में महान गुजरात नेता दादा भाई नारौजी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी।

मैं इस सरकार के द्वारा किए गए संरक्षणवादी दावे पर आपत्ति करता हूं कि यह सरकार भौतिक और सामाजिक अवसंरचना के संदर्भ में देश के पूर्वी क्षेत्र का विकास देश के पश्चिमी क्षेत्र की तर्ज पर करेंगे मैं राष्ट्रपति के भाषण से उदृत करना चाहता हूं। मैं अपने मित्र श्री भर्तृहरि महताब से थोड़ी अलग राय रखता हूं। मैं चाहता हूं कि ओदिशा में खुशहाली हो। मैं अपने आपको अच्छा ओडिशवासी समझता हूं क्योंकि मेरे दादाजी का जन्म कटक में हुआ था। यह वास्तविकता है कि पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों की तुलना में मानव विकास और सामाजिक अवसंरचना विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रत्येक विचारणीय सूचकांक के अत्यंत पिछड़े हैं। लिंग असंतुलन अर्थात् स्त्री-पुरुष अनुपात देश के पूर्वी और दक्षिण की तुलना में देश के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में अत्यंत दयनीय है। पश्चिमी क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र के पून्वोन्मेखी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्षेत्र से काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)* उदाहरण के रूप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने केन्द्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पूर्व ही दूरदर्शी कन्याक्षी योजना आरंभ की थी। जल सुरक्षा के लिए उनके जल धरो भरो कार्यक्रम जैसे अत्यंत सफल कार्यक्रम से प्रस्तावित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में काफी अनुभव प्राप्त किया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह किस प्रकार का भाषण है?... *(व्यवधान)*

प्रो. सुगाता बोस : राष्ट्रपति के अभिभाषण से आपने इन सबका उल्लेख किया है...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार का अनुसरण करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : यह उनका पहला भाषण है कृपया हस्तक्षेप न करें। मैं आपको बाद में अवसर प्रदान करूंगा। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। भाषण के दौरान किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करे। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

प्रो. सुगाता बोस : केन्द्र सरकार को यह सलाह देना चाहूंगा कि उन्हें पश्चिम बंगाल के आधुनिक मदरसा शिक्षा जिसमें राज्य सरकार का कम-से-कम हस्तक्षेप हो, का अनुसरण करना चाहिए। पूर्व में नया सूर्योदय हुआ है जिससे भारत के भविष्य का मार्ग प्रकाशित हो सकता है। फेडरल प्रश्न पर सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि सरकार को घुसपैठ अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर क्या कहना है। यह अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है, जिसका हमारे पड़ोसियों के साथ संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, जिस पर राज्यों के साथ पूर्व विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। हम यह कभी स्वीकार नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल कभी स्वीकार नहीं करेगा, नागरिकता की भाषा का प्रयोग गैर-अल्पसंख्यक पूर्वाग्रह हेतु दिखावे के रूप में किया जाएगा। हम उस तंत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिसके द्वारा राज्य प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने में योगदान दे सकते हैं। मैं, आज पीठासीन डॉ. तम्बिदुरई से सहमत हूं और जो पिछले कल यहां से बोले थे कि राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। राज्य और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों हेतु वित्त पोषण में अत्यधिक अंतर को हमारे युवाओं और युवा विकास के हितों में कम किया जाना चाहिए। यह विभिन्न राज्यों में केवल आईआईटी और आईआईएम के निर्माण मात्र से पूरा नहीं होगा। हमें प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षा की ठोस नींव पर विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों का निर्माण करना होगा।

सभापति महोदय, मुझे गंगा नदी को साफ करने संबंधी सरकार की योजना, एक आदर्श और उपयोगी परियोजना के बारे एक या दो निष्कपट शब्द कहने की अनुमति प्रदान करें। हम ग्रेट डेल्टा क्षेत्र से आते हैं, जहां गंगा की बड़ी सहायक नदियां समुद्र में मिलती हैं। हम दिविजेन्द्रलाल राय, के गीत *'पतितोधारणी गंगे, ओगो मां, पतितोधारणी गंगे'* को गाते हुए बड़े हैं। यह नदी बंगाल में हमारी मां है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यह बनारस के निवासियों के लिए है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे कवि काजी नज़रुल इस्लाम ने केवल गंगा के बारे में नहीं लिखा है: उन्होंने व्याख्या: *'गंगा सिन्धु, नर्मदा कावेरी जमुना ओई, बोहिया चोलेई अगेर मातो, कोई से अगेर मानुष कोई'*। गंगा और अन्य महान नदियां पहले की तरह बहती हैं; इन वर्षों के महान नदियां पहले की तरह बहती हैं; इन वर्षों के मनुष्य कहां हैं? विरह के साथ जुड़ा यह शोकगीत संभवत: नज़रुल इस्लाम के समय की तुलना में अब अधिक सटीक प्रतीत होता है। परन्तु भूपेन हजारिका की अमर आवाज में गाए गए गीत की पंक्तियां मुझे अभी भी याद आती हैं: *बिस्तिरणा दुपारेह असंख्या मानुषेर हाहाकार शुनेयो, निस्हाब्दे निराबे ओ गंगा तुमि, गंगा बोइयो को केनो?* सुषमा जी द्वारा *'हाहाकार'* शब्द का प्रयोग किया गया था यदि हम *हाहाकार* नहीं सुन सकते गंगा के मैदानों में दलित महिलाओं के साथ बर्बर हिंसा के कारण उनकी निराशा, तो हम स्वयं को भारत के लोगों के सच्चे प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकते। और गंगा के मैदानों से दूर हम मोहसिन शेख, पुणे में युवा कम्प्यूटर इंजीनियर की मौत पर रोते हैं। वह तथा कोचिन आकांक्षा वर्ग से संबंधित था, जिसके भविष्य के सपनों को शासक दल के निर्वाचन अभियान द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वह अच्छे दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहा, जिसका कि इस सरकार ने वादा किया है। उसका रोष केवल यह था कि ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद घर आते समय उसकी पहचान और वेशभूषा स्पष्ट थी। खेल जगत में हमारे राष्ट्र को गौरव दिलाने वाली हॉकी का प्रयोग हथियार के रूप में कर विविधता की अभिव्यक्ति को दबाने के लिए किया गया।

16वीं लोक सभा की संरचना भारत की समृद्ध विविधता को उस रूप में प्रदर्शित नहीं करती है, जिसमें इसे करना चाहिए। इसलिए यह हमारा विशेष कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वंचित अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को आवाज प्रदान की जाए। यदि आप सचमुच अच्छा समय लाना चाहते हैं, तो मैं सरकार से कहूंगा कि एकता के साथ एकरूपता, लोकतंत्र के साथ बहु-संख्यकवाद को भ्रमित न करें। अपने प्रसिद्ध निबंध *'भारतवर्ष'* में रविन्द्रनाथ ने चेतावनी दी थी: "जहां वास्तविक अंतर हो, यह केवल उस अंतर को सम्मान देकर और इसको इसके सही स्थान पर रखकर ही एकता प्राप्त करना संभव है। एकता केवल यह विधिक आदेश जारी कर प्राप्त नहीं की जा सकती कि हर कोई एक है।" सांस्कृतिक अंतर हेतु केवल स्वस्थ श्रद्धा रखकर हम हर किसी को भारत माता के चरणों में एकजुट करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते: *"ऐसो ही हिन्दु, ऐसो मुसलमान, ऐसो ही पारसी, बौद्ध, ईसाई, मिलो हो मायेर चारने"*।

मैं आपको एक आकृति के साथ छोड़ना चाहूंगा जब बंगाल के क्रांतिकारी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुजरात से हरीपुरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने गए थे।*...(व्यवधान)* उन्होंने और महात्मा गांधी ने मिलकर आधुनिक औद्योगिक भारत के विज़न को कृषि भारत दृश्य के साथ प्रवृत्त किया था। जवाहर लाल नेहरू और पटेल भी थे*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आइए उनके उदाहरण का अनुसरण करें और कहें कि हम भारत माता के लिए काम करेंगे कि वह पल्लबित हो और वह खुश हो...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मेरी बात समाप्त होती है।

[हिन्दी]

***श्रीमती रमा देवी** (शिवहर) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश की दशा एवं दिशा का उल्लेख है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार क्या करने वाली है, इसका लेखा-जोखा होता है। अभिभाषण में सरकार द्वारा देश की समस्याओं को दूर करने हेतु ठोस नीति का उल्लेख है। अभिभाषण के शुरुआत में ही राष्ट्रपति जी ने देश में व्याप्त गरीबी के प्रति चिंता व्यक्त की है तथा इसके पूर्ण निवारण और सहानुभूति, सहायता व सशक्तिकरण द्वारा सभी नागरिकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख कि है जो कि सराहनीय है। यूपीए की पिछली सरकार ने देश की जनता को निराश किया हैं जिसें विकास कम होता गया और महंगाई बढ़ती गई। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को प्राथमिकता से रोकने की बात कही है, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। देश की दो तिहाई से अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है इसके बावजूद पिछली सरकार वहां मूलभूत सुविधाएं और जीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करा सकी। हमारे देश की अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत कृषि है, परंतु कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहां किसानों को पिछले कुछ वर्षों के अत्यंत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति और भी दयनीय तब हो गयी जब देश के कुछ राज्यों के किसानों को आत्महत्या/ आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ा। यह पिछली सरकार की कृषि के प्रति गलत नीतियों को दर्शाती है। राष्ट्रपति जी द्वारा इस दुर्भाग्यपूर्ण हालात को बदलने के लिए वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता की बात से देश के हताश किसानों में ऊर्जा का संचार हुआ है तथा वैज्ञानिक तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी से कृषि की कल्पना से देश की जनता आशान्वित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" से किसानों को राहत मिलेगी तथा साथ-साथ सुखाड़ जैसी विभिषिका से भी कृषि को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह योजना सरकार की ऐतिहासिक योजना सिद्ध होगी। किसी भी राष्ट्र का विकास बहुत हद तक वहां की युवा शक्ति का आधारित होता है। आज हमारा देश विश्व का एक ऐसा देश है जहां युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। किन्तु, पिछली सरकार में युवाओं के विकास एवं उनके लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराने पर गंभीरता से धन नहीं दिया गया। जिसके कारण युवाओं की बेरोजगारी भी पिछली यूपीए सरकार की प्रमुख समस्या थी। वैसे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की बात एवं देश की आबादी के बड़े हिस्से को "हर हाथ को हुनर" स्कीम के उद्देश्य से और अत्यधिक हुनरमंद बनाने की बात राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कही है। देश में सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को सर्वसुलभ, किफायती और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी राष्ट्रपति जी ने इस सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है तथा नई स्वास्थ्य नीति तैयार करने का जिक्र किया है। सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली आगामी योजना "स्वच्छ भारत मिशन" के बारे में सुनकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा खुशी मिली है। क्योंकि, आज़ादी के इतने सालों बाद भी गांवों में गरीब परिवार की महिलाओं का खुले स्थान में शौच के लिए जाना अपमानजनक है। आज समाज के विकास और समृद्धि में महिलाओं की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। संसद एवं राज्य समाज के विकास और समृद्धि में महिलाओं की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। संसद एवं राज्य की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रति सरकार की वचनबद्धता से निश्चित रूप से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी तथा महिला सशक्तीकरण को भी बल मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि एक महिला दूसरी महिला की तकलीफ को बेहतर तरीके से समझ सकती है। आज महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा और भ्रूण हत्या जैसा अपराध आम बात हो चुकी है। भ्रूण हत्या का भयंकर परिणाम हमारी अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि, ताजा सर्वे में देश के अधिकांश राज्यों में लड़का-लड़की के अनुपात में भारी विषमता आयी है। जोकि सामाजिक दृष्टिकोण से भी चिंतनीय है। इस अभिभाषण में बालिका को बचाने एवं उनके शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है। पिछली सरकार में प्रशासन व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। जिसके कारण आतंकवाद, उग्रवाद एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को फैलने का मौका मिला। इस पर भी सरकार की नीति का राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है तथा सरकारी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने की बात की है। आज न्यायपालिका की जो स्थिति है, उसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। मैं विनम्रता के साथ सरकार से मांग करती हूं कि गुजरात की तर्ज पर देश के अन्य राज्यों में थी "नाईट कोर्ट" को सुचारू किया जाए तथा पुराने कानूनों एवं कोर्ट की प्रक्रिया की भी समीक्षा करायी जाये, जिससे कोर्ट में वर्षों से लंबित मुकदमों का शीघ्रताशीघ्र निष्पादन हो सके। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने सोशल मीडिया, आर्थिक नीति, कृषि-रेल नेटवर्क, हाई स्पीड ट्रेनों, जलमार्गों, विश्वस्तरीय 100 शहरों के निर्माण, स्वच्छ ईंधन, पर्यटन, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि विषयों पर सरकार की आगामी नीतियों का उल्लेख किया है, जो कि अपने आप में संतुलित है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की आगामी नीतियों द्वारा देश की प्रत्येक जनता के विकास पर ध्यान दिया है। इस अभिभाषण से देश का हर वर्ग आशान्वित है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री बी. श्रीरामुलु (बेल्लारी) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में यथानिर्दिष्ट नई सरकार के इरादों और दूरदर्शी कार्यक्रमों पर कतिपय टिप्पणियां करना चाहूंगा।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपनी चुनावी रैलियों के दौरान देश के लोगों के साथ किए वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता है।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि श्री नरेन्द्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए हर प्रयास करेंगे। उन्होंने लोगों में विश्वास जगाया है। उन्होंने सदा लोगों को प्रोत्साहित किया कि भविष्य में अच्छे दिन आएंगे।

नई सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई सकारात्मक निर्णय लेकर अच्छी शुरुआत की है। मैं कहूंगा कि यह ऐसा है जैसे "प्रथम प्रभाव, सबसे अच्छा प्रभाव।" नई सरकार ने देश के लोगों का दिल जीता है।

श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कार्य करने के अपने तरीके से युवा और अनुभवी दोनों प्रकार के संसद सदस्यों, जो देश के विभिन्न भागों से इस महान सदन में चुनकर आए हैं, को प्रभावित किया है।

नई सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की हैं इस देश के सभी आम लोग श्री नरेन्द्र मोदी जी की सकारात्मक भावना को समझ सकते हैं। शासन का अर्थ दिल्ली में बैठ कर आदेश जारी करना नहीं होता है। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शपथग्रहण के साथ ही सरकार के प्रत्येक पहलू में सुधार लाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया ताकि अगले पांच वर्षों के दौरान देश का चहुंमुंखी विकास सुनिश्चित हो।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जाति और पंथ निरपेक्ष समाज के सभी वर्गों के लोगों को शामिल कर समावेशी शासन के संबंध में नई सरकार की दृष्टि को उद्धृत किया गया है।

नई सरकार ने अपने पहली ही कैबिनेट की बैठक में देश से जुड़े मामलों से निपटने के तरीकों का प्रदर्शन किया।

विगत दस वर्षों में देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गयी है। मुद्रास्फीति नई ऊंचाई छू रही थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में अब तक की सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। इस देश के लोग बड़ी दुर्दशा में थे।

अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने का कर्त्तव्य हम में से प्रत्येक व्यक्ति का है। संसाधनों को जुटाने और इनके संवितरण में सरकार द्वारा उठाये गए कदम बड़े आशाजनक हैं। सरकार मूलभूत अवसंरचना, रेल नेटवर्क और कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर इनमें सुधार करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस कदम से औद्योगिक विकास होगा और हमारे युवाओं हेतु रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे।

देश के कतिपय शहरों का ही उच्च शिक्षा में वर्चस्व है। तथापि, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सभी राज्यों में आईआईटी और आईआईएम स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। इससे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्ष्ज्ञा देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचेगी। इसलिए यह सरकार का एक स्वागतयोग्य कदम है। मैं तो कहूंगा कि निकट भविष्य में अमेरिका और आस्ट्रेलिया के छात्र उच्च शिक्षा के लिए भारतीय वीजा लेना चाहेंगे। नई सरकार से पांच 'टी'-सूत्र से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठा रहीन है। ये पांच 'टी' है परम्परा (ट्रेडिशन), प्रतिभा (टैलेंट), पर्यटन (टूरिज्म) व्यापार (ट्रेड) और पर्यटन (टूरिज्म) श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यक्षेत्र के मुख्य केन्द्रबिन्दु हैं।

मैं नई सरकार के स्वच्छ गंगा नदी प्रस्ताव का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सबके लिए यह एक उदाहरण पेश किया है कि लोग आगे आकर अपने पर्यावरण की रक्षा करें। सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि देश के प्रत्येक गांव को सुलभ शौचालय, लगातार बिजली, स्वच्छ पेयजल, प्रदूषणरहित शहर और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों। सरकार के इस प्रस्ताव ने लोगों को आशावादी बना दिया है।

सरकार ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। इस पहल ने लोगों को खुश कर दिया है।

माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण हम सबके लिए मार्गदर्शी सिद्धांत है। इसमें उन कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है जिन्हें अगामी पांच वर्षों के दौरान हमें करने की आवश्यकता है। तीस वर्षों के पश्चात् केन्द्र में एक दलीय पूर्ण बहुमत वाली सरकार आयी है। इस महान सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेना मेरे लिए सम्मान की बात है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का नारा हमारी देशभक्ति का प्रतीक है।

मैं लोक सभा में बेल्लारी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या है। सिरागुप्पा, हगारी, बेम्मनहल्ली, लुडलिगी और अन्य क्षेत्रों में पेयजल में फ्लोराइट की मात्रा है। सड़कें खस्ताहाल हैं। मेरा जिला सूखा-प्रभावित है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि इन समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सहायता प्रदान करें। पीडीएस हेतु नई नीति लाने, लोकपाल अधिनियम को

*सभा पटल पर मूलत: कन्नड़ में रखे गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

9069043498 (SAKEEL)
9899643546

कार्यान्वित करने, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण जैसे अन्य कुछ कदम सचमुच स्वागत योग्य हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह नई सरकार देश के चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कराडी धाम एक पर्यटन स्थल है जो संदूर तालुक में दारोजी में स्थित है। मैं अनुरोध करता हूं कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाएं। दारोजी में रेलवे स्टेशन को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इस स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार इस देश के 100 शहरों को विकसित करके उनहें विश्वस्तरीय शहरों के रूप में उन्नत करेगी। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और यह भी अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना में मेरे बेल्लारी जिले को भी शामिल करें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सभी राज्यों में आईआईटी की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बेल्लारी जिले के लिए भी एक आईआईटी संस्वीकृत करें क्योंकि यहां भूमि, सड़क संपर्क, जल, बिजली आदि सहित सभी सुविधाएं हैं और यह एक पिछड़ा जिला है। इसलिए मेरे जिले में एक आईआईटी की स्थापना की जाए।

मैं एक बार पुन: भारत के महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अंतर्गत अपने विचार रखने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

***श्री विष्णु पद राय** (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में मैं निम्न बिन्दुओं को शामिल करना चाहता हूं:–

1. पर्यटन–572 द्वीपों को लेकर अंडमान निकोबार द्वीपसमूह बना है, जो थाईलैंड, सिंगापुर, वर्मा तथा इंडोनेशिया से काफी नज़दीक है। सिंगापुर की तरह यह द्वीपसमूह भी वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, लेकिन पिछले 65 वर्षों में इस दिशा में कोई संतोषजनक कम नहीं हुआ।

2. माननीय राम नायक जी पेट्रोलियम मंत्री, एनडीए सरकार के समय अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ऑयल एण्ड गैस की खुदाई के लिए नैल्प का आवार्ड हुआ था। उसके पश्चात् यूपीए वर्ण ने नैल्प का अवार्ड किया था। कुल मिलाकर 11 ब्लॉक, कुल एरिया 88 हजार रक्वायर किलो मीटर गैस और तेल के भंडार को उत्खनन का आवार्ड हुआ था, लेकिन यूपीए सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया।

3. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत का एक तिहाई इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, जहां समुद की मछली तथा समुद्र की संपदा का दोहन करने से भारत की आर्थिक मजबूती में सहायता मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोज़गार भी पैदा होंगे। आज इस संपदा को पड़ोसी देश लूटकर ले जा रहे हैं।

4. द्वीपसमूह में ब्रॉडबैंड बुरी हालत में है। ऑप्टिकल फाइबर केबिल सरकारर फाइलों में ही घूम रहा है।

5. एनडीए सरकार के समय पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का वीर सावरकर के नाम से नामकरण हुआ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा हुई, लेकिन 10 साल बीत गए और इस पर कोई काम नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि इसे जल्द-से-जल्द शुरू करवाया जाए।

6. एनडीए सरकार के समय में पोर्ट ब्लेयर के चिड़ियाटापू से डिगलीपुर तक 333 किलो मीटर नेशनल हाईवे की घोषणा हुई, लेकिन इन दस वर्षों में एक किलो मीटर रास्ता भी नहीं बना।

7. किसानों की जो जमीन 2004 के सुनामी में डूब गई थी, इसके लिए यूपीए सरकार के गृह मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की थी कि किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी और नुकसान की भरपाई करेंगे, लेकिन यूपीए सरकार ने किसानों की जमीन सरेंडर कराकर 9 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा देकर जमीन हड़प ली।

8. तत्कालीन रेल मंत्री, ममता बनर्जी ने पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक रेल लाइन का काम शुरू करने को आश्वासन दिया था, लेकिन यूपीए सरकार की ओर से इस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया।

9. सुनामी में भारत के अंतिम भाग कैम्पबेल-बे में जो इंडोनेशिया के बगल में (130 कि.मी.) है, लैंड रिक्लैम करने के लिए सनपब गेट, अर्दन बांध नहीं बनाया गया, जबकि इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए और लूट गयी। इस पर सीबीआई इन्क्वायरी जरूरी है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

10. वाइपर द्वीप (1857 के क्रांतिकारियों के चैन गैंग जेल) यूपीए सरकार के कैसिनों, याच मरीना बनाने के नाम पर द्वीप को बेच दिया था। जो बाद में कैंसल हुआ और उस पर सांसद के नाते मैंने गृह मंत्री शिंदे के खिलाफ प्रीविलेज मोशन मूव किया था, उस पर कार्यवाही हो और भारत सरकार लंदन लाइब्रेरी लाइब्रेरी में जाकर वाइपर द्वीप के जेल का फोटोग्राफ, ड्राइंग, रिकॉर्ड्स मंगाकर दोबार वाइपर द्वीप की रिप्लिका जेल का निर्माण करें। कालापानी के नाम से जाने वाली द्वीपों की पहली जेल वाइपर द्वीप में बनायी गयी और क्रांतिकारियों को कैदियों के रूप में लाकर उन पर अत्याचार किया गया। इसके 46 साल बादल सेल्युलर जेल का निर्माण हुआ।

11. अंडमान द्वीपसमूह के अर्बन सिटी पोर्ट ब्लेयर को एपीएल बना दिया गया है, जहां गरीबों की भरमार है। ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रतिशत बीपीएल बनाया गया, जो सरासर झूठ है। मांग है कि बीपीएल सर्वे दोबारा किया जाए।

12. स्पोर्ट्स में हमारे द्वीपसमूह के बच्चे काफी होनहार है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त अवसर दिया जाए, खासकर वाटर स्पोर्ट्स में।

13. यूपीए सरकार के समय में कोपरा खरीदने का समर्थन मूल्य 44/51 रुपया था, लेकिन एलेंसी ने खरीदा 20/22 रुपये में। इस तरह से रुपये की लूट मची। मांग है कि इस पूरे घोटाले की जांच के लिए सीबीआई इन्क्वायरी हो।

14. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक कॉ-ओपरेटिव बैंक है, इसके हालत बहुत खराब है, क्योंकि इस बैंक का रुपया गैर-कानूनी तरीके से रिज़र्व बैंक के नियम को तोड़कर लोन के रूप में दिया गया, डीआरएम की भर्ती की गई, लोन माफ किया गया और यह सब आज भी चल रहा है, क्योंकि इस कॉ-ओपरेटिव बैंक के चैयरमेन-कम-डायरेक्टर कांग्रेस पार्टी के हैं। प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है। मांग है कि इस गलत काम के ऊपर तुरंत इन्क्वायरी बैठाएं और बैंक बचाएं।

15. 50 साल बाद आज भी सिंचाई के लिए एक बीघा जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

16. 2004 की सुनामी के बाद जिला परिषद् ने ओवर हैड वाटर टैंक, पाइपलाइन आरओ प्लांट, अर्दन बांध, स्लूइस गेट के नाम पर करोड़ों रुपयों का गबन किया गया, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो।

17. अंतर्द्वीपीय जलयान सेवा को सुदृढ़ किया जाए।

18. द्वीपों में हवाई यात्रा भाड़ा पूरे देश में सबसे अधिक है। द्वीपसमूह के लोगों के लिए रियायत दी जाए।

19. मेडिक्लेम पॉलिसी तुरंत लागू की जाए।

20. बंबफ्लाट और चाथम के बीच ब्रिज बनाया जाए।

21. बंबफ्लाट-चाथम, मिडिल स्टेट-ओरलकच्छा, जेट्टी के बीच चलने वाले विहिकल फेरी सेवा को मजबूत बनाया जाए।

22. अंडमान मरीन ड्राइवर फाइल में दम तोड़ रही है। इस पर कार्यवाही हो।

23. पीएमजीएसवाई में पिछले 10 सालों में न के बराबर काम हुआ।

24. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वीपों के विकास के लिए, आईडीए के चैयरमेन हैं, इसलिए सभी द्वीपवासियों को उम्मीद है कि अब द्वीपों का विकास होगा।

कुछ बिन्दुओं पर मैं आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं— जैसे एनआईटी, मैरी टाइम इंस्टीट्यूट, स्मार्ट सिटी, पर्यटन ब्रॉडबैंड, नेशनल हाईवे आदि तथा राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जिसका जिक्र हुआ, उस पर जल्द-से-जल्द काम शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री धरम वीरा गांधी (पटियाला) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। चूंकि यह मेरा पहला भाषण है और मैं पहली बार संसद सदस्य चुना गया हूं इसलिए मैं अपने साथी सदस्य से आशा करता हूं कि वे मुझे धैर्य पूर्वक सुनें।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बजट संक्षेप में रखें। भले ही आप पहली बार संसद सदस्य बने हैं, आप के लिए पांच मिनट का समय नियत है। संक्षेप में बोलने का प्रयास करें।

श्री धरम वीरा गांधी : मैं मानता हूं कि सरकार के कार्यनिष्पादन का निर्धारण आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक और समेकित आयोजना तथा विभिन्न, योजनाओं, नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन होगा। आज कृपया मुझे देश के लोगों के हितों और कल्याण से जुड़े अतिआवश्यक मुद्दे पर प्रकाश डालने दे। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सप्ताह से जून महीने की गर्मी में दिल्ली के लोगों को बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि दिल्ली का शासन अभी केन्द्र और उप-राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है यह केन्द्र, उप-राज्यपाल और दिल्ली

प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इस सस्या का समाधान करें तथा दिल्ली के लोगों को राहत दें ताकि उन्हें इस समस्या से अतिशीघ्र निजात मिल सके। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली के उप-राज्यपाल एवं केन्द्र सरकार डिस्कॉम पर कार्रवाई करे तथा दिल्ली प्रशासन के साथ किए गए समझौते को लागू करने पर दबाव डाले एवं दिल्ली के नागरिकों को समुचित और तत्काल विद्युत आपूर्ति बहाल करे। यह मेरा पहला मुद्दा है।

दूसरी बात यह है कि प्रेस की रिपोर्टों तथा इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी से यह आशंका व्याप्त होती है कि सरकार 1 जुलाई, 2014 से गैस के कीमत को 4.2 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से बढ़ाकर 8.4 प्रति डॉलर एमएमवीटीयू करने की योजना बना रही है। हमारा दृढ़ मत है कि यदि इस निर्णय का क्रियान्वयन किया जाता है तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा तथा अधिसंख्यक भारतीय लोगों का जीवन ज्यादा कठिन और दुष्कर हो जाएगा।

मैं इस सम्मानित सभा के सभी माननीय सदस्यों को आगाह करना चाहता हूं कि यदि इस कॉर्पोरेट हितैषी और जनविरोधी निर्णय को लागू किया जाता है तो उर्वरकों, परिवहन और गैस आधारित बिजली की कीमतों में वृद्धि के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम पड़ेगा।

यहां यह उल्लेख करना प्रसांगिक है कि भाजपा के सभी नेताओं ने पूरे प्रचार अभियान के दौरान विशेष रूप से वर्तमान माननीय कानून मंत्री श्री रवि शंकर प्रसादख राज्य सभा में भाजपा के तत्कालीन उप-नेता ने 25 मार्च को इसका जोरदार विरोध किया था तथा सत्ताधारी संप्रग सरकार से गैस मूल्य नीति की समीक्षा किए जाने की मांग की चूंकि भाजपा और एनडीए अब सत्ता में हैं, इसलिए देश के लोग उनसे आशा करते हैं कि वे अपने वादों को पूरा करें तथा उनके हित में कार्य करें न कि किसी कॉर्पोरेट घराने के हित में।

अत: हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले वह सीएजी की रिपोर्ट को ध्यान में रखें जिसमें रिलायंस को सरकार के साथ अपने समझौते का कई बार उल्लंघन करते पाया गया है तथा इसमें इसके पूंजीगत व्यय का बीजक बनाना, अपने भंडार बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना तथा गैस का उत्पादन कम करना आदि शामिल है।

इसके अलावा सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए ओएनजीसी द्वारा दिल्ली उच्च न्याालय में रिलायंस के खिलाफ इसके 30,000 करोड़ रुपए का गैस चोरी करने के लिए एक मामला दर्ज किया गया है जिसमें यूपीए सरकार को भी वादी बनाया गया है तथा सभी ठेकों को निरस्त करने तथा उक्त कंपनी से तेल क्षेत्र वापस लेने की मांग की गई है।

यह रिकॉर्ड में है कि हामरी पार्टी तथा भारत निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप से यूपीए-दो ने गैस वृद्धि के निर्णय को आस्थगित कर दिया था तथा अब जबकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह देश तथा जनता के हित में गैस के मूल्य में वृद्धि न करे।

मैं अपने राज्य पंजाब, जहां से मैं इस सम्मानित सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, कि और सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि हमारे राज्य में युवाओं में नशाखोरी भयावह स्थिति तक पहुंच गई जहां 70 प्रतिशत युवा नशाखोरी की गिरफ्त में है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर लगातार दोष मढ़ रही है कि वह भारत-पाक सीमा की समुचित सीलिंग नहीं कर रही है। जब केन्द्र में एनडीए है और राज्य सरकार भी एनडीए की है तब मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भारत-पाक सीमा को सिद्ध करने के लिए प्रभावी और तत्काल कदम उठाए ताकि सीमा पार करने की कोई जगह न बचे एवं राज्य सरकार का यह बहाना आगे न चले।

हाल में हुए लोक सभा चुनाव के पश्चात् सरकार ने जो पंजाब में नशाखोरी के खतरे की चपेट में उठाए निर्दोष युवाओं को पकड़ा तथा नशामुक्ति अभियान के बहाने पंजाब के गांवों, शहरों तथा कस्बों से 20,000 से अधिक युवाओं को गिरफ्तार किया। यह समस्या के निपटने का तरीका नहीं है। चूंकि यह हताशाइर्न कदम चुनावों के होने के बाद उठाया जा रहा था इसलिए मुझे इस समस्या को समझने और निपटने के प्रति सरकार की ईमानदारी और गंभीरता के बारे में संदेह है। मेरे विचार में सरकार अभी भी चुनाव में लाभ या हानि जैसी संकीर्ण मानसिकता को ध्यान में रखकर इस समस्या का समाधान कर रही है जोकि सही दृष्टिकोण नहीं है। सरकार का कदम सफल नहीं होने जा रहा है क्योंकि जब तक ऊपर से लेकर नीचे तक मादक द्रव्य का नेटवर्क खत्म नहीं किया जाता, और जब तक समुचित नशा विरोधी अभियान के पश्चात् युवाओं को उपयोगी रोजगार नहीं दिया जाता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

मेरे विचार में यह सर्वविदित है कि किस प्रकार हमारा पंजाब राज्य 1980 से 1990 के दशक में कुछ राजनीतिक ताकतों के षणयंत्र तथा कुचक्र का शिकार हुआ और जन धन दोनों की भारी हानि हुई। आतंकवाद और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई दोनों इन राजनीतिक ताकतों द्वारा पंजाब के लोगों पर थोपा गया। जिससे पंजाब और दिल्ली में हजारों लोगों की मृत्यु हुई और बहुत से प्रभावित हुए। हमारा पवित्र स्वर्ण मंदिर, जो पंजाब के लोगों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है, को गिरा दिया गया।

महोदय, इस अशांत वर्षों के दौरान हमारा राज्य पंजाब बहुत हास्त हो गया तथा यह केन्द्र को हर वर्ष बड़ी धनराशि की किस्तों की अदायगी

कर रहा है। अत: मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह पंजाब के ऋण के बट्टे खाते में डाल दे तथा पंजाब के लोगों को दण्डित करना बंद करें क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है।

हमारा दल उत्तर प्रदेश के बदायूं में तथा देश के अन्य भागों में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटना की पुरजोर निंदा करता है और महिलाओं के प्रति ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर, त्वरित और अनुकरणीय दंड देने की मांग करता है।

हमारा दल, पुणे में बहुसंख्यक समुदाय के कट्टरपंथी तत्वों के हाथों अल्पसंख्यक समुदाय ने एक आईटी पेशेवर की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा भी करता है और इस जघन्य कृत्य में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजिजु : माननीय सभापति जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजीव प्रताप रूडी जी जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आए हैं, उस पर मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरी पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने बहुत ही विस्तार से बहुत ही प्रभावी ढंग से बात रखी है।

मैं केवल दो-तीन बातें ही कहूंगा। आज जब हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को ध्यान में रखते हुए सदन में बोलते हैं तो मेरे मन में एक नयी उम्मीद और नयी आशा जगी है कि हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी जातियां और ऐसे धर्म के लोग हैं जो अपने आपको सरकार से बहुत दूर महसूस करते हैं। दिल्ली उनके लिए बहुत दूर लगती है। दिल्ली पहुंचना और सरकार के पास पहुंचना असंभव था। लेकिन इस अभिभाषण में हमें यह देखने को मिला कि एक नयी दिशा के साथ और सबको विश्वास में लेते हुए जो एक नारा दिया है "एक भारत और श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास" इस बुलंद नारे के साथ इस सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू करने का निर्णय किया है।

अपराह्न 1.00 बजे

ये उन क्षेत्रों और उन लोगों के लिए एक नए दिन की शुरुआत है। मैं भी ऐसे ही क्षेत्र से आता हूं। मैं सांसद भी रहा हूं और सांसद रहते हुए मुझे दिल्ली दूर लगती है। आज मैं सिर्फ गृह राज्य मंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि इस सदन का सदस्य होने के नाते बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि सदन के नेता माननीय नरेन्द्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का सदस्य होने का मुझे फक्र है।

महोदय, मैं दो-तीन बातें संक्षेप में कहूंगा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिन्दुस्तान के आदिवासी लोगों के लिए मंत्रालय था, विभाग था लेकिन बहुत ठोस कार्यक्रम नहीं था। इसके लिए वन बंधु कल्याण योजना तैयार करने का सरकार ने निर्णय किया है। मुझे लगता है कि ये लोग जो जल, जंगल और जमीन के नाम पर पीछे धकेले गए हैं, अब उनके लिए मुख्यधारा में आने की शुरुआत है। सरकार ने जहां प्वाइंट आउट किया है मैं उन क्रिटिकल एरियाज़ को उजागर करना चाहता हूं। इस देश के पहाड़ी, रेगिस्तानी क्षेत्रों और खास तौर से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के सदस्यों के मन में खुशी पहुंची होगी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले अपने भाषण में जो कहा था, सचमुच महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सामने लाया गया है। ईस्टर्न इंडिया को पूरे भारत के साथ मिलाकर बराबरी का दर्जा देने का निर्णय किया है। मुझे लगता है कि सामान्य रूप से हिन्दुस्तान एक साथ आगे बढ़ेगा।

मैं पूर्वोत्तर से आता हूं इसलिए मैं पूर्वोत्तर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हुआ है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ अंतरसंपर्कता। पूर्वोत्तर में आठ राज्य हैं, लेकिन आपस में कनेक्टिविटी का आज तक कोई ऐसा कार्यक्रम सरकार की ओर से नहीं चलाया गया है। चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हम इसमें एक मुहिम चलाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे पूर्वोत्तर के लोग महसूस करेंगे कि इस सरकार ने हमारे दु:ख और दर्द को पहले ही दिन से समझा है। पूर्वोत्तर के जितने सांसद यहां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब हम यह कभी महसूस नहीं करेंगे कि दिल्ली पूर्वोत्तर से दूर है। यह कभी आगे चलकर महसूस ही नहीं होगा।

महोदय, हिमालय क्षेत्र के लिए पर्यावरण बहुत सेंसटिव सब्जेक्ट है। क्लाइमेट चेंज हो या एन्वायर्नमेंट इश्यू हो, उसे जोड़ते हुए हिमालय क्षेत्र के लिए नेशनल मिशन ऑन हिमालयाज़ की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। 14वीं लोक सभा में हम लोगों ने फोरम भी बनाया था, ट्रांस हिमालयन पार्लियामेंटरी फोरम। इससे हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम भी दिया था कि हिमालय का प्रोटेक्शन सिर्फ हिमालयन रीजन का प्रोटेक्शन नहीं है, यह हिन्दुस्तान का ताज है। हिन्दुस्तान की नदियों में फ्रेश पानी का 80 परसेंट जल हिमालय से बहकर आता है। जब हिमालय का संरक्षण नहीं होगा तो हिन्दुस्तान स्वस्थ भारत नहीं हो सकता है। सिर्फ यह बॉर्डर एरिया की बात नहीं है, बॉर्डर एरिया के साथ हिमालय देश का ताज है, इसका बचाव करना, संरक्षण करना सब हिन्दुस्तानियों का दायित्व है। सरकार ने इस चीज को समझा है।

हिन्दुस्तान एक विशाल देश है। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान विश्व का नैचुरल लीडर है, यह विश्व का आध्यात्मिक गुरू है। प्राचीन काल

से आज तक का इतिहास देखें तो पता चलता है कि हिन्दुस्तान विश्व का नेतृत्व करता आया है लेकिन पिछले 200 साल में हम काफी पीछे रह गए हैं। आप जापान, चीन, मंगोलिया, थाईलैण्ड, वियतनाम में जाकर बताते हैं तो वे हिन्दुस्तान की तरफ आस्था और विश्वास के रूप में देखते हैं और बहुत ऊंचा स्थान देते हैं क्योंकि यह युद्ध भगवान का देश है। हमें ऐसा लगता है कि इसके पहले दस साल जो सरकार रही है, वह बुद्ध भगतवान को भूल गई। महापरिनिर्वाण का 2550 का जब वर्ष आया था, तब हमने हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री को गुजारिश की थी कि इसे एक ऐसे तरीके से मनाइये कि दुनिया में जो हमारी लीडरशिप है, वह झलकनी चाहिए। लेकिन जिसे हम एक टोकन कहते हैं, आपने एक ऐसा कार्यक्रम किया। मैं खुद कुशीनगर में था, वहां राष्ट्रपति जी आए थे और एक छोटा सा कार्यक्रम करके इतने बड़े समारोह को खत्म कर दिया। जबकि वह एक अच्छा मौका था। हिन्दुस्तान में टूरिज्म को लेकर जो बातें सामने आई हैं, श्री राजीव प्रताप यडी ने भी उनका जिक्र किया है कि हमारा इतना विशाल देश है, लेकिन हमारे यहां कितने कम टूरिस्ट्स आते हैं। उसमें जो रिलीजिएस टूरिज्म का मामला है, इस सरकार के सामने जो आया है, आपने देखा होगा कि 50 टूरिस्ट्स सर्किट और पिलग्रिमेज टूरिज्म डेस्टिनेशन की एक रूपरेखा जो सामने देखने को मिली है, इससे मुझे लगता है कि आज अगर हमारे देश में पांच या छह मिलियम के आसपास टूरिस्ट्स आते हैं तो पांच साल के बाद जब यह कार्यक्रम पूरा चालू होगा ते यह कम से कम तीन, चार गुना जम्प होगा। हिन्दुस्तान एक नेचुरल एट्रैक्शन है, इसमें लोग आना चाहते हैं। लेकिन हमें जो सुविधा, जो बेसिक फैसिलिटी देनी चाहिए, वह हम दे नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान का विश्व में जो ओरिजिनल स्थान है, वह मिलने जा रहा है।

महोदय, हमने सिक्युरिटी के बारे में बातें कही हैं, सिक्युरिटी के विस्तार में हमारे बाकी नेताओं ने भी जिक्र किया है। मैं सिर्फ इंडो-चाइना बार्डर के एरिया को लेकर कहना चाहता हूं कि जो हमारी विदेश नीति है या जो हमारी सरकार की नीति है, वह एक्सपेंशनिस्ट नहीं है। हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं। लेकिन जो अपना क्षेत्र है, अपनी टैरिटरी है, जो अपने देश का इलाका है, उसका विकास करने से किसने रोका था। भूतपूर्व सरकार की ओर से जितने भी वक्तव्य हमें देखने को मिलते हैं कि यह सैंसिटिव सब्जैक्ट है, इसलिए बार्डर का मामला जनता के बीच उजागर नहीं होना चाहिए। हम सब विपक्ष में थे तो हमने इस मुद्दे को भी उठाया था। वहां उस पार चाइना की साइड से जो इनट्रूजन होता है, उसे धीरे-धीरे सरकार ने माना है। हम इसे लड़ाई या एग्रैशन के रूप में नहीं देखते हैं। लेकिन जो हमारा इलाका है, वहां के बारे में भूतपूर्व सरकार की जो निगेटिव पॉलिसी थी कि आप बार्डर एरिया में मत जाइये और बार्डर एरिया में सिविलियन्स को आप आने-जाने से जो रोकते हैं, यह नीति बदलनी है। इसलिए स्ट्रैन्थनिंग ऑफ बार्डर का और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जिक्र हुआ है, वहां बिल्कुल बार्डर एरिया में जो आम जनता रहती है, उसके लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पीने का पानी, बिजली, सड़क और आजकल सभी को मोबाइल फोन चाहिए, खाने-पीने का सामान भी चाहिए, मैं बताना चाहता हूं कि बर्फीले इलाके में खेती-बाड़ी नहीं होती है। वहां पर राशन पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि वहां जो याक जो अपना शिप है, उस जानवर के माध्यम से वहां के लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दि बार्डर एरिया की जो बात करते हैं तो यह सामूहिक रूप से सबको समझना होगा कि आज हम यह मानते हैं कि चाइना के साथ हमारा बार्डर डीलिनिएशन नहीं हुआ। लेकिन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चाइना के साथ एग्रीमैंट किया था, उसमें यह पाइंट है कि जब हम तय करेंगे कि हमारा बार्डर कहां हैं तो उस समय दोनों जगह में जो रहने वाले इनहैबिटेन्ट्स हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा। आज भी हम लोग इस चीज को मानकर चल रहे हैं। इसलिए हम दोस्ती के साथ-साथ यह चाहते हैं कि जब हम एक पड़ोसी के साथ अच्छे संबंधी रखते हैं तो वह संबंध बराबरी का होना चाहिए। हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रैन्थ से बात करनी चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी सरकार ने शुरुआत में जो कदम उठाया है, यह बहुत अच्छा काम उठाया है। हिन्दुस्तान के भविष्य के लिए यह बहुत अच्छी बात है।

सभापति महोदय, मैं लम्बी बात कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो इतना नम्बर्स आया है, अपोजीशन पार्टी ने कहा है कि आप एरोगेन्ट हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल एरोगेन्ट नहीं हैं। 2004 में मुझे याद है जब हम लोग उस पार बैठते थे और जब यहां कांग्रेस की सरकार आई थी तो वह हम लोगों के बारे में क्या कहते थे। यहां तक कि एक सीनियर मिनिस्टर ने यह कहा, वह आज सदन में नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उसने यह कहा था कि तुम रिजैक्टिड लोग हो, हम तुम्हें कुछ-कुछ सरकारी कार्यक्रमों में न्यौता भी नहीं देंगे। इस तरह की बातें हमें सुनने की मिली थीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन कहा कि सब को साथ ले कर चलेंगे। देश को चलाने के लिए हम दलगत राजनीति नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कितने बड़े दिल के साथ अपना कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जी ने ब्रांड इंडिया की जो बात कही है, जिसमें हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग जब एक साथ हिन्दुस्तान के नाम पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो विश्व में हमारा खोया हुआ अस्तित्व, हमारी खोई हुई ज़मीन हमें इज्ज़त के साथ वापिस मिलेगी क्योंकि भारत विश्व का स्वाभाविक गुरु है।

सभापति जी, इस बात को कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

[अनुवाद]

***श्री रमेन डेका** (मंगलदाई) **:** मैं माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत करता हूं जो नई सरकार की नीति को परिलक्षित करता है।

यह नीति आम आदमी के प्रति सरकार की चिंता को प्रदर्शित करती है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई रोकने की प्रतिबद्धता आम जनता को राहत देगी। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे अस्पतालों को प्रत्येक राज्य में स्थापित करके उठाए जाने वाले कदमों से पिछड़े राज्यों को, विशेषत: उत्तरपूर्वी क्षेत्र को मदद मिलेगी।

नई सरकार ने पारिस्थितिकी को बिना नुकसान पहुंचाए संवहनीय विकास पर जोर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में सरकार सशक्तीकरण, क्षमता और कुशलता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता कार्य संस्कृति को परिवर्तित करने और इसे डिजिटल इंडिया में रूपांतरित करने की है। 100 विश्व स्तरीय शहर बनाना, पानी, शौचालय, 24 घंटे बिजली और 2020 तक प्रत्येक परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो देय की जनता के प्रत्येक वर्ष को कवर करेगी।

सरकार की नीति अर्थव्यवस्था को पुनरूज्जीवित करने के लिए अवसंरचना हेतु बड़ी पहल को दर्शाती है। सभी तरह की मदद मुहैया कराते हुए निवेश बढ़ाने से रोजगार सृजित होंगे जो समय की मांग है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, जिस पर उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जोर दिया था।

इस नीति में अवसंरचना, शहरीकरण, परिवहन, पर्यावरण और ऊर्जा, देश के विकास को पुनरुज्जीवित करने के लिए रोजगार पर जोर दिया था, जो यूपीए-I और II के शासन काल के दौरान काफी नीचे गिर गया था।

उच्च गति वाली रेलगाड़ी और कम लागत वाला हवाई अड्डा संचार प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत करेगा।

अल्पसंख्यकों को आधुनिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है।

मुझे यह जानकर खुशी है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नई सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर घुसपैठ की समस्या से निपटने का वादा किया है और सरकार ने इस बात पर और जोर दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तारबंदी का कार्य यथाशीघ्र समय पर पूर्ण कर लिया जाएगा। इस समस्या को उत्तरवर्ती कांग्रेस सरकारों द्वारा नजरंदाज किया गया। उत्तरपूर्वी राज्यों विशेषकर असम में, घुसपैठ एक मुख्य समस्या है क्योंकि भेद्य सीमा के कारण गैर-कानूनी आप्रवासी दैनिक आधार पर आ रहे हैं और असम की जनसंख्यिकी में परिवर्तन हो रहा है। यह एक स्वागत योग्य कदम है कि यह समस्या श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली नई सरकार की प्राथमिकता सूची में है।

नई सरकार क्षेत्रों के अंदर संपर्क सुधारने पर विशेष जोर देने के लिए आश्वस्त करती है और सीमावर्ती अवसंरचना असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के नए आयाम की शुरुआत करेगा।

लोकपाल अधिनियम की संगतता के अनुकूल लोकपात नियम बनाने का वायदा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में मदद करेगा।

कई और चीजें "सबका साथ, सबका विकास" के सिद्धांत के अनुरूप इन वायदों में आएंगी। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, अनावश्यक खर्चों में कटौती करेगा।

जल सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथकिकता देने की प्रतिबद्धता ग्रामीण भारत की मदद करेगा।

युवा नेतृत्व वाला विकास कार्यक्रम लाखों युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगा और राष्ट्र के विकास हेतु उनकी योग्यता में सहयोग करेगा।

सरकार संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो एक स्वागत योग्य कदम है।

राष्ट्र भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक संगठित, सुदृढ़ और आधुनिक भारत "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" की उम्मीद कर रहा है।

[हिन्दी]

***श्री राजीव शंकरराव सातव** (हिंगोली) **:** मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सेंट्रल हॉल में मैं बड़ी आशा से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुन रहा था।

सबसे पहले महाराष्ट्र की बेटी इस सदन की अध्यक्षा बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं।

इस अभिभाषण के परिच्छेद 92 में ये कहा गया है कि "मेरी सरकार केवल युवा विकास की संकल्पना की बाए 'युवा संचालित' विकास व्यवस्था प्रदान करेगी।" जब आप युवा संचालित विकास की बात करते हैं तब शुरुआत आपके मंत्रीमंडल से होनी चाहिए। आपके मंत्रिमंडल में युवा चेहरे 50% होने चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस अभिभाषण में अधिकार की बात कही भी गयी है। यूपीए के सरकार ने सूचना के अधिकार शिक्षा का अधिकार, नरेगा, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, लेकिन इस अभिभाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सूचना का अधिकार आप खत्म तो नहीं करना चाहते?

2009 के राष्ट्रपति के अभिभाषण में सुषमा स्वराज जी महिला आरक्षण के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के लिए कहा था। मेरा सरकार से आग्रह होगा महिला आरक्षण की समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया था कि 'हम ऐसा तंत्र स्थापित करेंगे जो भ्रष्टाचार की गुंजाईश ही समाप्त कर देगा'।

लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी सूचना का अधिकार को ताकद देने की बात नहीं है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल, ग्रिवांसेज रिड्रेसल बिल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। आखिर मैं सरकार को लुभावनी वादों की जगह वादों को निभाने का आग्रह करता हूं।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : सभापति जी, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारी पार्टी एआईयूडीएफ के तीन सदस्य असम से आए हैं। सिराजुद्दीन अजमल, राधेश्याम बिसवास तथा में। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऊपर वाले ने उनको इस देश की सेवा करने का मौका दिया है। हमें उम्मीद है कि जैसे उन्होंने नारा लगाया है – "सबका साथ, सबका विकास" – उस पर सारे हिन्दुस्तानियों को, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का ख्याल नहीं होगा, बल्कि सारी इंसानियत का ख्याल होगा। उसमें माईनोरिटीज़ का खुसीसी तौर पर ख्याल होगा और मुसलमानों का ख्याल उसमें खास तौर पर रखा जाएगा।

मैं सुषमा जी से कई मर्तबा बहुत ही प्रभावित हुआ हूं। आप जब भी बोलती थीं, आपके बोलने का अंदाज़े बयां और है। मैं चाहूंगा कि जब भी आप बोलें तो इसी तरीके से बोलती रहें। बीच-बीच में शेरो-शायरी ज़रूर करें, इससे हमारा माहौल बहुत मीठा रहेगा। रूडी भाई ने कल जो बयान दिया, उसमें कई अच्छी-अच्छी चीज़ें थीं। ये कई कमेटियों में चेयरमैन रह चुके हैं। रामविलास पासवान जी इस वक्त सदन में उपस्थित नहीं है।

चेयरमैन साहब मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गए साल में हमने देखा कि पूरे साल में आधे साल भी हाउस ठीक से नहीं चला था। इस वक्त आप बड़े भाई हैं। हम तो छोटी-छोटी पार्टी के लोग हैं। न हम इधर हैं और न उधर हैं। कोई प्यार से उधर बुलाएगा तो उधर चले जाएंगे। अगर प्यार से आप बुलाएंगे हम इधर चले आएंगे। हमारा यह कहना है कि हाउस को चलने दिया जाए। बड़े भाई की तरह आपके दरख्त पर फल लग चुका है। आपका सर हमेशा झुका हुआ होना चाहिए। सामने वाले को मिठास से मौका देना चाहिए। हाउस का वक्त बर्बाद न किया जाए, नहीं तो लोग बड़ी हंसाई करते हैं। जो 315 नए सदस्य आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और उनकी तरफ से कहना चहता हूं कि हाउस को अच्छी तरह से चला कर हम एक मिसाल बनाएं कि हाउस इस तरीके से भी चल सकता है। लोगों ने हमको जिस काम के लिए यहां भेजा है, उसको पूरा करने की कोशिश करें।

चेयरमैन साहब, मैं बातें कम करते हुए असम के मसाइल के ऊपर आना चाहता हूं। असम के बारपेटा से मेरे भाई सिराजुद्दीन अजमल साहब आए हैं। उनके यहां फ्लड और इरोज़न का सबसे बड़ा मसला है। उनके यहां रोड़ कनैक्टिविटी का मसला है। उनके यहां इंडस्ट्रीज़ की कमी है। लोग बहुत ही बुरे हाल में हैं। हमारे राधेश्याम जी करीमगंज से चुन कर आए हैं। उनके यहां महासड़क का मसला है। रोड़ कनैक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो रही है। अभी असम सरकार ने मेगा ब्लॉक की बात की है। हमारे होम मिनिस्टर साहब अभी कह रहे थे कि पूरे नॉर्थ-ईस्ट को रोड़ कनैक्टिविटी दी जाए। वहां आने-जाने में बहुत मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि अपने नेतृत्व में आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। करीमगंज के मसाइल के ऊपर, उनकी महासड़क के ऊपर, रेलवे लाइन की कनैक्टिविटी के लिए, जैसे लोग कई-कई दिन तक अटके रहते हैं, वहां कोई मर भी जाता है तो उसकी लाश को हॉस्पीटल से ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है।

सभापति जी, हमारी बहन सुषमा स्वराज भी अभी कह रही थी कि गंगा मेरी मां का नाम और बाप का नाम हिमालय है। यह हमारा बहुत पुराना नारा है। हिमालय से जो पानी आता है, अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 80 प्रतिशत पीने का पानी या अच्छा पानी वहीं से आता है। इसी का एक लिंक हमारे असम की सबसे बड़ी समस्या है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रुलिंग पार्टी के हमारे मंत्रियों को और खासकर हमारी सुषमा बहन को वह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र हमारे लिए एक दैव बन चुका है। एक लाख 27 हजार हैक्टेयर से ज्यादा भूमि ब्रह्मपुत्र नदी ने 25-30 साल में बर्बाद कर दी है। 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे एक स्टेट में जहां इतनी बड़ी तबाही हुई हो और हर साल सैंकड़ों मील लोग इधर से उधर हो जाते हैं, आपको इसका बखूबी इल्म है। मैं चाहूंगा कि यह सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। इसके पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एयरपोर्ट पर ऐलान किया था कि हम इसको नेशनल कलैमिटी डिक्लेयर करेंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां इसकी डिमांड कर रही हैं। हमारी पार्टी की भी डिमांड है कि इसके ऊपर

आप जरा संजीदगी से ध्यान दें। मैं समझता हूं कि असम की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन यह ब्रह्मपुत्र नदी हो गयी है।

महोदय, मैं थोड़ा सा सदन का समय लेना चाहूंगा। मैं आपकी सरकार की भी तारीफ करूंगा। अच्छी-अच्छी बातें सामने आयी हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं और उसमें हम यह चाहते हैं कि गरीबों के भी अच्छे दिन आयेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है। दूसरी बात, अभी होम मिनिस्टर साहब यहां उपस्थित नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से सुषमा स्वराज जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, बीटीएडी का मसला वर्ष 1993 से है, जिस वक्त हमारे आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, उस वक्त यह एग्रीमेंट हुआ था। दुर्भाग्य की बात है कि उसके अन्दर सिर्फ बीटीएडी के लोगों को लेकर और असम सरकार को लेकर यह एग्रीमेंट कर लिया गया। जबकि वे सिर्फ 18 परसेंट हैं, 71 परसेंट नॉन बोडो उसके अन्दर रहते हैं। उनके हितों का ख्याल नहीं किया गया और इसी की वजह से वर्ष 1993 में फसाद हुआ, वर्ष 2002 में फसाद हुआ, वर्ष 2005 में फसाद हुआ, वर्ष 2007 में फसाद हुआ और अभी वर्ष 2012 में और वर्ष 2014 में अभी एक महीना पहले फसाद हुआ। मैं सरकारी पक्ष का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और अगर यह मसला हल होता है तो यह फसादों का सिलसिला बन्द होगा। अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब एक हफ्ता पहले असम जाकर आये हैं। हमारे वहां एडिशनल एसपी को गोली मार दी जाती है। एक गुलजार हसन को मार दिया जाता है, एक गोस्वामी को मार दिया जाता है। उनके पास हथियार नहीं है। इन लोगों के पास हथियार नहीं है और इनकी कोई सुरक्षा नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा?

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मदरसा एजुकेशन के बारे में आपने बात की। हम इसका बहुत ही स्वागत करते हैं। मदरसा एजुकेशन में 90 परसेंट मदरसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सरकारी मदरसे जो पूरे हिन्दुस्तान में हैं, मैं चाहूंगा कि उनको मॉडर्नाइज करें। उनकी 90 परसेंट समस्याओं का आज भी हल नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे। इसी तरीके से हमारे यहां डी-वोटर्स का मसला है। असम में घुसपैठ की बात आयी। घुसपैठ के मामले में हमारी पार्टी का यह क्लियर विजन है कि बांग्लादेश बॉर्डर को सील किया जाये। कल भी हमने प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया साहब के भाषण में सुना कि इसकी फेन्सिंग करेंगे, फेन्सिंग को प्लीज न किया जाये। करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान का बर्बाद हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है, फेन्सिंग भी चालू है और घुसपैठ भी चालू है। मैं इस हाउस की सिर्फ एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, मेरे पास एक डाटा है, एजीपी सरकार इसी घुसपैठ के नाम पर असम में दो बार पावर में आयी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है। यह राष्ट्रीय महत्व का इश्यू है। पहली बार वह तब सत्ता में आयी जिस वक्त आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे और उनकी छत्रछाया में बाकायदा यह मिनिस्ट्री बनी थी, एजीपी की। उन्होंने वर्ष 1985 से लेकर वर्ष 1990 तक पूरे पांच साल सरकार चलायी और सौ प्रतिशत मेजोरिटी से सरकार चलायी। उस वक्त उन्होंने सिर्फ 6,724 फॉरनर्स लोगों को आइडेन्टिफाई किया और 521 लोगों को पांच साल में डिपोट किया। दूसरी बार असम के लोगों ने उन्हें फिर मैन्डेट दिया।

महोदय, मैं इस बात को पूरा करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। दूसरी बार उनको वर्ष 1996 से वर्ष 2005 तक के लिए पांच साल का मौका मिला। इस पांच साल में उन्होंने सिर्फ 902 फॉरनर्स आइडेन्टिफाई किये और उसमें से सिर्फ 102 को डिपोट किया। हमारी पार्टी इसके डेड अगेंस्ट है कि एक भी फॉरनर्स असम एक्वायर होने के बाद, 25 मार्च, 1971 के बाद एक भी फॉरनर असम में ऐज ए बांग्लादेशी नहीं रहना चाहिए। उनको निकालना चाहिए, लेकिन यह कानून के अन्दर होना चाहिए, संविधान के अन्दर होना चाहिए और हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

***श्री रामसिंह राठवा** (छोटा उदयपुर) : मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मार्च, 2012 में टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी छपी थी जिसमें "कुनबे का आदमी" शीर्षक था। वैश्विक मीडिया में नरेन्द्र मोदी के बारे में कुछ कहा था जो इस प्रकार है, टाइम की दक्षिणा एशिया की ब्यूरो चीफ, ज्योति थोट्ठम के ब्लॉग में लिखा था, नरेन्द्र मोदी देश के सबसे प्रिय एवं तिरस्कृत नेता क्यों हैं? और बुकिंग्य एन्स्टीट्यूशन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विलियम एल्थोलिस ने उनके ब्लॉग पर भारत के सबसे प्रिय एवं सबसे शक्तिशाली नेता नरेन्द्र मोदी (16 मार्च, 2012)।

अत्यंत गौरव एवं आनंदपूर्वक गुजरात की सफलता की गाथा अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों द्वारा यह बात कही गयी थी। मेरा कहना यह है कि आज गुजरात भारत का विजन और ग्रोथ इंजिन बन गया है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का विजन है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में काम करके दुनिया को और देश को बताया है। मोदी जी आम जनता के विश्वासी एवं बुद्धिशाली नेता है और सपना साकार करने वाले नेता है इसीलिए हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो चुका है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में 282 की संख्या के साथ में सत्ता में आई है। हमारे प्रधानमंत्री जी कुशल प्रशासक, देश के लिए गर्व करने वाला राष्ट्रवादी, कामकाज के मामलों में तटस्थ, कुशल नीतिकार और तकनीकी मामलों में जोश से

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति ने देश की बागडोर संभाली है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है फिर भी "सबका साथ-सबका विकास" का नारा लेकर एनडीए की सरकार "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" बनाने आगे बढ़ रही है।

माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण में वनबंधु कल्याण योजना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह वनबंधु कल्याण योजना से हमारे गुजरात में आदिवासी विस्तार का बहुत विकास हुआ है, जिसमें 10 पॉइंट प्रोग्राम में रोज़गार, शिक्षा, आरोग्य, पीने का पानी, सिंचाई की सुविधा, रोड, बिजली और अन्य शहरी सुविधा प्रदान करने की योजना है।

भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। यही भावना को आगे ले जाना और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। यह पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुख शामिल हुए, जो आने वाले वर्षों में हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं।

भारत की जनता ने ऐसे अनेक नेताओं को देखा है जो घोटाले और हत्या के मामले से बरी हो गए हों, लेकिन उनमें से कोई भी मोदी की तरह नये अवतार में देखने को नहीं मिले। कांग्रेस की केंद्र की गठबंधन सरकार की हार ने यह संदेश दिया है कि ढीले-ढाले प्रधानमंत्री मनमोहन और लोगों की पहुंच से दूर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से देश की जनता ऊब चुकी थी। महंगाई, भ्रष्टाचार का पर्याय कांग्रेस बन जाने की वजह से कांग्रेस का सफाया हुआ है। ऐसे वक्त 2014 का चुनाव नई उम्मीदों के साथ एनडीए कि सरकार बनने के बाद चंद दिनों में मोदी सरकार की टीम ने जो कदम उठाया है, वह सराहनीय है। देश की जनता को अभी एहसास हुआ दिखाई देता है। आने वाले दिन अच्छे होंगे। हमें सरकार को समय देना चाहिए और पांच साल के बाद भारत को भ्रष्टाचार के दलदल और अकार्यक्षमता में से बाहर लाने के साथ-साथ देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाकर चीन के समकक्ष खड़ा करने में कामयाब हो सकें। हमारी नीति और नियत साफ है और देश आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरूवल्लुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं एआईए डीएमके की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आभार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। डॉ. पुरात्ची थलाईवा अम्मा जे. जयललिता जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का अत्यंत ही विस्तृत एवं समावेशी तरीके से स्वागत किया है।

विशेष रूप से संघीय भावना को पुर्नजीवित करने के लिए सरकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने का वादा प्रशंसा योग्य है जो कि गत वर्षों में कम हो गयी थी। मुझे विश्वास है कि ऐसे सहकारी संघवाद सामान्य रूप से राज्यों और मुख्य रूप से तमिलनाडु के विकास के एजेंडा को आगे ले जाने में अत्यंत सहायक होगा। राज्यों को स्वतंत्र रूप से मजबूत बनाने से भारत एक मजबूत संघ बनेगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से इस सरकार की बनाई गई नीतियों की प्राथमिकता अत्यंत अर्थपूर्ण और व्यापक तरीके से स्पष्ट हुई है। यह देखकर अच्छा लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण ने नागरिकों की आशाओं और उम्मीदों को पहचान दी है जिन्होंने इस सरकार को निर्णयात्मक आदेश से शक्ति प्रदान की है।

सरकार को आगे कई बड़े काम करने हैं। हर महीने खाने की वस्तुओं की कीमतें कढ़ती है। भारत के तेजी से विकास के साथ ही उच्च पोषण खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ रही है। उसी समय, केंद्रीय गोदामों में अनाज सड़ता है और बाजार तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाता। इसके बावजूद, भारत प्रतिवर्ष अनाजों का रिकॉर्डपूर्ण उत्पादन कर रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह वादा है कि सरकार बिचौलियों द्वारा अनाज की जमाखोरी पर सख्त होगी। हम आशा करते हैं कि बजट में खाद्य आपूर्ति सरल बनाने हेतु अवसंरचना में तेजी लाने के लिए राशि का आबंटन किया जाए या प्रोत्साहन दिए जाए।

प्रत्येक राज्य में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना का वादा एक स्वागत योग्य कदम है। तमिलनाडु में अब तक कोई एम्स जैसा संस्थान नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में एम्स जैसे संस्थान को प्राथमिकता दे और स्थापित करे।

सड़कों के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज पहल के बाद, नई बीजेपी सरकार मुख्य शहरों के बीच एक रेलवे हीरक चतुर्भुज पर विचार कर रही है। इससे मुख्य शहरों के बीच तीव्र-गति से संपर्क में तेजी आ सकती है। इससे वस्तुओं और सेवाओं के लिए शहरों के बीच संपर्क में तेजी आएगी और मुद्रा स्फीति नीचे लाने में सहायता मिलेगी। जहां तक रेल नटवर्क का संबंध है, तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया गया है। तमिलनाडु के अधिकतर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र रेल संपर्क विहीन है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में तमिलनाडु को नई रेलवे लाइनों और नई ट्रेनों का इसका यथा अंश मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति : श्री जयदेव गल्ला, मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात संक्षेप में कहें क्योंकि प्रधानमंत्री अपराह्न 4.00 बजे उत्तर देंगे। अनेक सदस्य छूट गए हैं जो बोलना चाहते हैं। मेरे पास उनके नामों की सूची है। इसलिए, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि संक्षेप में बोलें। कृपया अधिकतम पांच मिनट लें।

श्री जयदेव गल्ला (गुन्टूर) : धन्यवाद श्रीमान, यह मेरा पहला भाषण है। मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। तेलुगु देशम पार्टी और हमारे नेता श्री नारा चंद्रबाबू नायडू मारन, की ओर से, मैं राष्ट्रपति जी को उनके अत्यंत प्रेरणात्मक, प्रगतिशील, दूरदर्शी और अति महत्वपूर्ण अभिभाषण के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

महोदय, गुन्टूर जिले से, जहां से मैं आता हूं, और जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, वहां हाल ही के चुनाव में 84% मतदान हुआ। मेरा संसदीय क्षेत्र 50 प्रतिशत शहरी और 50 प्रतिशत ग्रामीण है। शहरी क्षेत्रों में, उनकी श्रेणी 65 से 70 प्रतिशत के बीच है जो कि गत चुनाव से 10 प्रतिशत से अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में, यह 85 प्रतिशत से अधिक है। लोगों ने विकास और संवृद्धि के लिए मतदान किया है, ताकि प्रभावी प्रशासन के द्वारा आधारभूत आवश्यकताओं में सुधार हो सके। वे सभी जल, विद्युत, सड़कें, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल निकासी, शिक्षा, कौशल और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुधार की आशा कर रहे हैं। प्रथम बार मत देने वालों युवाओं ने मुख्यतया रोजगार के लिए मत दिए हैं जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा और उर्ध्वगामी गतिशीलता आएगी। थीम "इकड़ा बाबू, अकड़ा मोदी" मतलब, यहां बाबू और वहां मोदी भरोसा है जिसके साथ उन्होंने मत दिया और वे, मुझे भरोसा है, कि अगले पांच वर्षों में निराश नहीं होंगे। अभिभाषण में "रूरबनाइशेसन" शब्द का प्रयोग किया गया। मुझे लागत है कि यह एक अति सराहनीय अवधारणा है जो पूर्व की कुछ आवधारणों को पुन: कह रही है।

जहां तक रोजगार की बात है, मैं एक बार कहना चाहूंगा कि क्योंकि चीन मॉडल अत्यंत विस्तृत पैमाने का है।, मुझे लगता है कि भारत के लिए एक नए मॉडल की आवश्यकता है और वह गैर-पलायनवादी नौकरियां उत्पन्न करे। मैं चीन गया था। मैंने वहां औद्योगिक परिस्थिति का अध्ययन किया, और कारखानों में सभी रिक्तियां भरने के लिए बड़ी संख्या में पलायन किए जाते हैं। लोग अपने घर और अपने गांव नहीं जाते। शायद वे वर्ष में एक या दो बार अपने घर जाते हैं। उन्होंने अपना परिवार पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि भारत में इस प्रकार का ढांचा सामाजिक ताने-बाने के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए, मैं आग्रह करूंगा कि जब हम औद्योगिक विकास पर नीतियां बनाते हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार गैस-प्रवासी नौकरियों का सृजन करें। हमने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखी है, जहां प्रोत्साहनों के कारण कारखाने स्थापित किए गए हैं, परंतु उन्हें श्रमिक नहीं मिल सके और उन्हें इन कारखानों के लिए दक्षिण भारत और पूर्व भारत से मजदूर लाने पड़े। हमारी औद्योगिक नीति में इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि जहां लोग हैं, वहां नौकरियों का सृजन किया जाए बजाए इसके कि जहां नौकरियां हैं, वहां लोगों को ले जाएं।

नि:संदेह नौकरियों का सृजन करने के लिए हमें विद्युत और श्रम की आवश्यकता होती है। अपनी अच्छी मंशाओं के बावजूद मनरेगा योजना ने वस्तुत: संगठित उद्योगों में श्रम बल को कम किया है। मेरे स्वयं के मामले में हमारे यहां तिरुपति में कारखाने हैं – जब हम 200 अभियंताओं की नौकरियों हेतु विज्ञापन देते हैं, तो हमें तत्काल साक्षात्मकारों के लिए 2000 आवेदन प्राप्त हुए, परन्तु जब हम कामगार की 2000 नौकरियों के लिए विज्ञापन देते हैं, तो हमें केवल 200 आवेदन प्राप्त होते हैं। यह मजदूरों की कमी का मामला नहीं है, बल्कि मजदूर काम करने के इच्छुक नहीं हैं। मनरेगा योजना के कारण, वे घर में रहकर धन पाना चाहता हैं। मेरा मानना हे कि मनरेगा योजना में कमी की समीक्षा करने की आवश्यकता है और नीतियां इस प्रकार बनाई जानी चाहिए ताकि न लेवल बेरोजगारी, बल्कि अल्प-बेरोजगारी का भी अध्ययन किया जाए। अभी भी कृषि कार्यबल में बेरोजगार हैं और जो मनरेगा जैसी योजनाओं के कारण संगठित कार्य बल में आने के इच्छुक नहीं है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भूमि अधिग्रहण है। यदि हम इस देश में भूमि प्रयोग देखते हैं, तो तीन प्रतिशत से कम भूमि का प्रयोग उद्योग के लिए किया जाता है। अधिकार क्षेत्रों, विशेषकर जहां प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और भूमि की कमी है में भूमि की कीमतें बढ़ रही हैं, आपको जहां विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कारखाने बनाने हैं भूमि की कीमतें अत्यधिक बढ़ रही हैं, औद्योगिक विकास के लिए भूमि की कीमत अवरोध नहीं होनी चाहिए और भूमि अधिग्रहण नीति और प्रोत्साहनों को नौकरी के सृजन से एक मैट्रिक्स के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

मैं विशेष आर्थिक जोनों के अतिरिक्त एक बात और प्रस्तावित करना चाहूंगा, हमें ग्रामीण आर्थिक जोन की अवधारणा पर विचार करना चाहिए जहां इन विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास सूचकांक पर आधारित प्रोत्साहन स्लाइडिंग स्केल पर होने चाहिए। मानव विकास सूचकांक जितना कम होगा, उन स्थानों पर कारखानों की स्थापना के लिए अधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। हमें उच्च तकनीकी नौकरियों के साथ-साथ निम्न तकनीकी नौकरियों की आवश्यकता है।

माननीय सभापति : हमें चर्चा को अपराह्न 4 बजे तक समाप्त करना है, अनेक वक्ता हैं, इसलिए कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जयदेव गल्ला : महोदय, मुझे कुछ मिनट दीजिए।

माननीय सभापति : कुछ मिनट नहीं, आप एक मिनट ले सकते हैं और अपने भाषण को समाप्त करें।

श्री जयदेव गल्ला : महोदय, हमें भारत में उच्च तकनीकी और निम्न तकनीकी नौकरियों दोनों की आवश्यकता है। हमें केवल अभियांत्रिक अध्ययन करने वाले और एमबीए योग्यता वालों के लिए नौकरियों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो लोग 10वीं पास और 10वीं फेल हैं उनके लिए भी नौकरियां होनी चाहिए क्योंकि वे हमारे बेरोजगार युवाओं का बड़ा हिस्सा हैं।

विश्वस्तरीय विनिर्माण केन्द्र बनाने के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है, ब्राण्ड निर्माण महत्वपूर्ण है, प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है; और अनुसंधान एवं विकास महत्वपूर्ण हैं, इस सभी के लिए स्थिति की आवश्यकता है, जो उद्योग, रक्षा, विश्वविद्यालयों और सीएसआईआर संस्थानों के बीच हमारी क्षमताओं को संयोजित करेगा।

महोदय, आज हमारे सामने ऐसी स्थिति है, जहां बहुत शीघ्र इलेक्ट्रॉनिक आयात तेल आयात से अधिक होने जा रहे हैं। यह हमारे देश के लिए काफी विकट स्थिति है। मेरा मानना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए एफएबी विनिर्माण इकाई अहम है। हमारे देश में आज एक भी सिलिकॉन माइक्रो चिप विनिर्माण इकाई नहीं है। यदि हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना है तो हमें संघटकों में ग्लोबल-स्केल की आवश्यकता है।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि 100 नए स्मार्ट शहर बनाए जायेंगे, और मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहला शहर आंध्र प्रदेश की राजधानी होना चाहिए। इन स्मार्ट शहरों को देखते हुए, हमें मानव-स्केल; लोक परिवहन; पार्किंग; और सबसे महत्वपूर्ण – जिसकी अधिकतर शब्दों में अनदेखी की गई है – वह पैदल यात्री और साइकिल चलाने वालों के अनुकूल शहरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज, किसी भी मुख्य शहर में सड़क को पार करना एक उरावना अनुभव है। हमारे यहां उपयुक्त फुटपाथ नहीं हैं, परन्तु हम उन लोगों की आवश्यकता को भूल रहे हैं, जो पैदल चलते हैं, और मेरा मानना है कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं, केवल एक और उल्लेख करना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में केवल एक कथन था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया इन दो राज्यों को कृपया न जोड़े; अब, हम दो भिन्न राज्य हैं, जिनकी भिन्न आवश्यकताएं हैं; अलग ताकतें हैं; और भिन्न कमजोरियां हैं। आज आंध्र प्रदेश का घाटे का बजट है। हमारे पास अधिकतम राजस्व नहीं है क्यों परिसंपत्तियां हैदराबाद में रह गई हैं, हमारे ऊपर अधिक ऋण है। हमारे यहां विद्युत उत्पाद अधिक है, परन्तु हम खपत-आधार पर तेलंगाना को अधिक विद्युत हिस्सा देने के लिए बाध्य हैं, और पानी की स्थिति का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, यदि दोनों राज्यों को आगे बढ़ना है तो इन मुद्दों पर स्पष्टता की अत्यधिक आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति : अगले वक्ता श्री अरविंद सावंत हैं, परन्तु कृपया अपना भाषण संक्षिप्त रखें।

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) **:** सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो अभिनंदन प्रस्ताव हमारे सहयोगी सदस्य सम्माननीय राजीव प्रताप रूडी जी ने रखा था, उसका समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। आप ने मुझे अवसर दिया, इसलिए पहले मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पहला ही एक वाक्य था कि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिनकी वजह से यहां आए हैं। मैं शुरू में यह कहता हूं कि हम यहां वंदनीय शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद, हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब की प्रेरणा और जिस शख्स ने इस देश में लहर पैदा की, वह हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की वजह से यहां आए हैं और पहले ही मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं। खासकर, मतदाताओं के प्रति भी कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूं।

मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात यह लगी कि उस भाषण में, आप ने अगर गौर से देखा होगा, तो राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र दिवस पर इस देश को संबोधित करते वक्त 26 जनवरी को जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि वर्ष 2014 विगत वर्षों की विभाजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला होगा। आज यहां मैं अपने साथी नागरिकों के विवेक की सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसे उदीयमान, भारत में स्थिरता, ईमानदारी और विकास के लिए मत दिया जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। मुझे बहुत, गर्व होता है कि गणतंत्र दिवस पर उन्होंने देखा था कि देश का भविष्य क्या होगा। टकराव की राजनीति, विभाजनकारी राजनीति, जो यहां देश में चलती है, उसको वर्ष 2014 में पराजित किया जाएगा और नरेन्द्र मोदी जैसे शख्स को इस देश में लाया जाएगा। उस उक्त राष्ट्रपति जी ने भविष्य देखा। वह भविष्य साकार होते हुए हम यहां देख रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य का भाषण में गौर से

सुन रहा था। उनका नाम मुझे याद नहीं है। वे नए सदस्य हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं:–

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है,
पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है।

हमारे नरेन्द्र मोदी साहब के हौसले बुलंद थे, इसलिए हम यहां आए हैं, हमने जीत पाई है। यह आशाओं का चुनाव था। हमारी आशाएं, आकांक्षाएं सारी पल्लवित हुईं और विश्वास भी दृढ़ हो गया।

महोदय, मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र से जीत कर आया हूं, दक्षिण मुम्बई, जो झुग्गी-झोपड़ियों का है, जो पुरानी इमारतों का है और जो रईसों का भी क्षेत्र है। इस देश के सारे रईस वहां रहते हैं। अंबानी से लेकर टाटा, बिड़ला सब वहां रहते हैं, मेरे क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन जब मैंने राष्ट्रपति जी का भाषण सुना, देखा, पढ़ा तो मुझे विश्वास हुआ कि पक्के घरों वाले ही नहीं, मेरे झुग्गी-झोपड़ी वाले, आज सब यह सपने देख रहे होंगे कि हमारा पक्का घर बनेगा।

यह सरकार हमारे राज्य में कैम्पाकोला की बिल्डिंग तुड़वा रही है और हम पक्का घर बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें गरीबी हटाओं के नारे पहले देते रहे, आज क्या हुआ? हमने तो गरीबी का पूरा निवारण करने की बात की। मुझे गर्व है कि मेरे प्रधानमंत्री जी सिर्फ सापने देखते नहीं, सपने साकार करते हैं। इस विश्वास को लेकर हरेक आदमी देख रहा था। सब दुखी हैं, कोई महंगाई से, बिजली से, कोई घर से, टैक्स से, कोई एलबीटी से दु:खी, उन्होंने तो एलबीटी का विस्तार भी बहुत अच्छा किया था, लूट-बूट का टैक्स है। हमारे राज्य में लोग देख रहे हैं कि कब लूट-बूट का टैक्स बंद होगा। अगर वे नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को यहां करना होगा। किसानों की आत्महत्या होती रही। आपने जीडीपी की बात भी की।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, मुम्बई शहर ऐसा है, जो इस देश की राशि में सबसे ज्यादा धन देता है। एक लाख 75 करोड़ से भी ज्यादा हर वर्ष हम यहां अपने देश की राशि में आय कर के माध्यम से पैसा देते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे शहर की तरफ देखें। झुग्गी-झोंपड़ियों एवं पुरानी इमारतों की तरफ देखें और जरा हमारी तरफ भी राशि दें। युवा विकास की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा की बात हुई। मैं राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में सब की बात सुन रहा था, कोई कह रहा था कि रीज़नल लैंग्वेज में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए और कोई कहता है कि हर भाषा में होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि रीज़नल लैंग्वेज भी हो, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंग्रेजी का अभाव नहीं होगा, लेकिन प्रभाव भी नहीं होगा। आज देश में हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी का प्रभाव ज्यादा हो रहा है। गरीब भी चाहता है, ऐसे-ऐसे स्कूल में जाए, सीबीएसई स्कूल में जाए। जब हम मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां हमारा स्लेबस पूरे भारतवर्ष में एक है। इंजीनियरिंग और लॉ के लिए भी पूरे भारतवर्ष में एक स्लेबस है। फिर हमारी डिस्पैरिटी और डिस्क्रिमनेशन प्राइमरी और सैकेंडरी एजुकेशन में क्यों? वहां हमारा स्लेबस क्यों न हो, किसी भी भाषा में हो। हर प्रांत की भाषा में हो, लेकिन स्लेबस सेम हो ताकि हमारा गरीब वही शिक्षा पाए जो शिक्षा अमीर का लड़का पाता है। यह काम मैं सोचता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा समिति है, वह करेगी, मुझे उस पर विश्वास है। हमने तत्परता से न्याय देने की बात की है। मुझे लगता है कि मुम्बई में भी सुप्रीम कोर्ट का एक बैंच होना चाहिए। अगर उसकी तरफ आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। यह काम करना होगा। राष्ट्रीय किसान की जो जल सिंचन योजना है, अभी-अभी हल में ही महाराष्ट्र में परसों 51 किसानों ने आत्महत्या की, कितनी बुरी बात है। केन्द्र की सरकार के चुनाव के समय से हम बार-बार मांग रहे थे, किसानों को मदद करे, लेकिन मदद नहीं की। आज मैं अपेक्षा करता हूं कि इन किसानों पर हमारी सरकार ध्यान देगी। उनके परिवार के ऊपर ध्यान देगी। हमारे यहां जो अमीर लोग हैं, उनकी भी बड़ी समस्याएं हैं। एलबीटी है, आपने जीएसटी की बात की है। ये व्यावसायियों को इतना परेशान करते हैं कि पूछो मत। आज आपने जो जीएसटी की बात की, मैं उसका बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरा मुम्बई शहर है, हमारा कोंकण रीज़न है, सागर तट है, सागर माला की बात की है। पुराने मंत्री हमारे मुम्बई के थे। पुराने हमारे मुंबई बंदरगाह की एक ज़माने में अंग्रेजों के जमाने में उस बंदरगाह की सराहना की जाती थी, आज वह बंदरगाह नाकाम है, कुछ नहीं आता। हमने जेएनपीटी खोला, तब भी खुला नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरी सरकार उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देगी। मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है, उसे मैं देख रहा हूं। सुषमा स्वराज जी ने गंगा के पुनरुद्धार की बात की, बहुत अच्छा लगा। उस भाषण में भी मैंने सुना, मुझे याद आता है राजकपूर जी ने एक पिक्चर निकाली थी – जिस देश में गंगा बहती है। वे कहते थे – "होठो पर सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है।" उसी राजकपूर ने 50 साल के बाद एक और पिक्चर निकाली – "राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते-धोते।" अब वे पापियों के पाप धोते-धोते गंगा इतनी मैली हुई, कि आपको पुनरुद्धार का काम करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है, सब लोग कहते हैं, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सी नदियां हैं, गोदावरी है, कावेरी है, बहुत सी नदियां हैं, लेकिन गंगा एक सिम्बोलिक है। जब हम गंगा का पुनरुद्धार करना चाहते हैं तो हमें विशास है कि देश की सारी नदियों का पुनरुद्धार होगा और वह जो काम आपने करने का सोचा है, उसकी मैं बहुत-बहुत सराहना करता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री अरविंद सावंत : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करुंगा।

माननीय सभापति : जी, नहीं समय सीमित है। कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत : महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। श्रम आधारित की बात की, मैन्युफैक्चरिंग की बात की, कल मुझे इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय के लोग मिले, उन लोगों को इतना परेशान किया कि वे लोग धंधा नहीं कर पाये। हम चाहते हैं, देखिये पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स सारी मर गईं, सारी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स घुटन सी महसूस करती है, चाहे वह पब्लिक सैक्टर बैंक्स हों, इंश्योरेंस हो, टेलीफोन हों, क्योंकि, सरकार की नीति ऐसी रही है, एलपीजी वाली नीति, लिब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजशेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस नीति में यह नहीं था कि अपना ही गला घोट लो और परदेशियों की मदद करो। इस नीति में जरा सुधार करना पड़ेगा।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया भाषण समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत : आखिर में मैं दो चीजें कहता हूं कि जो ब्रांड इंडिया बनाया है और हम जो कहते रहे 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' मुझे विश्वास है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, हमने जो कहा है, ट्रैडीशन, टेलेंट, टूरिज्म, ट्रेड एंड टैक्नोलोजी, इस पर आधारित हमारा श्रेष्ठ भारत होगा और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि 'दु:ख भरे दिन बीते रे भइया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे।' ऐसा रंग हमारी नई सरकार लाएगी, ऐसा विश्वास करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***डॉ. रत्ना डे (नाग)** (हुगली): सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री, अध्यक्ष महोदया और इस समानित सभा के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहती हूं।

सदा की भांति 2014 के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण वादों से भरा है। उदाहरण के लिए एनडीए की सरकार खाद्य मूल्य में वृद्धि को रोकेगी, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता, आईआईटी और आईआईएम की स्थापना, कृषि क्षेत्र में सरकारी-निजी निवेश में वृद्धि, 2022 तक प्रत्येक परिवार को बेहतर आवास मुहैया कराना, 2022 तक सप्ताह के सातों दिन चौबिस घंटे बिजली की आपूर्ति इत्यादि। सभी लंबे-लंबे वादे किये गए हैं। आप यह न समझें कि मैं निराशावादी हूं। मेरी इच्छा है कि एनडीए सरकार द्वारा दिखाए गए सारे सपने और किए गए सभी वादे सही सिद्ध हों।

हमारे देश में परेशान करने वाली कई समसएं हैं। देश में सूखे की संभावना है, और इसके बाद बाढ़ की विभीषिका होगी एवं इतनी विविधताओं वाले इस देश में इन समस्याओं से निपटना किसी भी सरकार के लिए बड़ा कठिन कार्य है।

खाद्य सुरक्षा योजना, मनरेगा जैसी कई लोकप्रिय योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। सरकार यह धनराशि कहां से जुटाएगी ?

पश्चिम बंगाल 34 वर्ष के सीपीएम नीत सरकार के कुशासन के कारण वित्तीय दबाव में है। मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि मई, 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के पश्चात् पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य ने केंद्र को 77,000 करोड़ रुपए लौटाया है। इस भारी ऋण के कारण पश्चिम बंगाल सरकार इस राज्य के गरीबों और पददलितों के लाभ के लिए 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य वाली विकास संबंधी परियोजनाओं को शुरू करने में समर्थ नहीं है। इसलिए, मैं यहां अनुरोध करूंगी कि सरकार ब्याज भुगतान पर तीन वर्ष का अधिस्थगन की घोषणा कर पश्चिम बंगाल सरकार को कर्ज से उबारने में हस्तक्षेप करे।

इसके बावजूद, ममता बनर्जी के कुशल नेतृत्व में हमारी पश्चिम बंगाल सरकार ने अच्छा कार्य किया है, जैसे – पहाड़ों की समस्याएं सुलझाना अथवा माओवादी संकट अथवा पश्चिम बंगाल के आम लोगों को संतुष्ट करना आदि। मैं संतुष्ट शब्द की बात कर रही हूं क्योंकि हम हाल के लोग सभा चुनाव में कुल 42 सीटों में से 34 सीटों पर विजयी रहे।

मैं एनडीए सरकार से पुरजोर आग्रह करुंगी कि वे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करे। इससे हमारे देश के गरीबों और पददलितों को मदद मिलेगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया है कि नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। यहां मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि वे नदियों को आपस में जोड़ते समय क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखें।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

साधारण बीमा कंपनी और कृषि विभाग एवं बैंकों के बीच कोई आपसी समझ नहीं है। किसान प्रीमियम की राशि बैंकों में जमा कर रहे हैं और साधारण बीमा कंपनी बैंकों से प्रीमियम ले रही है। वर्तमान में सरकार के पास इस संबंध में कोई निगरानी तंत्र नहीं है। कभी-कभी किसानों द्वारा जमा की गई राशि गलत खातों में चली जाती है और इसके परिणामस्वरूप किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। सरकार को किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को माफ करना चाहिए।

न्यूनतम मजदूरी को इस देश में कानून बनाया जाना चाहिए। सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। किसी भी प्राधिकारी को मजदूरों के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। यद्यपि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है किन्तु रिपोर्ट के अनुसार 26 करोड़ से अधिक लोग स्वास्थ्य सेवा नहीं ले सकते हैं और सरकारी अस्पताल केवल उन लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं जो उपचार के किसी स्रोत के बिना ही आशाहीन होकर सरकारी अस्पताल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों को अत्याधुनिक निजी अस्पतालों की भांति उन्नत बनाया जाए।

नई बीपीएल सूची की आवश्यकता है ताकि इस योजना का लाभ गरीबों और पददलितों को मिल सके।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में गरीबी उन्मूलन के स्थान पर गरीबी हटाओ का उल्लेख किया गया है। मेरी कामना है कि केन्द्र सरकार इस प्रयास में सफल हो।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका घन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया और श्री राम विलास पासवान जी द्वारा जो अनुमोदन किया गया, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा चार में जो उन्होंने मतदाताओं का आभार प्रकट किया है और आभार प्रकट करते-करते यह कहा है कि इस चुनाव के माध्यम से जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी मतदाताओं ने 30 साल के बाद इस देश को दी है, उसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का भी और रूडी जी, आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आये।

मैं पैरा वन का जिक्र करना चाहूंगा, जो यह कहता है कि यह 16वीं लोक सभा मोर प्रोडक्टिविटी धारण करेगी, यह ज्यादा उत्पादकता पैदा करेगी, यह ज्यादा उत्पादकता पैदा करेगी, विधायी कार्यों के लिए यूज़फुल होगी, फ्रूटफुल होगी, यह पैरा वन में कहा गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, उसने लोग बाहर घृणा की दृष्टि से देखने लग गये हैं। एयरपोर्ट पर लोग कहते हैं कि यह एमपी है क्या, तो यह गड़बड़ होगा। ऐसा लोग कई बार नेताओं के बारे में कहते हैं। यह इसलिए हुआ कि जो हमारी 15वीं लोक सभा थी, वह प्रोडक्टिविटी के बारे में काफी निचले पायदान पर चली गई थी। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि इसके लिए जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप 13वीं, 14वीं और 15वीं लोक सभा की बात देखेंगे। तो 13वीं लोक सभा में 297 बिल पास हुए, 14वीं लोक सभा में 248 बिल पास हुए और 15वीं लोक सभा में 179 बिल पास हुए और 68 बिल पैंडिंग रह गये। अब ये कह रहे हैं वह तो बीजेपी के कारण पेंडिंग रह गए। टू जी बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया था, किसने किया था? टू जी में हमने कहा कि जेपीसी दे दो, आपने पूरा सत्र निकाल दिया, आप अड़े रहे, दूसरे सत्र में आपने जेपीसी दी, किसकी गलती है? प्याज भी खाए और सौ जूते भी खाये। आपके कारण पन्द्रहवीं लोक सभा मं काम बाधित हुआ।

फिर आप तेलंगाना वाला ईश्यू ले लीजिए, मैं यह इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के नाते गुड गवर्नेंस नहीं दे पाए। सुषमा जी ने कहा था कि तेलंगाना बनाइए, बीजेपी समर्थन करेगी। आपने देखा कि अगर तेलंगाना बन जाएगा, तो इसका लाभ बीजेपी ले लेगी, इसलिए तेलंगाना के ईश्यू को डेफर किया। अगर हाउस तेलंगाना के कारण साल-डेढ़ साल डिस्टर्ब रहा तो इसकी गलती बीजेपी की नहीं है। यह गलती उस समय की जो यूपीए की सरकार थी, उनकी है। उन्होंने फ्लोर मैनेजमेंट भी ठीक नहीं किया। दो आदमी आते थे और कोई यहां से खड़े होकर निर्देश देते थे और हाउस एडजर्न हो जाता था।...*(व्यवधान)* निशिकांत जी पांचों साल यही रहा। इसलिए बीजेपी इज नॉट रिस्पांसिबल कि पन्द्रहवीं लोक सभा में काम कम हुआ है। अगर पन्द्रहवीं लोक सभा में काम कम हुआ है तो उसका कारण यूपीए सेकेंड और उस समय की जो सत्ताधीन पार्टी थी, वह रही।

दूसरी बात, 16वीं लोक सभा में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि यह मोर यूजफुल होगा, 16वीं लोक सभा के आने वाले सत्र विधायी कार्यों के लिए, हम यह चाहते हैं कि आप सब भी सहयोग करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। आपने भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के लिए सदन को आश्वासन दिया है। देश देख रहा है कि हम 16वीं लोक सभा में किस तरह की लेजिरलेटिव प्रोडक्टिविटी के काम करने वाले हैं? जो पहले पैरे में, इसको इंफेसिस किया है कि 16वीं लोक सभा बेहतर रिजल्ट देने वाली होगी, मैं विश्वास करता हूं कि नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व

में जो भाजपा की सरकार बनी है, वह बेहतर रिजल्ट देने वाली होगी, हम ऐसा विश्वास करते हैं।

महोदय, मैं एक पैनल डिस्कशन में चला गया था, वहां पर एक चर्चा आयी, मेरे साथ कांग्रेस के एक मित्र पैनल में थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने एक फ्रेज यूज किया कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल। मैंने कहा कि आपको कुछ दिखता ही नहीं है क्या? उनको बोतल दिखती नहीं, वाइन दिखती है। मैंने कहा कि आपको क्या कुछ दिखता ही नहीं है? वे बोले कैसे? अभी जैसे सुषमा जी ने कितनी नयी योजनायें बता दीं, लेकिन मैंने वहां कहा कि कैसे नया नहीं लगता? हम सौ शहर नये बनायेंगे। इसी हाउस में 15वीं लोक सभा में कई बार चर्चा हुयी कि इस देश में अर्बनाइजेशन इज ए प्रॉब्लम। कई बार कई लोगों ने कहा, लेकिन उसको चुनौती के रूप में स्वीकार नहीं किया। अर्बनाइजेशन को कैसे ठीक करेंगे, इसका किसी ने प्लान नहीं बनाया। अब जब नरेन्द्र भाई मोदी कहते हैं कि हम इस देश में सौ नये शहर बनायेंगे, तो वे कहते हैं कि आप सपने दिखा रहे हैं, आपकी कोई नीति नहीं है।

महोदय, 45 परसेंट रेट से अर्बनाइजेशन इस देश में बढ़ रहा है। सभापति जी, हमने अर्बनाइजेशन को ढंग से डील नहीं किया, तो इस तरह की समस्या शहरों में आने वाली है, ट्रैफिक की हो, जॉम की हो, लाइट जाने की हो, सीवरेज की हो, डिस्पोजल की हो, पानी की हो, इन समस्याओं का निदान नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार ने अपने पहले ही अभिभाषण में कह दिया कि हम सौ शहर बनाकर शहरीकरण की चुनौती को दूर करेंगे। क्या यह नयी योजना नहीं है?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इसी हाउस में 15वीं लोक सभा में कई बार चर्चा हुई। शरद यादव जी नहीं हैं, उन्होंने कई बार कहा कि इरीगेशन का रकबा बढ़ाओ, इरीगेशन ठीक नहीं कर रहे हैं। कई मित्र मुझे टेलीविजन में पूछ रहे हैं कि गुजरात मॉडल क्या है? मैंने कहा कि इरीगेशन की फैसिलिटी अगर 6 लाख चेकडैम बनाकर गुजरात ने पैदा की और उससे एग्रीकल्चर ग्रोथ, जो पूरे देश में चार परसेंट हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, दो और तीन परसेंट के बीच में है, जबकि गुजरात में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 11 परसेंट पहुंच गयी है, तो क्या यह गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है? वे इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की है, मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस देश में मील का पत्थर साबित हुयी है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी इस देश में मील का पत्थर साबित होगी। ऐसी कोई योजनाएं हैं जिनका जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को दिखता नहीं है।

रेल के बारे में जिक्र हुआ है कि रेल के बारे में सपने दिखा दिए। पॉलिटिकली जो सभा होती है उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम रेल को ग्रोथ को इंजन बनाना चाहते हैं, वही भावना राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रकट की गई है। रेल जिस तरह का महकमा है, जिस तरह का उपक्रम है उसको वह प्रायरिटी नहीं दी गई, जो यूपीए-I और यूपीए-II के समय में देनी चाहिए थी। उसका कारण यह रहा कि जब कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रेल का विकास इसलिए धीमी गति से होता है कि हम गठबंधन की राजनीति में जीते हैं और रेल मंत्रालय हमारे गठबंधन वाले दल ले जाते हैं। कोई विफलता – गठबंधन वाले दल, टू जी – डीएमके जिम्मेदार, रेल – कोई और जिम्मेदार तो अपने गठबंधन के कारण जो विफलताएं थीं उनके बारे में देश को कभी नहीं बताया कि रेल क्यों नहीं विकास कर पा रहा था, क्यों वह हाई स्पीड ट्रेन नहीं चला पा रहे थे, लेकिन पहली बार हमने हाई स्पीड ट्रेन, रेलवे के एक नेटवर्क और कॉरिडोर की भी बात प्राथमिकता से कही गई है। मैं राजस्थान से चुन कर आया हूं। अगर कॉरिडोर ठीक ढंग से बन गया तो हमारे राजस्थान का भी पूरा विकास होगा।...*(व्यवधान)* मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

लंबे समय से जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे हमारी भाषा राजस्थानी है, उसके विकास के लिए हम बात करते रहते हैं। तमिल, कन्नड और राजस्थानी भाषाओं का विकास हो।...*(व्यवधान)* रूडी जी, भोजपुरी और राजस्थानी भाषा से संबंधित मामला एक ही बिल में मान्यता के लिए पेंडिंग है। हमें उनके लिए एक ही बिल के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन, भाषा के बारे में कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र नहीं आया। मैं पिछले 5 सालों का अभिभाषण अपने थैले में लाया हूं। मेरे काले थैले में काफी सामान रहते हैं।...*(व्यवधान)* भाषा का कभी जिक्र नहीं आया, यह पहली बार है कि उन्होंने कहा है कि हम भारतीय भाषाओं का विकास करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए, ई-भाषा का मिशन चलाएंगे तो **भर्तृहरि** जी यह बड़ा काम नहीं है। क्या यह आपको नई योजना नहीं लगती है? मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय भाषाओं का विकास होगा तो यूपीएसपी में जिस तरह की विसंगति पैदा हुई, इसी हाउस ने कहा कि नहीं। यह जो सी-सैट का मामला आया। वर्ष 2011 से युवा लड़ रहे हैं कि हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों को अवसर कम मिल रहे हैं। उन्होंने आंदोलन किया कि हमें अवसर दिए जाएं। क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी भाषी लोग प्री परीक्षा में क्यों कम पास हो रहे हैं तो जो ई-भाषा वाला मिशन बनेगा, उससे मुझे लगता है कि यूपीएससी में हिन्दी भाषी लोग तो डर रहे हैं कि

हम आईएएस कम बन रहे हैं, तीन चार सालों से उनके नम्बर्स कम हो रहे हैं, उनकी समस्या का भी समाधान होगा।

माननीय सभापति जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं रेगिस्तान इलाके से आता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हिल्ली एरिया और डेजर्ट एरिया को एक करने की बात कही गई है। उनको एक तरह की सुविधाएं दी जाए। हम इंदिरा आवास की भी बात करते हैं। हमने दिल्ली एरिया और डेजर्ट एरिया के विकास की भी बात की है। मैं बिकानेर क्षेत्र से चुन कर आया हूं, उसके आसपास के 15-16 ऐसे जिले हैं जो रेगिस्तानी इलाकों से संबंध रखते हैं तो मुझे लगता है कि अब रेगिस्तानी इलाकों के भी अच्छे दिन आ गए हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति जी, मैं अपनी अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जुडिशियरी सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है। उसको भी बहुत से किसी ने टैकल नहीं किया है। जुडिशियल एकाउंटेबिलिटी वाला बिल भी पेंडिंग पड़ा है। न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए इस अभिभाषण में पूरा जोर दिया गया है। हमारी कार्यपालिका की बहुत आलोचना होती है। लेजिस्लेटिव विंग की भी बहुत आलोचना होती है। हमारी न्यायपालिका गरिमापूर्ण अस्तित्व रखती है, लेकिन उसके बारे में चर्चा कम होती है। लेकिन इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन्होंने जो बात कही है जिसका जिक्र किया है उसका मैं हवाला देना चाहता हूं कि इस देश में 3.25 करोड़ मुकदमें लंबित हैं। उच्च न्यायालयों के जजों की कुल संख्या 906 है, जिनमें से 250 पद खाली हैं। जो आपकी छोटी अदालतों के जज हैं, इनकी संख्या 18000 है जिनमें से 3000 पद खाली हैं तो जो न्याय व्यवस्था की बात कही गई है उससे मुझे लगता है कि सबका साथ और सबका विकास कर के भारत एक और श्रेष्ठ बनेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. काकली घोष दोस्तीदार (बारासात) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी की ओर से 9 जून को संसद में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के समर्थन में खड़ी हुई हूं।

महामहिम राष्ट्रपति ने जो आशा व्यक्त की है कि यह सत्र फलदायी हो ताकि आशाओं को पूरा किया जाए और यह सत्र निराशाजनक न हो।

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो इतने बड़े जनादेश के साथ आयी है, गत तीन वर्षों से सत्ता में रहने के बाद भी उन्हें राज्य में 30 प्रतिशत से अधिक ही मत प्राप्त हुआ। खुशी की बात यह है कि हमने महिलाओं को लगभग 30 प्रतिशत सीट देकर उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है और लोगों ने भी भारी संख्या में महिलाओं, जो लगभग 30 प्रतिशत हैं, को चुनकर अपना वादा पूरा किया है!

सत्ताधारी दल भी बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आया है। मुझे आशा है कि सत्ताधारी दल लोगों द्वारा दिए गए इतने बड़े जनादेश का मान रखेंगे। हम अपनी पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से रचनात्मक भूमिका निभाने का वादा करते हैं। हम वादा करते हैं कि लोगों के हितों से जुड़े कार्यों के लिए जब कभी भी सरकार गरीब लोगों के साथ खड़ी होगी, जब कभी भी वह गरीब लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी, हम उनके साथ होंगे, किन्तु निश्चित तौर पर हम लोकतांत्रिक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे और लोक विरोधी और लोकतंत्र विरोधी मुद्दों पर हम आलोचनात्मक रूख अपनाएंगे।

जैसा कि बाइबिल में भगवान ने कहा कि, 'प्रकाश हो'। तमसो मा ज्योतिर्गमय! यह जनादेश गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए कार्य करे, वे जिन मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, उनके सपने को पूरा करें, बेघर, बेरोजगार, कुशल और अकुशल कामगारों, उत्पीड़ित और अंतिम छोर पर खड़े लोगों के सपनों को पूरा करें, यह जनादेश उनके लाभ के लिए कार्य करे और हम आपके साथ खड़े होंगे।

किन्तु हमें इस प्रकार के सामाजिक न्याय के लिए कार्य करना चाहिए जिसमें गरीब लोगों को दो वक्त का खाना मिले, और उन्हें रोजगार तथा घर मिले। यह अभिभाषण वास्तव में सराहनीय है। मैं महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ रही थी जिसमें वादा किया गया था कि गरीबों के लिए पक्का मकान बनाया जाएगा तथा सड़क अवसंरचना पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है जिसकी ग्रामीण भारत को वास्तव में आवश्यकता है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री अभी यहां उपस्थित है। अब मैं इस देश की कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहती हूं। हमने यहां महिलाओं को समान अधिकार और संसद में उन्हें आरक्षण देने का वादा किया है। किन्तु हम एमडीजी-5 को पूरा नहीं कर पाए है; हम मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए है। यदि हम कारणों पर गौर करें तो सुदुवर्ती गांव जिसमें पक्की सड़क नहीं है, वहां रेफ्रिजरेटर के उपयोग के लिए बिजली कनेक्शन नहीं होता है जिससे कि हम कुछ निथेग्रिन के एम्प्यूल का भंडारण कर सकें जो महिला के बच्चा जनते समय खून को रोकने के लिए जरूरी होता है। अत: हमें इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सुदुवर्ती गांव तक सड़क का निर्माण करना चाहिए। हमें सड़क निर्माण तथा अंतिम घर तक विद्युत आपूर्ति करने तथा लड़कियों को शिक्षा देने के लिए विशेष एजेंडा बनाना होगा।

अपराह्न 2 बजे

बिटिया हमारी शान है, उन पर हमारी जान कुर्बान है। मैं यहां अपनी मुख्य मंत्री माननीय ममता बनर्जी द्वारा कन्याश्री प्रकल्प के माध्यम से

शुरू किए गए एजेंडे का हवाला देना चाहती हूं। कन्याश्री प्रकल्प क्या है? इसमें कहा गया है कि यदि हम कक्षा सात तक लड़कियों को शिक्षा देते हैं तो राज्य सरकार उसे सातवीं के बाद के अध्ययन को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देगी। 18 वर्ष के पश्चात् भी यदि वह अविवाहित रहती है तब उसे अध्ययन करने था अपने पसंद का व्यापार करने के लिए और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगा। '18 वर्ष की आयु' तथा '18 वर्ष तक अविवाहित' शब्दों को जानबूझकर रखा गया है क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में लड़की पूरी तरह परिपक्व नहीं होती है तथा प्रजनन के लिए उसके पास पर्याप्त शारीरिक शक्ति नहीं होती है। अत: 18 वर्ष तक अविवादित रहने से तात्पर्य वह अविवाहित और शिक्षित होगी तथा स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए और अधिक परिपक्व होगी। ऐसी स्थिति में राष्ट्र में स्वस्थ्य माताएं होंगी जिससे स्वस्थ बच्चे के प्रजनन में वृद्धि होगी। मेरे विचार में केन्द्र सरकार को उनसे कुछ जानकारी लेनी चाहिए तथा कन्याश्री प्रकल्प शुरू करना चाहिए जो वास्तव में प्रशंसनीय है।

जहां तक खाद्यान्न की बात है, जो जीवन की बुनियादी आवश्यकता है, हमारा पश्चिम बंगाल सरकार खाद्यान्न की मांग को पूरा करने में सफल रहा है और उसे 3.22 करोड़ गरीब लोगों तक पहुंचाया गया है। हम दो रुपए प्रति किलो चावल देकर वामपंथी चरमपंथी से निपटने में सफल रहे हैं। किन्तु हमें केन्द्र सरकार से इसके लिए और अधिक सहायता की आवश्यकता है क्योंकि इस देश में बहुत लोग हैं जो अक्षम तथा गरीब है तथा जो इस प्रकार की सहायता की बाट जोह रहे हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सफाई का है जोकि बहुत महत्वपूर्ण है घरों में शौचालय नहीं होने के कारण जन लड़कियां इसके लिए बाहर जाती है तो वे बदमाशों के हाथ बलातकार या प्रतारणा का शिकार हो जाती हैं। अत: हमें महिलाओं की देखभाल के लिए न केवल अधिक संख्या में शौचालय चाहिए बल्कि यह अपराध को कम करने का एक साधन भी है। हमारे राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन और महिलाओं के लिए समान रूप से शौचालय के निर्माण के लिए और अधिक निधि की आवश्यकता है। अत: मैं अपने भाषण के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि राज्य सरकारों को और अधिक निधि प्रदान किया जाए।

अपराह्न 2.03 बजे

[**डॉ. रत्ना डे (नाग)** *पीठासीन हुईं*]

राज्य सरकार को मदरसा शिक्षा, जिसका उल्लेख महामहिम के भाषण में किया गया है, सहित विभिन्न मुद्दों पर विश्वास में लेना चाहिए। जहां तक इसकी बात है, तो इस संबंध में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं।

जहां तक सीमा संबंधी मुद्दो की बात है, हमारा राज्य तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं – भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से लगा हुआ है। अत: हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले हम भी चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार को विश्वास में लिया जाए और मामले की चर्चा इनसे की जाए क्योंकि ऐसा करने से आसानी होगी।

यहां यह भी कहा गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पताल की योजना विभिन्न राज्यों के लिए बनाई जा रही है। मैं यहां आपसे अनुरोध करती हूं कि स्थल के चयन से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श लिया जाए क्योंकि यह निर्णय लेना राज्य सरकार का है कि राज्य के किस भाग को इसकी आवश्यकता अधिक है और भूमि कहां उपलब्ध है। हमारे राज्य सरकार की बहुत स्पष्ट नीति है; भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाए; भूमि का उपयोग उद्योग के लिए किया जाए तथा भूमि का उपयोग अस्पताल के निर्माण के लिए किया जाए। अत: हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आगे बढ़ने से पहले हमसे संपर्क करें।

जहां तक बीपीएल सूची की बात है, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हमने वर्षों से इसकी समीक्षा नहीं की है।

जहां तक रेल की बात है मैं बताना चाहती हूं कि हमारे नेता माननीय मंत्री ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहने के समय सबसे अधिक प्रगति हुई है। उन्होंने न केवल पूरे मासिक टिकट 'इज्जत' देकर गरीबों को इज्जत दी बल्कि उनके कार्यकाल में राजस्व संग्रहण में वृद्धि भी हुई थी। जहां तक यात्री भाड़े की बात है, तो इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 88.74 प्रतिशत वृद्धि हुए तथा माल भाड़ा संग्रहण में 8.56 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उन्होंने पूर्व में अपने किए गए वादे के अनुसार माल भाड़ा और यात्री भाड़ा को अलग-अलग किया तथा 2020 के अपने विजन दस्तावेज में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का एजेंडा लिया। किन्तु मैं पुन: अनुरोध करती हूं कि आप उस दस्तावेज पर विचार करें – जिसमें उन्होंने पहले ही पश्चिम समर्पित माल भाड़ा गालियारे का कार्य शुरू किया था जिसमें रेवाड़ी और बड़ोदरा खंड तथा खुर्जा लुधियाना खंड का पूर्वी समेकित गलियारा शालिम नहीं है।

माननीय सभापति : डॉ. काकली घोष दोस्तीदार कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. काकली घोष दोस्तीदार : आपने उनके 2020 विजन से इन मुद्दों को लिया है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं तथा हम इस बात पर बल देते हैं कि मेट्रो रेल जिसे कोलकाता शहर के चारों ओर चलाया जाना था, को कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने पहले ही धन की स्वीकृति कर दी है। किन्तु यह अपूर्ण पड़ा है, तथा जैसा कि मेरे विज्ञान मित्र ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे प्रतिपक्त कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे वस्तुत: अनुरोध करती हूं कि आप इस पर विचार करें क्योंकि इसे हमारी नेता और तत्कालीन रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने शुरू किया था। उन्होंने महिलाओं के लिए मातृभूमि लोकल

तथा बेरोजगार युवकों के लिए वातानुकूलित लोकल चलाई थी। अत: मैं आशा करती हूं कि इन मुद्दों पर विचार किया जाए। हम रेलवे के निजीकरण का विरोध करते हैं।

अंत में मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि ड्रीमलाइनरों में इन बिन्दुओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। नागर विमानन मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए कि ड्रीमलाइनर, जिनका उपयो किया जा रहा है, को पूरे विश्व में त्रुटिपूर्ण पाया गया है। यह बहुत जल्द किसी दुर्घटना का कारण हो सकता है। दो-तीन दिन पहले दिल्ली से कोलकाता की उड़ान में लोग बीमार हो गए क्योंकि केबिन मैं आक्सीजन का स्तर सांस लेने के लिए उपयुक्त स्तर से नीचे गिर गया। अत: मेरे विचार में इससे पहले की कोई विपत्ति आए, इन एयरलाइनों को हटाना चाहिए।

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम) : सभापति महोदया, हम माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर सभा के विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न विचार रखे गए हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं जितना संभव हो सके संक्षेप में बोलूंगा। फिर भी, मैं यहां पर दो-तीन मुद्दे रख रहा हूं।

मैं केवल यह कहता चाहता हूं कि मेरी पार्टी इस सभा में सन् 1952 से है। हमने 1952 से लेकर 2004 तक एक प्रतिपक्षी दल के रूप में हमने कार्य किया और उसके पश्चात् दस वर्ष के लिए हमें सत्तारूढ़ दल के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन हमने हमेशा एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में कार्य किया। जब कभी सरकार को हमारे समर्थन की आवश्यकता हुई, हमने हमेशा एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में कार्य किया। जब कभी सरकार को हमारे समर्थन की आवश्यकता हुई, हमने समर्थन दिया। लेकिन जब कभी सरकार ने हमारी नीतियों के विरुद्ध कार्य किया तो अपने कर्तव्यानुसार हमने उसका विरोध किया।

इसलिए, अटल बिहारी जी के समय के दौरान हमने एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में सरकार का विशेषकर, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दों पर समर्थन किया था। जहां हमारे विरोध की आवश्यकता थी, हमने विरोध भी किया। लेकिन वर्ष 2004 से 10 वर्ष तक हम सत्तारूढ़ गठबंधन में थे। इस अवधि के दौरान भी हमने एक ऐसी पार्टी के रूप में कार्य किया जिसने इस देश वर्ष 2004 से 10 वर्ष तक हम सत्तारूढ़ गठबंधन में थे। इस अवधि के दौरान भी हमने एक ऐसी पार्टी के रूप में कार्य किया जिसने इस देश के लोगों के लिए अच्छे कार्य किए। अब हम विपक्ष में हैं। इस अवधि के दौरान एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में कार्य करना हमारा कर्त्तव्य है। मैं इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभा का और अधिक कीमती समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल यहीं कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी का जनता और उस समुदाय जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं अर्थात् इस देश का अल्प-संख्यक समुदाय, के प्रति पूर्णत: जिम्मेदारी है। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे बड़ा वर्ग है। हम मुसलमानों को राष्ट्रीय अल्प-संख्यक मानते हैं। इस समुदाय के लोगों को सूरक्षा मुहैया कराना प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों के मन में सुरक्षा का भाव जगाने के लिए पर्याप्त और उचित कदम उठाए क्योंकि ये भी इस देश की जनसंख्या का अभिन्न अंग हैं।

माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में समावेशी विकास का भी उल्लेख है। समावेशी विकास में अल्पसंख्यक समुदाय सहित सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए, मैं सरकार से देश के विभिन्न वर्गों और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित लोगों के एक बड़े तबके के दिमाग में चल रहे भय और आशंका पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। नई सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् से ही लगातार साम्प्रदायिक हिंसा की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक छात्र की दिल्ली में मृत्यु की सूचना भी प्राप्त हुई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने से पहले इस कृत्य की राष्ट्रीय लज्जा के रूप में निंदा की थी और हम सभी उनके समान ही भावना रखते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हाल ही में एक निर्दोष तकनीकज्ञ व्यक्ति, अर्थात् मोहसिन शेख को हिन्दुत्ववादी समूहों द्वारा पुणे में मार दिया गया। हमारे देश के लिए यह शर्म की बात है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसके बारे में प्रचार किया है। मैं इस अवसर पर सरकार को यह बताना चाहूंगा कि ऐसी घटनाओं को रोका, नियंत्रित और बंद किया जाना चाहिए तभी भारत इस तथ्य पर गर्व कर सकता है कि यह वह देश है जो समाज के सभी वर्गों को संरक्षण प्रदान करता है। उक्त निर्दोष तकनीकीज्ञ पर घातक हमला किया गया और उसने अपनी जान गंवाई। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।

ऐसी वचनबद्धता की तात्कालिक आवश्यकता है कि वंचितों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश का राष्ट्रों के विश्व-विरादरी में विश्व के प्राणवंत लोकतंत्र के रूप में नाम है। यह देश मानवाधिकारों को महत्व देता है और इस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का सदस्य बनाने पर विचार किया जा रहा है। हमारे देश के ये सत्गुण हैं। इसलिए, तात्कालिक वचनबद्धता आवश्यक है कि सीमांत तबकों और अल्पसंख्यकों के लोगों पर हिंसा को रोका जाएगा।

मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में यह भी लाना चाजता हूं कि सरकार और सरकारी क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इस देश की तेरह से चौदह प्रतिशत आबादी का सरकार और सरकारी क्षेत्रों में पर्याप्त और यथोचित प्रतिनिधित्व नहीं है। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय, जिस पर हम सभी को गर्व है, सहित लोगों के सभी तबकों को प्रतिनिधित्व देना भी सत्तारूढ़ सरकार की चिंता होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला एकमात्र देश है। अन्य किसी

देश को यह गौरव प्राप्त नहीं है। इस पर हमें गर्व है। इसी के साथ ही उनके कानूनी अधिकारों और आकांक्षाओं पर भी अवश्य ध्यान दिया जाए।

मैं एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई बातों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न देशों और क्षेत्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों और संबंधों का उल्लेख किया गया है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, खाड़ी देशों – जिनके साथ हमारे बहुत नजदीकी संबंध हैं के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे देश के साठ लाख लोगों वहां रह रहे हैं। वे वहां पर कार्य कर रहे हैं। वे हमारे देश के नागरिक हैं। उनकी अधिकांश आय भारत में आ रही है। खाड़ी देशों ने विदेशी विनिमय में स्थिरता बनाए रखने में भी हमारी मदद की है।

मैं केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दशकों में खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ है। हमने आर्थिक प्रगति के लिए खाड़ी देशों के साथ भागीदारी की है। आज हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और अलग-अलग तरह के क्षेत्रों सहित अधिकांश देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी है। हमने इन देशों के साथ इस सीमा तक कि गहरी साझेदारी बनाई है। कि उस क्षेत्र में होने वाली किसी भी घटना का हमारे देश पर प्रभाव पड़ता है। हमने इन देशों के साथ नियमित उच्च स्तरीय संवाद, आर्थिक विनिमय, सतत् सुरक्षा संवाद और पारस्परिक जन-भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया बनाए रखा है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दु:ख हो रहा है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र छोड़ दिया गया है।

मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि माननीय विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज ने एक बहुत अच्छी बात कही है। यह सरकार आठ से ग्यारह मदों को वरीयता देने की कोशिश कर रही है और इसके बारे में हम प्रसन्न हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह सरकार उन वरीयताओं के क्रियान्वयन में समर्थ होगी। वह केवल इनके बारे में बात ही कहना और इनके राष्ट्रपति के भाषण में उल्लेख ही करना पर्याप्त नहीं होगा। यदि इस सरकार द्वारा उक्त वरीयताओं का क्रियान्वयन कर दिया जाता हे तो इस बारे में भी हमें प्रसन्नता होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***डॉ. ए. सम्पत** (अट्टिंगल) : दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए माननीय राष्ट्रपति द्वारा परसों दिया गया अभिभाषण राजस्व में बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जो कमी है वो केंद्र सरकार की रूप रेखा की है। इसमें मुख्य सत्तारूढ़ दल के चुनावी घोषणापत्र को मात्र दोहरा दिया गया है। यकीनन, चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे सभी के भरोसे और सहयोग से कार्यान्वित किए जाने चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बिना किसी हिचकिचाहट के मैं लोगों के देश जनादेश को भी स्वीकार करूंगा और नई सरकार को बधाई दूंगा। फिर कभी, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ आपत्तियां व्यक्त करूंगा और मैंने पहले ही संशोधन संख्या 162 से 170 के द्वारा संशोधनों हेतु नोटिस दे दिया है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण उन विभिन्न आवश्यक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मूक है जिसका सामना हमारा राष्ट्र कर रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी, हम कई माननीय सदस्यों के भाषण में चापलूसी और मिथ्या प्रशंसा देख सकते हैं। लेकिन इससे आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलती है। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में तापमान बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और इस कारण से बिना आशय के रहने वाले गरीबों की मौत हो रही है। महिलाओं सहित मजदूर चिलचिलाती धूप में बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं। सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

न तो इसमें केरल में आईआईटी की स्थापना और राजधानी जिले में इसके मुख्यालय के बारे में कोई उल्लेख है और ना ही तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की स्थाई शाखा की स्थापना की बात कही गई है। उच्चतम न्यायालय अब भी क्षेत्रीय शाखाएं क्यों नहीं खोलता है? न्यायपालिका भी विकेंद्रीकृत होनी चाहिए।

मैं हैरान हूं कि अट्टिंगल लोक सभा संसदीय क्षेत्र में चिरायनकीजू में एक राष्ट्रीय फिल्म संग्रालय की स्थापना के लिए कोई उल्लेख नहीं है जो कि प्रसिद्ध मलपालम सिने कलाकार स्वर्गीय श्री प्रेम नजीर का जन्म खता है जिन्होंने बड़ी संख्या में फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है।

तिरुवनंतपुरम में मुख्यालय वाले पेन्नीसुलर रेलवे जोन का निर्माण भी एक बहुत पुराने लंबित मांग है। हमारी रेलवे को लोक हितैषी होना चाहिए।

हम अब भी 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क नाश्ता और लंच प्रदान करने में क्यों हिचकिचाते हैं? उयह कहने मात्र से कि "आपके पास भोजन एवं शिक्षा का अधिकार है" हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएगें।

बिना किसी अपवाद और रियायत के सभी आधारभूत श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने और श्रम कानूनों की अवहेलना के लिए सख्त सजा आवश्यक है। त्वरित विकास की आड़ में, मानवों की कुर्बानी मत दो। बाल श्रम अब भी भारतीय उद्योगों में व्याप्त है। देश से बाल श्रम हटाने के लिए उपाय करना "आज का लोकाचार" है।

केंद्र सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों और सरकारी उपक्रमों में 1.50 मिलियन रिक्तियों को भरने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए। सभी वरिष्ठ नागरिकों को जिनको कोई अन्य पेंशन नहीं मिलती, उन्हें

1000/- रुपए की न्यूनतम पेंशन के नियमित भुगतान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी मछुआरों को और अधिक सुरक्षा और राहत उपाय प्रदान करना अति आवश्यक है क्योंकि इस क्षेत्र पर लाखों परिवार आश्रित है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ढांचागत परिवर्तनों और विधानों के द्वारा भूमि सुधारों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सरकार क्यों अपने इस संसदीय कर्त्तव्य को भूल गई है? मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि सरकार उन सभी किसान करे जिसमें भारत गत 30 वर्षों के दौरान एक पक्षकार बना हुआ है। किसानों द्वारा आत्महत्या के असंख्य मामले देश के विभिन्न भागों में अब भी जारी है।

सभी कर्मचारियों को कम से कम 10,000/- प्रति माह की न्यूनतम मजदूरी देने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। यदि आप श्रम कानूनों को और अधिक शिथिल कर देंगे तो यह ऐसा ही होगा जैसा कि श्रमिक वर्ग के अधिकारों को छीन लेना। कृपया कार्य दिवस बढाएं और मनरेगा कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 320/- रुपए प्रतिदिन भी करें।

सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि वह आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि को नियंत्रित करे। जब तक एफसीआई मजबूत नहीं होगा और इसकी गतिविधियां और अधिक विस्तृत नहीं होगी हम संपूर्ण राष्ट्र में एक मजबूत पीडीएस विकसित करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। गरीब लोगों की अधिकांश संख्या अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क से बाहर है। पूर्व सरकार जनसंख्या के बीपीएल वर्ग की पूर्णतया और पर्याप्त रूप से पहचान करने में असफल साबित हुई।

यदि सरकार चल रही आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त पैसा निवेश नहीं करती तो यह अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में असफल होगी। पीपीपी संजीवनी बूटी नहीं है। देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या से निपटने में असमर्थता यूं ही जारी रहेगी यदि हम स्वयं को ऐसे कॉर्पोरेट की दया पर निर्भर रखना जारी रखेंगे जिसने विकास के सारे फल हड़प लिए हैं और हर प्रकार से राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का भारी दोहन किया है। भारतीय उद्योगों को प्रभावित करने वाली वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना करना और लाखों कामगारों और कर्मचारियों का नौकरियों से हाथ धोना नई सरकार के लिए भी एक गंभीर समस्या होगी। सरकार को गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया में प्रभावी भाग लेना चाहिए। हमें पड़ोसी देशों के साथ-साथ ब्रिक्स देशों के साथ भी संबंधों को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

समेकित बाल विकास योजना को विकसित, सुदृढ़ बनाना चाहिए और इसका सार्वभौमीकरण किया जाना चाहिए और देश में महिलाओं बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। कुपोषण और अवरूद्ध विकास इस महान देश के लिए शर्म की बात है।

मीडिया क्षेत्र में 'पेड़ न्यूज' का उदय एक खतरनाक मुद्दा बन गया है। जिसमें संसदीय लोकतंत्र विकृत हो रहा है। उनके अपने कृत्यों की वजह से 'चौथे स्तंभ' की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया जा रहा है।

सरकार को देश में प्रभावी जल परिवहन विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। किन्तु, नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए और अधिक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। विश्व में जल सर्वाधिक बहुमूल्य संसाधन है और इसलिए जल संसाधनों का किसी भी कीमत पर संरक्षण किया जाना चाहिए।

राजसहायता प्राप्त दरों पर जीवन रक्षक दवाईयां प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम उठाने में असफलता और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कमी न भी इस सेवा को बहुत महंगा बना दिया है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। जिसमें सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के मानदंडों के आधार पर मुस्लिमों को 10 प्रतिशत आदि अन्य अल्पसंख्यकों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गयी है।

उनके अभिभाषण में विदेशों में कार्य करने वाले लाखें प्रवासी भारतीयों के लिए पुनर्वास पैकेज और उनके परिवार के सदस्यों के लिए राहत उपायों का भी अभाव है। मुझे आशा है कि हमारे देश की संघीय संरचना को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। विधानमंडल में बड़े राज्यों की सांख्यिकीय ताकत से छोटे राज्यों को दबाना आसान नहीं होगा। किसी भाषा को दूसरों पर मत थोपिए।

यह संप्रग-दो की जन-विरोधी नीतियां थीं जिससे वह सिकुड़ रहा है और इसमें अंत:कलह हो रहा है। अभी भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के विनियंत्रण के पीछे की युक्ति को कोई नहीं समझ सकता। लोगों को लाभ कमाने वाली तेल कम्पनियों की दया पर छोड़ दिया गया था। इससे कीमतों में वृद्धि और राज्य प्रायोजित मुद्रास्फिति की स्थिति उत्पन्न हो गई हैं तो फिर हमारे राष्ट्रपति तेल की कीमतों को नियंत्रित करने और आधार कार्ड को राजसहायताओं और अन्य लाभों को नहीं जोड़ने पर चुप क्यों थे?

नीतियां लोगों के राहत और लाभ के लिए होनी चाहिए न कि कॉर्पोरेट के लाभ के लिए जो केवल कानूनी व्यक्तित्व है। छवि बनाने के लिए 16वीं लोक सभा के दौरान बहुत से उच्च स्तरीय जनसंपर्क कार्य किए गए हैं। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि पहली दृष्टि में छवियां सुदंर हो सकती हैं परन्तु वास्तविकताएं कुछ अलग और कठिन हैं। उग्रवाद

और महिलाओं एवं बच्चों पर हमलों को सदन नहीं करना इस पर साभी सहमत होंगे। परन्तु हम किसी के लिए राजनीतिक सहिष्णुता की कुर्बानी नहीं दे सकते। संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखना हमारा कर्त्तव्य है।

विकास के जोरदार समर्थकों से देश के विभिन्न भागों में रहने वाली जनजातीय जनसंख्या को खतरा हो रहा है। कई ऐसे बड़े वर्ग हैं जिन्हें संस्थापनाओं में स्थान नहीं दिया गया और जो विगत अनेक दशकों में विकास प्रक्रिया में पीछे रह गये हैं। उन्हें कौन देखता है? उन्हें कौन सुनता है? उन्हें कौन समझता है?

हमें प्रकृति और पर्यावरण को बचाना है। परन्तु लोगों की सुरक्षा पहले है। केवल मनुष्य में ही जीवन है और यह बहुत बहुमूल्य भी हैं इसे मौद्रिक रूप में संक्षिप्त नहीं किया जा सकता। माधवराव गाडगिल और बाद में कस्तूरी रंगन की रिपोर्टों से संबंधित हाल ही के मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। सदियों पुरानी मानवीय बसावओं को विनाश की ओर ले जाना अविवेकपूर्ण और कूट भी होगा। यह एक सभ्यता को खत्म करने जैसा होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, कल सभा में कुछ देर के लिए उत्तेजनापूर्ण वाद-विवाद हुआ। किन्तु मैं अपने सहयोगियों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी निष्ठा से हमारे अंदर घमण्ड नहीं बल्कि और अधिक समझदारी और व्यापक आत्म-मंथन का प्रादुर्भाव होना चाहिए।

हम आशा करते हैं कि नई सरकार, नए प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद् सभी हित धारकों के साथ परामर्श और समझौते के मार्ग पर चलेगी। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि राष्ट्रपति संसद के कार्यकरण के न्यूनतम दिनों के संबंध में चुप हैं। विश्व में सबसे बड़े इस बहुदलीय लोकतंत्र के लिए कम-से-कम 100 दिनों की प्रभावी बैठकों की आवश्यकता है। अध्यादेशों की बजाय पारदर्शी और ईमानदार चर्चाओं से कानून बनाए जाने चाहिए।

***श्री एंटो एंटनी** (पथनमथीट्टा) : स्वच्छ गंगा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए, मैं केरल में पवित्र नदी पंपा की तरफ ध्यान दिलाता हूं। यहां पंपा नदी पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। मध्य केरल के जिलों को पानी के स्रोतों में से एक पंपा नदी है, और यह कुट्टानाद – राज्य का चावल का कटोरा, को भी आपूर्ति करती है। पंपा की विशिष्टता इसके सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक और पारिस्थितिकीय महत्व में है। पवित्र तीर्थ स्थल सबरीमाला से इसकी निकटता के कारण, पंपा नदी को 'दक्षिण गंगा' के रूप में जाना जाता है। पंपा नदी की पनधारा पश्चिमी घाटों में पेरियार टाईगर रिजर्व और अचेंकोविल वन मंडलों को कवर करती है। करीब 40 लाख लोग विभिन्न आवश्यकताओं के लिए इस नदी पर निर्भर है। इन कारकों के बावजूद, पंपा नदी प्रदूषण के कारण, आकार में घट रही है। परिणामस्वरूप, पंपा बेसिन की जैव-विविधता और जलीय मार्ग बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। अत: मैं सरकार से पंपा नदी की रक्षा करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने का विनम्र अनुरोध करता हूं।

सरकार देश में तीर्थ केन्द्रों पर सुविधाओं और अवसंरचना का सुधार करते जा रही है। मैं इस अवसर पर सरकार से केरल में सबरीमाला तक संपर्क सहित अवसंरचना सुविधाओं को सुधारने का अनुरोध करता हूं। प्रतिवर्ष करीब चार करोड़ श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से सबरीमाला की तीर्थ यात्रा करते हैं। सबरीमाला की तीर्थ यात्रा भी साम्प्रदायिक सौहार्द के संदेश को बढ़ावा देती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से सबरीमाला को राष्ट्रीय तीर्थ केन्द्र के रूप में घोषित करने और इस पवित्र तीर्थ पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं को अद्यतन करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री अनिल शिरोले** (पुणे) : संसद में दिनांक 9 जून, 2014 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर सदन में श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

लोक सभा के पहले सत्र की शुरुआत में अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ली है। मुझे विश्वास है कि जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को हमारी सरकार पूरा करेगी।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व ने एक नई उम्मीद, आशा जगाई है। पूरे देश में आनन्द व आशा का माहौल है। यह नये दिनों की शुरुआत है। जनता ने हमें स्थिर सरकार दी है। श्री नरेन्द्र मोदी जी जैसा नेतृत्व दिया है। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि ऐसे समय पर मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है।

एक बलशाली, समृद्धशाली भारत बनाने के इस मिशन में हम अब एक होकर हमारा ये सपना अवश्य साकार करेंगे।

शहरीकरण को चुनौती मानने के बजाय अवसर के रूप में लेते हुए हमारी सरकार विशिष्ट विषयों पर केन्द्रित और विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त 100 शहर बनाने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से मेरी विनती है कि पुणे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के इस मिशन में सम्मिलित किया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री हंसराज गंगाराम अहिर** (चन्द्रपुर) : आरदरणीय केन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष पर अपना वक्तव्य रख रहा हूं।

यह अभिभाषण सरकार की सोच और नजरिया लोगों के समक्ष रखता हूं। लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता का यह दस्तावेज आज की स्थिति को देखते हुए अहम साबित हो रहा है। इसका साथ-सबका विकास का वादा और इसके द्वारा एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए की जाने वाली पहल को देखते हुए मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अभिभाषण में सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है, की उद्घोषणा और गरीबी का पूर्ण निवारण का संकल्प इस सरकार के गरीबी उन्मूलन के मंतव्य को दर्शाता है। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार करने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की प्रतिबद्धता और कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने से वर्षों से उपेक्षित किसान और गांव खुशहाली की ओर बढ़ेंगे।

भारत में अधिकतर वर्षा जल आधारित कृषि की जाती है। इससे कृषि असुरक्षित रही है। इसका हल निकालने के लिए इस सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाने तथा हर खेत को पानी का संकल्प से कृषि क्षेत्र में समृद्धि आ सकती है। इससे हमारे देश में पुन: हरित क्रांति लाने का श्रेय इस सरकार को दिया जा सकता है।

सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से "हर हाथ को हुनर" के द्वारा युवाओं को रोज़गार दिलाने और उनका राष्ट्र के विकास में सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। उसी तरह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाने की बात कह बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं का संकल्प लिया हैं इससे देश में महिलाओं को सम्मान प्राप्त होगा और कन्या भ्रूण हत्या से निज़ात मिलेगी। सरकार ने अभिभाषण के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी आस्था जताकर उनके विकास और समृद्ध अविर्भाव के लिए प्रयासरत रहने का संकल्प लिया है।

पिछली सरकार के समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी। इससे लोग हलकान हो चुके थे। इस सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, इसके लिए आगे हर संभव प्रयास करेगी, यह विश्वास भी व्यक्त किया जा रहा है। महंगाई को कम करने के लिए अगर सरकार ने वस्तुओं तथा दवाइयों के उत्पादनों पर उनका उत्पादन मूल्य तथा मुनाफा मुद्रित करने की बाध्यता को लागू किया तो यह उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। इनकी मुनाफाखोरी खत्म होकर यह वस्तुएं आम आदमी के दायरे में आ सकती हैं, सरकार इस सुझाव पर उचित कदम उठाये ऐसा आग्रह करता हूं।

आज देश में सिंचाई की विषमता निर्माण हो गयी है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 95 प्रतिशत तो महाराष्ट्र समेत दक्षिणी राज्यों में सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है। महाराष्ट्र में केवल 19 प्रतिशत सिंचाई है। इससे यहां के किसानों के खेतों में उत्पादन औसत से कम होता है और सरकार द्वारा लागू किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य से उनके कृषि उत्पादों की लागत भी नहीं निकलती इसलिए सरकार लागत मूल्य के अनुसार जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की नीति बनाये ऐसा मैं अनुरोध करता हूं।

इसी तरह अभिभाषण में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिये सिंचाई को बढ़ावा देने का वादा किया गया है, इसके साथ अगर सिंचाई के लिए एक राष्ट्रीय कोष बनाया गया तो स्थिति और भी बेहतर बनायी जा सकती है। विदर्भ क्षेत्र में हज़ारों की तादाद में ब्रिटिशकालीन मालगुज़ारी तालाब हैं, इसके देखभाल के अभाव में यह नष्ट होने की स्थिति में है। इसे पुनर्जीवित देने के लिए केन्द्र सरकार पहल करें तो विदर्भ के किसानों को सिंचाई का एक बड़ा साधन उपलब्ध हो सकता है। सरकार को इसे अपनी प्राथमिकता में शामिल करना चाहिए, ऐसा मैं अनुरोध करना चाहता हूं। सरकार ने "सबका साथ-सबका विकास" की नीति अपनाई है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहा जाता है, के आज के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अधिकारिक रूप से 1930 में जनगणना के बाद ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। पिछली सरकार ने ओबीसी जनगणना करने का लोक सभा में किया वादा नहीं निभाया, मैं इस सरकार से ओबीसी जनगणना कराने का भी अनुरोध करता हूं।

गांधी जी ने गांव की ओर चलो तथा स्वावलंबी ग्राम की संकल्पना बनायी, लेकिन आज गांव उजड़ते जा रहे हैं और शहर बुनियादी सुविधा देने में अक्षम हैं। ऐसे समय हम ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक व्यवसाय जिसे हमारे यहां बारा बलुतेदारी कहा जाता है, उसका संरक्षण करने की जरूरत है। गांवों के कुम्हार, बढ़ाई, राजमिस्त्री, लुहार, चमार, बनुकर जैसे परम्परागत व्यवसायों को आधुनिकता प्रदान कर नये प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास के द्वारा छोटे उद्योग इकाइयों के माध्यम से पुनर्जीवित कर हम गांवों में बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए परम्परागत व्यवसायों के संरक्षण के लिए नई प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के कार्यक्रम सरकार को चलाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसे अपनी प्राथमिकता में शामिल करेगी।

उसी तरह कृषि उत्पादों को लागत मूल्य का फायदा किसानों को हो, इसके लिए कृषि उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगाना उचित नहीं। इसे आयात-निर्यात से मुक्त रखना चाहिए। उसी तरह किसानों को सब्जी और फल बाहर बेचने की अनुमति के लिए कृषि उत्पाद मंडी समिति कानून

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

(एपीएमसी) में उचित बदलाव करने की आवश्यकता है। आज देश के अविकसित क्षेत्र में भारी कुपोषण और रक्ताल्पता दिखाई देती है। जनजातीय क्षेत्र में बच्चों तथा महिलाओं में व्याप्त कुपोषण और रक्ताल्पता के विरुद्ध लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का गठन करने तथा पौषक तत्वों को पारम्परिक भोजन में शामिल करने के नये तरीके इज़ाद करने चाहिए।

इस सरकार को जनता ने भारी बहुमत देकर इस पर विश्वास जताया है। इसे सार्थक करने के लिए सरकार संकल्पकृत है, यह अभिभाषण के द्वारा दिखाई देता है। लोगों के जीवन में विकास की बयार बहाने के लिए कृतसंकल्प सरकार को धन्यवाद देता हूं। अभिभाषण के द्वारा जनता में जो विश्वास पैदा हो गया है, उस पर हम खरा उतरेंगे यह कहते हैं, सरकार को पुन: धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल (मिर्जापुर) : सभापति महोदया, मैं आपका अभिवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा सदन में पेश किए गए और श्री रामविलास पासवान द्वारा उसका अनुमोदन किए गए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने विचार रखने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं अपनी पार्टी अपने दल की ओर से इस चर्चा में हिस्सा ले रही हूं।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने नौ जून को संसद के केन्द्रीय कक्ष में अभिभाषण दिया था। राष्ट्र के भविष्य और गरिमामय गौरव को लेकर उम्मीदों एवम् आशाओं से भरे हुए अभिभाषण के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। मुझे खुशी है कि सरकार ने देश के 125 करोड़ भारतीयों को विकास और खुशहाली की राह पर ले जाने के संकल्प को इस अाभिषण में प्रस्तुत किया है।

मैं अपने विचारों को अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर और अपने राज्य उत्तर प्रदेश तथा पिछड़ी और दलित जातियों की चुनौतियों पर ही केन्द्रित रखते हुए अपनी बात कहना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। जहां यदि युवाओं की बात की जाए तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां के युवाओं के पास रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर नहीं हैं। जिसके कारण उन्हें अपने राज्य से पलायन करते हुए अन्य राज्यों की ओर उन्मुख होना पड़ता है। इससे वे अपने परिवार से दूर रहने की पीड़ा को सहन करते हैं, साथ ही हमारे बहुत से युवा रोजगार के अभाव में आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त होते हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के विशेष इलाकों में ज्यादा विकसित होती हैं जैसे कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड। मेरा मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र भी पूर्वांचल में आता है और अक्सर ऐसी परिस्थितियां वहां देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की जनता को सिर्फ वोट-बैंक के रूप में तमाम राजनैतिक दलों और सरकारों द्वारा इस्तेमाल होता आया है। लेकिन इस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वह अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए कारगार योजनाएं बनाएगी और विशेषकर युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कराएगी, जिससे कि उन्हें अपने राज्य से पलायन करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता को वोट-बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया और सोच है उस पर हमेशा-हमेशा के लिए पूर्ण-विराम लगेगा।

हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी जिक्र किया है जिसका उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई के पर्याप्त साधनों का अभाव है। यहां तक कि मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र जो पूर्वांचल में आता है वहां भी सिंचाई के साधनों का जबर्दस्त अभाव है जिसके चलते खेती के उत्पादन का नुकसान होता है और मैं इसे सिर्फ किसानों की हानि के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र की हानि के रूप में भी देखती हूं। मेरी सरकार से अपेक्षा है कि विशेष करके पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सिंचाई के साधनों को मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से इस क्षेत्र को लाभान्वित किया जाए।

बिजली का संकट एक ऐसा मसला है जिसे आज पूरा देश जान चुका है। उत्तर प्रदेश मं यह संकट गंभीर है। गांव में आज भी चार या पांच घंटे से ज्यादा और शहरी इलाकों में आठ या दस घंटों से ज्यादा बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती हैं महामहिम महोदय के अभिभाषण में राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का उल्लेख किया गया है जो अपने आप में एक महत्वाकांक्षी कदम है और मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़े इलाकों में इस ऊर्जा नीति की झलक का प्रभाव देखने को मिलेगा और एनडीए सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की जनता बिजली आपूर्ति के सुख का अनुभव कर सकेगी।

अभिभाषण में देश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं की भी बात की गयी है तथा 50 टूरिस्ट सर्किट्स बनाने तथा तीर्थाटन को बढ़ाने का विशेष उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में भी मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में और विशेषकर मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे तमाम स्थल हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं और जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाया जा सकता है। मिर्जापुर को इस देश के राजस्व में योगदान करने का एक अवसर मिल सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि 50 टूरिस्ट सर्किट्स बनाने का जो सरकार का संकल्प है उसमें उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल में विशेषकर मिर्जापुर का ख्याल रखा जाएगा।

राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय की है जिसे इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आज तक उनके हक, भागीदारी और सम्मान के नाम पर सिर्फ उनकी भावनाओं के

साथ खिलवाड़ हुआ है, उनका शोषण हुआ है। सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन वंचित जातियों तक पहुंचाना अति-अनिवार्य है जिससे उनके भरोसे को हमेशा के लिए कायम किया जा सके। मिर्जापुर में भी लालगंज और हलिया जैसे इलाके हैं जहां पर आदिवासी समाज की एक बड़ी आबादी रहती है जो विकास की धारा से वंचित है। सरकार से मैं अपेक्षा करती हूं कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने का सरकार द्वारा ईमानदारी से प्रयास होगा। हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, मैं समझती हूं कि वह एक ऐसे आयोग के रूप में है जिसकी कोई अपनी न्यायिक शक्ति नहीं है और वह अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है क्योंकि अभी कुछ भी दिन पहलू बदायूं में दो पिछड़ी जाति की बच्चियों के साथ जो अमानवीय घटना हुइर्अ उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का हस्तक्षेप होना चाहिए था और यदि उनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां होतीं तो निश्चित रूप से उन बच्चिों के परिवारों के साथ न्याय होता। न्यायिक शक्तियों के अभाव में न उचित हस्तक्षेप हुआ और न अभी तक इस परिवार को न्याय मिल पाया है। न्यायपालिका में भी सामाजिक विविधता की झलक देखने को नहीं मिलती है। मेरा सरकार से कहना है कि न्यायिक आयोग बनाने की विशेष आवश्यकता है। दलित और पिछड़ी जातियाके के योग्य उम्मीदवार भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जज की कुर्सियों पर नहीं बैठ पाते हैं। यह बहुत हैरानी की बात है कि जिला जज बनने के लिए पीसीएसजे और हायर ज्यूडिशियरी सर्विस एग्ज़ाम उत्तीण करना होता है, जबकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जज के लिए कोई न्यायिक आयोग नहीं है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि न्यायिक आयोग का शीघ्र गठन हो, ताकि हमारी न्यायपालिका में भी सामाजिक विविधता की झलक देखने को मिले।

हमारे केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय ये भी तमाम विसंगतियों का विशर हो चुके हैं। पिछड़ा वर्ग आरक्षण ठीक तरीके से दोनों विश्वविद्यालयों में लागू नहीं हो पाया है। जेएनयू में एमफिल और पीजी में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली पिछड़ी जाति के छात्रों को साक्षात्कार में शून्य अंक या बहुत कम अंक दिए जाने के कई उदाहरण मौजूद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछड़ी जाति के छात्रों का बैकलॉग जो वर्ष 2013 में लागू किया जा रहा है, जबकि यह वर्ष 2007 से ही मान्य है। अगर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की यह हालत है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। कई सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश के वंचित समाज के साथ न्याय किया जाए और उन विसंगतियों का संज्ञान लेते हुए सरकार इनका तुरंत निवारण करे।

आधी आबादी के विरुद्ध हिंसा के प्रति जीरो टोलरेंस यानी बिल्कुल सहन न करने की नीति अपनाने की बात भी बहुत ही सुखद है। इस संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि गरीब परिवारों से वंचित जातियों से आने वाली बच्चियों और महिलाओं के साथ ऐसी अधिकतम दुष्कर्म की घटनाएं शौच के लिए जाते समय घटित होती हैं। सरकार से मैं उम्मीद करती हूं कि शौच सुविधाओं का ग्रमीण एवं गरीब शहरी बस्तियों में निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम अपनी आधी आबादी को कुछ और नहीं तो कम-से-कम उनकी आबरू और उनके सम्मान की हिफाजत सुनिश्चित कर सकें।

सभापति जी, मैं जिस इलाके से चुन कर आती हूं, वह बेहद गरीब है, पिछड़ा है और मैंने अपने इलाके की जनता के दर्द को देखा है और उन्हीं के दर्द को उन्हीं के शब्दों में बताना चाहती हूं कि आज हर गरीब जो उत्तर प्रदेश राज्य में रहता है वह यही कह रहा है कि "जो उलझ कर रहे गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है कि किस तरह से खो गई, गरीब की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। जिन नीतियों ने छोड़ दिया गरीब को उसके हाल पर, ऐसी नीतियां न बना दे संसद इस हॉल में।" देश की गरीब जनता का यही दर्द है जो मैंने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। मैं उम्मीद करती हूं कि नई सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो हमारे पिछड़े तबके हैं, उनके विकास के लिए भी सरकार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें पूरी मजबूती के साथ लागू भी किया जाएगा।

[अनुवाद]

***श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम** (जामनगर) **:** यह हमारे देश के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण हैं। करीब 30 वर्ष के अंतराल के पश्चात्, इस देश के लोगों ने एक राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचंड जनादेश दिया है। इस देश के लोगों ने श्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी में विश्वास और उम्मीद जताई है। उन्होंने एक संगठित, सुदृढ़ और आधुनिक भारत के पक्ष के लिए मतदान किया है। "एक भारत – श्रेष्ठ भारत" और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों को दोहराते हुए .... भारत जीता है।

यह प्रचंड जनादेश लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी हममें से हर किसी पर डालता है। आशा करते हैं कि आने वाला कल उन्हें रोजगार दिलाएगा, वो भूखे नहीं सोएंगे, वे आंतरिक और बाहरी हमलों दोनों से सुरक्षित होंगे, स्वच्छ पेयजल तक उनकी पहुंच होगी, उनकी मां, बेटियां और बहनें सम्मान और गरिमा से घूम सकेंगी और लाखों अन्य आकांक्षाएं हैं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण, नई सरकार के दृष्टिकोण और रूपरेखा को परिलक्षित करता है। यह सबके उत्थान विशेषत: गरीबों के लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं की बात करता है। सुशशसन के जरिए विकास

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नई सरकार का उद्देश्य है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा "सबका साथ – सबका विकास" नारे पर जोर दिया है।

हमारी अर्थव्यवस्था में गत कुछ वर्षों से गिरावट हो रही है। निर्यात-आयात परिदृश्य निराशाजनक है। रोजगार क्षेत्र की कहानी दु:खद है। मंहगाई लगातार बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर वापस लाना इस सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। सरकार ऐसे नीति परिवेश को निर्मित करेगी, जो अनुमानयोज्य, पारदर्शी और निष्पक्ष हो। यह माल और सेवा कर को लागू करने का हर संभव प्रयास करेगी।

मैं, इस सरकार के हमारी महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित रखने के वायदे को इंगित करना चाहूंगी। अपने मंत्रिमंडल में सात महिला मंत्रियों को चयनित कर और इस सभा हेतु महिला अध्यक्ष नियुक्त कर इस सरकार ने हमारे समाज को एक मजबूत संदेश दिया है, यह सरकार संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रपति जी ने अपने पहले ही अभिभाषण में "बेटी बचाओं – बेटी पढ़ाओ" की हमारी प्रतिबद्धता को इंगित किया है। कन्या भ्रूण हत्या एक घिनौना अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या का मूल कारण इस देश की सामाजिक आर्थिक नीतियों सहित सांस्कृतिक कारण भी हैं। की जिम्मेदारी कन्या भ्रूण हत्या में सम्मिलित अधिकांश लोग जाने-अंजाने में इस बात को भूल जाते हैं कि अभिभावकों के मृत्यु के पश्चात् विपदा आने पर घर चलाने के लिए कोई नहीं होता। भारत में, प्रत्येक बितते दशक के साथ प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या घर रही है। क्या महिलाओं की संख्या में असंतुलन सचमुच चिन्ता का विषय है? हां सचमुच। यह अंतर देश के राजनीतिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से विकास हेतु अहम सिद्ध हो सकता है।

हमारी सरकार – प्रत्येक घर में शौचालय प्रदान करेगी – एक ऐसा उपाए जो महिलाओं की सुरक्षा में काफी सुधार करेगा। यह सरकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को सहन नहीं करेगी और भारत में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। हम अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए सम्मान और सुरक्षा का जीवन सुनिश्चित करेंगे। जो दूसरा मुद्दा मैं इंगित करना चाहती हूं, वह कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधारों से संबंधित है। हमारे दो-तिहाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और हमारे अधिकतर लोगों की आय की मुख्य स्रोत कृषि हैं। भारत की जीडीपी में कृषि का आर्थिक अंशदान देश की व्यापक आर्थिक वृद्धि के साथ निरंतर घट रहा है। अभी भी जनसांख्यिकीय आधार पर कृषि सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है और भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विगत में हमने किसानों को निराशा की स्थिति के कारण आत्महत्याएं करते देश है। अनेक अध्ययनों ने महत्वपूर्ण कारकों की पहचान की है जैसे सरकारी सहायता को बंद करना, अपर्याप्त या जोखिम ऋण प्रणाली, अर्थ-शुष्क क्षेत्रों में कृषि करने में कठिनाई, कम कृषि आय, वैकल्पिक आय अवसरों की अनुपस्थिति और उपयुक्त परामर्शी सेवाओं की अनुपस्थिति। यह सरकार कृषि क्षेत्र और वैज्ञानि प्रक्रियाओं में निवेश बढ़ाकर, मूल्य निर्धारण और खरीद प्रक्रिया को सुकर कर, फसल बीमा लागू कर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कर कराई उपरांत प्रबंधन द्वारा हमारे किसानों में विश्वास बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदया, मुझे विश्वास है कि यह सरकार दूसरी हरित क्रांति लाएगी, जो हमारे किसानों को अपेक्षित खुशी प्रदान करेगी।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी बल दिया है। द्वारका, जोकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, एक ऐसा ही स्थान है, जिसमें विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इस मंदिर नगर के विकास के लिए वायु संपर्क, पर्याप्त होटल अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार काफी उपयोग सिद्ध होंगे।

मेरा अंतिम मुद्दा देश में एमएसएमई की स्थिति से संबंधित है। मैं गुजरात के जामनगर जिले से आती हूं, जोकि भारत के पीतल उद्योग का घर है। जामनगर के पीतल, उद्योग की 4500 से अधिक इकाइयां हैं; जो 1,50,000 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं। उद्योग अन्य एमएसएमई के साथ अनेक दैनिक प्रचालनों में समस्याओं से घिरा है अर्थात् इनके उत्पादों का उत्पादन और विपणन। उन्हें अपने निर्माण को लाभकारी मूल्यों में बेचना कठिन हो रहा है क्योंकि विज्ञापन, विपणन अनुसंधान इत्यादि पर वे अत्यधिक व्यय नहीं कर सकते। उन्हें अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं और ऋण तक पहुंच की कमी के जैसी मुख्य समस्याओं के अतिरिक्त बड़ी फार्मों, से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। एमएसएमई को मशीनरी, उपस्कर और कच्चे माल सहित दैनिक व्यय के वहन के लिए खरीद हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में प्राय: कठिनाई होती है। हमें इसे बदलने की आवश्यकता है। भारतीय विनिर्माताओं को मूल्य में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सभी प्रकार के फेरस और गैर-फेरस कचरा सामग्रियों के आयात पर 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क की समाप्ति, कर लाभ आसियान रेशों से आयात के लिए समान स्तर प्रदान करना, और आधुनिक प्रौद्योगिकी समय की मांग है। हमें सभी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है या अन्यथा हम इस उद्योग को हमेशा के लिए खो देंगे।

मुझे पूरा विश्वास है कि परिवर्तन का युग प्रारंभ हो गया है। निराशा से आशा का परिवर्तन होगा। इस उम्मीद को श्री नरेन्द्रभाई मोदी जो के विज़न द्वारा लगाया गया हैं एक ऐसी आशा जो प्रत्येक भारतीय के चेहरे पर मुस्कराहट लाएगी। संतुष्टि, सम्मान और मर्यादा की मुस्कान। और वह मुस्कराहट हमारा रिपोमर्ट कार्ड होगा और विश्वास कीजिए कि हममें से प्रत्येक इस परिवर्तन को प्राप्त करने में प्रत्येक मिनट मेहनत करेगा।

श्री सुरेश चन्नाबसप्पा अंगाडी (बेलगाम) : महोदया, मैं अपने मित्र, श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा प्रस्तुत और माननीय मंत्री, श्री रामविलास पासवान द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, इस देश को वास्तविक रूप में पिछले महीने 16 मई को ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई है क्योंकि यदि आप याद करें तो 1947 में बिनरा किसी जनादेश के केवल सत्ता अंतरण हुआ था। कांग्रेस ने अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त की थी। यह नई बोतल में पुरानी शराब के जैसे ही था। इस देश के लोगों ने जाति, पंथ और अन्य चीजों को परे छोड़कर देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी को वोट दिया है। इस देश के युवा को उनमें विश्वास है।

कांग्रेस ने 1947 में अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त किया था। सत्ता प्राप्त करने के पश्चात् भी, उन्हीं नियमों और विनियमों का अनुसरण किया गया। 65 वर्षों के शासन के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति का प्रयोग करते हुए इस देश का शासन कर रहे थे। उन नियमों को आज भी अपनाया जाता है। समाज में दलित, मुसलमान और अन्य कई विभाजन किए गए और ये विभाजन आज भी विद्यमान हैं। किन्तु इस बार भारत के लोगों ने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में *एक भारत, श्रेष्ठ भारत* के लिए मत दिया। आज, हमें वास्तविक लोकतंत्र प्राप्त हुआ है।

मुझे यह कहते हुए गर्व भी हो रहा है कि अभी भी हमें इस सदन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का अधिनियमन करना है। यदि कोई इतिहास नहीं पढ़ सकता तो, वह इतिहास नहीं गढ़ सकता है। कर्नाटक में भगवान बसवेश्वर बारहवीं सदी में प्रत्येक व्यक्ति के लिए लोकतंत्र लेकर आए थे।

अल्लामाप्रभु अनुसूचित जाति समुदाय से थे। वे अपने समय के अंबेडकर माने जाते थे। उन्होंने उस समय महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था किन्तु हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 66 वर्ष बीत जाने के बाद अभी भी विधान मंडलों में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : महोदया, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 352 (सात) के अंतर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सभापति : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री गौरव गोगोई : माननीय सदस्य बोलते समय देशद्रोहात्मक, राजद्रोह अथवा निन्दात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माननीय सदस्य कांग्रेस पार्टी की तुलना औपनिवेशिक सरकार से की है। माननीय सदस्य को इतिहास याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने कई सदस्यों की प्राणों की आहूति दी है और कांग्रेस पार्टी की तुलना औपनिवेशिक सरकार से करना निन्दात्मक है, यह देशद्रोहात्मक है। अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने शब्दों को वापस लें।

माननीय सभापति : इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री सुरेश चन्नाबसप्पा अंगाडी : मैंने इस इरादे से नहीं कहा है। मेरा तात्पर्य यह था कि जो नियम और कानून आज विद्यमान हैं यथा आईपीसी या अन्य कोई कानून, ये नियम और कानून हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल में ही बने थे। आज भी हम उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल अभी संदर्भ में मैंने ये टिप्पणियां की थीं। मेरा उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया है। मैं भी उनमें से एक हूं। हमारे नेता ने भी कहा है– *[हिन्दी]* जो पिछली सरकार ने अच्छा काम किया है, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और जो काम खराब है, उसके बारे में हम सोचेंगे। *[अनुवाद]* मेरे नेता ने यह स्पष्ट रूप से यह कहा है कि पिछली सरकार ने जो भी अच्छा कार्य किया है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। *[हिन्दी]* इस देश में जो डिवाइड एंड रूल इतने साल में किया है, वह कांग्रेस वालों ने किया है। मैं यह बोलना चाहता था। *[अनुवाद]* लेकिन इतने दिनों में रीजनल पार्टीज, थर्ड-फ्रंट, फोर्थ-फ्रंट, मुस्लिम लीग यह सब कांग्रेस वाले करते थे। किन्तु इस बार इस देश के लोगों, विशेषकर इस देश के युवा ने, इस सबके बावजूद, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के लिए मतदान दिया है। उन्होंने कहा कि हम देश को आगे ले जाएंगे। *[हिन्दी]* अभी बहुत-बहुत काम बोल रहे हैं कि इतना वह काम करो, ऐसा कह रहे हैं। जो 65 वर्षों में काम नहीं हुआ है, वह काम पांच साल के अंदर कैसे कर सकते हैं *[अनुवाद]* उन्होंने कहा कि 125 करोड़ लोगों के साथ वे आगे बढ़े सकते हैं। *[हिन्दी]* एक पांव हम आगे बढ़ाएं तो बहुत काम हो सकता है लेकिन हम एक ही दिन में सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। *[अनुवाद]* उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मेरे देश के लोगों को सर्वप्रथम नागरिक सुविधाएं प्रदान करेंगी। *[हिन्दी]* अभी भी गांवों में शौचालय, टॉयलेट्स हमारी महिलाओं के लिए बनाने हैं, वह काम हम पहले पूरा करेंगे। गंगा स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ भारत करेंगे। अभी जिस नगर में हम रहते हैं, *[अनुवाद]* नगर नरक बन चुके हैं। कई समाचार पत्रों में यह समाचार छपी है। शहरीकरण के कारण स्थिति नारकीय हो गयी है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? *[हिन्दी]* आज किसी शहर में जाते हैं तो पूरी गंदगी दिखती है। किसी भी विलेजे में जाएं तो, विलेज स्वच्छ है। आज हमें पूरा स्वच्छ और श्रेष्ठ भारत करने में कामयाब होना है। मेरी विनती है कि भारत के जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता के पूर्व से भी इस देश में स्वतंत्रता लाने के लिए कर्नाटक से जो आए हैं, मुझे गर्व महसूस होता है। *[अनुवाद]* बारहवीं शताबादी में

उन दिनों बासवेश्वर ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया था। अभी भी काम करो और सब बांटकर खाओ। बासवेश्वर ने उन दिनों भी समाजवाद को अपनाया था। तद्नुसार ही, आज उसी सिद्धान्त को संसद में लागू किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, मेरा संसदीय क्षेत्र बेलगाम है और मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार वहां आईआईटी और आईआईएम की स्थापना करे। मेरा संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से घिरा है। यहां पर लोग कम-से-कम चार भाषा बोलते हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार मेरे संसदीय क्षेत्र आईआईटी और आईआईएम को शुरू करें।

इसके अतिरिक्त, हमारे देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या शुद्ध पेयजल की उपलब्धता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे सभी गांवों और शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया करे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। इस संबंध में मैं माननीय भारी उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र में कतिपय बड़े सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना करें ताकि रोजगार प्रदान किये जाएं। इसलिए उन्हें रोजगार के लिए मुंबई या अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इसके लिए प्रावधान करें।

पिछले कई वर्षों से हमारी रेल परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। बेलगाम के एक ओर बंगलौर है और दूसरी ओर मुम्बई है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे बुलेट ट्रेन या फास्ट ट्रेक ट्रेन से बेलगाम को रेल कनेक्टिविटी प्रदान करें। इसी के साथ, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे क्षेत्र के लोगों की सहायता करें। यहां अधिकांश लोग बेरोजगार हैं।

महोदया, एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

***श्री राजेन्द्र अग्रवाल** (मेरठ) सोलहवीं लोक सभा का यह प्रथम सत्र है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार का राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के रूप में यह प्रथम नीति वक्तव्य है। इस लोक सभा में यूपीए-2 की सरकार चलाने वाली कांग्रेस के पचास से भी कम सदस्य हैं तथा एनडीए की इस सरकार के प्रमुख घटक दल भाजपा के 272 से अधिक सदस्य है। अध्यक्ष जी, इस जनादेश के अनेक अर्थ तथा इसकी अनेक प्रकार से व्याख्या हो रही है। वास्तव में यह जनादेश कांग्रेस के भ्रष्ट कुशासन के खिलाफ तथा श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुशासन दिये जाने के विश्वास के पक्ष में है, यह जनादेश वोट बैंक की जातिवादी व साम्प्रदायिक राजनीति के खिलाफ तथा देश के 125 करोड़ के सम्पूर्ण जन को साथ लेकर चलने के संकल्प के पक्ष में है, यह जनादेश रीढ़विहीन कमजोर नेतृत्व के खिलाफ तथा दृढ़ इच्छाशक्ति सम्पन्न मजबूत प्रधानमंत्री के पक्ष में है। कुल मिलाकर यह जनादेश ऐतिहासिक तथा युग परिवर्तनकारी है। भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश की गुरूता एवं चुनौती को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती है तथा अध्यक्ष जी उस ओर बैठे मेरे कांग्रेस के मित्रों भी मेरा आग्रह है कि ये भी इस जनादेश के मर्म को समझने का साहस दिखायें।

राष्ट्रपति जी ने 16 पृष्ठों के अपने भाषण में सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के लगभग सभी पहलुओं को स्पर्श किया है। मैं उनमें से कुछ पर अपनी बात कहना चाहता हूं।

कृषि हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है इसलिये स्वाभाविक ही हमारे लिए कृषि तथा किसान सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। इस दृष्टि से राष्ट्रपति जी ने खेती को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए अनेक उपायों की चर्चा की है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात कही है। हापुड़ तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन होता है, मेरठ-बागपत-जे.पी. नगर-बुलंदशहर जनपदों में हापुड के चारों ओर फलों की बेल्ट है। यह मेरे क्षेत्र का सौभाग्य है कि किसानों की जीवन भर लड़ाई लड़ने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह का जन्म स्थान मेरे चुनाव क्षेत्र में हापुड़ के निकट नूरपुर मढैया नामक गांव में है। मेरा निवेदन है कि चौधरी साहब की स्मृति में उनके जन्म स्थान पर एक राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र का निर्माण किया जाये ताकि आलू तथा विभिन्न फलों के प्रसंस्करण में किसानों को मार्गदर्शन एवं मदद मिल सके। किसानों को लाभ हो तथा नये रोज़गार का भी निर्माण हो।

राष्ट्रपति जी ने मजबूत बुनियादी ढांचे की कमी को भारत की मुख्य बाधाओं में से एक माना है तथा कहा है कि सरकार एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम तैयार करेगी, हाई स्पीड ट्रेनों की हरिक चतुर्भुज परियोजना शुरू करेगी तथा छोटे नगरों में हवाई सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले हवाई अड्डे बनाये जायेंगे। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेरे संसदीय क्षेत्र का बुरा हाल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की बात थी, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण की बात थी, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की बात थी, परन्तु क्या हुआ? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के गठन को 27 वर्ष हो रहे हैं, परन्तु अभी हाई स्पीड ट्रेन की बातें प्रारंभिक अवस्था में है, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे अभी तक अस्तित्व में नहीं आया, हवाई अड्डा हवा में लटका हुआ है। दिल्ली में नित्य आवागमन करने वालों का 40 प्रतिशत केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश से है, परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का बुरा हाल है। मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों से बात की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तो वे बताते हैं कि क्षेत्र के लिए बनाई गई योजनाओं को राज्य सरकार का समर्थन व प्रोत्साहन नहीं है। बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण मेरठ-हापुड की औद्योगिक प्रगति ठप है। दो-तिहाई इकाइयां बंद हो चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। मेरा अनुरोध है कि मेरठ-हापुड़ के बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ले तथा इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करे।

राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा है कि प्रत्येक राज्य में आईआईटी और आईआईएम संस्थानों की स्थापना की जायेगी। उत्तर प्रदेश में कानपुर में आईआईटी है तथा लखनऊ में आईआईएम है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के युवाओं की जरूरत केवल इन दो संस्थानों से पूरी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक संस्थान चाहिए। मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केन्द्र है, मेरा निवेदन है कि क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से मेरठ में एक आईआईटी या आईआईएम होना चाहिए।

"न्याय में विलम्ब का अर्थ है न्याय न मिलना", अत: बड़ी संख्या में लम्बित मामलों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बहु-आयामी दुष्टिकोण अपनाने की बात कही है। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 45 लाख से भी ज्यादा वादों में से लगभग एक-चौथाई बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सम्बन्धित है। खंडपीठों तथा जजों की कम संख्या के परिणामस्वरूप जिस गति से उच्च न्यायालयों में इन वादों का निपटान हो पा रहा है उससे इन वादों को निपटाने में सौ साल से भी अधिक का समय लगेगा। निर्णय में इतना विलम्ब किसी भी प्रकार से वादी के हित में नहीं है। इसके कारण से न्याय व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास खत्म होता है। वर्षों तक वकील की फीस देने तथा इलाहाबाद आने-जाने व ठहरने-खाने का इंतजाम करने में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वादियों के खेत व मकान तक बिक जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक पहल की जानी चाहिए तथा मेरठ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना की जानी चाहिए।

गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का "भगीरथी" संकल्प अभिनन्दनीय है। इसके साथ ही अन्य नदियों तथा भूजल को भी प्रदूषण मुक्त करने व रखने की आवश्यकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गोवंश सहित पशुओं के अवैध तथा अमर्यादित कटान से जहां पशुधन समाप्त हो रहा है तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध दूध की उपलब्धता घट रही है वहीं प्रदूषित अपशिष्ट को नदियों में डालने अथवा बोरिंग के द्वारा सीधे गहरे जमीन में डालने से भूजल प्रदूषित हो रहा है। यह वास्तव में मानवता के विरुद्ध अपराध है, जिसे प्रभावी ढंग से रोके जाने की जरूरत है।

देश की सुरक्षा संबंधी योजनाओं का राष्ट्रपति जी ने अनेक प्रकार से उल्लेख किया है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि आई.टी. के क्षेत्र में हार्डवेयर उत्पादन की पिछली सरकार द्वारा घोर अपेक्षा होती रही है जिससे देश की सुरक्षा को भी गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। आईटी हाडवेयर के क्षेत्र में हम लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है, जिन मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके प्राय: सारे पुर्जे विदेश से आते हैं। केवल मोबाइल फोनों में ही नहीं, हार्डवेयर के अन्य सभी उपकरणों में चीन का लगभग एकाधिकार बनता जा रहा है। यह बहुत गंभीर विषय है तथा मेरा आग्रह है कि आईटी में हार्डवेयर उत्पादन को सरकार प्राथमिकता पर ले, ऐसे उत्पादनकर्त्ताओं को सरकार प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान करे ताकि हमारा देश भी आईटी हार्डवेयर के उत्पादन में क्रमश: आत्मनिर्भर हो सके।

मैंने कुछ विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम.आई. शानवास (वयनाड) : सभापति महोदया, धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्री रूडी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मैंने दृष्टि और कुछ कार्यक्रमों आदि के बारे में जानना चाहा। दुर्भाग्यवश मैं किसी दृष्टि और किसी नए कार्यक्रम के बारे में नहीं जान पाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में संप्रग के 10 वर्ष के कार्यक्रमों का विस्तार ही देखा गया।

मैं बहुत सारे बिन्दुओं को दुहराना नहीं चाहता। उप-नेता द्वारा पहले ही एक रैंक एक पेंशन के बारे में बताया गया। मैं 'एक रैंक, एक पेंशन' के संबंध में केन्द्र सरकार के एक आदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने फरवरी, 2014 में अपने आंतरिक बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार ने रक्षा बलों के लिए 'एक रैंक, एक पेंशन' को सिद्धांत: स्वीकार कर लिया है। अत: इसे पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। आप किसी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कैसे कर सकते हैं जिसका पहले कार्यान्वयन कर दिया गया है? अधिक से अधिक इतना कहा जा सकता है कि हम कार्यान्वयन प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

अब मैंने उनके भाषण पर गौर किया। चूंकि भाजपा देश में सत्ता में है, मैंने भाषण में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मैंने 'संविधान' शब्द को ढूढ़ा। हम सभी संविधान में विश्वास करते हैं। हम सभी संविधान की शपथ लेते हैं। मैंने 'संविधान' शब्द को ढूंढा। मेरे प्रिय संसदविद् साथियों, 'संविधान' शब्द राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है। इसके पीछे का अंतव्य निहित है?

मैंने भाषण को पढ़ा; मैंने श्री रूडी के भाषण को सुना। इसमें चीन की प्रशंसा की गई है। चीन में लोकतंत्र है ही नहीं। भारत की महानता उनके लिए मायने नहीं रखता। भारत ने कैसे उन्नति की है? 55 वर्षों से

अधिक समय तक इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शासन किया। भारत के की क्या कहानी है?...*(व्यवधान)*

वर्ष 1950-51 में भारत का जीडीपी 9719 करोड़ रुपए था। वर्ष 2008 में जीडीपी 52.28 लाख करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1951 में भारत का निर्यात 606 करोड़ रुपए था और अब यह 8 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 1951 में विदेशी मुद्रा भंडार 1000 करोड़ रुपए से कम था और अब यह 12.3 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 1951 प्रति हजार मृत्यु दर 27.4 और अब यह 7 प्रति हजार है। जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1947 में गरीबी 85 प्रतिशत थी और योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार अब यह 27.5 प्रतिशत है। जब आप वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं तब आपको अतीत का उल्लेख भी करना चाहिए। अतीत का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

अब इस सरकार में क्या हो रहा है? महोदया, सत्ता के गलियारें में कुछ न कुछ गड़बड़ है। माननीय प्रधानमंत्री ने सचिवों की एक बैठक बुलाई तथा मंत्रियों को उस बैठक में भाग लेने नहीं दिया गया। अत: सत्ता के गलियारे से क्या संदेश दिया जा रहा है? संदेश यह जा रहा है: चाहे जो हो, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। यही संदेश माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने साथी कैबिनेट मंत्रियों और नौकरशाही को दिया जा रहा है।

यह शक्ति का केन्द्रीकरण है। शक्ति के केन्द्रीकरण से निश्चित रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को हानि पहुंचेगी। अब भाजपा चुनाव जीत गई है। उनका मानना है कि चुनाव जीतने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया। किन्तु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं करें...*(व्यवधान)* वर्ष 1977 में इंदिरा गांधी की हार हुई थी। उस समय आप सबने कहा था कि कांग्रेस समाप्त हो गई। तीस महीने के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुन: सत्ता में आई।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, उनकी बात में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

श्री एम.आई. शानवास : महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा को लगता है कि हर चीज खत्म हो गई है...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसके अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम.आई. शानवास : महोदया, कृपया मुझे एक मिनट का समय और दें।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एम.आई. शानवास : महोदया, मैं गांधी जी को उद्घृत करना चाहता हूं। गांधी जी ने 'हरिजन' में अपने लेख में – 'महात्मा गांधी – द लास्ट फेज बाई प्यारे लाल' अध्याय बाइस में कहा है:–

> "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है तथा जिसने अहिंसा के तरीके से स्वाधीनता के लिए कई लड़ाइयां लड़ी है, को समाप्त होने नहीं दिया जा सकता। यह राष्ट्र के साथ ही समाप्त हो सकती है।"

कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। कांग्रेस केवल राष्ट्र के साथ खत्म हो सकती है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जब सोनिया जी बोलने के लिए खड़ी होती है तो यह कम-से-कम दस करोड़ लोगों की आवाज होती है। हम कभी समाप्त नहीं होंगे। हम वापसी करेंगे। चिंता न करें? भले ही आप जीत गए हैं, केवल जीत ही मायने नहीं रखती। हिटलर जीत गया था, मुसोलिनी जीत गया था तथा स्टालिन जीत गया था, जीत ही अवश्य नहीं है। मैं सम्मानित सभा में आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सभा में गांधी की तरह जोरदार वापसी करेगी।

***श्री पी.के. बीजू** (अलथूर) : सरकार ने कार्यकाल के प्रारंभ में राष्ट्रपति जी का यह अभिभाषण एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है – क्योंकि इसमें सरकार के कार्यकाल के आरंभ में परिकल्पित लक्ष्य और उद्देश्य कई प्रकार के प्रतिबिंबत होते हैं। लेकिन दु:ख की बात है कि यह वक्तव्य बहुत ही महत्वाकांक्षी है और भाजपा के इस घोषणा-पत्र का प्रतिरूप है जिसमें हमारी जनता से बड़ी-बड़ी बातें की गई थीं। संपूर्ण अभिभाषण लोक-लुभावन उक्तियों से भरा है जिसमें कोई ठोस बात नहीं है, उदाहरण के लिए बिना किसी ठोस रणनीति के 'गरीबी उन्मूलन' की बात झूठी ही साबित होती।

महामहिम राष्ट्रपति, श्री मुखर्जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था "अत्यन्त कठिन चरण" से गुजर रही है और इस पटरी पर लाना सरकार के लिए एक बड़ा कार्य है। लेकिन इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए कोई ठोस रणनीति या रूपरेखा नहीं बताई गई है और वस्तुत: इसका स्वरूप प्रतिक्रियावादी है। यहां पर मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करना चाहता हूं।

यह अत्यन्त सराहनीय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि पर जोर दिया गया है। गरीब किसानों की रक्षा संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

को दुराहते हुए कृषि में अधिक निजी निवेश को भी समान महत्व दिया गया है। यह स्पष्ट: गरीब किसानों की जिंदगी की कीमत पर कृषि के पूर्णत: निगमीकरण की इच्छा दर्शाता है। सरकार कृषि का बिना सोचे समझे निजीकरण करके किसानों को आत्महत्याओं को कैसे रोक सकती है? कृषि के विकास की बात करने के अलावा इस मुद्दे के समाधान की कोई रणनीति नहीं है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रबल रूप से कहा गया है कि "हम अपनी अर्थव्यवस्था को सतत् उच्च विकास पथ पर ले जाने के लिए मिल-जुलकर कार्य करेंगे, **मंगाई नियंत्रित** करेंगे।" यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत की निगरानी किए बिना सरकार मुद्रास्फीति पर कैसे लगाम लाएगी। यूपीए सरकार द्वारा अपनाए गए नई-उदारवादी एजंडा को जारी रखने के नई सरकार के स्पष्ट संकेत के पश्चात् डीजल के मूल्य बढ़ाए गए हैं।

हम अपने देश की सुरक्षा के मामले में संवेदनशील रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति दें – इसका कोई कारण नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या सरकार विदेशी बाजार में लेन-देन को सुगम बनाने के बजाय तकनीक के हस्तांतरण विदेशी कम्पनियों के लिए अनिवार्य बनाएगी।

"फास्ट-ट्रेक, निवेश-हितैषी और स्पष्ट लगाए "पीपीपी तंत्र की नीति" के साथ अवसंरचनाओं में निवेश एक आकर्षक अवधारणा हैं "सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा तंत्र आधुनिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच" के बारे में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। लेकिन रोजगार सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों जो निजी क्षेत्र और पीपीपी मॉडल के कारण पहले ही दांव पर लगे हुए हैं, के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।

अंतत: यही कहना है कि राष्ट्रपति जी का यह बहु-प्रीक्षित और प्रचारित अभिभाषण जो वायदे किए गए हैं उनमें स्पष्ट रूप देखा आशा की बात करने वाली यह सरकार उन काल्पनिक स्वप्नों की बात का अभाव है। "आशाएं" करने लगी है जो भी साकार नहीं हो पाएंगे। इसलिए "न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन" जैसे नारे केवल बाजार के उछाल का प्रश्रय देने के संदर्भ में ही तर्क संगत हैं, न्याय दान में नहीं।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालन्दा) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण जो सरकार का लिखित दस्तावेज होता है, शब्दों का मायाजाल है। हालांकि मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जब भी नई सरकारें आती हैं तो ऐसे ही लोक-लुभावन वायदे किये जाते हैं, लेकिन वे लागू नहीं हो पाते हैं। मगर मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जो वायदे उन्होंने किय हैं, वह उन्हें पूरे करें, अन्यथा इस सरकार का भी वही हाल होगा, जो बाकी सरकारों का होता रहा है। अभिभाषण उम्मीद, आशा और अपेक्षा जगाता है, परंतु इसकी कोई समय-सीमा नहीं है। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आदि ऐसे विषय हैं जो महंगाई बढ़ाते हैं। इसमें राज्यों का सहयोग अपेक्षित है। यह कैसे होगा, इसका जिक्र नहीं है। सबका साथ, सबका विकास तथा सब पिछड़े राज्यों का विकास कैसे होगा, इसका कोई रोडमैप नहीं है।

महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का विकास कैसे हो, इस पर चुप्पी है। चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के नेताओं ने वायदा किया था कि जब एनडीए सत्ता में आयेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और विशेष पैकेज भी मिलेगा। पिछड़े राज्यों के विकास के लिए विशेष पैकेज और पिछड़े राज्य का दर्जा की मांग पर सरकार की खामोशी आज इन राज्यों की बैचेनी बढ़ा रही है। रघुराजन कमेटी ने बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी की मांगा का समर्थन करते हुए कहा था कि बिहार, ओडिशा के बाद सबसे पिछड़ा राज्य है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के दौरान इसकी घोषणा करें, क्योंकि बिहार के 11 करोड़ जनता की जो भावना है, यह मामला उससे जुड़ा हुआ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का जिक्र न होना बिहार के 11 करोड़ जनता के साथ धोखा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर पटना के गांधी मैदान में ही नहीं बल्कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भी ऐतिहासिक रैली की गई थी। बिहार के तमाम लोगों की भावना थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इतना ही नहीं बल्कि बिहार भाजपा के कई नेताओं ने उसका समर्थन भी किया था। महामहिम के अभिभाषण में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का उल्लेख है, हम उसका स्वागत करते हैं। यह योजना बिहार में पहले से लागू है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की लाखों बेटियों को मुफ्त पोषाक, मुफ्त किताब और साईकल दे कर शिक्षित करने का काम किया। महामहिम के अभिभाषण में लोकपाल के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की घोषणा की गई है, जो कि स्वागत योग्य है। यह योजना पहले से बिहार में लागू हैं। तत्कालीन मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी के सफल नेतृत्व की वजह से काफी कारगर हो रही है। भ्रष्टाचार उन्मूलन के अंतर्गत भ्रष्ट अधिकारी जेल गए। उनके मकान को जब्त किया गया। उनके मकान में बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। यह अनूठा प्रयोग है। अभिभाषण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा का कहीं भी

उल्लेख नहीं है। जब कि हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने 450 एकड़ जमीन उपलब्ध करा कर इसे फिर से विकसित करने का काम शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उसे बनवाया जाए ताकि विश्व की धरोहर के रूप में इसे फिर से ख्याति मिले। महामहिम के अभिभाषण में किसानों के उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया है। किसान कड़ी मेहनत करता है। उसे उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। किसान का ध्यान रखने की जरूरत है। बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने 250 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे कर बिहार के किसानों के लिए खुशहाली लाने का प्रयास किया है। मेरी मांग है कि पूरे देश में इस तरह से किसानों के लिए बोनस की प्रथा शुरू की जाए।

महोदया, शहरों के विकास के लिए बात कही गई है कि सौ शहरों को विकसित कर सभी चीज़ों से लैस किया जाएगा। महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि भारत गांवों का देश है, गरीबों का देश है तो गांवों को भी विकसित करने की योजनाएं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों को चकाचौंध बिजली की तरह चमकाय जाए और गांवों को छोड़ दिया जाए। महामहिम के अभिभाषण में रक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिकीकरण की घोषणा की गई है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र नालंदा में राजगीर आयुध फैक्ट्री की स्थापना सन् 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी जी के समय में हुई थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री, नालंदा से सांसद थे। तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार थे। उस समय उसकी शुरुआत की गई थी। सन् 2005 में उसे पूरा होना था लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही उसको चालू करावाया जाए। देश की तरक्की के लिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना अनिवार्य है। इसका जिक्र माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी है। पर्यटन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार सन् 2011 में पर्यटकों का आंकड़ा लगभग 10 लाख पहुंच गया है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी और बोधगया को टूरिज्म सर्कल से जोड़ा जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कौशलेन्द्र जी, कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार : चुनाव प्रचार के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बिहार की जो बंद चीनी मिले हैं, उन्हें खोलने का प्रयास किया जाएगा। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि लगभग 19 बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराया जाए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए। यहां पर बोलने के लिए और भी बहुत वक्ता हैं।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) **:** सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आज आपने इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी की ओर से मुझे बोलने का मौका दिया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पूरे देश की ओर से एक जो सपना दिखाया गया था, उस सपने को कहीं न कहीं उस भाषण के अंदर रखा गया। हर पहलू को छुआ गया। सबसे युवा होने के नाते मैं तो एक चीज कहता हूं कि एक पहलू जो भारत के लिए सबसे अहम है, उसको छोड़ दिया गया। वह पहलू पॉपुलेशन कन्ट्रोल का है। आज के दिन हमारे देश की आबादी 123 करोड़ है और दिन-प्रतिदिन देश आगे बढ़ता जा रहा है। हम बात करते हैं कि चाइना को पीछे छोड़ेंगे। एक चीज में हम चाइना को जरूर पीछे छोड़ सकते हैं, 15 साल बाद जनसंख्या में। 15 साल बाद अगर हमारा देश चाइना से आगे होगा तो जरूर, परन्तु जनसंख्या के विषय में, भारत विश्व में जनसंख्या में प्रथम स्थान पर होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार बड़ी गंभीरता से इस विषय को देखने का काम करे क्योंकि आज हमारे देश को यंगिस्तान कहा जाता है, 60 प्रतिशत लोगों को युवा कहा जाता है। हम बात करते हैं कि प्रोग्रेस लेकर आयेंगे, 100 नये शहर बसायेंगे। जरूर बसाइयें, 100 नहीं 200 बसाइये, मगर पहले पॉपुलेशन पर तो कंट्रोल लाइये, नहीं तो आपको गांव को शहर बनाना पड़ जायेगा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ जायेगी। कहीं न कहीं सपना दिखाया गया कि 100 नये शहर बसाये जायेंगे। वर्ष 2001 के अन्दर चार शहरों को दिल्ली का काउंटर मैगनेटिक सिटी इसलिए बनाया गया कि दिल्ली का जनसंख्या और इंडस्ट्रियल लोड उन पर ले जाया जायेगा। मेरी कांस्टीट्यूएंसी हिसार है, उसको भी चूज किया गया मगर पिछले 13 सालों के अंदर हिसार में केन्द्र की तरफ से कोई निवेश नहीं किया गया। हमारे यूपीए के साभ यहां बैठे हैं। उन्होंने नये काउंटर मैगनेटिक सिटी वर्ष 2011 के अंदर बनाये, जिसके अंदर अंबाला को बना दिया गया। अंबाला के अंदर विकास जरूर शुरू कर दिया गया मगर हिसार को छोड़ दिया गया। कोटा के अंदर विकास रोक दिया गया। जयपुर को काउंटर मैगनेटिक सिटी बना दिया गया। आज जयपुर के अंदर मेट्रो है। मगर जो वर्ष 2001 से काउंटर मैगनेटिक सिटीज हैं, उनको छोड़ दिया गया, तो कहीं न कहीं सरकार उन सौ शहरों के अंदर जो काउंटर मैगनेटिक सिटी पहले बने हैं, उन पर भी थोड़ा विचार-विमर्श करके उनके अंदर भी निवेश करने के बारे में सोचने का काम करे।

मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं जो कृषि प्रधान है। हमारे प्रदेश की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या खेतों के अंदर काम करती है। आज अगर

सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए कोई है तो वह बिजली और पानी का है। दिल्ली के अंदर बिजली की कटौती हो जाती है तो लोग नारे लगाते हैं, बड़े-बड़े टीवी हाउसेज वहां पहुंचकर उनको दिखाने का काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, हारे मुख्यमंत्री जी ने दस साल पहले एक वादा किया था कि हमें जरूर पीछे से बिजली कम मिली, दस सालों में बिजली की आपूर्ति कर देंगे। दीपेंद्र हुडा जी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि अब दस साल का समय हो चुका है। हमारे प्रदेश के अंदर तो *...(व्यवधान)*

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) **:** हरियाणा के किसी भी शहर में बिजली नहीं जाती है।*...(व्यवधान)* आपके समय में जितनी बिजली आती थी, आज उससे दोगुनी बिजली आयी है।*...(व्यवधान)*

श्री दुष्यंत चौटाला : दीपेन्द्र हुड्डा जी आइए, आप दोगुनी लेकर आइए, चार गुना लेकर आइए, मगर जो वादा जनता के साथ किया था, उसे जरूर पूरा जरूर कीजिए। आज 12 थर्मल यूनिट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसमें से 9 थर्मल यूनिट्स बंद पड़े हैं। केंद्र ने उनके विकास के लिए पैसा भेजा है, मगर सरकार आंख-कान बंद करके वहां बैठी है, मात्र प्राइवेट बिजली कंपनियों से बिजली लेने के लिए। हमने बार-बार विधान सभा में मुद्दा उठाया, मगर हमारे विधायकों को निलम्बित कर दिया गया। कहीं न कहीं जो चौ. देवी लाल जी का सपना था कि हर नौजवान, हर किसान, हर जवान सुरक्षित हो और कहीं न कहीं हमारी माताएं, बहनें सुरक्षित हों। आज हमारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मेरी कांस्टीट्यूएंशी के अंदर जब लोक सभा की पोलिंग खत्म होने से काउंटिंग के लिए 35 दिन का समय था, तो उस समय 11 वारदातें हुईं। उन 11 वारदातों में लूट थी थी, डकैती भी थी, गोली भी मारी गयी और रेप के मुकद्मे भी दर्ज किये गये। आज हमारे प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो एक साल के अंदर 1500 किडनैपिंग के मुकदमे दर्ज होते हैं और वर्ष 2005 की बात करें तो यह आंकड़ा 375 हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री दुष्यंत चौटाला जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : दुष्यंत जी, आपका, समय समाप्त हो गया।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण कृपया उन्हें टोकिए मत। यह उनका पहला भाषण है।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला : जहां पानी की बात करते हैं, बड़ा ही सराहनीय फैसला सरकार द्वारा किया गया कि सारी नहरों को जोड़ा जायेगा। सरकार ने बात की कि नहरों को जोड़ा जायेगा। वर्ष 2003 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के हक में फैसला दिया था कि सतलुज यमुना लिंक को जोड़कर हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का पानी दिया जायेगा। मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि सतलुज यमुना लिंक पर भी दोबारा गौर करके जल्द हमारे किसानों के खेती में पानी पहुंचाया जाये। इसके साथ-साथ चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे:—

"हर पेट को सेटी, हर हाथ को काम,
हर सिर पर छह, बाकी सब बात खोटी।"

सरकार ने मुख्य तौर पर ये मुद्दे रखे हैं कि वह हर व्यक्ति को अवास देगी, हर बेरोज़गार को रोज़गार देगी। हम सरकार की इस बात पर सराहना करते हैं, मगर कहीं न कहीं जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, उन पर भी ध्यान देना होगा। आज हरियाणा में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर बड़ी गंभीरता से सरकार को फैसला लेना पड़ेगा दूसरी ओर जहां सरकार पिछले दस सालों में करोड़ों के स्कैम्स में फंसी पड़ी है, जहां हमारे किसानों की हजारों एकड़ ज़मीन कहीं एजुकेशन के नाम पर, कहीं एसईजैड के नाम पर छीनी जा रही है, यहीं केन्द्र सरकार को फैसले लेने पड़ेंगे कि उन किसानों को भी मुआवज़ा दिया जाए।*...(व्यवधान)*

मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री गणेश सिंह (सतना) **:** सभापति महोदय, मैं अपने काबिल दोस्त राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्तुत प्रस्तुत हुआ है, उसके समर्थन में अपनी बात कह रहा हूं।

सभापति जी, हमारे विपक्ष के कई मित्रों को नई सरकार के दृष्टिकोण के बारे में बड़ा आश्चर्य लग रहा हैं चुनाव के समय जब हम लोग गए थे तो देश की जनता के सामने हमने जो वायदे किये थे घोषणापत्र के रूप में, सरकार बनने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उन सारे विषयों का उल्लेख हुआ है, जिन बिन्दुओं को लेकर हम चुनावों में गए थे। हमारे विपक्ष के कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये लोग तो सचमुच में काम करेंगे। वाकयी में लोकतंत्र के भीतर कथनी और करनी में बड़ा अंतर अभी तक देखने को मिला लेकिन पहली बार

ऐसा लग रहा हैं कि जब कोई राजनीतिक दल चुनाव में जो वायदा करके आए और सत्ता में जब पहुंचने का अवसर मिले तो उन सारे मुद्दों को हूबहू सरकार अपने एजेन्डा में ले और उनको कार्यरूप में परिणत करके देश की समस्या का समाधान करे। आज इसमें एक-एक मुद्दे शामिल हैं।

आज़ादी के बाद से पहला नारा रोटी, कपड़ा और मकान का चला था। फिर दूसरा गरीबी मिटाने का नारा आया। अभी जब यूपीए-1 आई थी, तो उसने यही बात कही थी कि हम इन सारी समस्याओं का हल खोजेंगे। जब यूपीए दोबारा चुनाव लड़ने गई तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की, उसको हम सौ दिन में खत्म करेंगे। फिर काले धन के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि एक साल के अंदर हम विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे। हर वर्ष दो करोड़ बेरोज़गार नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। यूपीए के दस साल पूरे हो गए लेकिन एक भी समस्या का हल नहीं हुआ, बल्कि उन समस्याओं को और उलझा दिया गया। आज जब हम इस बात को कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान हर आदमी की, विशेष रूप से गरीब वर्ग की बेसिक जरूरत है।

हमारे देश की आबादी 70 फीसदी गांवों में है गांव में बुनियादी जरूरतों के लिए आज भी लोग परेशान है। उनकी जरूरत पूरी नहीं हुई। लोग रोटी मांग रहे हैं, कपड़ा मांग रह हैं, मकान मांग रहे हैं। खरगे साहब ने कहा कि आपको को पांच साल का अवसर मिला लेकिन आपने 2022 तक का एजेंडा बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबों को काम देने की योजना सबसे पहले आपने शुरू की, इंदिरा आवास योजना आपने शुरू की। एक पंचायत को इंदिरा आवास एक से ज्यादा आज तक नहीं मिला जबकि एक पंचायत के भीतर आवासहीन परिवारों की सैकड़ों की सूची है। दादा ने मांगा था, नहीं मिला। फिर बेटे ने मांगा, पिताजी ने मांगा, उसको भी नहीं मिला।

अपराह्न 3.00 बजे

फिर अब बेटा मांग रहा है, उसको भी नहीं मिला। अब नाती-पोते को क्या 99 साल मकान के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हमारे काबिल मित्र राहुल गांधी जी बुंदेलखंड के दौरे पर गए थे। एक आदिवासी के परिवार में पहुंच गए और वहां देखा कि बहुत गरीबी है। टूटी खाट थी, सूखी रोटी थी और टूटी हुई झौंपड़ी थी। उसको देख कर के स्वाभाविक है कि दु:ख तो होगा ही कि हमारे देश की हालत ऐसी क्यों? इतना प्रोपगेंडा इस को लेकर हुआ, लेकिन शायद वह भूल गए कि हमारी सरकार थी, हमारी दादी जी थी, हमारे पिता जी थे हमारे और भी लोग थे आज आज भी हम सरकार में हैं। यदि ट्राइब्लस को चिन्हित करके उन्होंने उनको आवास देने का काम कर दिया होता, एक पक्का मकान, तो क्या समस्या का हल नहीं हो सकता था? लेकिन आपने नहीं किया। कथनी और करनी में वही अंतर देखने को मिला। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, साढ़े छह लाख गांव के लिए उन्होंने कह दिया कि हम इनको पक्की सड़क से जोड़ने का इरादा रखते हैं। योजना शुरू हो गई। आज देश के सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़े रहे हैं।

अपराह्न 3.01 बजे

[**श्री अर्जुन चरण सेठी** *पीठासीन हुए*]

एक प्रधानमंत्री जब चाहते हैं तो देश के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ देते हैं, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं और सरकार चलाते हैं तो आप एक भी समस्या का हल नहीं खोजते हैं। वह आपके वोटर थे, उस वर्ग के लोग आपके परम्परागत वोटर थे, उनकी गरीबी पर आप हंस जरूर रहे हो, लेकिन जब काम करने का अवसर आया, उसकी गरीबी दूर करने का अवसर आया, तब आप चुप हो गए। आज जब हमारी सरकार यह कहती है कि हम इस काम को शुरू करने वाले हैं और इस काम को हम वर्ष 2022 तक पूरा करके दिखा देंगे तो इसमें तो आपको धन्यवाद करना चाहिए और यह प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। इसमें टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? हमारी सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र भाई मोदी ने कहा कि यह सरकार गरीबों को समर्पित है, यह सरकार युवाओं को समर्पित है, यह सरकार किसानों को समर्पित है और हमने कहा कि हमारे देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अगर किसी का है तो वह गरीब का है। इस बात को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है लेकिन जब आप आते हैं तो कहते हैं कि हमारे देश में उपलब्ध संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यक का है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप दीजिए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा हूं कि आपने दस साल तक शासन किया है औ क्या किसी एक भी अल्पसंख्यक की बुनियादी समस्या का हल अपने किया है तो मुझे बताइए? भाषण देने से और दस्तावेज देने से काम नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, हम लोग वचनबद्ध हैं कि जो वायदे हमने देश के सामने किए हैं, उसको हम पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का इरादा एकदम मजबूत है। हमारी सरकार का इरादा मजबूत है, हमने जो वायदे किए हैं, उनको पूरा करेंगे।

देश के भीतर एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है। आज लोक जरूरत की चीजों के लिए भी परेशान हैं। गांव में आदमी काम के लिए जाता है, आपने मनरेगा चलाया। मनरेगा की हालत यह है कि उसकी वास्तविक रिपोर्ट पढ़ कर देखिए, हम लोगों ने पिछले सत्रों में कइ बार सवाल उठाए थे जब उधर बैठते थे और आपकी सरकार के मंत्री जवाब दे रहे थे, लेकिन वह जवाब सब कागजों पर थे, धरती पर कुछ नहीं हुआ। ईमानदारी की बात है कि मनरेगा में इतना घनघोर

भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं है, घनघोर भ्रष्टाचार हुआ। ...*(व्यवधान)* सवाल स्टेट का नहीं है। आपकी नीतियों में खामियां थीं। योजना इतनी अव्यवहारिक थी, जिससे उसका लाभ लोगों को नहीं मिला और भ्रष्टाचार हुआ।...*(व्यवधान)* कई जगह बहुत गड़बड़ हुई है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

माननीय सभापति : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार गरीबी का पूरी तरह से उन्मूलन करना चाहती है। गरीबी कैसे खत्म हो, इसकी जड़ में जाइए। इसका पूरी तरह से निदान होना चाहिए और इस दिशा में काम शुरू है। लेकिन इन लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने गरीबी हटाने का नारा दिया। गरीबी हटी नहीं तो गरीबों को हटाना शुरू कर दिया। इनके योजना आयोग ने गरीबी के जो मापदंड निर्धारित किए थे कि शहर में रहने वाला परिवार 32 रुपये खर्च करेगा, वह गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : महोदया, मैं वही कर रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र में जो रहेगा, जो परिवार 26 रुपये रोज़ खर्च करेगा, वह गरीबी रेखा से आउट हो जाएगा। यह इनके आंकड़े थे। बड़े-बड़े लोग, बड़े अर्थशास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग के वाइस चेयरमैन थे और वित्त मंत्री भी थे। लेकिन इनको पता नहीं 26 रुपये में कौन सा परिवार आज की महंगाई में अपने परिवार को दो वक्त की रोटी दे पाएगा? शहर के भीतर रहने वाला कोई आदमी अगर 32 रुपये खर्च कर देगा तो वह गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा। इस तरह की गलत नीतियों का परिणाम देश भुगत रहा है। आज हम लोगों को कहना पड़ रहा हैं आज हम कहते हैं कि गांव में हम पानी पहुंचाएंगे, घर में हम लोगों को पीने का पानी देंगे, हम उसको दो वक्त की रोटी देंगे, रहने के लिए मकान देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे। 67 वर्ष आज़ादी के हो गए। बुनियादी जरूरत थी। हम लोग क्यों नहीं कर पाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए तो वे वहीं बात पूरा करना चाहते हैं जो वर्ष 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था और जो समस्या देश की थी, उसी समस्या का हल वे खोज रहे हैं। काश! अगर आप लोगों ने कुछ किया होता तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज नरेन्द्र मोदी की सरकार कोई बड़ा एजेंडा ले कर आती, जो विश्व स्तर का, सबसे ऊंचा एजेंडा होता। लेकिन हमें बुनियादी जरूरतें देश को देनी हैं। यह हम पूरा करने वाले हैं।

महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि एक अनुकूल माहौल देश में बन चुका है और आप सब इस बात से सहमत होने चाहिए कि अब सरकार को काम करने का पूरा अवसर मिल गया है। आप सब उस के साथ चलिए। आप पूरा सहयोग दीजिए, रचनात्मक सहयोग दीजिए। हम लोग जो काम ठीक करेंगे, उसमें हम चाहेंगे कि आपका सहयोग हमें मिले, लेकिन कहीं अगर हम से त्रुटि हो रही है तो निश्चित तौर पर हम आप के प्रस्तावों का स्वागत करेंगे। लेकिन देश विकास चाहता है, हमारी सरकार सुशासन देना चाहती है। विकास करना चाहती है। हर व्यक्ति का विकास, हर क्षेत्र का विकास, सभी तरह का विकास हम लोग कहरना चाहते हैं। इसमें हम लोग आप सब का सहयोग चाहते हैं।

महोदय, अगर आप हमें दो मिनट और वे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गणेश सिंह : महोदय, ठीक है, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) **:** महोदय, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है। सरकार की भविष्य की रणनीति एवं कार्यक्रमों का लेखा जोखा होता है। सम्पूर्ण भारत में एक माहौल बना है कि नई सरकार सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ करेगी। ये इस बात का प्रतीक है। कि सम्पूर्ण देशवासियों को मौजूदा सरकार में भरोसा एवं विश्वास है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि आपने दूसरी सरकारों को साठ साल दिए हैं लेकिन मेरी सरकार को केवल 80 महीने चाहिए। साठ महीने बाद जब हम इस सदन में आएंगे तो अपनी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकारी का रिपोर्ट कार्ड ले कर आएंगे। मेरी सरकार उस समय आपको अपने किए गए वायदे को पूरा करके दिखाएगी। नई सरकार की कार्य संस्कृति का एहसास इसी बात से हो सकता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने शपथ लेने के दूसरे दिन ही प्रात: आठ बज कर चालीस मिनट पर प्रधानमंत्री कार्यालय जा कर काम शुरू कर दिया। किसी भी सरकार एवं उसके प्रधानमंत्री की सरकार का पहला दिन शुभकामनाओं का दिन होता है। लेकिन मोदी सरकार ने शुभकामनाओं की जगह समस्याओं के समाधान का दिन शुभकामनाओं का दिन होता है लेकिन मोदी सरकार ने शुभकामनाओं की जगह समस्याओं के समाधान का दिन निर्धारित किया। प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से निकल करके 9.30 बजे सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। हैदराबाद हाउस की दरो-दीवार कई राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात का गवाह रहा है लेकिन इस बार मेरी सरकार के प्रधानमंत्री की कूटनीतिक सफलता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में न तो कश्मीर के मुद्दे का जिक्र किया और न ही भारत के हुर्रियत नेताओं से मिलने का समय दिया। जबकि नवाज शरीफ के लिए आमंत्रण स्वीकार करना काफी मुश्किल था। सेना, आईएसआई एवं आतंकवादी संगठन का दबाव था इसके बावजूद भी पीएम नवाज शरीफ की बेटी ने ट्विट किया और वहां की जनभावनाओं को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सार्क के राष्ट्राध्यक्षों का दौरा केवल शपथ ग्रहण समारोह तक सीमित नहीं रहा बल्कि उस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता का अवसर ले कर भारत की स्थिति एवं विदेश नीति का भी स्पष्ट संकेत दिया। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन जी कई बार कह चुके हैं कि मेरा दिन कहता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, लेकिन 10 वर्षों में एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। आखिर कहां से भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ता प्रगाढ़ होता। जबकि खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि भारत दौरा उनका ऐतिहासिक रहा तथा अपेक्षा से अधिक सार्थक रहा। उन्होंने श्री मोदी जी को पत्र लिख कर अपनी वार्ता को काफी सफल एवं संतोषजनक कहा। नवाज शरीफ जी ने कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान की वार्ता वहीं से शुरू करेंगे जहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात छूटी थी। दोनों देशों के बीच खड़ी नफरत एवं अविश्वास की दीवार टूट जाएगी।

भाजपा एवं एनडीए सरकार का पहला सप्ताह कार्य संस्कृति, मौलिकता एवं नए विश्वास के साथ शुरू हुआ। सरकार में आने के बार श्री मोदी जी ने पहला फैसला और हस्ताक्षर किए जो उत्तर प्रदेश में रेल दुर्घटना में मृतक परिवार के आश्रितों को प्रति परिवार दो-दो लाख रुपए देने का फैसला किया। हमारी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण फैसला विदेशों में जमा काला धन को वापिस लोने के लिए एसआईटी का गठन करके का निर्णय लिया। नई सरकार के गठन के बाद देश में मजबूत होता रुपया और सोने की गिरती कीमतें इस बात का संकेत हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ महीने पहले 69 रुपए का एक डॉलर था जो अब घट कर 59.19 रुपए एक डॉलर के बराबर पहुंच गया है। जब आयात सस्ता होगा तब कीमतें भी काबू में आएंगी। एसोचेम जो पिछली सरकार में आर्थिक मंदी पर काफी चिंता व्यक्त करती थी, आरोप लगाती थी कि पॉथ्लसी पैरालिसिस हो गया है आज उसी एसोचेम के मुताबिक भारत में साठ अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है। विगत सरकार में विदेशी एवं घरेलू निवेश बंद हो गया था। मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता निवेश है जिसके लिए इनवेस्टमेंट सम्मिट की घोषणा की गइ है। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कम्पनियों ने भारत के व्यापार में काफी निवेश करना शुरू किया है। अनुमान है कि विदेशी संस्थागत निवेशक खुल कर निवेश नई सरकार में करेंगे। लोक सभा के चुनाव की मतगणना 16 मई को हुई। परिणाम में हमारी सरकार को प्रचण्ड बहुमत का संदेश दिया। इसके बावजूद 20 मई को वित्त मंत्रालय ने सैंट्रल एक्साइज एवं कस्टम के 104 असिस्टेंट कमिश्नर एवं 47 डायरेक्टर्स के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। एक बड़े वकील, जो प्रवक्ता भी थे उन्होंने कहा कि रुटीन ट्रांसफर है। जबकि ये हक नहीं सरकार का है। मोदी जी चाहते तो पहले भारत सरकार के सचिवों का स्थानांतरण करते। उन्होंने ऐसा न करके 72 सैक्रेटीज की बैठक बुलाई और स्पष्ट तौर से कहा कि सचिवों को निर्णय लेने की आजादी होगी और अधिक अधिकार दिए जाएंगे। कोई जरूरत हो तो आप मुझसे फोन पर वार्ता कर सकते हैं। ई मेल कर सकते हैं लेकिन जनता एवं सरकार के प्रति जवाबदेही होगी। उन्होंने कहा कि लेस गवर्नमेंट-मोर गवर्नेंस की नीति हमारी सरकार की होगी। इसीलिए चीन में मीडिया ने मोदी जी की तुलना निक्सन से की है। उन्हें दुनिया का छठा मोस्ट फालोड लीडर इन वर्ल्ड ऑन ट्विटर पर उनकी लोकप्रियता मानी गई है। अर्थशास्त्रियों ने माना है कि नई सरकार में ई-कामर्स के विकास से रोजगार के 20 परसेंट अधिक अवसर बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि नई सरकार के कार्यकाल में ऑटो, पर्यटन, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में रोज़गार बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज देश में 90 जिले एमएसडीपी के अंर्तगत आते हैं। जिसमें से उत्तर प्रदेश में 22 जिले आते हैं। उक्त जिलों में अल्पसंख्यक आबादी 20 परसेंट से लेकर 40 परसेंट तक है, फिर भी उस क्षेत्र की जनता ने भी भाजपा के उम्मीदवार को जिताया है। इससे साबित होता है कि अल्पसंख्यकों ने भी भाजपा को वोट दिया है। इसलिए विपक्ष को अब तुष्टीकरण की राजनीति बंद करनी चाहिए। अब विपक्ष को हिन्दू-मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए। आज मोदी जी देश के हर नागरिक को जाति के आधार पर नहीं बल्कि उन्हें भारतीय के रूप में देखते हैं। अब विपक्ष को जातिवाद, तुष्टीकरण एवं साम्प्रदायिकता को बंद करना चाहिए। ऐसे में जिसका कर्म, जिसका धर्म, जिसकी सोच, जिसकी कल्पना, जिसका लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, वह

है श्री नरेन्द्र मोदी जी। हमारी नई सरकार ने पिछली सरकार में 37 जोओएम को समाप्त किया। क्योंकि पिछली सरकार नें किसी चीज को ठण्डे बस्ते में डालना होता तो उसके लिए जीओएम का गठन कर दिया जाता था। नइ सरकार का लक्ष्य एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाना है। मेरी सरकार देश की 125 करोड़ जनता के साथ मिलकर काम करेगी। सरकार गरीबों के लिए समर्पित होगी। इसी के साथ मैं श्री राजीव प्रताप रूडी के द्वारा महामहिम के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्रीमती कमला पाटले** (जाँजगीर-चम्पा) : मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करती हूं।

भारत के आम लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुशासन द्वारा विकास के पक्ष में एकजूट होकर निर्णायक मत दिया है। लोगों को मौजूदा सरकार से भारी अपेक्षाएं हैं। लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरने और उनकी आशाओं को पूरा करने के लिए सरकार "सबका साथ-सबका विकास" सिद्धांत को अपनाते हुए "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" पर काम करने को वचनबद्ध है।

अभिभाषण में सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, दिशाएं दिखाई देती हैं। सारे कार्यक्रमों का लाभ गांव, गरीब किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित देश की 125 करोड़ जनता को मिलेगा। राज्य सरकारें केन्द्र के साथ टीम की तरह काम कर यह लक्ष्य हासिल करेंगी।

आज देश में आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, सरकार आतंरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से कोई समझौता न करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलोरेंस, सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीकी से लैस करके आधुनिक करने, तटीय सुरक्षा के लिए ऑथोरिटी बनाने, घुसपैठ रोकने पर जोर देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के सात जिले नक्सल प्रभावित होने के कारण विकास कार्य प्रभावित है। ऐसे में यहां प्रशिक्षित जवानों की तैनाती, बॉडेर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) की तैनाती आरवश्यक है। प्रदेश के आधे से अधिक जिले नक्सल उग्रवाद से प्रभावित, बीपीएल परिवारों का अनुपात देश में सबसे अधिक, देश का सबसे पिछड़ा हुआ एवं सबसे कम विकसित राज्य होने के कारण सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य को "विशेष राज्य का दर्जा" दिये जाने की मांग करती हूं।

महिलाओं को संसद और राज्य विधान सभाओं में 33% आरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं की प्रतिबद्धता, महिलाओं के प्रति हिंसा को जीरो टोलोरेन्स की नीति के लिए आभारी हूं।

कश्मीरी पंडितों को घाटी में लौटने की योजना, कमज़ोर तबके अल्पसंख्यकों को बराबरी पर लाने की योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का उद्धार करने की सरकार की जो भावना है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में जो कटौती की गई है, उसे यथावत 16% रखने की मांग करती हूं, क्योंकि 2011 की जनगणना में 2% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है।

अभिभाषण में करीब से लेकर अमीर तक सबके लिए कुछ न कुछ है, महंगाई कम करने, जमाखोरी रोकने, कालाधन वापस लाने, भ्रष्टाचार मिटाने, युवाओं की अगुवायी में विकास करने, खेलों को बढ़ावा देने, स्वच्छ भारत विश्व, वनबंधु कल्याण योजना, पंचायती राज सशक्त करने, कृषि में निवेश, देश की नदियों को जोड़ने, हर खेत को पानी, हर राज्य में आईआईटी, आईआईएम की स्थापना, हर हाथ को हुनर, सागरमाला मिशन से पोर्ट को जोड़ने, नेशनल मिशन ऑफ हिमालय, कोर्ट की संख्या दो गुना करने, सभी देशों से अच्छे संबंध, भारतीय भाषाओं को विकसित करने जैसी योजनाओं से निश्चित ही भारतका स्वरूप बदलेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिला जांजगीर-चम्पा में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं 70% से 80% कृषि सिंचित क्षेत्र होने के कारण केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, हवाईअड्डे का निर्माण, कोटमी सुनार मगरमच्छ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिये जाने, विधान सभा क्षेत्र कसडोल-बिलाईगढ़ रेल लाइन सर्वे को रेल बजट में रेल लाइन बिछाने के कार्य सम्मिलित कर आवश्यक धनराशि का प्रावधान करने की मांग करती हूं।

मैं विश्वास दिलाती हूं कि सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ राष्ट्रपति द्वारा घोषित सभी कार्यक्रमों को लागू करेगी।

[अनुवाद]

श्री कादीयाम श्रीहरी (वारंगाल) : माननीय सभापति महोदय, यह मेरा पहला भाषण है, इसके अतिरिक्त, मैं तेलंगाना से हूं, यह एक नव गठित राज्य है जिसे इस सभा के ध्यान की आवश्यकता है। *[हिन्दी]* मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए।

[अनुवाद]

महोदय, माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में वायदा किया है कि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी एवं कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर हेतु एक ईको-प्रणाली लागू करने के लिए कदम उठाएगी। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि वे किस प्रकार से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सामान अवसर हेतु प्रणाली विकसित करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण इस पर मौन है।

सदियों तक सामाजिक आर्थिक भेदभाव झेले जाने के कारण कमजोर वर्गों को समान अवसर नहीं मिल सके हैं। इस वास्तविक को पहचान कर,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारे संविधान ने शिक्षा संस्थानों और लोक सेवाओं में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कतिपय प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कई नीतियां और आरक्षण भी थे जिनका सभी का उद्देश्य समता और विकास लाना था। लेकिन दुर्भाग्यवश, विकास के फल के वितरण में असमानताए अभी भी हमें मुह मिडा रही हैं। इस संदर्भ में हमें कमजोर वर्गों के जीवनयापन के अवसरों में वृद्धि करने के अतिरिक्त उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके उनका सशक्तिकरण किए जाने की हमारी वचनबद्धता को पुन: व्यक्त किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं इस गरिमामयी सभा का ध्यान एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाए जाने के बारे में कटु वास्तविकताओं की ओर दिलाना चाहता हूं। यद्यपि कमजोर वर्गों के बच्चों के स्कूलों में नामांकन की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमीं लाए जाने में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। उच्च शिक्षा में कमजोर वर्गों का नामांकन अभी भी बहुत कम है। गुणात्मक शिक्षा तक पहुंच के संदर्भ में भी, कमजोर वर्गों के बच्चे, विद्यालयों की घटिया अवसंरचना और हमारे सरकारी स्कूलों में गैर-प्रशिक्षित स्कूल अध्यापकों के कारण पिछड़ रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा के अधिकार से भी कमजोर वर्गों के लिए कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है।

मैं सरकार की "बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ" पहल का स्वागत करता हूं जिसका उद्देश्य बालिकाओं को बयाने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए एक जन आंदोलन चलाना है। मैं यह देखकर प्रसन्न हूं कि सरकार इस संबंध में राज्यों से सर्वोत्तम कार्यों को शामिल करके एक व्यापक योजना आएगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैं भूतपूर्व आंध्र प्रदेश से एक सर्वोत्तम उदाहरण देना चाहूंगा जहां हमने एससी, एसटी समुदाय से संबंधित बालिकाओं को बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की थी। पूर्णा नामक एक गरीब आदिवासी लड़की और एक एससी लड़का, जिसका नाम आनंद कुमार है, तेलंगाना के एक ऐसे ही आवासीय विद्यालय से हैं जिन्होंने हाल ही में एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की और एवरेस्ट पर्वत पर सबसे छोटी उम्र के लड़का और लड़की बन कर इतिहास रच दिया। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों का विस्तार करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करे ताकि देश में प्रत्येक ब्लॉक या मंडल में कमजोर वर्गों से संबंधित बालिकाओं के लिए कम-से-कम एक एक आवासीय विद्यालय उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, कमजोर वर्ग सरकार द्वारा चलाए जा रहे चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। अधिकांश कमजोर वर्गों के परिवार निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा वसूली जाने वाली उच्च लागत का भुगतान करके निर्धन हो जाते हैं। हमें इस प्रचलन को रोकने की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कमजोर वर्गों को 'स्वास्थ्य के अधिकार' को गारंटी देने पर विचार करे और निजी या सार्वजनिक चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रकार के इलाजों हेतु कैश लेस सुविधा सुनिश्चित करे।

सरकारी क्षेत्र में रोजगार हेतु आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन में कई कमियां हैं। एससी और एसटी की आरक्षण पर केंद्रीय कानून के लिए चिर लंबित मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008 अभी भी संसद में लंबित है। इस विधेयक को शीघ्रता से पारित करना होगा।

पदोन्नतियों में एससी और एसटी के लिए आरक्षण कानूनी पचड़ों में फंस गया है। संविधान (एक सौ सत्रह) संशोधन विधेयक 2012 जो इन रूकावटों को हटाने हेतु है, अभी भी संसद में लंबित है। हमें इस विधान को बिना और समय गवाएं पारित करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना और जनजातीय उप-योजना नीति एक महत्वपूर्ण नीति है और एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसका उद्देश्य एससी और एसटी के लिए तथाकथित समान अवसर प्रदान करना है। यह नीति एससी और एसटी के विकास की गति में तेजी लाने के लिए योजना संसाधनों हेतु निर्देश देती है ताकि एससी और एसटी के विकास में अन्यों की तुलना में जो अंतर है उसे शीघ्रता से भरा जा सके। यद्यपि अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजाति उप-योजना नीति के वास्तविक कार्यान्वयन का राज्यों और केन्द्र, दोनों में अभाव रहा है। योजनाओं के मूल्यांकन से पता चला है कि कई राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना हेतु एससी और एसटी जनसंख्या की तुलना में पर्याप्त निधियां निर्धारित नहीं की है। अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत आबंटित राशियों को अन्य कार्यक्रमों में विपथित करने के कई उदाहरण हैं। कई वर्षों से, देश में एससी और एसटी, अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक केंद्रीय विधान की मांग कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना पर केंद्रीय विधान लाएगी।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कादीयाम श्रीहरी : मुझे खुशी है कि सरकार दीर्घ लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने करने और 'हर खेत को पानी' उद्देश्य के साथ 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'

प्रारंभ करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों को बदलने में अत्यधिक क्षमता होने के कारण यह सरकार की एक प्रशंसनीय पहल है। भूतपूर्व आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना क्षेत्र ने, तेलंगाना से गुजरने वाली नदियों के जल का प्रयोग करने में भारी अनदेखी झेली है। मैं आपका ध्यान नवगठित राज्य तेलंगाना में दीर्घ लंबित परियोजना प्राणहिता – चेवल्ला की ओर दिलाना चाहूंगा। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए और आगामी 5 वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए।

रेलवे की बात करें तो हमारे मंत्री जी यहां बैठे हैं। हमारा राज्य एक नया राज्य है। इस संबंध में हमें रेलवे के ध्यान की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 में तेलंगाना में एक रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना किए जाने का उल्लेख किया गया है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें और यह देखें कि काजीपेट में रेल डिब्बा कारखाना स्थापित किया जाए। मैं रेल मंत्री से काजीपेट में एक रेल मंडल की स्थापना हेतु परीक्षण करने के लिए भी अनुरोध करूंगा। वर्ष 2012-13 में, यहां पहले ही एक वैगन विनिर्माण इकाई को मंजूरी दी जा चुकी है। मैं रेल मंत्री से इस संबंध में तेजी लाने और इस बजट में कुछ धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करूंगा और वे यह भी देखें कि यह परियोजना आरंभ हो जाए।

[हिन्दी]

***कुंवर भारतेन्द्र** (बिजनौर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं।

पूर्व सरकार द्वारा घोषित किसानों का पिछले वर्षों का गन्ने की फसल का बकाया भुगतान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी गन्ना किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार से आशान्वित हैं कि उनकी फसल की देनदारी सरकार द्वारा अवश्य चुकायी जाएगी।

वर्ष 1950 में पूर्वी पाकिस्तान से आए हिन्दु शारणार्थियों को आज तक मूल निवास पत्र, जाति प्रमाण-पत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। 50 वर्ष से भारत में बसे इन नागरिकों को समस्त भारतीयों जैसे अधिकार दिये जाएं। इनमें से बहुत बड़ी संख्या "नमो शूद्र" नाम की जाति के हैं। विडम्बना है कि इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल रहा। सुनिश्चित, राष्ट्रवादी व परिश्रमी इन नागरिकों को सभी सामान्य अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

गंगा जी के किनारे बसी जनता व किसानों को बढ़ व कटान की समस्या को मुक्त कराया जाए। गंगा जी की धार को नियंत्रित कर लाखों एकड़ कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित कर करोड़ों गरीब किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाए।

उत्तर प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से जाति व सम्प्रदायवाद के ताने-बाने से बुनी सरकारें महिलाओं/कन्याओं पर अत्याचार और दंगों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ है। मेरे क्षेत्र के ग्राम सफदलपुर थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर में तेरह वर्षीय पूनम पुत्री छोटे सिंह की 9.6.2014 को प्रात: 5.30 बजे बलात्कार कर हत्या कर दी गई। 10.6.2014 की मेरे ही क्षेत्र मीरापुत्र में ओमवीर फौजी की प्रात: छह बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओमवीर फौजी हमारी पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष थे तथा पूर्व सैनिक थे। आपकी पीठ से उत्तर प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था और निरंतर बढ़ रहे बलात्कार और हत्याओं पर तत्काल रोक लगाने की हिदायत देने की कृपा करें।

आशा है कि उक्त लिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में सम्मिलित कर सरकार इसका संज्ञान लेगी।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहती हूं कि मैं सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में हूं। उक्त भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का स्पष्ट रोड मैप है। यह देश कृषि प्रधान देश है किन्तु यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। कृषि उत्पाद का सही समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता। इस सरकार ने इसे सुधारने के लिए कदम उठाया है। शहरों में रहने वालों के निवास की स्थिति काफी खराब है। अत: 100 स्मार्ट शहर जिनमें बिजली, पानी, शौच समेत घरों में सभी सुविधाएं हों, का निर्माण किया जाएगा। देश के ग्रामीण इलाकों में घरों में शौच की व्यवस्था नहीं होने के कारण महिलाओं को काफी कठिनाई होती हैं अत: देश के सभी गांवों के घरों में शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य की सेवा में सुधार किया जाएगा तथा देश के सभी राज्यों में एम्स की स्थापना की जाएगा। गांवों सहित पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा अच्छी होगी। देश में एक वार मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। गंगा समेत देश की सभी नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है, अत: गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने का सरकार का कृत संकल्प है।

अत: मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : महोदय, मैं सत्तापक्ष के संसद सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव, जिसका श्री राम विलास पासवान द्वारा समर्थन किया गया है, का विरोध करता हूं। सत्तारूढ़ दल बहुत भारी बहुमत के साथ आया है। मुझे वह बात याद आ रही है जो विन्सटन चर्चिल ने स्वेज नहर संकट के दौरान कही थी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उन्होंने इडेन से कहा, "वापसी करने के लिए यह कितना उत्कृष्ट स्थान है।"

श्री पासवान ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपने भाषण के दौरान कहा कि हम गोदरा का राग क्यों अलापते रहते हैं। मेरे विचार में इस देश के इतिहास में चार ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने इस देश की नींव को हिला दिया। पहली घटना महात्मा गांधी की हत्या थी, दूसरी घटना दिल्ली में सिक्खों का नरसंहार थी, तीसरी घटना बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करना थी और चौथी घटना वर्ष 2002 में गुजरात में हुआ सामूहिक हत्याकांड थी। हम यह नहीं भूल सकते *[हिन्दी]* जिसमें इन्सानियत होगी, वह इन वाकयात को याद रखेगा। जिसमें इन्सानियत जिंदा होगी, वह इन लोगों को, इन खामियों को कभी माफ नहीं करेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री असादुद्दीन ओवैसी : अगर ऐसी बात है तो वह दिन दूर नहीं जब यह सम्माननीय सभा नाथू राम गोडसे को मरणोपरांत भारत रत्न देगी और यदि भारत रत्न नहीं दिय गया तो वीर चक्र देगी।

तीसरा मुद्दा है, मैं प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा हूं...*(व्यवधान) [हिन्दी]* आप अपने भाई को समझाइये। अगर आप बोलना चाहें तो मैं बैठ जाता हूं...*(व्यवधान) [अनुवाद]* मुझे मंजूर है। यदि आप माइक पर कहना चाहते हैं, तो कृपया कहिये। मुझे मंजूर है। *[हिन्दी]* आप माइक पर बोलिये, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। मेरे भाई, आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। आप याद रखिये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए। जब तक सभापति अनुमति नहीं देते तब तक कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री असादुद्दीन ओवैसी : महोदय, मैं मुस्लिम वोट बैंक के इस रहस्य को तोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। आपने इसे खत्म कर दिया हैं मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन इस प्रक्रिया में अपने वही किया है, आपने वही बात दोहरायी है जो मैं कहता आ रहा हूं कि 1950 से हिन्दू वोट बैंक रहा है जिसे आपने अपने पक्ष में किया हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी जीत एक अनर्थकारी जीत है...*(व्यवधान) [हिन्दी]* आप माइक पर बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। ...*(व्यवधान)* मैं बैठता हूं, आप माइक पर बोलिये।...*(व्यवधान)* आप इतना मत पुकारिये, आवाज़ बैठ जाएगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

...(व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : उनके हस्तक्षेप पर राजनीति करने की बजाय उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए कहा जा सकता है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : मुझे आपसे शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने भाईयों को शिक्षा दें। आपने अपने भाई को शिक्षित और नियंत्रित नहीं किया। मुझे शिक्षा मत दीजिए। मेरे बारे में बात मत कीजिए। अध्यक्षपीठ को बताइए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर भारतेन्द्र (बिजनौर) **:** मान्यवर, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

माननीय सभापति : कृपया बैठ जाइए। उनके पास बोलने के लिए केवल कुछ ही मिनट है। कृपया बैठ जाइए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सरकार समावेशी विकास की बात करती है। मैं माननीय सदस्यों से प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं; आप मुझसे घृणा कर सकते हैं। कृपया यह बात समझें कि विविधता और बहुलवाद इस देश की प्रकृति है। इस सम्माननीय सभा में समावेशन कैसे हो सकता है? यहां कितने मुस्लिम संसद सदस्य हैं? ...*(व्यवधान)* मैं इस पर बोलूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री असादुद्दीन ओवैसी]

मैं इस बात पर सहमत हूं कि कश्मीरी पंडितों को श्रीनगर वापस जाना चाहिए। इसके बारे में हम आपसे 2019 में पूछेंगे। मैं चाहता हूं कि उग्रवाद के कारण कुलगाम जैसी जगहों से अपना घर छोड़ने वाले मुस्लिम कश्मीरियों को भी वापस कश्मीर जाना चाहिए।

जहां तक समावेशन की बात है, तो ऐसा क्यों है कि केवल 21 मुस्लिम संसद सदस्य ही निर्वाचित हुए हैं? ऐसा क्यों है कि मैं अभी भी यहां हूं? मैंने श्रीमान मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में विरोध किया और मैं जीत गया। लेकिन समावेशन कहां है? बहुलवाद कहां है? विविधता कहां है? मैं सत्तापक्ष से यह प्रश्न पूछता हूं।

पैरा संख्या 17 में, माननीय राष्ट्रपति ने अल्पसंख्यकों को बराबर का भागीदार बनाने की बात की है। बराबर की भागीदारी कैसे हो सकती है जब कार्यभार संभालने के पहले ही दिन प्रभारी मंत्री कहते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं? क्या मैं यह विश्वास करूं की मंत्री जी को केवल 80,000 पारसियों की देखभाल के लिए मंत्रालय दिया गया है? ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बताते हैं। मुझे इससे अधिकार प्राप्त होते हैं।

मेरा सत्तापक्ष से यह प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों, जिसमें मुस्लिम नहीं हैं और सिक्ख जैसे अन्य अल्पसंख्यक हैं, को दिए गए 4.5 प्रतिशत आरक्षण का क्या होगा? क्या सिक्ख इसे नहीं चाहते? क्या बौद्ध लोगों को यह नहीं चाहिए? क्या ईसाईयों और मुस्लिमों को यह नहीं चाहिए? जब प्रधानमंत्री इस वाद-विवाद पर उत्तर देने के लिए खड़े होंगे, यदि वे देश में समावेशन पर विश्वास करते हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि उनकी सरकार का अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण पर क्या करने का विचार है।

सरकार बराबरी के भागीदार बनाने की बात करती है। अक्षरधाम का निर्णय 16 मई को आया। क्या उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन गृह मंत्री, जो अब प्रधानमंत्री हैं, पर अक्षरधाम मामले में विवेक इस्तेमाल नहीं करने के लिए निदेश जारी नहीं किए थे?...*(व्यवधान)* क्या राज्य सरकार उसके लिए क्षमा मांगेगी? मेरे संसदीय क्षेत्र से एक गौरी सात वर्ष के लिए साबरमती जेल में थे। उन्होंने जो नुकसान उठाया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन ग्यारह वर्षों को कौन वापस लाएगा?

महोदय, मैं आपके समक्ष, ...* एक बेटे की तरह खड़ा हूं। मैं आपके समक्ष ....* के भाई की तरह खड़ा हूं। मैं यहां आपके समक्ष ...* के चाचा के रूप में खड़ा हूं...*(व्यवधान)* क्योंकि गुजरात में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, मैं उन गरीब लोगों के लिए न्याय चाहता हूं। मैं सरकार से उसके बारे में जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

पैरा संख्या 39 में, सांप्रदायिकता को बिल्कुल भी न सहने की नीति का उल्लेख किया गया है। देश में क्या हो रहा है? 16 मई बीजापुर, 16 मई अहमदाबाद, मेवात, अब पुणे में। महाराष्ट्र सरकार कमजोर और रीढ़विहीन है। उन्हें अभिनव भारत पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। दुर्भाग्यवश वे ऐसा नहीं कर सके।

माननीय सभापति : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : महोदय, कृपया मुझे आधा मिनट दें।

महोदय, कृपया मुझे मेरे राज्य तेलंगाना के बारे में बोल कर समाप्त करने दें। यह कैसा है कि मैं जिस किसी स्थान का अधिकारिक स्वामी हूं, मेरा स्थान पोलावरम परियोजना के अंतर्गत अन्य राज्य को दे दिया जाता है। यह असंवैधानिक है। दस लाख आदिवासी विस्थापित होंगे। क्या डूबी हुई भूमि ओडिशा और छत्तीसगढ़ से ली जा रही है और आंध्र प्रदेश को दी जा रही है?

मैं यह मांग करता हूं कि तेलंगाना में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। वर्तमान मुख्यमंत्री तेलंगाना के लिए पृथक उच्च न्यायालय नहीं चाहते। मैं इस संबंध में सरकार से आग्रह करता हूं कि तेलंगाना के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए।

मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) **:** महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...*(व्यवधान)* इशरत जहां केस सबज्युडिस है।...*(व्यवधान)* इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है।...*(व्यवधान)* रूल 352 में दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय सभापति : मैं इसकी जांच करूंगा। यदि यह सबज्युडिस है, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री नेफिड रिओ (नागालैंड) **:** माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिन्होंने 9 जून, 2014 की संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था, प्रस्ताव को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा प्रस्तुत किया गया और श्री रामविलास पासवान द्वारा समर्थन किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सर्वप्रथम, मैं माननीय प्रधानमंत्री, श्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल को अपनी हार्दिक बाधाई देता हूं। मैं भाजपा और इसके सहयोगियों, राजग, जिसका मैं भी वास्तव में सदस्य हूं, को बधाई देता हूं।

महोदय, मैं नागालैंड से हूं और मैं एक मात्र सदस्य हूं, परन्तु मैं नार्थ ईस्ट रीजनल पार्टीज फ्रंट का भी प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं सभी क्षेत्रीय दलों, जिसमें दस दल हैं, की तरफ से बोल रहा हूं। मैं अपने राज्य के बारे में और संपूर्ण क्षेत्र के रूप में कुछ बातों को उजागर करना चाहूंगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण ने देश को आगे ले जाने की दूरदृष्टि प्रदान करते हुए राजग सरकार की चिंताओं को उजागर और रेखांकित किया और इसने सभी वर्ग के लोगों – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, जनता के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए चिंता व्यक्त की गयी है। मैं इस बात का विशेष रूप से आभारी हूं कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और मैं उसके लिए बहुत प्रसन्न हूं। यह इंगित करता है कि राजग सरकार संपूर्ण देश के समावेशी विकास, चाहे वह प्रमुख स्थानों में हो या देश के कोने में हो की नीति शुरू कर रही है।

मैं विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसमें सिक्किम सहित आठ राज्य हैं। आपको पता है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के इस हिस्से का 98 प्रतिशत भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और मात्र 2 प्रतिशत प्रमुख जगहों से जुड़ा है। इसीलिए उत्तर-पूर्व विशेष क्षेत्र बन गया है।

तथापि, हमारे समक्ष अनेक समस्याएं हैं, जिनका हमें समाधान करना है – अर्थात्, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और साथ ही अंतर्राज्यीय सीमाएं भी। हमें राज्यों में घुसपैठ की समस्याओं सीमा समस्याओं, जातीय और विशेषत: गैर-कानूनी प्रवासियों की घुसपैठ की समस्याओं का समाधान करना है। हम आर्थिक रूप से पिछड़े क्यों हैं? ऐसा विकास की कमी और मंद आर्थिक विकास के कारण है।

इसलिए हम ऐसी स्थिति में है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र हमेशा ही गलत कारणों से खबरों में रहता है और अच्छे कारणों की खबरों को देश में नहीं दिखाया जाता है। इसलिए इस कारण से शेष भारत का मानना है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र देश पर बोझ हैं।

परंतु, मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि उत्तर-पूर्व में काफी क्षमताएं हैं। मैं चाहता हूं कि देश उत्तर-पूर्व की अच्छाइयों और हमारे पास क्षमताओं को देखें।

हमारे पास काफी जन संसाधन हैं। हमारे पास खनिज भंडार और अन्य क्षमताएं हैं। अत:, मैं महसूस करता हूं कि हमें उत्तर-पूर्व की, विशेषत: युवाओं की क्षमताओं का उपयोग और दोहन करना चाहिए।

अभिभाषण के पैरा 7 में कहा गया है कि राजग सरकार गरीबों और भारत में गरीबी के अभिशाप को समाप्त करने के लिए समर्पित है। न केवल इसने गरीबी उपशमन की बात की, बल्कि लक्ष्य गरीबी उन्मूलन का है। मैं सोचता हूं कि यह अधिकतम अन्य पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों को लक्षित कर रहा है जो हमारी तरह पिछड़े हैं। इस संबंध, मैं कहना चाहूंगा कि हम खाद्य सुरक्षा विधेयक का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें खाने की आवश्यकता है, सभी को खाने की आवश्यकता है और हम भूखे नहीं रह सकते हैं। परंतु मैं यहां एक विनम्र सुझाव दूंगा – न केवल हमें खाद्य सुरक्षा विधेयक लाना चाहिए, परंतु हमें रोजगार सुरक्षा विधेयक लाना चाहिए, जिससे कार्य संस्कृति विकसित हो, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, हम कमाते हैं और हम खाते हैं। अन्यथा, यदि हम केवल खाना देते हैं, कार्य संस्कृति समाप्त हो जाएगी; देश आगे नहीं बढ़ेगा।

महोदय, मैंने आपसे समय देने का अनुरोध किया था। मुझे बहुत कुछ कहना है परन्तु मैं उसे संक्षेप करके नागालैंड की ही बात करूंगा। आपको पता है कि नागालैंड देश का 16वां राज्य है जो 50 वर्षों पुराना है। हमारे नागा-राजनीतिक मुद्दे का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। 1997 में, श्री आई.के. गुजराल, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आई-एम समूह के साथ संघर्षविराम पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2001 में, वाजपेयी जी ने एक संघर्षविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब, पिछले 17 वर्षों से समझौते का प्रयास चल रहा है, शांति प्रक्रिया चल रही है और लगभग सत्तर दौर की बातचीत हो चुकी है किंतु कोई तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इसलिए, मेरी अपील है कि इसमें तेजी लायी जाए और इसका समाधान हो ताकि न सिर्फ राज्य से बल्कि बाहर से भी निवेशक आएं।

महोदय, संभवत:, अगली बैठक में आप मुझे अधिक समय दें। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अपनी पार्टी की ओर से मेरा विश्वास है कि समग्र राष्ट्र के लिए, विशेषकर जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं।

[हिन्दी]

***श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे** (रावेर) : संसद के दोनों सदनों की साझा बैठक के समक्ष दिनांक 9 जून, 2014 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आज सदन में माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने 16वीं लोक सभा के पहले सत्र के शुरुआत में अपने अभिभाषण में जिन बिन्दुओं का जिक्र किया है, उसी को भारत की जनता ने लोकतांत्रिक परम्पराओं से भारी बहुमत देकर जनादेश दिया है और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत की जनता ने "सबका साथ-सबका विकास" और "न्यूनतम सरकार-अधिकतम सुशासन" का मंत्री चुना, इसी में ही पिछली सरकार के कामकाज के प्रति जनता का रवैया क्या है? यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। मुझे इस बात पर गर्व है कि 30 साल पश्चात् भारत की ग्रामीण एवं शहरी जनता ने हमारे नेता श्रीमान नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और मित्र पक्षों की एनडीए सरकार को स्पष्ट जनादेश दिया है। जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो विकास के बिन्दु और नीतिगत मामले आए हैं, वह हमारी सरकार आने वाले पांच सालों में पूरा करने के लिए तत्पर है।

मैं रावेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित महिला सदस्य हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने हमें स्पष्ट जनादेश देकर भारी बहुमत से विजयी बनाया है। हमारी जनता की कुछ अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विभिन्न बिन्दुओं पर निर्देशित हैं। उनमें कृषि एवं ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण, प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पिछडे वर्गों के समाज के कल्याण के लिए विभिन्न योजना, गरीबी का पूर्ण निवारण, रोज़गार, ऊर्जा के मामले में स्वयं आत्मनिर्भरता, सिंचाई के द्वारा हर खेत को पानी, युवा विकास जैसी विभिन्न योजनाएं कही गई हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ते तापमान से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। वहां पर जलवायु प्रयोगशालाएं न होने के कारण बीमा एजेंसियों से किसानों को मदद मिलने में परेशानियां हो रही थी, बहुत वर्षों से हमारे किसानों की मांग है कि केले को फल का दर्जा प्राप्त हो, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। मेने निर्वाचन क्षेत्र में श्रीमुक्ताई परिसर टूरिस्ट सर्किट के साथ कई अन्य तीर्थाटन परियोजनाएं लम्बित रही है तापी नदी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में विशाल जल पुनर्भरण योजना कार्यान्वित करने की मांग लम्बे समय से केन्द्र में लंबित है, किसानों को अपनी फसल बाज़ार एवं सब्जी मंडियों में लाने के लिए खेत-खेलिहान से मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनाने की आवश्यकता है। भुसावल से इंदौर हाईवे बनाने की आवश्यकता है।

मैं इस अवसर पर यह बात कहना चाहूंगी कि जब हम 16वीं लोक सभा के चुनाव में व्यस्त थे, तभी हमारा किसान नैसर्गिक आपदाओं से घिरा हुआ था। बे-मौसम बारिश और बर्फबारी जैसे ओले की मार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र और पूरे महाराष्ट्र के किसान दु:खी हैं, गत 10 साल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के समेत पूरे महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे जो कुटुम्ब है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा कमज़ोर वर्गों की छात्राओं को फीस एवं छात्रवृत्ति केन्द्र की तरफ से अदा नहीं हुई है, उन्हें निश्चित तौर पर हमारी सरकार पूरी मदद करेगी। यह भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रतिबिम्बित हुआ है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भुसावल से मुम्बई छात्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन जाने के लिए एक गाड़ी रात के समय चलाने की मांग भी बहुत अर्से से लम्बित है। यह रास्ते से नयी दिल्ली जाने के लिए एक गरीब रथ एक्सप्रेस और एक राजधानी एक्सप्रेस चलाने की भी मांग हो रही है। मैं इस अवसर पर जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो हाई स्पीड और फास्ट ट्रेक ट्रेनों का संकल्प किया है वह भी जनता के सपनों को पूरा करेगा। इसीलिए मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर में माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रेम दास राय (सिक्किम) : महोदय, श्री रूडी जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री और सरकार को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण पर बधाई देता हूं। इस अभिभाषण में आगामी पांच वर्षों में सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली नीतिगत रूपरेखा के उद्देश्य और दिशा का स्पष्ट उल्लेख है। मुझे भी इसकी तात्कालिकता और ससंजक्ता का बोध है और मुझे आशा है कि यह समस्त सभा 16वीं लोक सभा के अगले पांच वर्षों के दौरान एक जूट कार्य करेगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक अहम बात प्रत्येक राज्य में आईआईटी और आईआईएम का खोला जाना है। मैं इसका पूर्ण स्वागत करता हूं क्योंकि इन दोनों ही महान संस्थाओं में मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो यह कह सकते हैं कि इससे आईआईटी और आईआईएम का महत्व कम हो जाएगा किन्तु मैं उनसे कहूंगा कि विद्यमान आईआईएम में 3000 सीटें पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि लाखों इच्छुक युवा छात्रों को इन महान संस्थाओं में पढ़ने का मौका नहीं प्राप्त होता है। इसलिए, सरकार को इसके लिए कार्य करना चाहिए ताकि उनका मौका मिल सके और मेरा विश्वास है कि सिक्किम में आईआईटी और आईआईएम की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है।

हम राज्यों के साथ कार्य करते समय सहकारी संघवाद की नीति को मजबूत करने संबंधी सरकार के इरादे का स्वागत करते हैं। तथापि, कुछ मुद्दे मैं उठाना चाहते हूं। पहला मुद्दा यह है कि यद्यपि प्रस्तावित राष्ट्रीय हिमालय मिशन तथा हिमालय से जुड़े अध्ययन के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय एक स्वागतयोग्य कदम है, किन्तु इसमें पर्याप्त कार्य नहीं हुए हैं। मेरा मानना है कि इसके लिए एक हिमालयी राज्य मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि इस दिशा में चिंतन प्रक्रिया चल रही है और मुझे आशा है कि जल्द ही इसकी आवश्यकता महसूस की जाएगी। देश की सुरक्षा,

जैव-विविधता की सुरक्षा, मानव सुरक्षा और जल सुरक्षा हिमालय पर निर्भर करता है।

दूसरा, मुझे यह कहते हुए दु:ख है कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए किसी कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है। यह समस्या आतंकवाद जितनी बड़ी है और इसका समाधान विधि-व्यवस्था तंत्र और विधायी क्षमता के साथ उतनी ही जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

तीसरा, इस अभिभाषण में हाशिए पर खड़े लोगों, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के वित्तीय समावेशन का कोई उल्लेख नहीं है। मेरा मानना है कि भारत के पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजित करने और आजीविका के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण साधन है।

अंत में, मैं ग्रामीण और शहरी कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की इच्छा की सराहना करता हूं। मैं इस महान सदन में यह कहना चाहूंगा कि श्री पवन चामलिंग के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत सिक्किम ने सकारात्मक प्रगति की है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा इस सदन में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जोस के. मणि (कोट्टयम) : माननीय सभापति, सर्वप्रथम मैं नवगठित सरकार और हाल के संसदीय चुनावों में जीत कर आए अपने सहयोगियों को बधाई देता हूं।

अपनी पार्टी, केरल कांग्रेस (एम) की ओर से मैं राष्ट्र निर्माण से जुड़े सभी अच्छे कार्यक्रमों और हजारों लोगों के लिए न्याय और समानता लाने वाले कानून का रचनात्मक समर्थन करता हूं। एक कॉर्पोरेट कंपनी का विज्ञापन है जिसमें यह कहा जाता है – आप बताएं और हमारे पास समाधान है। यह कुछ ऐसा ही है कि इस सरकार के पास देश के समक्ष उपस्थित सभी समस्याओं का समाधान है। किन्तु मैं महसूस करता हूं कि सरकार को धनराशि और अन्य चीजों के मामले में प्राथमिकता और तौर तरीके तय करते समय अपने दृष्टिकोण के प्रति सुस्पष्ट होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने सभी के लिए भोजन, पानी, आश्रय, शिक्षा और अन्य कई चीजों का उल्लेख किया है। आपने एक अच्छी तस्वीर प्रस्तुत की है। आपने शाहरूख खान की ओम शांति ओम जैसी एक अच्छी फिल्म बनायी है। उस फिल्म में एक संवाद था – *'पिक्चर अभी बाकी'* है। इसलिए, हम प्रतीक्षा करेंगे। सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए हैं किन्तु यदि हम निर्धारित समय-सीमा में इन कार्यों को पूरा कर सकें तो ये वादे सफल होंगे। इसके लिए निर्धारित समय-सीमा होनी चाहिए। इसकी समय-सीमा 2025 या 2030 नहीं होनी चाहिए।

महोदय, श्री कतिपय बिन्दुओं पर आ रहा हूं जिन्हें मैं सरकार को बताना चाहता हूं। ये मुद्दे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में है। सभी राज्यों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। हम जानते हैं कि सभी योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाते हैं। इन योजनाओं के लिए निबंधन और शर्तें सभी राज्यों के लिए एक जैसी होती हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए राज्यों को दिए जाते हैं। किन्तु शर्त यह है कि चौड़ाई न्यूनतम आठ मीटर होनी चाहिए, ढ़लान एक मीटर से अधिक होना चाहिए और इसकी दर राष्ट्रीय स्तर पर तय होनी चाहिए। किन्तु यदि आप इन योजनाओं की उपयोगिता की जांच करें, तो इनमें से कई योजनाएं राज्यों द्वारा उपयोग में नहीं लायी जाती हैं। मुख्य रूप से राज्यों की विविधता भरी प्राकृतिक दशाओं के कारण इनमें से अधिकांश योजनाओं का उपयोग कम होता है। उदाहरण के लिए केरल राज्य, जहां से मैं आता हूं, में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। यहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ही अधिक है और कृषि भू-भाग भी अधिक है। अत: इन विशिष्टताओं के साथ बहुत-सी सड़कें बनना बहुत कठिन है। इसके परिणामत: उनका धन बर्बाद हो रहा है या योजनाएं असफल हो रही है, जिसका उपयोग उन्होंने कर लिया होता। अत: मैं कभी-कभी महसूस करता हूं कि केरल की सफलता हो केरल की असफलता है।

शिक्षा के अधिकार का क्या हुआ? यह राष्ट्रव्यापी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। यह एक शानदार कार्यक्रम है जो छह से चौदह आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। किन्तु जैसा कि आप जानते हैं, केरल ने प्रारंभिक शिक्षा में शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त की है। हमें उच्च शिक्षा तथा विशेष कौशल कार्यक्रमों के लिए सहायता देनी चाहिए। यदि आप सर्व शिक्षा का मामला लें तो हमारे यहां 4500 सरकारी विद्यालय और 7500 सरकारी सहायता वाले विद्यालय हैं एवं दोनों ने मिलकर शिक्षा के विकास में केरल मॉडल में योगदान दिया है जो अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल हो सकता है तथा यहां तक कि यह पूरे देश के लिए मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन वित्तीय सहायता केवल सरकारी विद्यालयों को दी जाती है। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं क्योंकि इनमें अवसंरचना की कमी है। यदि सभी राज्यों को ध्यान में रखा जाए तो कुछ ऐसे राज्य है जो कम विकसित हैं किन्तु जब राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है तब उसे राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाता है तथा निर्धारित शर्तें सभी राज्यों पर लागू नहीं होती हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जब योजनाएं बनाई जाती है तो उन्हें राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर बनाया जाए ताकि योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

महोदय, केरल के किसानों को दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा अन्य राज्य के किसान भी पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी

की समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं आपको एक बात का आश्वासन देता हूं कि भारत के लोग पारिस्थितिक के संरक्षण का बहुत ध्यान रखते हैं...*(व्यवधान)* वास्तव में किसान एक माध्यम हैं जो पारिस्थितिकी का संरक्षण करते हैं। लेकिन यदि कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट और गाडगिल रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार किया जाता तो मानव बसावटें, कृषि क्षेत्र तथा पौध रोपण क्षेत्र प्रभावित होते। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ईएसए का निर्णय करने से पहले उस क्षेत्र को निकाल दे।...*(व्यवधान)*

मेरा अंतिम मुद्दा रबड़ की कीमत से संबंधित है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। पिछले एक वर्ष में कीमत 243 रुपए से घटाकर 140 रुपए हो गई है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। यह पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के भारी आयात पाटन के कारण ऐसा हुआ है...*(व्यवधान)* मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कम-से-कम एक वर्ष तक बाजार में चढ़ाव होने तक प्राकृतिक रबड़ के आयात को रोक दे और इसी बीच आयात शुल्क में 25 प्रतिशत की कृषि की जाए एवं मूल्य स्थिरीकरण निधि का उपयोग किया जाए।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला) : राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये अभिभाषण का समर्थन करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने नई सरकार, जो हाल ही में आम चुनावों में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसकी दिशा तय की है। मुझे खुशी है कि हम 16वीं लोक सभा के सदस्य चुनकर पुन: आये हैं। लोगों ने श्री मोदी जी के नेतृत्व में वे भाजपा की नीतियों व कार्यक्रम में विश्वास व्यक्त किया है और काफी समय के पश्चात् देश में एक राष्ट्रीय दल को पूर्ण बहुमत दिया है। इन चुनावों में हमें 282 सीटें प्राप्त हुई हैं। लोगों की उम्मीदें काफी हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है कि यह चुनाव उम्मीदों का चुनाव रहा है। इस बार जिस तरह से मतदाताओं ने अपना वोट दिया। 66.4 प्रतिशत मतदान अपने आप में दर्शाता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। आम जन की उम्मीद इस सरकार से है और जिस तरह गत पांच वर्षों में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा व घोटाले पर घोटाले हुए लोग इससे परेशान थे। अब हमसे लोग चाहते हैं कि महंगाई पर लगाम लगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व प्रशासन हो। इस ओर अब सरकार को ठोस कदम उठाकर जन आकांक्षाओं व उम्मीदों पर खरे उतरना ही प्राथमिकता होगी, जिस तरह कि अभिभाषण में प्रतिबिम्बित है।

इन चुनावों में युवा वर्ग को नई सरकार से बहुत-सी अपेक्षाएं हैं। उन्हें रोज़गार उपलब्ध हो, उनके दो हाथों को काम मिले, यह उम्मीद है। अभिभाषण में कहा गया है "हर हाथ को हुनर" यानी उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले। इसका मैं खासतौर से स्वागत करता हूं। हुनरमंद भारत के लक्ष्य से नेशनल स्किल मिशन की शुरुआत की बात कही गई है, जोकि स्वागत योग्य है।

सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों के हित में जो कहा गया है कि किसानों के खेत को पानी मिले इसके लिए "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" की शुरुआत होगी। इससे हमारे किसान खुशहाल तो होंगे, परंतु गांव का युवा वर्ग जो आज सूखी खेती के कारण व कोई भी सुविधाएं न मिलने के कारण शहर की ओर चले जाता है और गांवों में हमारी खेती बंजर होती जा रही है, उस पर भी रोक लगेगी। गांव-गांव में रोज़गार के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। रेल का विस्तारीकरण हो और पहाड़ी राज्यों में व क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रेलमार्ग मिले और इस ओर भी इस अभिभाषण में उम्मीद जताई गई है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहाड़ी प्रांत है, जिसमें आज़ादी के बाद कुल 44 कि.मी. रेल मार्ग का निर्माण हुआ है, जोकि काफी चिंता का विषय है। अब नई सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ऐसी उम्मीद हिमाचल वासियों को है। इससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे।

अभिभाषण में कहा गया है कि "राष्ट्रीय हिमालय मिशन" शुरू किया जायेगा। बहुत ही स्वागतयोग्य बात है, इसमें मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सभी पहाड़ी राज्यों के त्वरित विकास के लिए समान योजनाएं बनाकर केन्द्रीय योजनाओं में 90 : 10 के अनुपात से धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। जिसकी अभी आवश्यकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में आज भी केन्द्र सरकार गैर-बराबरी बनाये हुए हैं। पहाड़ी राज्यों के लिए विकास के लिए ज्यादा धन उपलब्ध करवाया जाए।

हमारे पूर्व-सैनिक कई वर्षों से "वन रैंक-वन पेंशन" की मांग करते आ रहे हैं। इस दिशा में पहले की सरकारों ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। अब इस ओर योजना लागू करने की बात कहीं गई है और उनको अब आस जगी है कि नई सरकार उनके साथ हो रहे अन्याय को दूर कर सकेगी।

प्रत्येक परिवार को एक पक्का घर मिलेगा-स्वागतयोग्य है। देश की लगभग आधा आबादी बिना घर के बिना छत के जन्म लेती है और फिर उसी तरह संसार को छोड़ जाती है। सभी को एक छत तो मिलनी ही चाहिए। सरकार ने अपनी नियत साफ की है कि गरीबी उन्मूलन उसकी प्राथमिकता होगी। यह बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में गरीबों को ही नहीं सभी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। यह उम्मीद इस अभिभाषण से झलकती है।

मैं इस अभिभाषण का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आने वाले दिनों में पहाड़ी लोगों, किसानों, बागवानों के लिए विशेष योजनाओं के माध्यम से उनका विकास होगा।

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद-प्रस्ताव आया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि कृषि हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है। लेकिन पिछले कई दिनों से देश के किसान दु:खी हैं। यूपीए सरकार ने कृषि ऋण माफी का निर्णय तो लिया, लेकिन इसका फायदा बैंकों में घोटाले करने वाले एवं दलालों को ज्यादा मिला और किसानों को कम मिला। इसलिए 70 हजार करोड़ रुपए का ऋण माफी होने के बावजूद देश में जो किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, उनमें न कमी आयी, न किसानों को लागत मूल्य ही मिल पाया। किसानों की मांग इतनी थी कि कम-से-कम उन्हें लागत-मूल्य तो मिलना चाहिए। लेकिन लागत-मूल्य मांगने के लिए सड़क पर उतरे किसानों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ीं और गोलियां झेलनी पड़ीं। किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो गया, लेकिन उसे पैसा नहीं मिला। जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि कृषि क्षेत्र हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है और कृषि के बुनियादी ढांचे में सरकारी और निजी निवेश बढ़ाने की बात कही, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई भी निजी कंपनी इसमें निवेश बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि खेती घाटे में है। किसान जो खर्च करता है, वह भी उसे वापस नहीं मिलता है। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने कृषि बीमा तथा उपज पश्चात् प्रबंधन के मुद्दों को उठाया। एक व्यापक कृषि बीमा योजना लाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को कुछ राहत मिले। आज देश का किसान प्रकृति से जूझ रहा है। कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं अकाल पड़ रहा है। एक किसान होने के नाते में स्वागत करता हूं सरकार का उन्होंने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करेंगे। अगर किसान के खेत में पानी की सुविधा होगी, तो किसानों को खेती करने में सुविधा हो जाएगी। अब तक वह किसान प्रकृति से जूझ रहा है, बारिश पर निर्भर रहा है, इससे उसे राहत मिलेगी। बिजली हो सड़क हो। आज किसानों को न बिजली मिल रही है, न अपने खेत तक जाने के लिए सड़क मिल रही है। बुनियादी ढांचा बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस देश की अर्थव्यवस्था ने किसानों की तरफ कभी गंभीरता से नहीं देखा। मैं सरकार से विनती करता हूं कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, तो हमें खेती को गंभीरता से देखना पड़ेगा। आज दिन-ब-दिन डॉलर महंगा हो रहा है और रुपये की कीमत कम हो रही है। एडिबल ऑयल हो, पल्सेज हों या क्रूड ऑयल हो, इनमें हमारे सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। अगर हम अपने किसानों को एडिबल ऑयल के लिए एमएसपी बढ़ाकर देते हैं, तो हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर होगा, एडबिल ऑयल और पल्सेज के मामले में देश आत्मनिर्भर होगा। लेकिन हम आयात करके बाहर के किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारा किसान भूखा है, आत्महत्या कर रहा है। आज चीनी उद्योग हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है, लेकिन इसकी तरफ सरकार कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। मेरी विनती है कि इथेनॉल की पॉलिसी लाने की जरूरत है और साथ ही साथ चीनी के दाम में जो उतार-चढ़ाव हो रहा है, फ्यूचर मार्केट में जो घोटाले हो रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

***श्री रतन लाल कटारिया** (अंबाला) : मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा संसद के इस महान सदन में दिये गए अभिभाषण एवं श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा इसका समर्थन किये जाने व श्री राम विलास पासवान द्वारा इसके समर्थन में अपने उद्गार प्रकट किये जाने का समर्थन करता हूं।

16वीं लोक सभा के चुनाव परिणामों ने देश के 125 करोड़ लोगों में एक नई आशाओं को और उमंगों का सृजन किया है। खास कर भारत का वो 10 करोड़ नया मतदाता जिसने आधुनिकीकरण व सुधार कार्यक्रम लागू होने के पश्चात् याने की 1991 के पश्चात् जन्म लिया। वो देश में रोजगार के अवसरों का सृजन चाहता है वो भारत की अमेरिका व चीन से भी शक्तिशाली राष्ट्र देखना चाहता है इसी प्रकार से आज भारत का दलित समाज, महिला समाज अपने अधिकारों व गरिमापूर्ण जीवन के प्रति आशा संजोएं हैं। पिछले दस वर्षों में दलितों एवं महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ हैं उनके इनका मनोबल टूटा है वे आज जन नायक नरेन्द्र मोदी को अपने मसीहां के रूप में देख रहे हैं। दिसंबर, 2012 की दिल्ली की निर्भय की निमर्म हत्या, हरियाणा में दलितों पर अत्याचार व उत्तर प्रदेश के बदायूं की घटना ने इन वर्गों में भय का वातावरण पैदा किया है। आज किसान भी ऋण जाल में डूबकर आत्म हत्याएं कर रहा है। वो अपनी फसलों के जायज मूल्य के लिये संघर्ष कर रहा है।

प्रधानमंत्री जी ने देश में रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी तथा एयर कनेक्टिविटी का जो वीजन दिया है वो भारत को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों की सूची में लाकर खड़ा कर देगा सरकार ने देश के पहाड़ी इलाकों को उन्नत करने की बात की है मैं चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र अंबाला का शिवालिक का पहाड़ी ऐरिया औद्योगिक दृष्टि से इस प्रकार पिछड़ा घोषित किया जाए जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने हिमाचल के बद्री व काला आम्ब ऐरिया को किया था। इस क्षेत्र मोरनी हिल ऐरिया को विश्व विख्यात पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने देश में ही रक्षा से संबंधित उपकरणों के केन्द्र स्थापित करने का संकल्प प्रकट किया है। मेरे लोक सभा का अंबाला कैंटोनमेंट एरिया सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में रक्षा के उपकरणों को बनाने का केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। आज देश को स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से डायबिटीज व टी.बी. जैसी बिमारियां भारत में पैर पसार रही है उन पर काबू पाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन कारगर कार्य करेगा। आज जिस तरह से देश में अमीरी व गरीबी की खाई बढ़ रही है उस पर लगाम लगानी होगी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार को गरीबों के प्रति वचनबद्ध होने के स्पष्ट संकेत देकर गरीबों की आशाओं को जगाया है। गरीबी का समूल उन्मूलन होना चाहिए। आज देश की 71% आबादी को कुपोषण भुखमरी अशिक्षा के बचाने की आवश्यकता है। ब्रांड इंडिया बनाने का संकल्प भारत की दुनिया में तसवीर बदल कर रख देगा। प्रधानमंत्री जी ने पांच टी का क्रांतिकारी विचार हमारे सामने रखा है हमें उस पर कार्य करना होगा। आज भारत को उर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने की जरूरत है। जब तक हम उर्जा के उपलब्ध सभी साधनों का दोहन नहीं करेंगे हमें दिक्कते आती रहेगी। मैं चाहूंगा की शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए उचित कदम उठाए जाए। गंगा के साथ-साथ यमुना व सरस्वती के ऊपर भी कार्य होना चाहिए। मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

आज देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रासंगिक बनाए जाने की अति आवश्यकता है। जिस प्रकार से वितरण प्रणाली में फैले व्यापक भ्रष्टाचार व अनाज के गोदामों में सड़ने की खबरे प्रकाशित होती है उससे आम आदमी में निराशा का वातावरण पैदा होता है। एक तरफ तो अन्न का काफी हिस्सा बेकार चला जाता है दूसरी और डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में आज भी सब सहारा राष्ट्रों से भी ज्यादा भूखमरी के शिकार लोग रहते हैं। इस पर युद्धस्तर पर हमला करना होगा, यूपीए सरकार ने इस विषय में कोई कारगर कदम नहीं उठाए थे।

राष्ट्रपति महोदय ने देश की आबादी के काफी बड़े हिस्सों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आने की और भी ध्यान दिलाया है। हमें अपने ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत ढांचे को मजबूत रूप से खड़ा करना पड़ेगा। हमें अपने गांवों में उन सभी सुविधाओं को प्रदान कराना होगा जिस की ग्रामीण जनता अधिकारी है। आज भारत में कृषि सिंचाई योजना लागू करने की बहुत जरूरत है। हमें वर्षों के पानी की एक-एक बूंद का भी लाभ उठाना होगा। हम अगर अपने साधनों का भरपूर लाभ करते हैं तो हम अपने देश के अधिकांश मांग को सुखे की लपेट से बचाने में सक्षम होंगे।

आज भारत को विश्व स्तर पर जो मान्यता मिली है उसने साबित कर दिया है कि आज भारत को नरेन्द्र मोदी के रूप में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनका विजन बिल्कुल साफ है जिनकी राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट बिल्कुल साफ है। जिनके पास भारत को महान राष्ट्र बनाने के इनोवेटिव आईडिया है। दुनिया उनकी क्रिएटीविटी का लोहा मानती है। उन्होंने ठीक कहा है कि हम ना आंख दिखा कर जियेंगे परन्तु ना ही आंख झुकाकर जियेंगे। हम सभी राष्ट्रों के साथ बराबरी का रिश्ता बनाएंगे ये उनके स्पष्ट दर्शन को प्रदर्शिता करता है। अपने शपथ समारोह में सार्क देशों के सभी राष्ट्रों को बुलाकर इन्होंने भारत की विदेश नीति में एक नया इतिहास रच दिया है।

श्री अजय (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय राजीव प्रताप रूडी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

वर्ष 2014 का आम चुनाव पूर्व में हुए चुनावों से सर्वथा अलग था। चुनाव से पूर्व पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद व किसानों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण पूरे देश में हताशा व निराशा का वातावरण था तथा देश की सीमा पर असुरक्षा के कारण लोग पूर्व सरकार से निराश थे। ऐसे में लोग देश में एक मजबूत और काम करने वाली सरकार चाहते थे, लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा था, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेजी जी की सरकार के साथ-साथ लोगों ने कई प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी थी। ऐसे में भाजपा ने जैसे ही श्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, पूरे देश ने बड़ी आशा व विश्वास के साथ माननीय मोदी जी को वोट डालने से पहले ही स्वीकार्यता दी, क्योंकि माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने न केवल गुजरात प्रदेश में एक सफल सरकार दी, जो लोगों को बिजली, पानी, सड़क, स्कूल के साथ-साथ अच्छा रोजगार, किसानों को फसल का पूरा दाम दे रही थी। लोग खुशहाल थे, बल्कि बहुत से विरोधी दलों व मीडिया के बहुत सारे कुप्रचार व हमलों के बावजूद और मजबूत होकर निकले। "तूफान कर रहा था, आपके अज्म का तवाफ दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है।"

माननीय मोदी जी पूरे देश के लोगों की आशा के प्रतीक बनकर उभरे। लोगों ने माना कि मोदी जी एक कुशल प्रशासक हैं, उनमें काम करने की योग्यता है तथा वह देश की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसीलिए देश ने भारी जनादेश देकर भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दलों की सरकार माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनायी है। इस सरकार का स्पष्ट मत है, सबका साथ व सबका विकास तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा सपना है, हमारा उद्देश्य है। हमारे देश में बहुत सारे धर्म,

जातियां व भाषायें हैं। यहां अलग-अलग तरह का रहन-सहन खानपान है, परंतु पूरे भारत देश का एक ईकाई के रूप में विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार चाहती है कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों को शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार का समान अवसर प्राप्त हो। उसे कार्यरूप में परिणित करने की योजना माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्रस्तुत की। शिक्षा, चिकित्सा, युवाओं को रोजगार, खेल के क्षेत्र की प्रतिभाओं को अवसर, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य, आवास, उद्योग, व्यापार, देश से महंगाई समाप्त करने, खाद्य-वितरण प्रणाली में सुधार के माध्यम से इस देश के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करना तथा भारत देश को खुशहाल बनाना तथा देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाना, यह हमारी सरकार की प्राथमिकतायें हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बेहद पिछड़े क्षेत्र लखीमपुर खीरी से चुनकर आया हूं। मुझे आशा है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के खीरी लखीमपुर सहित अन्य सीमावर्ती जिलों से बाढ़ की समस्या दूर करने की प्रभावी योजन बनायेगी। वह किसानों को गन्ना सहित अन्य फसलों का लाभकारी मूल्य, सड़क, शिक्षा, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, पचपेड़ी घाट पुल का निर्माण करायेगी। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक प्रभावशाली सरकार के रूप में काम करके देश की समस्याओं को दूर करके भारत को एक मजबूत व खुशहाल देश बनायेगी। ऐसा मेरा विश्वास है।

'अनगिन बाधायें झेल बढ़ा, यह यान हमारा अनुपम है, नायक पर है विश्वास अटल, दिल में बांहों में दमखम है, वह रात अंधेरी बीत गयी, ऊषा जय मुकुट चढ़ायेगी, पतवार चलाते जाओ तुम, मंजिल आयेगी आयेगी'।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राजीव प्रताप रूडी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमाचंद्रन (कोल्लम) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे अपनी पार्टी आरएसपी की ओर से मत व्यक्त करने का अवसर दिया।

इस सभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण इस सरकार की मूल नीति का दस्तावेज है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार करते हैं तब हम पाते हैं इसमें बहुत से कार्यक्रमों, योजनाओं तथा नारों का उल्लेख है। किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट विशिष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। इसका उसमें उल्लेख नहीं है जिसको मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपने प्रथम मुद्दे के रूप में उल्लेख करना चाहता हूं। हमने **एक भारत-श्रेष्ठ भारत,** सुशासन के माध्यम से विकास, **सबका साथ सबका विकास** और न्यूनतम सरकार की अधिकतम शासन जैसे नारों को देखा। बहुत सी योजनाओं, कार्यक्रमों और नारों का उल्लेख है।

मैं सरकार से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में इसकी बुनियादी और विशिष्ट नीतियों के बारे में जानना चाहता हूं। इसका अभिभाषण में उल्लेख नहीं है। अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार का अर्थ क्या है? क्या यह मंत्रियों की भूमिका को न्यूनतम कर रहा है और प्रधनमंत्री की भूमिका को अधिकतम कर रहा है? क्या 'न्यूनतम सरकार की अधिकत्म शासन' नारे का यही अर्थ है। अभी हमारे एक विद्वान मित्र सचिवों की बैठक के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसकी बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई थी। लगभग सभी मंत्रियों को पता नहीं है कि सचिवों की बैठक में क्या हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री संसद के माध्यम से लोगों के प्रति जिम्मेदार है। अभी के लिए गुजरात का अनुभव ठीक है। किन्तु यह आगे चलकर संसदीय लोक तांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है जोकि हमारे देश में विगत छह दशकों से चला आ रहा है। मेरा यह पहला मुद्दा है जो मैं कहना चाहता था।

मैं सरकार को मिले राजनीतिक अधिदेश के बारे में विवाद नहीं कर रहा हूं कि इस सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इसके पास केन्द्र में स्थिर सरकार देने के लिए पर्याप्त बहुमत है। मेरा विद्वान मित्र श्री राजीव प्रताप रूडी राजनीतिक अधिदेश के बारे में दलील दे रहे थे जिसे लोगों ने दिया है। हम भी इसकी सराहना करते हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। हम इस स्थिति की सराहने करते हैं। कांग्रेस विधायी दल के नेता 69 प्रतिशत की बात कर रहे थे। चुनाव के बाद के विशिष्ट परिदृश्य जोकि चुनाव परिणाम है, को देखना भी रोचक है। यदि हम आंकड़ों पर नजर डाले तो यह देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 31 प्रतिशत वोट मिले और इसे 282 सीटें मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 19.3 प्रतिशत वोट मिले लेकिन उसे केवल 44 सीट ही मिली। अखिल भारतीय अन्ना डीएमके को 3.4 प्रतिशत वोट मिले परन्तु इसे 37 सीटे मिली। तृणमूल कांग्रेस को 3.8 प्रतिशत वोट मिले लेकिन उसे 34 सीट मिली। यहां नोट करने वाली उल्लेखनीय बात यह है कि मायावती जी के नेतृत्व वाली बीएसपी को 4.1 प्रतिाश्त वोट मिले लेकिन सभा में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि यह भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस पार्टी को लोक सभा चुनाव में 47 प्रतिशत वोट मिले लेकिन उसका एक भी प्रतिनिधि नहीं है जबकि जिस दल को 3.4 प्रतिशत वोट मिले सभा में उसके 37 सदस्य हैं। मुख्य बात यही है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन 69 प्रतिशत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, नीतियां और कार्यक्रम बनाते समय

उनका भी ध्यान रखा जाएं। अन्यथा वहां कभी भी समावेशिता नहीं होगी और समावेशित तभी होगी जब आप उन 69 प्रतिशत लोगों या मतदाताओं के हितों के लिए काम करेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के पक्ष में मतदान नहीं किया।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : आपके पास थोड़ा समय है। कृपया जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री एन.के. प्रेमाचंद्रन : मेरी अगली बात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और कार्यक्रमों को जारी रखने के बारे में है। यद्यपि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए हमें सरकार की नीति का भलीभांति आभास है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा अपनायी गयी नीतियों को जारी रखेगी, जिसे पिछले चुनाव में मतदाताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यह नव उदारवादी नीति है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा शासन में कॉर्पोरेट हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। मेरे व्यक्तिगत मत के अनुसार और मेरे दल के मतानुसार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन विशेषकर कांग्रेस का यह सबसे खराब प्रदर्शन है जिसमें कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली है इसका प्रमुख कारण इन नीतियों का अपनाना ही है।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मुझे पता है कि आप अच्छी बातें कह रहे हैं लेकिन समय थोड़ा है। अपराह्न चार बजे माननीय प्रधानमंत्री को वाद-विवाद का उत्तर देना है। हमारे पास थोड़ा समय ही बचा है।

श्री एन.के. प्रेमाचंद्रन : रक्षा नीति कैसी है? यह पहले ही जाहिर हो चुका है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने रक्षा मंत्री के रूप में श्री ए.के. एंटोनी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए क्या किया है? मैं रिकॉर्ड पर यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जा रही है।...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकृष्ट करने या आमंत्रित करने के स्थान पर हम रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सशक्त क्यों नहीं बनाते?...*(व्यवधान)* महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत से सराहनीय कार्यक्रम हैं। लेकिन उनकी असली सराहना तभी होगी जब उन्हें वास्तव में लागू किया जाएगा।

अच्छे भविष्य की आशा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री शरद त्रिपाठी** (संत कबीर नगर) : मैं श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। युवा होने के नाते जो क्रमांक 12, 13, 14 पर युवाओं के लिए विशेष रूप से कहा गया है निश्चित ही सरकार द्वारा युवा विकास, युवा संचालित विकास व्यवस्था लागू हो जाएगी तो इस देश में भारत एवं इंडिया का अंतर मिट जाएगा। सरकार द्वारा जो हर हुनर को काम देने की बात कही गई है उससे गांव में बैठे हुए तमाम युवाओं को अपनी प्रतिभा द्वारा अपने कौशल को देश स्तर पर स्थापित करने का अवसर मिलेगा। हमारे ही क्षेत्र के महुली बाजार के एक नौजवान ने अपने हुनर से ट्रैक्टर से भूसा बनाने का एक संयंत्र तैयार किया था जो बहुत ही सस्ता था किन्तु उसको विकसित करने के लिए सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिली। किन्तु इस सरकार द्वारा उसे अब जरूर प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने जो भारतीय ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करने की बात कही है उससे लगता है कि आने वाले समय में भारत के नौजवानों को ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक मेडल मिलेगा। सरकार ने योग एवं आयुष के द्वारा जो युवाओं के स्वास्थ्य पर बल दिया है उससे यह शक्ति अवश्य चरितार्थ होगी कि

'शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्'।

संसार के सभी धर्मों की पूर्ति स्वस्थ शरीर के माध्यम से हो सकती है क्योंकि शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : अब श्रीमती गीता बोलेंगी।

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने नेता श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी तथा अपनी पार्टी और अपनी ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद् को हार्दिक धन्यवाद देती हूं...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति : महोदया, आपके पास केवल दो मिनट है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं।

श्रीमती कोथापल्ली गीता : सबसे पहले मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देती हूं जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया है। मैं प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और हम नीतियों में किए गए वादों को पूरा करने में अपना पूरा समर्थन देंगे।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदया को भी मुबारकबाद देना चाहती हूं जिन्हें सर्वसम्मति से इस सभा का अध्यक्ष चुना गया है। एक महिला और ऐसी

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संसदविद् होने के नाते जिन्हें 8 लोक सभा के कार्यकालों का व्यापक अनुभव है इसलिए हम आशा करते हैं। कि वे पहली बार चुनकर आने वाली महिला सांसदों के लिए एक रोल मॉडल होगी।

मैं चुनावों में जीतकर आने वाले साथी सदस्यों और अपने सहयोगी संसदविद्ों को मुबारकबाद देती हूं। मैं स्वयं अपना परिचय देते हुए यह बताना चाहती हूं कि मैं अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हूं जोकि आन्ध्र प्रदेश में एकमात्र अनुसूचित जनजाति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिसकी सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के बाद के 67 वर्षों से उपेक्षा की गई है। मैं पहली बार आंध्र प्रदेश से चुनकर आयी हूं और आंध्र प्रदेश के लोगों को आज इस सभा में पहली बार चुनकर आए हुए संसद सदस्यों से बहुत आशाएं हैं। यद्यपि हमें स्वतंत्र हुए 67 वर्ष हो चुके हैं लेकिन फिर भी हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अपराह्न 3.58 बजे

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

ऐसा देश में शासन करने वाले नेताओं की प्रतिबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा के अभाव के कारण हुआ है। आज भी हमें निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी, विद्युत आपूर्ति की कमी और महिला उत्पीड़न संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरवत्ती सरकारों द्वारा घोषित योजनाओं और नीतियों के लाभ वंचितों, कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक नहीं पहुंचे है।

महोदया, राष्ट्रपति जी ने ठीक ही कहा है कि हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण गरीबी ही है। हमारा विकास कुछ सेक्टरों और नगरों तक ही समिति है और पूर्व सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। दो तिहाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूं और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 2000 गांवों का अभी विद्युतीकृत किया जाना है और 10,000 गांवों को अभी सड़क से जोड़ा जाना है। सरकार की नीति ग्रामीण समुदाय का उत्थान करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समान अवसर सृजन करना है। मैं संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की तहेदिल से सराहना करती हूं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार की प्रगतिशील नीतियों को हर संभव समर्थन देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर) : माननीय अध्यक्ष, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं भारतीय कम्युर्निस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण का सावधानीपूर्वक स्वागत करता हूं। मैं सचेत हूं भाषण में उद्धृत आदर्शों के प्रति नहीं अपितु इसके कार्यान्वयन के वास्तविक परिणामों के प्रति जिनका मूल्यांकन अभी किया जाना है।

हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के विकास के संबंध में, मैं सरकार की अच्छी मंशा की सराहना करता हूं जबकि हम हमारी राजनीति में धन शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यद्यपि हमारे देश की वर्तमान निर्वाचन प्रणाली का विश्व में स्वागत किया गया है फिर भी इसमें लोगों की इच्छा प्रतिबिंबित नहीं होती। मैं इसका वर्णन नहीं करना चाहता।

हम विगत छह दशकों से गरीबी उपशमन संबंधी घोषणाएं देख रहे हैं। अब, हम गरीबी उपशमन की बात कर रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

पर कैसे? इसे प्राप्त करने की प्रविधियां क्या है? मुझे पूरा यकीन है कि गहन भूमि सुधारों और ग्रामीण जनता के लिए उचित आजीविका सुनिश्चित किए बिना गरीबी उन्मूलन की कोई भी घोषणा प्रभावी नहीं होगी। मैं केरल मॉडल के बारे में कहना चाहता हूं न कि वर्णन करना चाहता हूं। लोक सभा के बाहर हम गुजरात मॉडल की बात सुन रहे थे, लोक सभा के अंदर रूडी जी ने माध्यम से हम चीनी मॉडल की बात सुन रहे हैं। मैं केरल मॉडल को दिखाना चाहता हूं जिसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा नोट किया गया है। उन्होंने कहा कि केरल मॉडल से केरल में गरीबी समाप्त हो गई है। केरल में ऐसा कोई नहीं है जो गरीब हो। वहां सभी के पास आवास है। आप यह समझने के लिए केरल आए कि हम कैसे इस उद्देश्य को हासिल कर सके हैं। कानूनों के माध्यम से एक घोषणा को प्राप्त किया जा सकता है। केरल में ऐसा ही हो रहा है।

मूल्य वृद्धि संप्रग सरकार की असफलता के मुख्य कारणों में से एक है और जिसकी वजह से राजग सरकार सत्ता में आई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसा कि इसे केरल में लागू किया गया है, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सार्वजनिक वितरण, समुचित बाजार हस्तक्षेप, कालाबाजारियों और राजनीतिक और नौकरशाह वर्ग के गठजोड़ को तोड़ना समुचित मूल्य नियंत्रण को प्राप्त करने की सफलता के मुख्य कारक है।

विशेषरूप से सऊदी अरब और खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्य कर रहे केरल के प्रवासी भारतीयों ने देश की आर्थिक स्थिरता में मुख्य योगदान दिया है। वर्तमान निशाकत कार्यक्रम, जो कि उनका स्वदेशीकरण कार्यक्रम है, ने हजारों गैर-निवासी केरल वासियों को बेरोजगार किया है। *...(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर) : माननीय अध्यक्ष, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बुलेट ट्रेन की बात कही जा रही है, डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ देश की राजधानी, जो देश का दिल है, वहां लोगों को सजस्ट किया जा रहा है कि 10 बजे से 11 बजे तक वल्ब न जलाओ, 12 बजे से 2 बजे तक एसी न चलाओ। दस बजे के बाद मॉल में मत जाओ। ये कैसे दिन आने वाले हैं? ...*(व्यवधान)* मुझे बता दीजिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब सप्लाई दोगुनी थी और रेट आधे थे। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार गई, उसके बाद एक अप्रैल से सप्लाई आधी ओ गई और रेट दोगुने हो गए। मैं पंजाब से बड़े मैनडेट से सांसद चुन कर आया हूं। मैं दिल्ली में भी रहता हूं और इस समस्या से दो-चार हो रहा हूं। एनडीए की भागीदार अकाली दल की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि पंजाब की जनता को पिछले पांच-छह साल से बिजली के बिना रहने की आदत पड़ गई है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पंजाब में बिजली नहीं है। कैसी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री के नाम में "प्रकाश" शब्द आता है लेकिन सूबा अंधेरे में डूबा हुआ है।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि बिजली और पानी की समस्या दिल्ली में है, उसे जल्द से जल्द हल करना चाहिए।...*(व्यवधान)* सैंटर में बीजेपी है, एमसीडी में बीजेपी है और दिल्ली के सातों सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन धरना भी बिजली, पानी के खिलाफ वही दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष जी, मैं मैडम सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करती हूं। रूडी जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रस्ताव को चर्चा के लिए सदन में रखा है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सुना है प्रधानमंत्री जी का सीना भी बहुत बड़ा है और दिन भी बहुत बड़ा है। एक महिला होने के नाते मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि दो मिनट का वक्त स्पीकर साहब ने दिया है, यदि बीजेपी की तरफ से आप हमें तीन मिनट दे देंगे तो कुछ प्वायंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं क्योंकि आज आप सत्ता में हैं। मेरे ख्याल से जब हम 14वीं लोक सभा में थे, तो सत्ता में रहने वाले व्यक्ति सुनते ज्यादा हैं क्योंकि उन्हें करना होता है और विपक्ष का काम है लड़ना। आपका काम है अपने काम को करना। मुझे रूडी जी की एक बात से बहुत आश्चर्य हुआ। सभी ने कहा था कि वे बहुत अच्छा भाषण देते हैं। भाषण बहुत अच्छा था लेकिन स्पेसिफिक प्वायंट्स नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है – जीत व्यक्ति को अंधकार देती है, आंख बंद कर देती है और जो हार है वह व्यक्ति की आंख खोल देती है। इस वक्त हमारी आंखें खुली हैं।...*(व्यवधान)* शायद आपकी आंखों में अंधेरा है। दूसरे, आपने कहा कि हम 44 हैं। मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगी। हमारे बहुत सीनियर लोग यहां बैठे हैं। नदी के साथ चलने वाले लोग जो होते हैं, यहां मैं कहूंगी कि नदी की धारा में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, बहुत सारा ऐसा सामान भी बहकर आ जाता है जिनकी जरूरत इस सरकार को और इस देश को नहीं होती है लेकिन नदी के विपरीत चलकर जो लोग डगर बनाते हैं, उनको पूरी दुनिया सैल्यूट करती है यदि आज हम 44 लोग भी आये हैं तो निश्चित तौर पर यह मैं आपको आगाह करूंगी कि आपने विकास की बातें जो भाषण के वक्त की थी, अब आप उसको क्रियान्वित करेंगे या नहीं, यह हम आपको पग पग पर याद दिलाने का काम करेंगे।

दूसरे, जनता की रुचि आप क्या करेंगे, उसमें नहीं है। आप इग्पलीमेंट क्यों करेंगे, क्या कर सकते हैं, उसमें है। आप सब्जी कब सस्ती कर रहे हैं, आप दूध पचास रुपये से तीस रुपये कब कर रहे हैं, सिलिंडर को कब सस्ता कर रहे हैं, जनता ने आज इसके लिए आपको मत दिया है और जनता सुनना चाहती है कि आप क्या करेंगे?

मैं सुषमा जी की एक बात जो उन्होंने कही, वह मेरी बहुत सीनियर हैं और आपसे इन पांच सालों में यह जरूर सीखूंगी कि भाषण कैसे देना है, तर्क कैसे देना है? मैं आपको ही सैल्यूट करके बोलना चाहूंगी और आपने कहा कि प्रोडक्ट बिका। निश्चित तौर से आज दुनिया में शुद्ध भैंस के दूध को छोड़कर सुधा के दूध की पैकेजिंग के कारण मार्केट वह नकली दूध बिक जाता है। जो आप पैकेज गिफ्ट बनाते हैं, आज उसकी पूछ है। आज आपका पैकेट बना हुआ है। आपका पैकेट बहुत सुंदर है। आप बहुत सुंदर गिफ्ट पैक लेकर आए हैं,...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : रंजन जी, अब आपका भाषण हो गया।

श्रीमती रंजीत रंजन : लेकिन जिस दिन वह गिफ्ट पैकेट खुलेगा, अपकी समीक्षा उस दिन होगी कि उसके अंदर क्या है?...*(व्यवधान)* उसके बाद एक कहानी जरूर मैं बताना चाहूंगी।...*(व्यवधान)* एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। एक गांव के लड़के को जिम्मेदारी दी गई।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : अब केवल रमेश पोखरियाल जी की बात कार्यवाही में जाएगी। बाकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। रंजीत जी, अब आपकी बात हो गयी।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***श्री ए.टी. नाना पाटिल** (जलगांव) : मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार को माननीय राष्ट्रपति जी के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए जो अभिभाषण दिया है। इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

जब माननीय राष्ट्रपति जी अभिभाषण दे रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि आज सच में हम लोग कुछ करने के लिए इस सदन में चुनकर आए हैं। पिछले पांच सालों में हमें इतनी निराशा हाथ लगी है कि आम लोगों का विश्वास जनप्रतिनिधियों से उठने लगा था। लेकिन इस तरह से हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है, आज आम जनता में एक आशा की किरण दिख चुकी है। जिस तरह से सरकार के चरणबद्ध तरीकों से आम जनता की समस्याओं को दूर करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है इससे सच में देश का कायापलट हो जाएगा। जैसे महंगाई को रोकने को प्राथमिकता देने की बात कही है और महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हो और सबसे जरूरी जो गांव के आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा 2022 तक हर आदमी को पक्का घर और हर घर में शौचालय बनाने को प्राथमिकता में रखा है और हर राज्य में एम्स की स्थापना करना। यह केवल आम आदमी ही नहीं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम है। आम जनता ने जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें एतिहासिक जीत दिलाई है उसे साकार करने में हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ऊर्जावान, व्यक्तित्व के धनी माननीय मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। सच में हम सभी भारत को सर्व-शक्तिमान बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। इस तरह से सरकार ने एक-एक विषयों पर इतनी बारीकी से ध्यान रखकर योजना बना रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हो या सेना का आधुनिकीकरण करने के संदर्भ में हो या हर हाथ को हुनर देने की बात हो। जैसे जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कदम उठाने की बात हो। हर विषय में मजबूती से काम करने की बात कह कर यह सरकार ने अपने स्पष्ट उद्देश्य बता दिया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से स्पष्ट हो गया है कि भारत नई दिशा की ओर बढ़ चला है और इसका लक्ष्य टुकड़ों में बंटे समाज को जोड़ना होगा जिससे 'एक भारत और श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना साकार हो सके।

जैसे कि माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा 'मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है' इस एक वाक्य में पूरे भारत के विकास और प्रगति का एजेंडा उल्लिखित है। और इसी में समूचे भारत की जनता की अपेक्षाओं की आपूर्ति की संभावनाएं समाहित है चाहे वह आर्थिक प्रगति का मामला हो या सामाजिक विकास अथवा विज्ञान या ज्ञान का मामला हो, सभी के दर्द की दवा यह अकेला वाक्य करने में समर्थ है। इसकी वजह यह है कि जब कोई भी सरकारी योजना या कार्यक्रम अथवा विकास की रूपरेखा तैयार होगी तो उसके केन्द्र में गरीब आदमी ही रहेगा और जो भी काम होगा वह उसके स्तर को ऊपर उठाने की गरज से ही होगा। राष्ट्रपति ने इस मुद्दे का खुलासा भी बहुत खूबसूरती के साथ किया है कि गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, मूर्ख की कोई नस्ल नहीं होती और मुफलिसी का कोई भूगेल नहीं होता।

इसी का अर्थ है कि 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत है। ऐसा भारत तभी बन सकता है जब सुशासन के जरिए विकास के काम हो और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा।

श्री रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री राजीव प्रताप रूडी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं समझता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण किसी भी सरकार की नीति और नियति का खुलासा है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण किसी भी सरकार का मूल दस्तावेज होता है। किसी भी सरकार की नीति और नियति का खुलासा होने के साथ-साथ सरकार के विजन और मिशन को प्रदर्शित करता है। मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यदि यह सारा का सारा जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, यह सरकार की नीति और नियति दोनों का खुलासा करता है और यह इसके मिशन और विजन को प्रदर्शित करता है चाहे वह सरकार के सभी वर्गों के किसानों के प्रति समर्पित हो, चाहे गरीबों के लिए समर्पित हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो या महिलाओं के लिए हो या हर वर्ग के लिए समर्पित होकर एक सूत्र में जिस तरीके से यह अभिभाषण आया है, यह निश्चित तौर से वंदनीय है। मैं समझता हूं कि चाहे शहरों के लिए हो या गांवों के लिए हो, चाहे किसी अल्पसंख्यक वर्ग हो या अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, किसी भी धर्म या किसी भी क्षेत्र में चाहे वह कोई पर्वतीय क्षेत्र हो या कोई पिछड़ा राज्य हो, छोटे से कुछ पेजों के इस दस्तावेज में पूरा एक निचोड़ दिया है कि हम उस भारत को जिसने गरिमा खोई थी, उसको पुनर्स्थापित करके विश्व के शिखर तक पहुंचाएंगे।

मैं समझता हूं कि नीतियों की दिशा में चाहे कृषि नीति हो या विदेश नीति हो या युवा नीति हो या खेल नीति हो या स्वास्थ्य नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो या पर्यटन नीति हो, चाहे जल नीति हो, मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि समय मेरे पास और आपके पास कम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलना है, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जिस बात को दस बिन्दुओं में समाहित किया था, मैं समझता हूं कि वह छोटा सा गुलदस्ता पूरे देश को दुनिया में शिखर पर पहुंचाने के लिए एक मार्ग तय करता है।

मैं उत्तराखंड से आता हूं। ऐसा उत्तराखंड जो भारत का भाल है। जिस माथे पर आंख भी है तो नाक भी है। कान भी है तो मुंह भी है और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मस्तिष्क भी है। यदि माथा सशक्त होगा तो शरीर का भी अस्तित्व होगा। ये वो उत्तराखंड है जो वेद, पुराणों और उप-निषदों का जन्मदाता है। यह उत्तराखंड है जो ओशो-वेद-आयुर्वेद कहकर पूरी दुनिया के तन और मन को ठीक करने का माद्दा रखता है। यहां हिमालय है, जहां गंगा भी स्वर्ग से अवतरित होकर इस धरती पर विश्व के कल्याण के लिए आती है। मुझे आज गौरव होता है, खुशी होती है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया है। मैं आज इस अवसर पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूं। उत्तराखंड जो देश का माथा है, जिसके लिए 50 वर्षों से हम चीखते और चिल्लाते रहे कि इस माथे को सशक्त करने की जरूरत है लेकिन कांग्रेस ने उसको कुचला, उसकी उपेक्षा की, छल कपट किया। यहां देशभक्त लोग हैं, जहां औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमा पर अपनी कुर्बानी देता है और दूसरे पंक्ति में उसकी मां और बहनें सैनानियों के होते हुए दो-दो विदेशी सीमाओं पर रहकर देशभक्ति का अनन्य प्रमाण देते हैं।

माननीय अध्यक्ष, छावनी और पानी देश को समर्पित है, यहां तक कि ऑक्सीजन भी। 65 प्रतिशत वनाच्छित क्षेत्र देश को ऑक्सीजन देता है। ऐसा क्षेत्र देश की ताकत बनने के लिए है। मुझे गौरव होता है कि माननीय अटल बिहारी जी ने राज्य दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, औद्योगिक पैकेज दिया। वहीं दूसरी ओर देश के अंदर यूपीए सरकार का पहली बार शर्मनाक उदाहरण हुआ होगा जब किसी सरकार ने किसी पिछड़े क्षेत्र को, ऐसा क्षेत्र जो देशभक्त क्षेत्र है, कुछ पैकेज दिया हो और दूसरी सरकार ने छीन लिया हो। हां, मैं मुख्यमंत्री था, मैं और प्रेम कुमार धूमल जी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने गिड़गिड़ाए। हम आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में गए। आदरणीय गडकरी जी, आरदरणीय सुषमा जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में गए कि ऐसे क्षेत्र के साथ कम-से-कम अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप कुछ नया मत दीजिए लेकिन जो मिला है उसे मत छीनिए। आज पांच लाख नौजवानों को जो रोजगार मिलना था, उनके सीने पर छुरा घोंपा गया। मैं यह संदर्भ केवल इसलिए कहना चहाता हूं कि जो गंगा मां का अभियान लिया है, गंगा के लिए अलग मंत्रालय बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं।...*(व्यवधान)* मुझे भरोसा है कि उसी भागीरथ की तरह, गंगा की तरह जो गंगोत्री से तमाम थपेड़े खाने के बाद, तमाम प्रदूषण अपने में समाने के बाद पवित्रता नहीं खोती है, ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम थपेड़े खाने के बाद भी इस राष्ट्र को उसके शिखर तक पहुंचाएंगे।

[अनुवाद]

***डॉ. थोकचोम मेन्या** (आतंरिक मणिपुर) : मैं माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा प्रस्तुत और माननीय श्री रामविलास पासवान द्वारा समर्पित प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि उनकी नई सरकार मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने, विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए कदम उठाएगी। हमारे साथी नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने का केवल एक यही रास्ता है। माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 1 में हमारी प्राथमिकता अर्थात् "उनकी (हमारी साथी नागरिकों) सेवा करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए" की पहचान करने के लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमारे जैसे विकासशील देश में, जहां लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, हमारे नागरिकों को सशक्त बनाना एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे कैसे करना है यह हमारे सम्पूर्ण प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह संभव है। यह उनके अभिभाषण के पैरा संख्या 4, 5 और 6 में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। नागरिकों को सशक्त बनाते हुए सरकार स्वच्छ शासन के माध्यम से विकास द्वारा लोगों को भरोसा दिलाने में सक्षम होनी चाहिए। इस तरह हम न्यूनतम सरकार और अधिकतम सरकार के साथ लोकतंत्र की संस्थाओं की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने के लिए एक साथ कार्य करेंगे। अब तक सब अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं नई सरकार के साथ है। तथापि, सावधानी बरतनी चाहिए। करने की बजाय सदैव कहना आसान होता है। हम सभी को याद रखना चाहिए कि मार्ग भले ही लंबा हो परन्तु निरंतरता बनाए रखकर हमारी यात्रा चलती रहनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि शासन करना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि समाज हमेशा ही प्रगतिशील होता है। मैं इस सम्माननीय सभा में सभी माननीय सदस्यों से बहुत आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं कि शासन में निरतंरता बनाए रखने के लिए वे अपना पूर्ण सहयोग करें।

अभिभाषण के पैरा 20 में, 'एक सामंजस्यपूर्ण टीम इंडिया' और 'सहकारी संघवाद' के उल्लेख के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास परिषद् और अंतर्राज्यीय परिषद् को जीवंत कर 'मिश्रित भारत' का उल्लेख किया गया है जिसमें पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र; पूर्वी क्षेत्रों का पश्चिमी क्षेत्रों के समान होना; आंध्र प्रदेश और तेलंगाना; उत्तर-पूर्व और जम्मू और कश्मीर – अवैध आप्रवासी और सीमा तारबंदी – कश्मीरी पंडित शामिल हैं। सभी कुछ मिश्रित है। उत्तर-पूर्व भारत में घुसपैठियों का कोई उल्लेख नहीं है। अभी-अभी जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व में सुरक्षा स्थिति में अमानवीय सुधार दिखा है। हम इसके बारे में बहुत प्रसन्न हैं। हम सभी प्रार्थना करें कि यह प्रवृत्ति जारी रहे और उम्मीद करें कि शांति बनी रहे क्योंकि हम जानते हैं शांति ही विकास करती है।

हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्र, चाहे उत्तर-पूर्व या जम्मू और कश्मीर, जो अन्यथा विशेष श्रेणी राज्यों के रूप में वर्गीकृत हैं नुकसान उठाते हैं। इन राज्यों में, सशस्त्र बल (विशेष) शक्तियां अधिनियम (एएफएसपीए) को लगाया जा चुका है और थलसेना यहां अधिनियम के अंतर्गत

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

घुसपैठ-विरोधी अभियान में लगी हुई है। यह अधिनियम थलसेना को केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना अभियोजित करने से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

मैं हमेशा इस एएफएसपीए के हटाने के पक्ष में हूं। इस अमानवीय अधिनियम को हटाने का समय आ गया है। मैं केंद्र सरकार से बहुत गंभीरता से आग्रह करता हूं – मानवता के लिए कृपया इस अधिनियम को हटाएं। इस अधिनियम के अंतर्गत, मणिपुर राज्य में कई अनाथ, विधवा, अभिभावक हैं जिन्हें अपने गुमशुदा बच्चों की जानकारी नहीं है। संप्रग शासन के दौरान, इस एएफएसपीए को हटाने के लिए चार सिफारिशें की गई हैं। यह एएफएसपीए स्पष्ट रूप से पुराना हो चुका है। इस पुराने कानून को हटाया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में **मणिपुर राज्य की क्षेत्रीय अखंडता** के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। तत्कालीन संप्रग सरकार मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध थी। मणिपुर ने अपनी स्वतंत्रता 1891 में ब्रिटिश के अधीन कर दी। जब 1947 में ब्रिटिश अधिपत्य समाप्त हुआ, मणिपुर स्वत: एक स्वतंत्र संप्रभु साम्राज्य बना। मणिपुर 1947 तक इसके अपने संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के साथ एक राजतंत्र के अधीन था, जब मणिपुर साम्राज्य भारतीय संघ (यूओआई) के साथ विलय हो गया था। यूओआई के साथ विलय होने तक मणिपुर का एक स्पष्ट क्षेत्र था। हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते। भारतीय संघ को मेरे राज्य, मणिपुर की क्षेत्रीय सीमाओं का सम्मान और रक्षा करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, विगत राजग काल के दौरान, 2001 में भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) के बीच युद्ध विराम का बैंकॉक घोषणा समझौता को 'क्षेत्रीय सीमाओं के पार' बढ़ा दिया गया था। इस समझौते द्वारा एनएससीएन (आईएम ने मणिपुर के चार जिलों, अरुणाचल प्रदेश के दो जिलों और अक्षम के एक जिले को नागालिम (ग्रेटर नागालैंड) में विलय किए जाने का दावा किया है। इससे मणिपुर में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति बन गई है। वहां बड़ी जन क्रांति हुई और मुख्यमंत्री के बंगले सहित कई सरकारी कार्यालयों के साथ मणिपुर विधान सभा को जला दिया गया था। क्रांति के दौरान कीमती जानें गंवा दी गईं। तब भारत सरकार ने तीन शब्दों "क्षेत्रीय सीमाओं के पार" को वापस लिया।

हम सभी केन्द्र सरकार से मणिपुर और अन्य राज्यों की क्षेत्रीय सीमा को प्रभावित किए बिना दर्द भरे दर्दनाक नागा मुद्दे के शीघ्र समाधान रखने का आग्रह करते हैं। अभिभाषण के पैरा 39 में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में अत्याकि सतर्कता बरतेंगी। आतंकवाद, चरमपंथ, दंगा और नाक्रो आतंकवाद और साइबर खतरों सहित अपराधों को बिल्कुल भी नहीं सहने की नीति अपनाई जाएगी। यह वास्तव में काफी उत्साहवर्धक है। मैं महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की विनम्रता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र एवं जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ हम सबके लिए काफी चिंतापूर्ण है।

3एस – स्किल, स्केल, स्पीड

5टी – ट्रेडिशन, टेलेंट, टूरिज्म, ट्रेड और टेक्नोलॉजी

3डी – डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड

कृपया और एसटीडी न बनाएं।

अगला विषय आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मामला है। हम सबकी दिली आशा है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तत्काल स्थिर हो जाएं। तथापि, हम सभी को इस तथ्य का पता है कि देश के विशाल आकार और इसकी आबादी पर विचार करते हुए, यह स्वाभाविक है कि सीमित आपूर्ति की तुलना में मांगें ज्यादा हैं। मांग-आपूर्ति का यह सिद्धांत, बहुत हद तक, मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। परंतु हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते। हमारी राजसहायता पद्धति के साथ, हमें इसे ईमानदारी और शीघ्रता से कम करने का उपाय करना चाहिए। मैं बड़े सम्मान से यह तथ्य रखता हूं कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के बेहतर कार्यक्रमों और कल्याणकारी उपायों ने इस दिशा में परिणाम देने में चमत्कार किया है।

इसका एक अन्य कारण किसी भी सरकार का सेवा निष्पादन करने वाले तंत्र होते हैं। मैं यहां पर संघ सरकारों अर्थात राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के सम्मिलित उत्तरदायित्वों का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अभी भी संघ सरकारों के कई विभागों में पारदर्शिता की कमी है। इस योजना और इन कार्यक्रमों को न्यायोचित रूप से समग्ररुपेण लागू किए जाने की आवश्यकता है। इनके लिए भी केन्द्र सरकार के नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि यह योजनाएं उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनको इनकी आवश्यकता है।

अब मैं देश और देश के बाहर आतंकवाद के मुद्दे के समाधान के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहता हूं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एक अहम मुद्दा है। आतंकवाद, जैसा मैं समझता हूं, मानवता के विरुद्ध एक युद्ध है। इस संबंध में हमारी सरकार की शून्य सहनशीलता नीति अक्षरस: व्यवहार में लाया जाये। लाखों लोगों के त्याग से इस सभ्यता का विकास हुआ है जहां अभी भी वही विचाराधारा जाएं है कि राजा गलत कार्य नहीं करता और यही मानवता की सबसे दु:खद स्थिति रही है।

हम लोगों को जो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, को बेहतर विश्व के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए और काम करना चाहिए ताकि उनके बच्चे जन्म अपनी जिंदगी खुशी से जी सकें। ऐसा करके हम अपने बच्चों को बेहतर कल देने में समर्थ होंगे। अंत में, मैं माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा प्रस्तुत और माननीय श्री रामविलास पासवान द्वारा समर्थित प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं और सभी माननीय सदस्यों से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय प्रधानमंत्री जी।

प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में पहली बार, मेरा प्रवेश भी नया है और भाषण का अवसर भी पहली बार मिला।...*(व्यवधान)*

इस सदन की गरिमा, परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफी अनुभवी तीन-चार दशक से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी विराजमान हैं। जब मुझे जैसा एक नया व्यक्ति कुछ कह रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोक सभा में 50 से अधिक आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सदन में रहते हुए और कुछ अपने कमरे में करीब-करीब सभी भाषण सुने हैं।

आदरणीय मल्लिकार्जुन जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, डॉ. थम्बीदुराई जी, भर्तृहरि जी, टी.एम.सी. के नेता तथा सभी वरिष्ठ महानुभावों को मैंने सुना। एक बात सही है कि एक स्वर यह आया है कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, इन्हें कैसे करोगे, कब करोगे। मैं मानता हूं कि सही विषय को स्पर्श किया है और यह मन में आना बहुत स्वाभाविक है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूं, मैं नया-नया गुजरात में मुख्यमंत्री बनकर गया था और एक बार मैंने सदन में कह दिया कि मैं गुजरात के गांवों में, घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। खैर ट्रेजरी बैंच ने बहुत तालियां बजाईं, लेकिन सामने की तरफ सन्नाटा था। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता थे, चौधरी अमर सिंह जी, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बड़े सुलझे हुए नेता थे। वह बाद में समय लेकर मुझे मिलने आये। उन्होंने कहा कि मोदी जी, कहीं आपकी कोई चूक तो नहीं हो रही है, आप नये हो, आपका अनुभव नहीं हैं, यह 24 घंटे बिजली देना इस्पासिबल है, आप कैसे दोगे। एक मित्र भाव से उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि हम करेंगे। वह बोले संभव ही नहीं है। दो हजार मेगावाट अगर डेफिसिट है तो आप कैसे करोगे। उनके मन में वह विचार आना बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन मुझे इस बात का आनन्द है कि वह काम गुजरात में हो गया था। अब इसलिए यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभावों के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। अभी तक नहीं हुआ, इसलिए शक होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है, उसे पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारे लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सिर्फ परम्परा और रिचुअल नहीं है। हमारे लिए उनके माध्यम से कही हुई हर बात एक सैंक्टिटी है, एक पवित्र बंधन है और उसे पूरा करने का हमारा प्रयास भी है और यही भावना हमारी प्रेरणा भी बन सकती है, जो हमें काम करने की प्रेरणा दे। इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को आने वाले समय के लिए हमने हमेशा एक गरिमा देनी चाहिए, उसे गंभीरता भी देनी चाहिए और सदन में हम सबने मिलकर उसे पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए।

जब मतदान हुआ, मतदान होने तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में आने के बाद हम जनता की उम्मीदों के दूत हैं। तब तो हम उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। किसी का दायित्व दूत के रूप में उसे परिपूर्ण करना होगा, किसी का दायित्व अगर कुछ कमी रहती है तो रखवाले बनकर पूरी आवाज उठाना, यह भी एक उत्तम दायित्व है। हम सब मिल कर उस दायित्व को निभायेंगे।

मुझे इस बात का संतोष रहा कि अधिकतम इस सदन में जो भी विषय आए हैं, छोटी-मोटी नोंक-झोंक तो आवश्यक भी होती है। लेकिन पूरी तरह सकारात्मक माहौल नजर आया। यहां भी जो मुद्दे उठाये गये, उनके भीतर भी एक आशा थी, एक होप थी। यानी देश के सवा सौ करोड़ नागरिकों ने जिस होप के साथ इस संसद को चुना है, उसकी प्रतिध्वनि इस तरफ बैठे हो या उस तरफ बैठे हुए हों, सबकी बातों में मुखर हुई है, यह मैं मानता हूं। यह भारत के भाग्य के लिए एक शुभ संकेत है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चुनाव, मतदाता, परिणाम की सराहना की है। मैं भी देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कई वर्षों के बाद देश ने स्थिर शासन के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए, मत दे कर 5 साल के लिए विकास की यात्रा को सुनिश्चित किया है। भारत के मतदाताओं की ये चिंता, उनका यह चिंतन और उन्होंने हमें जो जिम्मेवारी दी है, उसको हमें परिपूर्ण करना है। लेकिन हमें एक बात सोचनी होगी कि दुनिया के अंदर भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस रूप में तो कभी-कभार हमारा उल्लेख होता है। लेकिन क्या समय की मांग नहीं है कि विश्व के सामने हम कितनी बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं, हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी ऊंची हैं, हमारे सामान्य से सामान्य, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की रंगों में भी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा कितनी अपार है। अपनी सारी आशा और आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक परंपराओं के माध्यम से परिपूर्ण करने के लिए वह कितना जागृत है। क्या कभी दुनिया में, हमारी इस ताकत को सही रूप में प्रस्तुत किया गया है? इस चुनाव के बाद हम सबका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि विश्व को डंके की चोट पर हम यह समझाएं। विश्व को हम प्रभावित करें। पूरा यूरोप और अमेरिका मिल कर जितने मतदाता हैं, उससे ज्यादा लोग हमारे चुनावों में शरीक होते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी ताकत है। क्या विश्व के सामने, भारत के इस सामर्थवान रूप से कभी हमने प्रकट किया है? मैं मानता हूं कि यह हम सब का दायित्व बनता है। यह बात

सही है कि कुछ वैक्युम है। 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हमसे थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिले तो, सर ऊंचा कर के बात करने की हमारी ताकत नहीं होती है। कभी-कभार चमड़ी का रंग भी हमें प्रभावित कर देता है। उन सारी बातों से बाहर निकल कर भारत जैसा सामर्थ्यवान लोकतंत्र और इस चुनाव में इस प्रकार का प्रगट रूप, अब विश्व के सामने ताकतवर देश के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है। हमें दुनिया के सामने सर ऊंचा कर, आंख में आंख मिला कर, सीना तान कर, भारत के सवा सौ करोड़ नागरिकों के सामर्थ को प्रकट करने की ताकत रखनी चाहिए और उसको एक एजेंड़ा के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। भारत का गौरव और गरिमा इसके कारण बढ़ सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है इस देश पर सबसे पहला अधिकार किसका है? सरकार किसके लिए होनी चाहिए? क्या सरकार सिर्फ पढ़े-लिखे लोगों के लिए हो? क्या सरकार सिर्फ इने-गिने लोगों के लाभ के लिए हो? मेरा कहना है कि सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। अमीर को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो वह दुनिया का कोई भी टीचर हायर कर सकता है। अमीर के घर में कोई बीमार हो गया तो सैकड़ों डॉक्टर तेहरात में आ कर खड़े हो सकते हैं, लेकिन गरीब कहां जाएगा? उसके नसीब में तो वह सरकारी स्कूल है, उसके नसीब में तो वह सरकारी अस्पताल है और इसीलिए सब सरकारों का यह सबसे पहला दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुनें और गरीबों के लिए जियें। अगर हम सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं चलाते हैं तो देश की जनता हमें कतई माफ नहीं करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदया जी, यह इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। हम तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के आदर्शों से पले हुए लोग हैं। जिन्होंने हमें अंत्योदय की शिक्षा दी थी। गांधी, लोहिया और दीन दयाल जी, तीनों के विचार सूत्र को हम पकड़े हैं, तो आखिरी मानविकी छोर पर बैठे हुए इन्सान के कल्याण का काम इस शताब्दी के राजनीति के इन तीनों महापुरुषों ने हमें एक ही रास्ता दिखाया है कि समाज के आखिरी छोर पर जो बैठा हुआ इन्सान है, उसके कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। यह हमारी प्रतिबद्धता है। अंत्योदय का कल्याण, यह हमारी प्रतिबद्धता है। गरीब को गरीबी से बाहर लाने के लिए उसके अंदर वह ताकत लानी है जिससे वह गरीबी के खिलाफ जूझ सके। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार होता है – "शिक्षा"। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है – "अंधश्रद्धा से मुक्ति"। अगर गरीबों में अंधश्रद्धा के भाव पड़े हैं, अशिक्षा की अवस्था पड़ी है, अगर हम उसमें से उसे बाहर लाने में सफल होते हैं, तो इस देश का गरीब किसी के टुकड़ों पर पलने की इच्छा नहीं रखता है। वह अपने बलबूते पर अपनी दुनिया खड़ी करने के लिए तैयार है। सम्मान और गौरव से जीना गरीब का स्वभाव है। अगर हम उसकी उस मूलभूत ताकत को पकड़कर उसे बल देने का प्रयास करते हैं और इसलिए सरकार की योजनाएं गरीब को गरीबी से बाहर आने की ताकत दें। गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दें। शासन की सारी व्यवस्थायें गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए और सारी व्यवस्थाओं का अंतिम नतीजा उस आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के लिए काम में आए उस दिशा में प्रयास होगा, तब जाकर उसका कल्याण हम कर पाएंगे।

हम सदियों से कहते आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यह गांवों का देश है। ये नारे तो बहुत अच्छे लगे, सुनना भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम आज अपने सीने पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि हम हमारे गांव के जीवन को बदल पाए हैं, हमारे किसानों के जीवन को बदल पाए हैं। यहां मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि भारत के गांवों के जीवन को बदलने के लिए उसको हम अग्रिमता दें, किसानों के जीवन को बदलने के लिए उसको अग्रिमता दें। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उस बात को करने के लिए हमने कोशिश की है। यहां एक विषय ऐसा भी आया कि कैसे करेंगे? हमने एक शब्द प्रयोग किया है – "रुर्बन"। गांवों के विकास के लिए जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने देखा है। जहां सुविधा शहर की हो, आत्म गांव की हो। गांव की पहचान गांव की आत्मा में बनी हुई है। आज भी वह अपनापन, गांव में एक बारात आती है तो पूरे गांव को लगता है कि हमारे गांव की बारात है। गांव के एक मेहमान आता है तो पूरे गांव को लगता है कि यह हमारे गांव का मेहमान है। यह हमारे देश की एक अनमोल विरासत है। इसको बनाना है, इसको बचाये रखना है, लेकिन हमारे गावं के लोगों को आधुनिक सुविधा से हम वंचित रखेंगे क्या? मैं अनुभव से कहता हूं कि अगर गांव को आधुनिक सुविधाओं से सज्ज किया जाये तो गांव देश की प्रगति में ज्यादा कान्ट्रिब्यूशन कर रहा है। अगर गांव में भी 24 घंटे बिजली हो, अगर गांव को भी ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी मिले, गांव के बालक को भी उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले; पल भर के लिए मान लें कि शायद हमारे गांव में अच्छे टीचर न हों, लेकिन आज का विज्ञान हमें लांग डिस्टैन्स एजुकेशन के लिए पूरी ताकत देता है। शहर में बैठकर भी उत्तम से उत्तम शिक्षक के माध्यम से गांव के आखिरी छोर पर बैठे हुए स्कूल के बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। हम सैटेलाइट व्यवस्था का उपयोग, उस आधुनिक विज्ञान का उपयोग उन गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों न करें? अगर गांव के जीवन में हम यह बदलाव लाएं तो किसी को भी अपना गांव छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा। गांव के नौजवान को क्या चाहिए? अगर रोज़गार मिल जाए तो वह अपने मां-बाप के पास रहना चाहता है। क्या गांवों के अंदर हम उद्योगों का जाल खड़ा नहीं कर सकते हैं? एट लीस्ट हम एक बात पर बल दें – एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पर। अगर हम मूल्यवृद्धि करें और मूल्यवृद्धि पर अगर हम बल दें। आज उसकी एक ताकत है, उस ताकत को हमने स्वीकार

किया तो हम गांव के आर्थिक जीवन को भी, गांव की व्यवस्थाओं के जीवन को भी बदल सकते हैं और किसान का स्वाभाविक लाभ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है।

सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, बहुत कम आबादी है। लेकिन उस छोटे से राज्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत ही निकट भविष्य में सिक्किम प्रदेश हिन्दुस्तान के लिए गौरव देने वाला "ऑर्गैनिक स्टेट" बनने जा रहा है। वहां का हर उत्पादन ऑर्गैनिक होने वाला है। आज पूरे विश्व में ऑर्गैनिक खेत उत्पादन की बहुत बड़ी मांग है। होलिस्टिक हैल्थकेयर की चिन्ता करने वाला एक पूरा वर्ग है दुनिया में, जो जितना मांगो उतना दाम देकर ऑर्गैनिक चीज़ें खरीदने के लिए कतार में खड़ा है। यह ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए सिक्किम के किसानों ने जो मेहनत की है, उसको जोड़कर अगर हम इस योजना को आगे बढ़ाएं तो दूर-सुदूर हिमालय की गोद में बैठा हुआ सिक्किम प्रदेश कितनी बड़ी ताकत के साथ उभर सकता है। इसलिए क्या कभी हम सपना नहीं देख सकते हैं कि हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गैनिक स्टेट के रूप में हम कैसे उभार सकें। पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर ऑर्गैनिक स्टेट के रूप में हम उभारें और विश्व के मार्केट पर कब्ज़ा करने के लिए भारत सरकार की तरफ से उनको मदद मिले तो वहां दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की ज़िन्दगी में, कृषि के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारी इतनी कृषि यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत रिसर्च हो रही हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य रहा है कि जो लैब में है, वह लैंड पर नहीं है। लैब से लैड तक की यात्रा में जब तक हम उस पर बल नहीं देंगे, आज कृषि को परंपरागत कृषि से बाहर लाकर आधुनिक कृषि की ओर ले जाने की आवश्यकता है। गुजरात ने एक छोटा सा प्रयोग किया था – सॉयल हैल्थ कार्ड। हमारे देश में मनुष्य के पास भी अभी हैल्थ कार्ड नहीं है। लेकिन गुजरात में हमने एक इनीशियेटिव लिया था। उसकी ज़मीन की तबीयत का उसके पास कार्ड रहे। उसके कारण से पता चला कि उसकी ज़मीन जिस क्रॉप के लिए उपयोगी नहीं है, वह उसी फसल के लिए खर्चा कर रहा था। जिस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, उतनी मात्रा में वह फर्टिलाइज़र डालता था। जिन दवाइयों की कतई ज़रूरत नहीं थी, वह दवाइयां लगाता था। बेकार ही साल भर में 50 हज़ार रुपये या लाख रुपये यूं ही फेंक देता था। लेकिन सॉयल हैल्थ कार्ड के कारण उसको समझ आई कि उसकी कृषि को कैसे लिया जाए। क्या हम हिन्दुस्तान के हर किसान को सॉयल हैल्थ कार्ड देने का अभियान पूर्ण नहीं कर सकते? हम इसको कर सकते हैं। सॉयल टैस्टिंग के लिए भी हम अध्ययन के साथ कमाई का एक नया आयाम ले सकते हैं। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे करोगे, मैं इसलिए एक विषय को लंबा खींचकर बता रहा हूं कि कैसे करेंगे।

हमारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडैन्ट्स अप्रैल, मई और जून में गांव जाते हैं और पूरे हिन्दुस्तान में 10+2 के जो स्कूल्स हैं, जिनमें एक लैबोरेटरी होती है। क्यों न वैकेशन में उन लैबोरेटरीज़ को "सॉयल टैस्टिंग लैबोरेटरीज़" में कनवर्ट किया जाए। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के स्टूडैन्ट्स जो वैकेशन में अपने गांव जाते हैं, उनको स्कूलों के अंदर काम में लगाया जाए और वैकेशन के अंदर वे अपना सॉयल टैस्टिंग का काम उस लैबोरेटरी में करें। उस स्कूल को कमाई होगी और उसमें से अच्छी लैबोरेटरी बनाने का इरादा बनेगा। एक जन आंदोलन के रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? कहने का तात्पर्य यह है कि हम छोटे-छोटे प्रायोगिक उपाय करेंगे तो हम चीज़ों को बदल सकते हैं।

आज हमारे रेलवे की आदत क्या है? वह लकीर के फकीर हैं। उनको लिखा गया है कि मण्डे को जो माल आए, वह एक वीक के अंदर चला जाना चाहिए। अगर मण्डे को मार्बल आया है स्टेशन पर, जिसे मुम्बई पहुंचाना है और ट्यूज़डे को टमाटर आया है, तो वह पहले मार्बल भेजता है, बाद में टमाटर भेजता है। क्यों? मार्बल अगर चार दिन बाद पहुंचेगा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर टमाटर पहले पहुंचता है तो कम-से-कम वह खराब तो नहीं होगा। हमें अपनी पूरी व्यवस्था को सैंसेटाइज़ करना है।

आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर दुनिया में हम छाये हुए रहे, साफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हमारी पहचान बन गई लेकिन आज हमारे देश के पास एग्रो प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा नहीं है। क्या हम इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क के माध्यम से एग्रो प्रोडक्ट का रीयल टाइम डाटा इक्ट्ठा कर सकते हैं? हमने महंगाई को दूर करने का वायदा किया है और हम इस पर प्रमाणिकता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह इसलिए नहीं कि यह केवल चुनावी वायदा था इसलिए करना है, यह हमारी सोच है कि गरीब के घर में शाम को चूल्हा जलना चाहिए। गरीब के बेटे आंसू पीकर के सो जाएं, इस स्थिति में बदलाव आना चाहिए। यह हम सभी का कर्त्तव्य है चाहे राज्य सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो। हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हिन्दुस्तान का कोई गरीब भूखा न रहे। इस कर्त्तव्य की पूर्ति के लिए हम इस काम को करना चाहते हैं। अगर रीयल टाइम डाटा हो तो आज भी देश में अन्न के भंडार पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अन्न के भंडार नहीं हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी है। अगर सरकार के पास यह जानकारी हो कि कहां जरूरत है, रेलवे का जब लाल पीरियड हो उस समय उसे तभी शिफ्ट कर दिया जाए और वहां अगर गोदाम बनाएं जाएं और वहां रख दिया जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सालों में एक ढांचा चल रहा है। क्या उसे आधुनिक नहीं बनाया जा सकता है? प्रोक्योरमेंट का काम कोई और करे, रिजर्वेशन का काम कोई अलग करे, डिस्ट्रिब्यूशन का काम कोई अलग करे, एक ही व्यवस्था को अगर तीन हिस्सों में बांट दिया जाए और तीनों की रिस्पोंसिबिलटी बना दी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम इन स्थितियों को बदल सकते हैं।

एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे किसानों को, अभी एक बात पर बल देना पड़ेगा, यह समय की मांग है। जैसा मैंने आधुनिक खेती के बारे में कहा, हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में जितनी तेजी से लाएंगे उतना लाभ होगा क्योंकि परिवारों का विस्तार होता जा रहा है और जमीन कम होती जा रही है। हमें जमीन में प्रोडक्टीविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का काम बढ़ाना पड़ेगा। कितने वर्षों से दालों पर कोई रिसर्च नहीं हुआ है। दालें हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। आज गरीब आदमी को प्रोटीन पाने के लिए दालों के अलावा कोई उपाय नहीं है। दालें ही हैं, जिनके माध्यम से उसे प्रोटीन प्राप्त होता है और शरीर की रचना में प्रोटीन का बहुत महत्व होता है। अगर कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें इन सवालों को एड्रेस करना होगा। दालों के क्षेत्र में कई वर्षों से न हम प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा ले पाए हैं और न ही दालों के अंदर प्रोटीन कंटेंट के अंदर वृद्धि कर पाए हैं। हम शुगरकेन में शुगर कंटेंट बढ़ाने में सफल हुए हैं, लेकिन हम दालों में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हमारे वैज्ञानिक, हमारी कृषि यूनिवर्सिटीज को प्रेरित करेंगे? हम इन समस्याओं पर क्यूमलेटिव इफैक्ट के साथ अगर चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो मैं मानता हूं कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसका यह रास्ता है।

हमारी माताएं-बहनें, जो हमारी पचास परसेंट की जनसंख्या है, भारत की विकास यात्रा में उन्हें निर्णय में, भागीदार बनाने की जरूरत है। उन्हें हमें आर्थिक प्रगति से जोड़ना होगा। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है तो हिन्दुस्तान की पचास प्रतिशत हमारी मातृ शक्ति है, उसकी सक्रिय भागीदारी को हमें निश्चित करना होगा। उनके सम्मान की चिंता करनी होगी, उनकी सुरक्षा की चिंता करनी होगी।

पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी हैं, हम सत्ता में हों या न हों, पीड़ा करने वाली घटना है। चाहे पुणे की हत्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुई हत्या हो, चाहे मनाली में डूबे हुए हमारे नौजवान हों, चाहे हमारी बहनों पर हुए बलात्कार हो, ये सारी घटनाएं, हम सब को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करती हैं। सरकारों को कठोरता से काम करना होगा। देश लम्बा इंतज़ार नहीं करेगा, पीड़ित लोग लम्बा इंतज़ार नहीं करेंगे और हमारी अपनी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं तो राजनेताओं से अपील करता हूं। मैं देश भर के राजनेताओं को विशेष रूप से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि बलात्कार की घटनाओं का "मनोवैज्ञानिक विश्लेषण" करना कम-से-कम हम बंद करें। हमें शोभा नहीं देता है। हम मां-बहनों की डिग्निटी पर खिलवाड़ करते हैं। हमें राजनीतिक स्तर पर, इस प्रकार की बयानबाजी करना शोभा देता है क्या? क्या हम मौन नहीं रह सकते? इसलिए नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा, यह हम सब की, सवा सौ करोड़ देशवासियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं! हम उस युग चक्र के अंदर आज जीवित है। हम उस युग चक्र में संसद में बैठे हैं जब हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है।

डेमोग्राफिक डिवीजन - इस ताकत को हम पहचानें। पूरे विश्व को आने वाले दिनों में लेबर फोर्स की, मैन पावर की, निपुण मेन पावर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो लोग इस शास्त्र के अनुभवी हैं, वे जानते हैं कि पूरे विश्व को निपुण मैन पावर की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में चीन बूढ़ा होता जा रहा है, हम नौजवान होते जा रहे हैं। यह एक एडवांटेज है। इसलिए दुनिया के सभी देश समृद्ध-से-समृद्ध देश का एक ही एजेंडा रहता है – स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश की प्राथमिकता होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट। उसके साथ-साथ हमें सफल होना है तो हमें 'श्रमेव जयते' – इस मंत्र को चरितार्थ करना होगा। राष्ट्र के निर्माण में श्रमिक का स्थान होता है। वह विश्वकर्मा है। उसका हम गौरव कैसे करें।

भाइयो-बहनो, भारत का एक परसेप्शन दुनिया में बन पड़ा है। हमारी पहचान बन गयी है स्कैम इंडिया की। हमारे देश की पहचान हमें बनानी है निपुण इंडिया की और उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए पहली बार एक अलग मंत्रालय बनाकर के – इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट – उस पर विशेष रूप से बल दिया गया है।

हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। किसी से पूछा जाए कि क्या पढ़े-लिखे हो तो वह कहता है कि ग्रैजुएट हूं, एम.ए. हूं, डबल ग्रैजुएट हूं। हमें अच्छा लगता है। मैंने बहुत बचपन में दादा धर्माधिकारी जी की एक किताब पढ़ी थी। महात्मा गांधी के विचारों के एक अच्छे चिंतक रहे, बिनोवा जी के साथ रहते थे। दादा धर्माधिकारी जी ने एक अनुभव लिखा था कि कोई नौजवान उनके पास नौकरी लेने गया। उन्होंने पूछा कि भाई, क्या करते हो, क्या पढ़े हो बगैरह। उस ने कहा कि मैं ग्रैजुएट हूं। फिर कहने लगा कि मुझे नौकरी चाहिए। दादा धर्माधिकारी जी ने उस से पूछा कि तुम्हें क्या आता है? उसने बोला – मैं ग्रैजुएट हूं। फिर उन्होंने कहा – हां, हां भाई, तुम ग्रैजुएट हो, पर बताओ तुम्हें क्या आता है? उसने बोला – नहीं, नहीं। मैं ग्रैजुएट हूं। चौथी बार पूछा कि तुम्हें बताओ क्या आता है। वह बोला मैं ग्रेजुएट हूं। हम इस बात से अनुभव कर सकते हैं कि जिन्दगी का गुजारा करने के लिए हाथ में हुनर होना चाहिए, सिर्फ हाथ में सर्टिफिकेट होने से बात नहीं होती। इसलिए हमें स्किल डेवेलपमेंट की और बल देना होगा, लेकिन स्किल्ड वर्कर जो हैं, उसका एक सामाजिक स्टेट्स भी खड़ा करना पड़ेगा। सातवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ बच्चा, गरीबी के कारण स्कूल छोड़ देता है। कहीं जा करके स्किल डेवेलपमेंट के कोर्स का सौभाग्य मिला, चला जाता है, लेकिन लोग उसको महत्व नहीं देते, अच्छा सातवीं पढ़े हो, चले जाओ। हमें उसकी इक्वीवैलंट व्यवस्था खड़ी

करनी पड़ेगी। मैंने गुजरात में प्रयोग किया था। जो दो साल की आईटीआई करते थे, मैंने उनको दसवीं के इक्वल बना दिया, जो दसवीं के बाद आए थे, उनको 12वीं के इक्वल बना दिया। उनको डिप्लोमा या आगे पढ़ना है तो रास्ते खोल दिए। डिग्री में जाना है तो रास्ते खोल दिए। सातवीं पास था, लेकिन डिग्री तक जा सकता है, रास्ते खोल दिए। बहुत हिम्मत के साथ नये निर्णय करने होंगे।

अगर हम स्किल डेवेलपमेंट को बल देना चाहते हैं तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पैदा करनी होगी। मैंने कहा कि दुनिया में वर्क फोर्स की आवश्यकता है। आज सारे विश्व को टीचर्स की आवश्यकता है। क्या हिन्दुस्तान टीचर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। मैथ्स और साइंस के टीचर अगर हम दुनिया में एक्सपोर्ट करें, एक व्यापारी विदेश जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा डॉलर लेकर आएगा, लेकिन एक टीचर विदेश जाएगा, तो पूरी की पूरी पीढ़ी अपने साथ समेट करके ले जाएगा। ये ताकत रखनी है। विश्व में हमारे सामर्थ्य को खड़ा करना है तो ये रास्ते होते हैं। क्या हम अपने देश में इस प्रकार के नौजवानों को तैयार नहीं कर सकते? ये सारी संभावनाएं पड़ी हैं, उन संभावनाओं को ले करके अगर आगे चलने का हम इरादा रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम परिणाम ला सकते हैं। दलित, पीड़ित, शोषित एवं वंचित हो।

हमारे दलित एवं वनवासी भाई-बाहनों, क्या हम विश्वास से कह सकते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद उनके जीवन में हम बदलाव ला सके हैं। ऐसा नहीं है कि बजट खर्च नहीं हुए, कोई सरकार के पास गंभीरता नहीं थी। मैं ऐसा कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि स्थिति में बदलाव नहीं आया। क्या हम पुराने ढर्रे से बाहर आने को तैयार हैं? हम सरकार की योजनाओं को कंवर्जेंस कर-करके, कम-से-कम समाज के इन तबकों को बाहर ला सकते हैं। क्यों नहीं उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। मुसलमान भाई, मैं देखता हूं, जब मैं छोटा था, जो साइकिल रिपेयरिंग करता था, आज उसकी तीसरी पीढ़ी का बेटा भी साइकिल रिपेयरिंग करता है। ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? उनके जीवन में बदलाव कैसे आए? इस बदलाव के लिए हमें फोकस एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उस प्रकार की योजनाओं को ले करके आना पड़ेगा। मैं उन योजनाओं को तुष्टिकरण के रूप में देखता नहीं हूं, मैं उनके जीवन को बदलाव के रूप में देखता हूं। कोई भी शरीर अगर उसका एक अंग विकलांग हो तो उस शरीर को कोई स्वस्थ नहीं मान सकता। शरीर के सभी अंग अगर सशक्त हों, तभी तो वह सशक्त शरीर हो सकता है। इसलिए समाज का कोई एक अंग अगर दुर्बल रहा तो समाज कभी सशक्त नहीं हो सकता है। इसलिए समाज के सभी अंग सशक्त होने चाहिए। उस मूलभूत भावना से प्रेरित हो करके हमें काम करने की आवश्यकता है और हम उससे प्रतिबद्ध हैं। हम उसको करना चाहते हैं। हमारे देश में विकास की एक नयी परिभाषा की ओर जाने की मुझे आवश्यकता लगी। क्या आजादी का आंदोलन, देश में आज़ादी की लड़ाई बारह सौ साल के कालखंड में कोई वर्ष ऐसा नहीं गया, जिसमें आज़ादी के लिए मरने वाले दीवाने न मिले हों। 1857 के बाद सारा स्वतंत्र संग्राम का इतिहास हमारे सामने है। हिन्दुस्तान का कोई भू-भाग ऐसा नहीं होगा, जहां से कोई मरने वाला तैयार न हुआ हो, शहीद होने के लिए तैयार न हुआ हो। सिलसिला चलता रहा था, फांसी के तख्त पर चढ़ करके देश के लिए बलिदान होने वालों की शृंखला कभी रूकी नहीं थी।

भाइयों और बहनों, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, जो आजादी के बाद पैदा हुए होंगे। कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं, जो आजादी के पहले पैदा हुए होंगे, आजादी की जंग में लड़े भी होंगे। मैं आजादी के बाद पैदा हुआ हूं। मेरे मन में विचार आता है। मुझे देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का मौका तो मिला है। हम यह बात लोगों तक कैसे पहुंचाये कि हम देश के लिए जियें और देश के लिए जीने का एक मौका लेकर वर्ष 2022 में जब आजादी के 75 साल हों, देश के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले उन महापुरुषों को याद करते हुए हम एक काम कर सकते हैं। बाकी सारे काम भी करने हैं, लेकिन एक काम हो प्रखरता से करें कि हिन्दुस्तान में कोई परिवार ऐसा न हो, जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। ऐसा घर जिसमें नल भी हो, नल में पानी भी हो, बिजली भी हो, शौचालय भी हो। यह एक मिनिमम बात है। एक आंदोलन के रूप में सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर, हम सभी सदस्य मिलकर अगर आठ-नौ साल का कार्यक्रम बना दें, धन खर्च करना पड़े, तो खर्च करें, लेकिन आजादी के 75 साल जब मनायें तब भगत सिंह को याद करके, सुखेदव को याद करके, राजगुरू को याद करके, महात्मा गांधी, सरदार पटेल इन सभी महापुरुषों को याद करके उनको हम मकान दे सकते हैं। अगर हम इस संकल्प की पूर्ति करके आगे बढ़ते हैं तो देश के सपनों को पूरा करने का काम हम कर सकते हैं।

मैं जानता हूं कि शासन में आने के बाद जिसको नापा जा सके, ऐसा कार्यक्रम हाथ में लेना बड़ा कठिन होता है। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैंने सरकार चलायी है। सरकार चलायी है, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई यह कैसे करोगे, यह कैसे होगा? उनकी सद्भावना के लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है, लेकिन हम मिल-बैठकर के रास्ता निकालेंगे। हम सपना तो देखे हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुछ कठिनाई आयेगी तो आप जैसे अनुभवी लोग हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। गरीब के लिए काम करना है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है।

यहां यह बात भी आयी, नयी बोतल में पुरानी शराब है। उनको शराब याद आना बड़ा स्वाभाविक है। यह भी कहा कि ये तो हमारी बातें हैं, आपने जरा ऊपर-नीचे करके रखी हैं, कोई नयी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हम कह रहे हैं, वह आपको भी पता था। कल से महाभारत की चर्चा हो रही है और मैं कहना चाहता हूं कि एक बार दुर्योधन से पूछा गया कि भाई यह धर्म और अधर्म, सत्य और झूठ तुमको समझ है कि नहीं है, तो दुर्योधन ने जवाब दिया था, उसने कहा कि जानामि धर्मम् न च मे प्रवृत्ति: मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन यह मेरी प्रवृत्ति नहीं है। सत्य क्या है, मुझे मालूम है। अच्छा क्या है, मुझे मालूम है, लेकिन वह मेरे डीएनए में नहीं है। इसलिए आपको पहले पता था, आप जानते थे, आप सोचते थे, मुझे इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन दुर्योधन को भी तो मालूम था। इसलिए जब महाभारत की चर्चा करते हैं, महाभारत लंबे अरसे से हमारे कानों में गूंजती रही है, सुनते आए हैं, लेकिन महाभारत काल पूरा हो चुका है। न पांडव बचे हैं, न कौरव बचे हैं, लेकिन जन-मन में आज भी पांडव ही विजयी हों, हमेशा-हमेशा भाव रहा है। कभी पांडव पराजित हों, यह कभी जन-मन का भाव नहीं रहा है।

भाइयों और बहनों, विजय हमें बहुत सिखाता है और हमें सीखना भी चाहिए। विजय हमें सिखाता है नम्रता, मैं इस सदन को विश्वास देता हूं, मुझे विश्वास है कि यहां के जो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे वह किसी भी दल के क्यों न हों, उनके आशीर्वाद से हम उस ताकत को प्राप्त करेंगे, जो हमें अहंकार से बचाये।

अपराह्न 5.00 बजे

जो हमें हर पल नम्रता सिखाए। यहां पर कितनी ही संख्या क्यों न हो, लेकिन मुझे आपके बिना आगे नहीं बढ़ना है। हमें संख्या के बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना है। इसलिए उस सामूहिकता के भाव को ले कर आगे बढ़ना चाहते हैं।

इन दिनों मॉडल की चर्चा होती है — गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। जिन्होंने मेरा भाषण सुना होगा उन्हें मैं बताता हूं कि गुजरात का मॉडल क्या है? गुजरात में भी एक जिले का मॉडल दूसरे जिले में नहीं चलता है। क्योंकि यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। अगर मेरा कच्छ का रेगिस्तान है और वहां का मॉडल मैं वलसाड में हरे-भरे जिले में लगाऊंगा तो नहीं चलेगा। इतनी समझ के कारण तो गुजरात आगे बढ़ा है।... *(व्यवधान)* यही उसका मॉडल है कि जिसमें यह समझ है।... *(व्यवधान)* गुजरात का दूसरा मॉडल यह है कि हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हो, उन अच्छी बातों से हम सीखते हैं, उन अच्छी बातों को हम स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में भी हम उस मॉडल को ले कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में अच्छा हुआ हो, जो अच्छा है, वह हम सब का है, उसको और जगहों पर लागू करने का प्रयास करना है।

कल तमिलनाडु की तरफ से बोल गया था कि तमिलनाडु का मॉडल गुजरात के मॉडल से अच्छा है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस देश में इतना तो हुआ कि विकास के मॉडल की स्पर्धा शुरू हुई है। ...*(व्यवधान)* एक राज्य कहने लगा कि मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से आगे बढ़ने लगा है। मैं मानता हूं कि गुजरात मॉडल का यह सबसे बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है कि पहले हम स्पर्धा नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में राज्यों के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा हो। राज्य और केन्द्र के बीच विकास की स्पर्धा हो। हर कोई कहे कि गुजरात पीछे रह गया है और हम आगे निकल गए हैं। यह सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। देश में यही होगा, तभी तो बदलाव आएगा। छोटे-छोटे राज्य भी बहुत अच्छा करते हैं। जैसा मैंने कहा है कि सिक्किम, ऑर्गेनिक स्टेट बना है। तमिलनाडु ने अर्बन एरिया में रेन हार्वेस्टिंग का जो काम किया है, वह हम सब को सीखने जैसा है। माओवाद के जुल्म के बीच जीने वाले राज्य छत्तीसगढ़ ने पी.डी.एस. सिस्टम का एक नया नमूना दिया है और गरीब से गरीब व्यक्ति को पेट भरने के लिए उसने नई योजना दी है।...*(व्यवधान)*

हमारी बहन ममता जी पश्चिम बंगाल को 35 साल की बुराइयों से बाहर लाने के लिए आज कितनी मेहनत कर रही हैं, हम उनकी इन बातों का आदर करते हैं। इसलिए हर राज्य में...*(व्यवधान)* केरल से भी... *(व्यवधान)* आप को जान कर खुशी होगी कि मैंने केरल के एक अफसर को बुलाया था। वह बहुत ही जुनियर ऑफिसर थे और वहां लेफ्ट की सरकार चल रही थी। उनकी आयु बहुत छोटी थी। मैंने अपने यहां एक चिंतन शिवर किया और मैं और मेरा पूरा मंत्री परिषद् एक स्टुडेंट के रूप में बैठा था। मैंने उनसे "कुटुम्ब श्री" योजना का अध्ययन किया था। उन्होंने हमें दो घंटे पढ़ाया।

मैंने नागालैंड के चीफ सेक्रेट्री को बुलाया था कि आइए मुझे पढ़ाइये। नागालैंड में ट्राइबल के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनी थी। यही तो हमारे देश का मॉडल होना चाहिए। हिन्दुस्तान के कोने में किसी भी विचारधारा की सरकार क्यों न हों, उसकी अच्छाइयों का हम आदर करें, अच्छाइयें को स्वीकार करें।...*(व्यवधान)* यही मॉडल देश के काम आएगा। हम बड़े भाई का व्यवहार कि तुम कौन होते हो? तुम ले जाना दो-चार टुकड़े, ऐसा नहीं चाहते हैं, हम मिल कर के देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम ने "कोपरेटिव फेडरलिज्म" की बात की है। सहकारिता के संगठित स्वरूप को ले कर चलने की हमने बात की है और इसलिए एक ऐसे रूप को आगे बढ़ाने का हम लोगों का प्रयास है, उस प्रयास को ले कर आगे चलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष महोदया जी, यह जो प्रस्ताव रखा गया है, उसके लिए आज मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का आभारी हूं और कुल मिला कर कह सकता हूं कि आज एक सार्थक चर्चा रही है और समर्थन में चर्चा रही है और अगर आलोचना भी हुई तो अपेक्षा के संदर्भ में हुई है। मैं इसे बहुत हेल्दी मानता हूं, इसका स्वागत करता हूं और आज किसी भी दल की तरफ से जो अच्छे सुझाव हमें मिले हैं उन्हें मैं अपनी आलोचना नहीं मानता हूं, उन्हें मैं मार्गदर्शक मानता हूं। उसका भी हम उपयोग करेंगे, अच्छाई के लिए उपयोग करेंगे और लोकतंत्र में आलोचना अच्छाई के लिए होती है और होनी भी चाहिए। सिर्फ आरोप बुरे होते हैं आलोचना कभी बुरी नहीं होती है, आलोचना तो ताकत देती है। अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतवर कोई जड़ी-बूटी है तो वह आलोचना है। हम उस आलोचना के लिए सदा-सर्वदा के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा हर नीतियों का अध्ययन करके गहरी आलोचना होनी चाहिए ताकि तप करके प्रखर होकर सोना निकले जो आने वाले दिनों में देश के लिए काम आए। उस भाव से हम चलना चाहते हैं।

आज नए सदन में मुझे अपनी बात बताने का अवसर मिला। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, कहीं कोई शब्द इधर-उधर हो गया हो, अगर मैं नियमों के बंधन से बाहर चला गया हूं तो यह सदन मुझे जरूर क्षमा करेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि सदन के पूरे सहयोग से, जैसे मैंने पहले कहा था, मतदान से पहले हम उम्मीदवार थे, मतदान के बाद हम उम्मीदों के रखवाले हैं, हम उम्मीदों के दूत हैं, सवा सौ करोड़ देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने का हम प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ इसे आप सबका समर्थन मिले। इसी बात को दोहराते हुए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए एक साथ रखूं?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

माननीय अध्यक्ष : अब, मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुएं

माननीय अध्यक्ष : अब, मैं सभा के मतदान के लिए प्रस्ताव रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 9 जून, 2014 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी है'।"

अपराह्न 5.08 बजे

विदाई उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम 4 जून, 2014 को प्रारंभ हुए सोलहवीं लोक सभा के पहले सत्र के समापन की ओर अग्रसर हैं।

सुस्थापित परंपरा के अनुसार नए सदन की पहली बैठक 4 जून, 2014 को अवसर की गंभीरता को देखते हुए कुछ क्षणों के मौन के साथ प्रारंभ हुई थी। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही 16वीं लोक सभा के माननीय सदस्य और केन्द्रीय मंत्री श्री गोपीनाथ राव मुंडे के दु:खद निधन के कारण स्थगित कर दी गई। 5 जून, 2014 को 513 सदस्यगणों ने शपथ अथवा प्रतिज्ञान लिया।

6 जून, 2014 को अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रस्ताव किया गया। मेरे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि सभा ने सर्वसम्मति से मेरा चयन लोक सभा अध्यक्ष के गरिमामय पद हेतु किया।

आज सभा द्वारा दोनों सदनों में 9 जून, 2014 को माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 12 घंटे से ज्यादा तक चले इस सुसंरचित वाद विवाद के उपरांत यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें 52 सदस्यों ने भाग लिया एवं 48 सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे।

सदस्यों द्वारा नियम 377 के अंतर्गत 34 मामले उठाए गए।

मैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सामयिक अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी और सभापति तालिका के सदस्यों को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने 16वीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ अथवा प्रतिज्ञान दिलाने हेतु प्रारंभिक दिनों में अध्यक्षता करने का दायित्व संभाला।

मैं, सभापति तालिका में सम्मिलित अपने माननीय सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में अपना

सहयोग दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मामले के मंत्रिगण, सभी मंत्रीगण, विभिन्न दलों और गुटों के नेतागण और माननीय सदस्यों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी।

मैं आप सभी की ओर से प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरा मीडिया और हमारे सभी मित्रों को भी धन्यवाद देती हूं। मैं इस अवसर पर महासचिव की उनके दक्ष और कुशल सहयोग के लिए प्रशंसा करना चाहूंगी। मैं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सभा के प्रति उनकी समर्पित और तत्पर सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं सभा की कार्यवाही को सुसंगठित रूप से चलाने में कुशल सहयोग प्रदान करने के लिए अनुषंगी सभी एजेंसियों का आभार व्यक्त करती हूं।

अपराह्न 5.12 बजे

राष्ट्र गीत

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब सभी माननीय सदस्य कृपया वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं।

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 5.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।